



# वार्षिक रिपोर्ट • 2013-14



रक्षा मंत्रालय  
भारत सरकार





विमान क्षेत्र पर सी-130जे का अवतरण



सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश का प्रयोक्ता परीक्षण

मुख्य पृष्ठ:  
दक्षिणावर्त

सी-17 ग्लोबमास्टर उत्तरी सेक्टर में संक्रियारत  
मिग-29के, आईएनएस विक्रमादित्य से  
पोखरण में भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास  
सियाचिन में सैनिक प्रौल पर

# वार्षिक रिपोर्ट 2013-14



सत्यमेव जयते

रक्षा मंत्रालय

भारत सरकार





# विषय सूची

1. सुरक्षा परिवेश	1
2. संगठनात्मक गठन और कार्य	11
3. भारतीय सेना	19
4. भारतीय नौसेना	29
5. भारतीय वायु सेना	41
6. भारतीय तटरक्षक	49
7. रक्षा उत्पादन	59
8. रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन	81
9. अंतर-सेवा संगठन	107
10. भर्ती एवं प्रशिक्षण	125
11. भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास तथा कल्याण	149
12. सशस्त्र सेनाओं तथा सिविल प्राधिकारियों के बीच सहयोग	159
13. राष्ट्रीय कैडेट कोर	171
14. विदेशों के साथ रक्षा सहयोग	183
15. समारोह और अन्य कार्यक्रम	195
16. सतर्कता यूनिटों की गतिविधियां	209
17. महिला सशक्तीकरण और कल्याण	217
परिशिष्ट	
I रक्षा मंत्रालय के विभागों के कार्यों की सूची	225
II 1 जनवरी, 2013 से आगे पदासीन मंत्री, सेनाध्यक्ष और सचिव	230
III रक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की अद्यतन रिपोर्ट का सारांश	232
IV सीएंडएजी रिपोर्टों/पीएसी रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों के संबंध में 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों की स्थिति	241
V रक्षा उत्पादन विभाग (2012-13) के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी)	242

1

# सुरक्षा परिवेश



**भारत** का सुरक्षा परिवेश क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा घटनाक्रमों और चुनौतियों का एक जटिल ताना-बाना है। हमारे देश का आकार और सामरिक अवस्थिति हमें सुरक्षा गतिकी का केन्द्र बिन्दु बनाती है जिस पर एक तरफ क्षेत्रीय और वैश्विक संयोजकता की सकारात्मक शक्तियों और दूसरी तरफ हमारे आस-पड़ोस में सीमा से लगे हुए देशों और उससे आगे के भू-भाग में अनिश्चितता, अस्थिरता और हल चल से उत्पन्न होने वाले परिणामों का एक साथ प्रभाव पड़ता है।

1.1 भारत का सुरक्षा परिवेश क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा घटनाक्रमों और चुनौतियों का एक जटिल ताना-बाना है। हमारे देश का आकार और सामरिक अवस्थिति हमें सुरक्षा गतिकी का केन्द्र बिन्दु बनाती है जिस पर एक तरफ क्षेत्रीय और वैश्विक संयोजकता की सकारात्मक शक्तियों और दूसरी तरफ हमारे आस-पड़ोस में सीमा से लगे हुए देशों और उससे आगे के भू-भाग में अनिश्चितता, अस्थिरता और हलचल से उत्पन्न होने वाले परिणामों का एक साथ प्रभाव पड़ता है।

1.2 भारत, जहां देश के भीतर आमूल चूल राष्ट्रीय प्रगति और विकास हासिल करने का प्रयास कर रहा है, वहीं हम एक सुदृढ़ रक्षा रणनीति और नीतियों पर अमल कर रहे हैं जिनका उद्देश्य देश के समक्ष मौजूद व्यापक पारम्परिक और गैर-पारम्परिक चुनौतियों से निपटना है। रणनीतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों के जरिए ताकत जुटाने के सिद्धांत पर चलते हुए, भारत अपनी स्वयं की क्षमताओं में वृद्धि करने और शान्ति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में अपने पड़ोसियों तथा अन्य वैश्विक सहयोगी

देशों के साथ रचनात्मक सहयोग की दिशा में प्रयासरत है।

## वैश्विक सुरक्षा परिवेश

1.3 भारत की भू-सामरिक अवस्थिति इसे इसके निकट पड़ोस से आगे, एशिया प्रशान्त, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और हिन्दमहासागर क्षेत्र में घटित हो रहे घटना क्रम के प्रति संवेदनशील बनाती है। वर्तमान में घटित हो रहे प्रमुख भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक घटना क्रम वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को अनिश्चितता और अस्थिरता के माहौल में परिवर्तित कर रहे हैं।

1.4 शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से वैश्विक सुरक्षा परिवेश में बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। एक तरफ विश्व में भूमंडलीकरण में तेजी और आर्थिक दृष्टि से परस्पर निर्भरता में वृद्धि देखने में आई है जिससे भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के विकास में तेजी आई है। दूसरी तरफ, विश्व के अधिकांश भाग संघर्ष और हिंसा से निरन्तर रूप से ग्रस्त हैं। वैश्विक शक्ति संतुलन में नए समायोजन और गत्यात्मकता देखने में आई है जिससे नई सामरिक



अनिश्चितताएं उत्पन्न हुई हैं जो प्रायः प्रतिस्पर्धाओं और विवादों के रूप में परिलक्षित होती हैं।

1.5 भले ही शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से पूर्ण स्तरीय परंपरागत युद्ध की संभावना कम हो गई मान ली गई हो, तो भी अनेक कारक क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में नई चुनौतियों की बढ़ोत्तरी के कारण बने हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर वर्चस्व हेतु गहन प्रतिस्पर्धा राष्ट्रों के बीच भू-भागीय विवादों के मौजूदा विस्तार में अस्थिरता का एक और दौर जोड़ती है और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मानकों तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के स्वीकृत मानदण्डों के लिए चुनौती पैदा करती है।

1.6 आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों द्वारा उत्पन्न राष्ट्र-पारीय खतरों में अन्तः राज्य और अन्तर्राज्य संघर्षों के फैलाव के चलते और तीव्रता आई है और ये खतरे इनके उद्गम स्थलों से इतर देशों के लिए भी खतरा उत्पन्न करते हैं। लड़ाकू सैनिकों की एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्रों में आवाजाही और आतंकवादी गतिविधियों हेतु संभारिकी सहायता ने विश्व भर में देशों के लिए आन्तरिक सुरक्षा संबंधी चुनौती उत्पन्न की है। दूरसंचार और साइबर डोमेन में तकनीकी उन्नति ने आतंकवादी गतिविधियों की क्षमताओं और प्रभाव को बढ़ाने में बल प्रवर्धक का काम किया है। भारत के पड़ोस से उत्पन्न होने वाले आतंकवादी खतरों और राष्ट्र-पारीय तथा अन्य संपर्कों, जिनके जरिए इन आतंकवादी गुटों को पनाह मिल रही है, पर लगातार चिंता बनी हुई है।

1.7 विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में शान्ति और स्थिरता की संभावना को व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार

से भी धक्का पहुंचा है और यह परमाणु सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सरकारी नियंत्रण रहित संगठनों को परमाणु सामग्री हासिल करने से रोकने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की एक प्रमुख चिन्ता बनी हुई है। समुद्री उकैती और समुद्री सुरक्षा की अन्य चुनौतियां क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं।



8. वैश्विक शक्ति संतुलन के यूरोप से एशिया - प्रशान्त क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाने से आर्थिक, सैन्य और राजनियक कारकों का एक जटिल और गतिशील गठजोड़ सामने आया है और यह सामुद्रिक क्षेत्रीय विवादों, सैन्य स्थितियों और शक्तिप्रतिद्वन्द्विताओं में वृद्धि में परिलक्षित होता है, इन सबने मिलाकर इस क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति में अनिश्चितताओं में वृद्धि की है। एशिया प्रशान्त में द्वीपीय क्षेत्रों पर एक दूसरे के विरोधी दावों ने इस क्षेत्र में तनाव उत्पन्न किया है और एशिया प्रशान्त समुदाय के ध्रुवीकरण की आशंका पैदा की है। कोरियाई प्रायद्वीप, जहां उत्तरी कोरिया ने अपना तीसरा परमाणु परीक्षण किया है, में भी उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य तनाव के चलते

स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इन घटनाक्रमों के चलते वैश्विक शक्तियां क्षेत्रीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही हैं जो इस क्षेत्र में सैन्य संतुलन को प्रभावित कर रहा है और देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर प्रभाव डाल रहा है। गैर-परम्परागत चुनौतियां जैसे कि राष्ट्र-पारीय अपराध, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा, वैश्विक महामारियां, साइबर सुरक्षा तथा खाद्य और उर्जा सुरक्षा भी इस क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं।

1.9 भारत के एशिया प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनैतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और सामाजिक हित हैं और इस क्षेत्र में निरंतर शांति और स्थिरता बने रहने में भारत का हित निहित है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में नौ वहन की स्वतंत्रता और आवाजाही के अधिकार का समर्थक है। भारत का दृष्टिकोण यह है कि सभी देशों को संयम बरतना चाहिए और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार द्विपक्षीय मुद्दों का बल का प्रयोग किए बिना या बल-प्रयोग की धमकी दिए बिना राजनयिक ढंग से समाधान करना चाहिए। भारत का यह मत है कि वर्तमान क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में सहकारिता के सिद्धांत को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अतः हम एशिया-प्रशांत देशों के साथ द्विपक्षीय के साथ-साथ बहुपक्षीय मंचों जैसे ईस्ट एशिया समिट, एडी एम एम-प्लस और आसियान रीजनल फोरम (एआरएफ) के तंत्र के जरिए सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं ताकि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता में योगदान दे सकें।

1.10 मध्य एशियाई क्षेत्र ने हाल के दिनों में हाइड्रोकार्बन और खनिज संसाधनों की मौजूदगी के कारण प्रमुखता हासिल की है। इस क्षेत्र में बढ़ती हुई

सामरिक प्रतिस्पर्धा के कारण भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ा है। इस क्षेत्र में अपने वृहत भू - सामरिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए, भारत ने मध्य एशियाई गणतंत्रों के साथ सुदृढ़ राजनीतिक-आर्थिक और सुरक्षा संबंधी भागीदारियां विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित किया है।

1.11 यूक्रेन की स्थिति ने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए एक नई चुनौती सामने ला खड़ी की है और टकराव की इस स्थिति के लम्बा खिंचने से अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारत का विश्वास है कि मौजूदा समस्या के एक राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान की गुंजाइश है।



1.12 पश्चिमी एशियाई क्षेत्र अरब स्प्रिंग द्वारा लाए गए परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में निरंतर उथल-पुथल और अस्थिरता का सामना कर रहा है। इन परिवर्तनों से इस क्षेत्र के कई भागों में मूलभूत राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन आए हैं। इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में अनेक सरकारी नियंत्रण रहित संगठन पनप आए हैं। साम्प्रदायिक अलगाव भी गहरा हुआ है जिससे इस क्षेत्र में विभिन्न देशों

की स्थिरता और आन्तरिक एकजुटता में व्यवधान पहुंचा है। भारत के इस क्षेत्र में न केवल महत्वपूर्ण हित समाहित हैं, वरन् यहां के देशों और लोगों के साथ उसके दीर्घकालिक संबंध हैं। पश्चिम एशिया में निरन्तर अशांति और अनिश्चितता का इस क्षेत्र में भारत के वैविध्यपूर्ण हितों पर भारी प्रभाव होगा जिसमें इस क्षेत्र में रह रहे और काम कर रहे लगभग सात मिलियन भारतीयों की सुरक्षा और हिफाजत के साथ इस क्षेत्र से भारत के उर्जा आयातों का अबाधित प्रवाह शामिल है। अतः भारत साझा सरोकार के रक्षा और सुरक्षा संबंधी विषयों पर इस क्षेत्र के देशों के साथ सतत सम्पर्क में है।

1.13 **सीरिया और इराक** में उभरती स्थिति इन देशों की स्थिरता पर वर्तमान घटना क्रमों के प्रभाव तथा इस क्षेत्र के भीतर और उससे आगे के अन्य देशों के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप प्रभावों की दृष्टि से बढ़ती चिंता का विषय है। सीरियाई संघर्ष के इराक तक फैल जाने से इस क्षेत्र में गंभीर स्थितियां पैदा हुई हैं जिसने उग्रवादी और साम्प्रदायिक अलगाव को बढ़ावा दिया है। भारत ने सीरिया में हिंसा और मानवीय क्षति पर गहरी चिंता प्रकट की है और निरन्तर रूप से एक समावेशी और व्यापक राजनीतिक समाधान की मांग की है जिसमें सीरियाई लोगों की विधि सम्मत आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाएगा। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई तथा अपनी एकता और प्रादेशिक अखण्डता बनाए रखने के उसके प्रयासों में इराक को दृढ़ समर्थन भी व्यक्त किया है।

1.14 इजराइल और फिलीस्तीन के बीच हिंसा में वृद्धि एक चिंता का विषय है और इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए और खतरा पैदा करता है।

1.15 इरान भारत के आर्थिक और सुरक्षा संबंधी ताने बाने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत ने ई-3+3 और इरान के बीच अन्तरिम परमाणु करार का स्वागत किया है और वह संबंधित पक्षों के बीच एक व्यापक वार्ता के जरिए इरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करने का समर्थन करता है।

1.16 **अफ्रीका** के कई क्षेत्रों में उथल-पुथल मची है क्योंकि कई उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में विद्रोह और बगावत की लहर फैली हुई है। विशेष चिंता का विषय क्षेत्र में आतंकी संगठनों का बढ़ता प्रभाव है। जबकि पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री डकैती के खतरे में कमी आई है, गीनी की खाड़ी में इसने गंभीर रूप अख्तियार किया है। गीनी की खाड़ी में कई भारतीय समुद्री यात्री समुद्री डकैती के कृत्यों से प्रभावित हुए हैं। नाइजीरिया और अन्य देशों में आतंकी संगठनों की गतिविधियां इन देशों की आंतरिक स्थिरता के लिए खतरा हैं और उनके और अन्य आतंकी संगठनों के बीच सांठ-गांठ गहरी चिंता का विषय है। भारत का कई अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ ऐतिहासिक संबंध रहा है और यह भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के जरिए आपसी संबंधों को गहरा बनाने हेतु सामरिक पहल करता है जो अफ्रीकी देशों के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और महादेश-स्तर पर



राजनैतिक, आर्थिक विकास और सामरिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है ।

1.17 **हिंद महासागर** का क्षेत्र भारत की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है । ऐतिहासिक परंपराओं के कारण एक समुद्री राष्ट्र होने और अपने भू-भौतिकीय आकृति और भू-राजनैतिक परिस्थितियों के कारण भारत अपने चारों ओर के महासागरों पर निर्भर है । हिन्द महासागर प्रदेश में भारत का महाद्विपीय फैलाव इसे संसार के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के निकट लाकर खड़ा करता है जो स्वेज नहर और फारस की खाड़ी से लेकर मलक्का जलडमरूमध्य तक फैला हुआ है । भारत की सुरक्षा और समृद्धि इन्हीं समुद्री मार्गों और इसके समुद्री व्यापार और वाणिज्य में स्वतंत्र रूप से लगे रहने की इसकी योग्यता पर निर्भर करता है ।



18. हिन्द महासागर का क्षेत्र समुद्री उकैती, आतंकवाद, मानव व्यापार, डब्ल्यूएमडी का प्रसार और समुद्री संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न होने वाली कई सुरक्षा चिंताओं के स्रोत के रूप में उभर

रहा है । इसके परिणामस्वरूप, हिंद महासागर में इतर-प्रादेशिक शक्तियों की उपस्थिति बढ़ी है जिससे उनके बीच भू-सामरिक प्रतिस्पर्धा की संभावना बढ़ी है । चूंकि समुद्री सुरक्षा के मुद्दे अत्यधिक तात्कालिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं, हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति में शामिल होने की प्रतिस्पर्धा को नजदीक से मानीटर किए जाने की जरूरत है क्योंकि इस क्षेत्र में भारत के सामरिक हित इसकी सुरक्षा गणना के हिसाब से अति महत्वपूर्ण हैं ।

1.19 भारत हिंद महासागर क्षेत्र में या इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में अवस्थित विभिन्न क्षेत्रीय मंचों में सक्रिय रूप से कार्यरत है ताकि एक सहकारी संरचना तंत्र का निर्माण किया जा सके जो आपसी हितों पर आधारित सभी पणधारियों को एकजुट करेगा। भारत और हिन्द महासागर में स्थित विभिन्न द्विपीय देशों नामतः श्रीलंका, मालदीव, मारीशस और सेशेल्स के बीच विस्तृत समुद्री सुरक्षा सहयोग ढांचा स्थापित करने की पहल समुद्री सुरक्षा की साझी चुनौतियों और सहयोगात्मक उपायों की जरूरतों की आपसी समझ की उपज है ।

## क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश

1.20 एक सुरक्षित, स्थायी, शांतिपूर्ण और समृद्ध पड़ोस का होना भारत के सुरक्षा परिदृश्य के केन्द्र में है । दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश हमारे निकटतम पड़ोसी देश से उभरने वाले आतंकवाद, बगावत और साम्प्रदायिक झड़पों के कारण हमेशा परिवर्तनशील रहा है जिससे हमारे क्षेत्र के स्थायित्व पर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है । किए जा रहे

प्रयासों के बीच, पड़ोसी देशों के साथ व्यापक स्तर पर संबंधों को मजबूत करने के लिए नया जोश और गति प्रदान करने हेतु सामरिक अनिश्चितता की इस अवधि में एक सहयोगात्मक सामरिक संरचना विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। भारत, समता और आपसी लाभ एवं सम्मान पर आधारित पड़ोस के सभी भागीदारों के साथ खुली और वार्ता आधारित सुरक्षा सहयोग के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

1.21 चूंकि अफगानिस्तान से अन्तरराष्ट्रीय सैन्य बल वापसी करने के चरण में हैं, अतः अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति की निकट से मानीटरिंग किए जाने की आवश्यकता है। अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों (एएनएसएफ) द्वारा देश की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी लिए जाने के साथ, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि एएनएसएफ को सुसज्जित करने और उसकी क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं के लिए सतत सहयोग अवश्य उपलब्ध कराएं ताकि वे संभावित सुरक्षा चुनौतियों के सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य का सामना कर सकें। अफगान-चालित और अफगान की स्वामित्व वाले राष्ट्रीय सुलह प्रक्रिया के नए अवसरों के साथ देश में होने वाले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन अफगानिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक भागीदारी करार, आतंकवाद और अन्य सुरक्षा चुनौतियों के विरुद्ध लड़ाई में आपसी क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से रक्षा और सुरक्षा सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बनाने हेतु दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है।

1.22 भारत पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध विकसित करना चाहता है। तथापि इसके नियंत्रणाधीन भू-भाग से कार्यरत आतंकी संगठनों की निरंतर गतिविधियों के कारण पाकिस्तान के साथ सुरक्षा चिंताएं बनी हुई हैं। भारत ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हम सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण, द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया के जरिए समाधान करना चाहते हैं। तथापि, ऐसी वार्ताओं को सार्थक बनाने के लिए आतंक और हिंसामुक्त वातावरण बनाए जाने की आवश्यकता है। हाल में दिसम्बर, 2013 में बाघा में हुई दोनों देशों के सैन्य संक्रिया महानिदेशकों की बैठक के दौरान पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर शांति और अमन बनाए रखने और युद्ध विराम सुनिश्चित करने की अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है। तथापि, भारत-पाक सीमा रेखा और नियंत्रण रेखा के पार आतंकी शिविरों का होना और नियंत्रण रेखा पर और उसके पार से लगातार हो रही घुसपैठ और ऐसी घटनाएं इस संबंध में चुनौतियां दर्शाती हैं। भारत का मानना यह है कि पाकिस्तान के भूभाग में कार्यरत आतंकी समूहों के निपटने में पाकिस्तान द्वारा अपनाई जा रही नीति से न तो इस क्षेत्र के हित-साधन होगा और न ही पाकिस्तान का, विशेषकर चूंकि ये संगठन पाकिस्तान की स्वयं की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं।

1.23 यद्यपि भारत और चीन के बीच अनसुलझा सीमा विवाद भारत के सुरक्षा परिकलन का एक मुख्य कारक है, तथापि भारत, चीन के साथ आपसी विश्वास और एक-दूसरे के हितों तथा संबंधों के लिए सम्मान के सिद्धान्तों पर चलता रहा है। दोनों देश सीमा पर अमन

और शान्ति बनाए रखने की आवश्यकता पर सहमत हैं और दोनों पक्षों की सशस्त्र सेनाओं के बीच बातचीत और विश्वास बनाने के उपायों को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। वर्ष 2013 में चीन के साथ सम्पन्न सीमा रक्षा सहयोग करार दोनों देशों के बीच विश्वास बनाने के उपायों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और इससे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अमन और शान्ति बनाए रखने में योगदान की आशा है। भारत, चीन द्वारा सीमा-क्षेत्र में सामरिक अवसंरचना के विकास के साथ-साथ निकट तथा विस्तारित पड़ोस में उसकी सैन्य स्थिति के प्रभावों के प्रति सचेत और चौकस भी बना हुआ है। भारत अपनी सुरक्षा पर किसी प्रतिकूल प्रभाव का सामना करने हेतु वांछित क्षमताओं का विकास करने के लिए आवश्यक उपाय भी कर रहा है।

1.24 भारत और **भूटान** के परम्परागत और अपूर्व द्विपक्षीय संबंध हैं जो कि वर्षों में बने अत्यधिक आपसी विश्वास और आपसी गहरी समझ से बना है। भारत और भूटान 1961 से ही विशेषाधिकार युक्त सामाजिक-आर्थिक भागीदार रहे हैं। आज दोनों देशों के बीच जलविद्युत, रक्षा और सुरक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंध सहित व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में गहरा सहयोग है।

1.25 निकट पड़ोसियों के रूप में, भारत और **नेपाल** के बीच मित्रता और सहयोग के अनोखे संबंध हैं। खुली सीमाएं तथा एक दूसरे के नागरिकों के बीच अत्यंत करीबी रिश्तेदारी और संस्कृति इन संबंधों की विशेषताएं रही हैं। सीमाओं पर लोगों

के खुले आने जाने की एक लंबी प्रथा रही है। भारतीय हितों के प्रति कुछ विरोधी तत्वों द्वारा खुली सीमाओं का दुरुपयोग एक ऐसी चुनौती है जिसका निवारण दोनों देश संयुक्त रूप से कर रहे हैं। चूंकि दोनों देशों की सुरक्षा और आर्थिक हित मिले हुए हैं, भारत, समीपस्थ मित्र और पड़ोसी के रूप में, आपसी सम्मान और समानता के सिद्धान्तों के आधार पर राष्ट्रीय प्रयास के सभी क्षेत्रों में सरकार और नेपाल की जनता के साथ भागीदारी करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है।

1.26 **म्यांमार** के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक, जातीय सांस्कृतिक और धार्मिक बंधनों में गहराई से जुड़े हुए हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। सीमा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन भारत और म्यांमार के मध्य मई, 2014 में किया गया जिसमें समन्वित निगरानी, आसूचना सहयोग, प्रति-विद्रोह, शस्त्र-तस्करी, ड्रग, मानव और वन्य जीव तस्करी के क्षेत्र में भारत और म्यांमार सुरक्षा एजेंसियों के बीच सुरक्षा सहयोग और आसूचना आदान-प्रदान करने के मजबूत ढांचे का प्रावधान है। 2012 में हुए सीमा क्षेत्र विकास पर एक समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत म्यांमार में स्कूल, अस्पताल और पुल निर्माण से संबंधित परियोजनाओं में सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है।

1.27 भारत और **बांग्लादेश** के मध्य सहयोगी संबंध क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में सकारात्मक तथ्य के रूप में रहे हैं। सुरक्षा मुद्दों और सीमा सुरक्षा सरोकारों



के प्रबंधन पर दोनों देशों की चिन्ताओं और विचारों में उच्च स्तर की समभिरूपता है। भारत बांग्ला देश को अपनी सुरक्षा चिन्ताओं, विशेषकर भारतीय विद्रोह समूहों (आईआईजी) और दूसरे राष्ट्रों के आतंवादियों द्वारा बांग्लादेशी भू-भाग का प्रयोग करने पर लगातार जोर देता रहा है।

1.28 जुलाई, 2011 में दोनों देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए एक समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सीपीएमपी) सीमा पार अवैध क्रिया - कलापों और अपराधों के साथ-साथ भारत बांग्ला देश सीमा पर शान्ति और सदभावना बनाएं रखने हेतु और प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए दोनों देशों के सीमा रक्षक बलों के प्रयासों में सहक्रियाशीलता शामिल है। सभी स्तर की बैठकों के माध्यम से सीमा प्रबंधन पर चर्चा के लिए संस्थागत विचार-विनिमय की एक प्रणाली ऐसे सभी चिन्ताओं को दूर करती हैं।

1.29 भारत और **श्रीलंका** के बीच संबंध साझा सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषायी और ऐतिहासिक बंधनों के आधार पर हैं और ये सहयोगी और सृजनात्मक बने रहे हैं। समुद्रवर्ती सुरक्षा चुनौतियां और हिन्द महासागर क्षेत्र में शांति और स्थायित्व को बनाए रखना सामान्य चिन्ताएं हैं जो दोनों देशों के बीच सामरिक हितों की समभिरूपता प्रदान करते हैं और रक्षा के क्षेत्र में सतत सहयोग पर बल देते रहे हैं। भारत श्रीलंका में आपसी मेल-मिलाप की प्रक्रिया में सहयोगी रहा है और संगठित श्रीलंका के ढांचे के भीतर दीर्घ कालिक राजनीतिक बंदोबस्त का समर्थन करता है जो समानता, न्याय, शान्ति और गरिमा समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।

1.30 भारत और **मालदीव** के मध्य सुरक्षा सहयोग द्विपक्षीय सहयोग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है, क्योंकि दोनों देशों के सुरक्षा हित आपस में जुड़े हुए हैं। द्विपक्षीय संबंध उच्चतम स्तर और दोनों देशों के रक्षाबलों के विभिन्न स्तर पर नियमित सम्पर्क के माध्यम से पोषित और सुदृढ़ किए जा रहे हैं।

1.31 क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा चुनौतियों की सामान्य प्रकृति त्रिपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग संबंधी रूपरेखा के लिए नींव है जिसके माध्यम से भारत, श्रीलंका और मालदीव विविध समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त क्षमताएं विकसित करने के लिए कार्यरत है। यह प्रयास नियमित आधार पर वार्ता और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी तीनों देशों के रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को सक्षम बनाता है। आशा की जाती है कि यह प्रयास इस क्षेत्र में सुरक्षा के सहयोगी दृष्टिकोण के विकास में सहायता प्रदान करेगा।

1.32 गैर-परम्परागत खतरे जैसे कि व्यापक संहार के हथियारों का प्रसार, आतंकवाद, मादक पदार्थ, मानव तस्करी इत्यादि द्वारा सामने आई चुनौती भारत की सुरक्षा कार्यसूची में निरंतर ऊपर बने हुए हैं। कुछ देशों द्वारा आपराधिक क्षमताओं के प्रदर्शन से साइबर और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में नई चुनौतियां उभर कर सामने आई हैं। भविष्य में, इनके सुरक्षा स्थिति को आकार देने की संभावना है। अतः इनका विभिन्न सरकारों, बहु-एजेंसी दृष्टिकोण, जिसका सशस्त्र सेनाएं महत्वपूर्ण और मूलभूत भाग हैं, के माध्यम से समाधान किया जा रहा है।

## आंतरिक सुरक्षा परिवेश

1.33 भारत के सामने बहुमुखी आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं जिनमें वामपंथी उग्रवाद, जम्मू एवं कश्मीर में चल रहा परोक्ष युद्ध और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में विद्रोह, शामिल हैं।

1.34 अलगाववादी और राष्ट्र विरोधी तत्व जम्मू एवं कश्मीर में मौजूदा शांति को भंग करने के लिए अपने प्रयासों में लगे हुए हैं। तथापि सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सरकार की कारगर संक्रियाओं के कारण इस राज्य में सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सेना और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा प्रभावी आंतक विरोधी संक्रियाओं से 2013 और 2014 में अनेक कट्टर आंतकवादियों का खात्मा करने में सफलता मिली है। अफगानिस्तान में अंतरराष्ट्रीय बलों की वापसी के संभावित प्रभावों सहित विभिन्न कारकों का जम्मू एवं कश्मीर

अनिश्चितता और अस्थिरता से पूरिपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश में भारत की रक्षा सेनाएं तमाम सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहती हैं।

में भावी सुरक्षा स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है।

1.35 पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति स्थिर है और हिंसा के स्तरों में गत वर्ष काफी कमी आई है। 47 से अधिक विद्रोही समूह वर्तमान

में युद्ध विराम/संक्रियाओं के आस्थगन और वार्ताओं के दौर में हैं जिससे संघर्ष विराम उपायों के कार्यान्वयन के लिए अनुकूल वातावरण पैदा हुआ है।

1.36 अनिश्चितता और अस्थिरता से पूरिपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश में भारत की रक्षा सेनाएं तमाम सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहती हैं। इसके साथ-साथ भारत सहयोगी, रचनात्मक और पारस्परिक रूप में हितकारी संबंधों के माध्यम से क्षेत्रीय और वैश्विक समुदाय के साथ इस विधि से जुड़ा रहता है जो राष्ट्रीय हितों को पूरा करें और वैश्विक शांति एवं स्थायित्व के बृहतर हितों में भी योगदान कर सकें।

## संगठनात्मक गठन और कार्य



साउथ ब्लॉक



**इ**स मंत्रालय का मुख्य काम रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में नीति-निदेश बनाना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सेना मुख्यालयों, अंतर-सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं और अनुसंधान तथा विकास संगठनों को भेजना है ।

## **संगठनात्मक ढांचा और कार्य**

2.1 स्वतंत्रता के बाद रक्षा मंत्रालय का गठन एक कैबिनेट मंत्री के अधीन किया गया था और प्रत्येक सेना को उसके अपने कमांडर-इन-चीफ के अधीन रखा गया। 1955 में, कमांडर-इन-चीफ का सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष तथा वायुसेनाध्यक्ष के रूप में पुनः नामकरण किया गया था । नवंबर, 1962 में रक्षा उपस्करों के अनुसंधान, विकास तथा उत्पादन संबंधी कार्य के लिए रक्षा उत्पादन विभाग का गठन किया गया था । नवंबर, 1965 में, रक्षा आवश्यकताओं के आयात प्रतिस्थापन के लिए योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए रक्षा पूर्ति विभाग बनाया गया था । बाद में, इन दोनों विभागों को मिलाकर रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग बना दिया गया था। वर्ष 2004 में रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग का नाम बदलकर रक्षा उत्पादन विभाग रख दिया गया । 1980 में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग बनाया गया । वर्ष 2004 में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग बनाया गया।

2.2 रक्षा सचिव, रक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और इसके अलावा, मंत्रालय के चारों

विभागों के कार्यों में समन्वय बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी हैं ।

## **मंत्रालय और इसके विभाग**

2.3 इस मंत्रालय का मुख्य काम रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में नीति-निदेश बनाना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सेना मुख्यालयों, अंतर-सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं और अनुसंधान तथा विकास संगठनों को भेजना है । मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सरकार के नीति-निर्देशों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए और अनुमोदित कार्यक्रमों का निष्पादन आबंटित संसाधनों के अंतर्गत किया जाए ।

2.4 इन विभागों के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:-

- (i) रक्षा विभाग, एकीकृत रक्षा स्टाफ, तीनों सेनाओं और विभिन्न अंतर सेवा संगठनों से संबंधित कार्य करता है । यह विभाग रक्षा बजट, स्थापना मामलों, रक्षा नीति, संसदीय मामलों, अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग और रक्षा संबंधी सभी कार्यकलापों के समन्वय संबंधी कार्य के लिए भी उत्तरदायी है ।

(ii) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं और यह विभाग रक्षा उत्पादन कार्यों, आयात किए जाने वाले सामान, उपस्करों और कलपुर्जों के देशीकरण, आयुध निर्माणी बोर्ड और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की विभागीय उत्पादन इकाइयों के बारे में योजना तैयार करने तथा उन पर नियंत्रण रखने से संबंधित कार्य करता है ।

(iii) रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं जो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। इस विभाग का कार्य सैन्य उपस्करों और संभारतंत्र से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को सलाह देना और तीनों सेनाओं द्वारा अपेक्षित साज-समान के अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यों के लिए योजनाएं तैयार करना है ।

(iv) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं और यह विभाग भूतपूर्व सैनिकों के सभी पुनर्वास, कल्याण तथा पेंशन संबंधी मामलों को देखता है ।

2.5 रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों और वित्त प्रभाग द्वारा निपटाई जाने वाली मदों की सूची इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट-I** में दी गई है ।

2.6 इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान रक्षा मंत्रालय के मंत्रियों, सेनाध्यक्षों और मंत्रालय के विभागों के सचिवों और सचिव (रक्षा वित्त)/वित्त सलाहकार (रक्षा सेवाएं) के पदों पर कार्यरत अधिकारियों से संबंधित सूचना इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट-II** में दी गई है ।

## मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ

2.7 'उच्चतर रक्षा प्रबंधन' की पुनरीक्षा के लिए गठित मंत्रिसमूह की सिफारिशों के आधार पर मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ 1 अक्टूबर, 2001 को अस्तित्व में आया। सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष के तत्वावधान में यह संगठन सेनाओं के बीच सम्बद्धता तथा सहक्रियाशीलता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है ।

2.8 **मानवीय सहायता और आपदा राहत (एच ए डी आर):** मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ देश के भीतर और देश से बाहर दोनों जगह मानवीय सहायता और आपदा राहत (एच ए डी आर) कार्रवाइयों के दौरान सशस्त्र सेनाओं की प्रतिक्रिया के समन्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है । मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ मानवीय सहायता और आपदा राहत में शामिल विभिन्न अभिकरणों जैसे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण (एन डी एम ए), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम), गैर-सरकारी संगठनों और कार्पोरेट सेक्टरों से नियमित रूप से संपर्क बनाए रखता है।

2.9 वर्ष के दौरान, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ ने विभिन्न मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों, जिनमें उत्तराखंड आपदा राहत अभियान, प्रचण्ड तूफान फेलिन, टाईफून लहर, तिरुपति मंदिर के निकट तिरुमाला (शेशचलम जंगल) में लगी दावानल, फिलिपिंस में आया तूफान हैयान और मलेशियाई एयरलाइनर एमएच 370 का

ऑपरेशन 'सर्चलाइट-सार' शामिल है, में समन्वय का कार्य किया ।

2.10 'मिलन' भारतीय नौसेना द्वारा पोर्ट ब्लेयर के अंडमान और निकोबार कमान में द्विवार्षिक रूप से संचालित तटीय नौसैनिकों की एक मिलन मंडली है। यह "समुद्रपार मित्रता" विषय के साथ दिनांक 4 से 9 फरवरी, 2014 तक पोर्ट ब्लेयर में संचालित किया गया । मिलन-2014 में कुल 17 देशों ने भाग लिया । भाग लेने वाले देशों द्वारा वहां प्रभावशाली ढंग से नगर मार्च भी किया गया । विदेशी जहाजों को स्कूली बच्चों और आम जनता के देखने के लिए भी खुला रखा गया। मिलन 2014 का समापन सभी भागीदारी समुद्री पोतों द्वारा समुद्री अभ्यास **पासेक्स** के साथ हुआ ।

2.11 **समन्वित गश्त (कोरपैट):** अंडमान व निकोबार कमान की पोतें और वायुयानों ने इंडोनेशिया, थाइलैंड और म्यांमार के नौसैनिकों के साथ समन्वित गश्त "कोरपैट" में भाग लिया। इसका लक्ष्य नौसेनाओं के बीच आपसी समझा और अन्तर संक्रियात्मकता को

**'मिलन' भारतीय नौसेना द्वारा पोर्ट ब्लेयर के अंडमान और निकोबार कमान में द्विवार्षिक रूप से संचालित तटीय नौसैनिकों की एक मिलन मंडली है।**

बढ़ावा देना है।

2.12 **भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (इंदू):** माननीय प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री, सामाजिक न्याय और

अधिकारिता मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, विदेश मंत्री, हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, एनएसए, गुडगांव के संसद सदस्य और तीनों सेना प्रमुखों की उपस्थिति में बिनोला एवं बिलासपुर, गुडगांव में दिनांक 23 मई, 2013 को इंदू की स्थापना के लिए शिलान्यास किया।

2.13 **संयुक्त सिद्धांत का प्रख्यापन:** महत्वपूर्ण संक्रियात्मक विषयों पर 10 संयुक्त सिद्धांतों (भारतीय सशस्त्र बलों के लिए कैपस्टोन संयुक्त सिद्धांत सहित) का प्रख्यापन किया गया। इससे भारतीय सशस्त्र बलों की एकजुटता को बढ़ावा देने में बड़ा संबल मिला। पिछले वर्ष संचालित अभ्यासों और मानवीय राहत अभियानों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर, संगत पक्रियाओं और प्रचलनों को आगे अद्यतित किया गया ।



2.14 **सैन्य सहयोग :** सरकार की समग्र विदेश नीति के अनुरूप अन्तरराष्ट्रीय रक्षा सहयोग निदेशालय पहले से ही क्रियाशील है और मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के स्तर पर मित्र राष्ट्रों के साथ कई रक्षा कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान कर रहा है। ये प्रयास दुनिया के अन्य भागों में स्थित हमारे महत्वपूर्ण संबंधों को मजबूत बनाने के साथ-साथ सुरक्षा, पड़ोसियों के साथ राष्ट्र की सामरिक हितों और आसियान देशों के साथ भागीदारी पर केन्द्रित थे ।

2.15 **तीनों सेनाओं का आईसीटी रोडमैप:** तीनों सेनाओं का आईसीटी रोडमैप सेनाओं में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रणाली के एकीकरण करने, मानकीकरण और अधिप्राप्ति की प्रक्रिया की अंतरसंक्रियात्मकता बढ़ाने व सुव्यवस्थित करने के लिए वर्ष 2008 में प्रख्यापित किया गया था। आई सी टी डोमेन में हुई समकालीन परिवर्तनों को शामिल करने के लिए इस रोडमैप की समीक्षा की गई। यह ट्राइ सर्विसेज आइसीटी रोडमैप को अंतिम रूप दिए जाने और अनुमोदित किए जाने के अंतिम चरण में है।

2.16 **चिकित्सा शाखा:** चिकित्सा सेवा सलाहकार समिति की सिफारिशों पर सीओएससी द्वारा कर्तव्यों का चार्टर जनशक्ति और ऑर्गेनोग्राम आदि अनुमोदित किया गया । चिकित्सा शाखा ने रिपोर्टाधीन अवधि में मेडिकल स्टोरों और आपूर्ति प्रबंधन, टेलिमेडिसिन और संयुक्त चिकित्सा प्रशिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है । सशस्त्र बल खेलकूद

चिकित्सा केन्द्र को पुनर्जीवित करने और सैन्य अस्पताल के प्रत्यायन की परियोजना चल रही है।

## सशस्त्र बल अभिकरण

2.17 सरकार ने सशस्त्र बलों के सदस्यों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के लिए, सेवा मामलों से संबंधित विवादों और शिकायतों तथा तीनों सेनाओं (सेना, नौसेना और वायुसेना) के सदस्यों के कोर्ट मार्शल के निर्णयों से उत्पन्न अपीलों के अधिनिर्णय के लिए एक सशस्त्र बल अधिकरण की स्थापना की है ।

2.18 वर्तमान में, दिल्ली स्थित प्रधान पीठ सहित चेन्नै, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, कोच्चि, गुवाहाटी और मुंबई में क्षेत्रीय पीठ कार्यरत हैं । हाल में, मंत्रिमंडल ने श्रीनगर और जबलपुर में सशस्त्र बल अधिकरण की स्थायी एकल पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है ।

## रक्षा (वित्त)

2.19 रक्षा मंत्रालय में वित्त प्रभाग वित्तीय प्रभाव डालने वाले सभी मामलों का कार्य देखता है । इस प्रभाग के प्रमुख सचिव ( रक्षा वित्त )/वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) हैं और यह रक्षा मंत्रालय के साथ पूर्णतः एकीकृत है । यह एक सलाहकार की भूमिका भी निभाता है ।

2.20 शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए, रक्षा मंत्रालय को वर्धित वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। इन शक्तियों का प्रयोग वित्त प्रभाग की सहमति से किया जाता है । रक्षा अधिप्राप्ति मामलों के संबंध में इन शक्तियों के



कार्यान्वयन की पारदर्शिता और निर्धारित नीति संबंधी मार्ग-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया और रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है ।

2.21 वित्त प्रभाग, रक्षा सेवाएं प्राक्कलनों, सिविल प्राक्कलनों तथा रक्षा पेंशनों से संबंधित प्राक्कलनों को तैयार करता है तथा उसकी मानीटरिंग करता है । रक्षा सेवा प्राक्कलनों से संबंधित वर्ष 2011-12 और वर्ष 2012-13 के वास्तविक व्यय और 2013-14 के लिए संशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2014-15 के बजट प्राक्कलन के ब्योरे तालिका

सं 2.1 में दिए गए हैं तथा इससे संगत ग्राफ/चार्ट इस अध्याय के अंत में दिया गया है।

2.22 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा यथा प्रस्तुत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक अद्यतन रिपोर्ट का सारांश इस वार्षिक रिपोर्ट के **परिशिष्ट-III** पर दिया गया है ।

2.23 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों / लोक लेखा समिति की रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट की दिनांक 31-12-2013 के अनुसार स्थिति इस वार्षिक रिपोर्ट के **परिशिष्ट IV** पर दी गई है ।

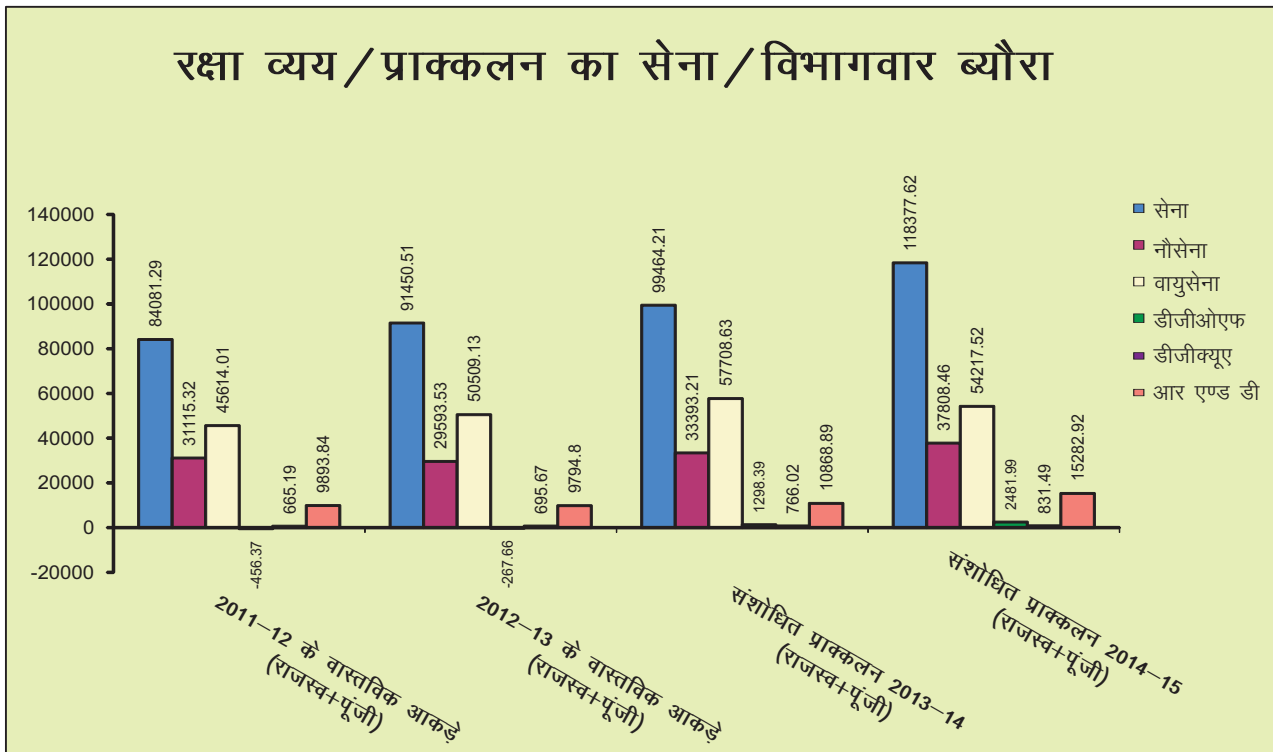
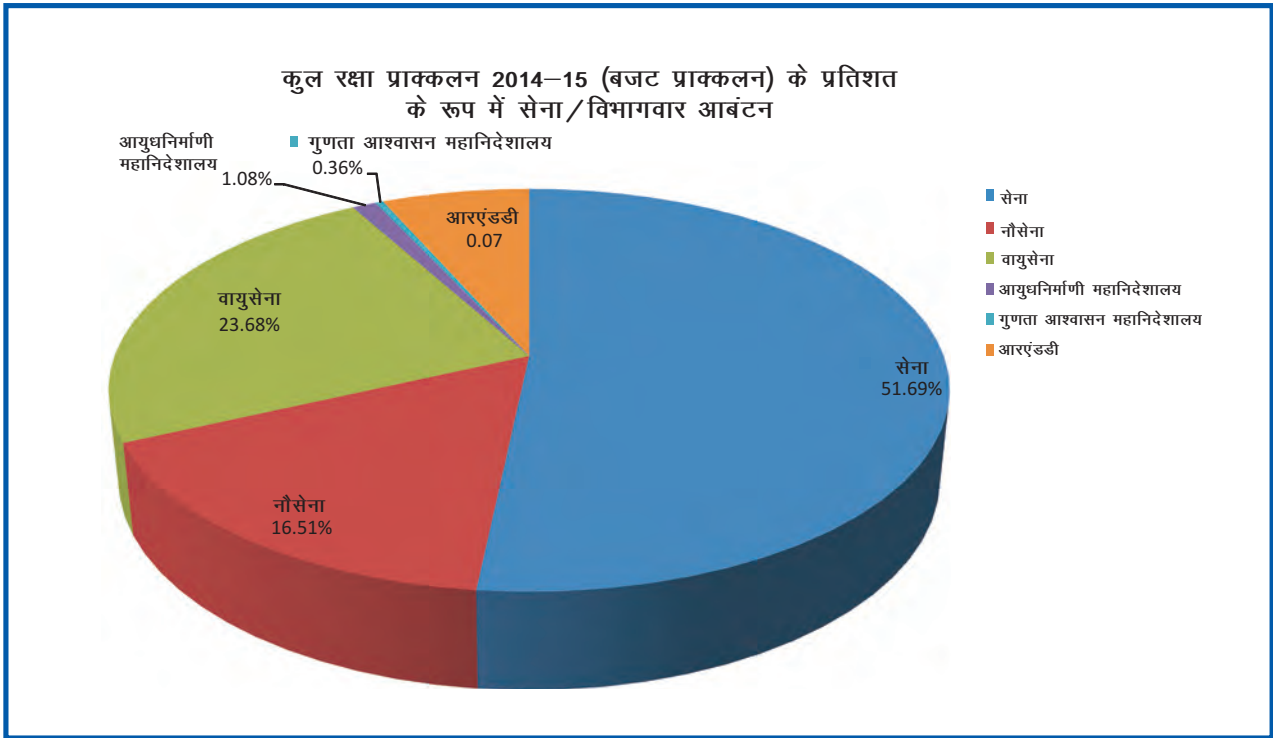
## सारणी 2.1

### रक्षा व्यय/प्राक्कलन का सेना/विभागवार ब्यौरा

(₹ करोड़ रु. में)

	2011-12 वास्तविक (राजस्व+पूंजी)	2012-13 वास्तविक (राजस्व+पूंजी)	संशोधित प्राक्कलन 2013-14 वास्तविक (राजस्व+पूंजी)	बजट प्राक्कलन 2014-15 वास्तविक (राजस्व+पूंजी) अंतरिम
सेना	84081.29	91450.51	99464.21	118377.62
नौसेना	31115.32	29593.53	33393.21	37808.46
वायुसेना	45614.01	50509.13	57708.63	54217.52
रक्षा उत्पादन विभाग आयुध निर्माणी महानिदेशालय	(-) 456.37	(-) 267.86	1298.39	2481.99
-रक्षा उत्पादन विभाग गुणता आश्वासन महानिदेशालय	665.19	695.67	766.02	831.49
अनुसंधान तथा विकास	9893.84	9794.80	10868.89	15282.92
<b>योग</b>	<b>170913.28</b>	<b>181775.78</b>	<b>203499.35</b>	<b>229000.00</b>

डीडीपी-रक्षा उत्पादन विभाग  
डीजीओएफ-आयुध निर्माणी महानिदेशालय  
डीजीक्यूए-गुणता आश्वासन महानिदेशालय  
आर एंड डी-अनुसंधान तथा विकास





## भारतीय सेना



सेना दिवस परेड के दौरान टी-90 टैंक सैन्य टुकड़ी



**भारतीय** सेना, युद्ध पद्धति के संपूर्ण स्पेक्ट्रम में बाहरी एवं आंतरिक खतरों से अपने देश की रक्षा करने के लिए समर्पित है ।

### **सुरक्षा रूपरेखा**

3.1 विश्व भर में लगातार बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण सुरक्षा बनाए रखने की कई चुनौतियां देश के सामने हैं । सामने दिखाई दे रही सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी सक्रियात्मक तैयारी/स्थिति की लगातार समीक्षा करते हुए भारतीय सेना, युद्ध पद्धति के संपूर्ण स्पेक्ट्रम में बाहरी एवं आंतरिक खतरों से अपने देश की रक्षा करने के लिए समर्पित है । साथ ही, विपत्ति/प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ित लोगों की सहायता करने एवं उन्हें आसरा देने के लिए भारतीय सेना हमेशा आगे रही है ।

### **जम्मू-कश्मीर**

3.2 जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर लेकिन नाजुक है । सीमा पार आतंकवादी ठिकाने यथावत् बने हुए हैं और राज्य में पाकिस्तान की सहायता से चल रहे छद्म युद्ध लगातार जारी हैं । पाकिस्तान-आतंकवादी-अलगाववादी संबंधों द्वारा राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दुर्बल बनाने की कोशिशें करता रहता है ।

3.3 जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में सैलानियों का जाना एवं अमरनाथ यात्रा के दौरान कोई अप्रिय

घटना न होना कुछ ऐसे सकारात्मक पहलू हैं जिन्हें आगे भी जारी रखने की आवश्यकता है। फिर भी, जम्मू कश्मीर की स्थिति काफी असमंजसपूर्ण है और इसे सुरक्षा बलों तथा सिविल प्रशासन की मिली जुली कोशिशों से सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है ।

3.4 **सीमा पर स्थिति** : जम्मू कश्मीर की वास्तविक भू-स्थिति रेखा (ए जी पी एल) नियंत्रण रेखा (एल सी) एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में कुछ उल्लंघनों को छोड़कर सामान्य तौर पर युद्ध विराम की स्थिति बनी हुई है । यह उल्लंघन नियंत्रण रेखा एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे कुछ सैक्टरों तक ही सीमित हैं । तथापि, पिछले दो वर्षों की तुलना में वर्ष 2013 के दौरान युद्ध विराम उल्लंघनों (सी एफ वी) की संख्या बढ़ी है । इस संदर्भ में, युद्ध विराम उल्लंघनों के मुद्दे पर एक अंतराल के बाद 24 दिसंबर 2013 को भारत एवं पाकिस्तान के डी जी एम ओ की बैठक आयोजित की गई । इन बातचीतों के परिणामस्वरूप वर्ष 2014 में युद्ध विराम उल्लंघनों की संख्या में कमी आई ।

3.5 सेना द्वारा लगातार आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करने से आतंकवादी एवं उनके सरगना काफी शिथिल एवं निष्क्रिय हो गए हैं ।

## उत्तर पूर्व

3.6 मणिपुर को छोड़कर उत्तर पूर्व में केंद्र एवं राज्य सरकारों के संरक्षण में सेना, असम राइफल्स एवं अन्य सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से मौजूदा सुरक्षा स्थिति में स्थिरता आई है। पिछले वर्षों की तुलना में हिंसा के स्तर में भी महत्वपूर्ण कमी आई है। इस समय 17 प्रमुख गुप्तों के साथ ऑपरेशन के बंद करने (SoO)/युद्ध विराम (सी एफ) संबंधी बातचीत प्रगति पर है। उत्तर-पूर्व में राज्य वार सुरक्षा की स्थिति का विवरण इस प्रकार है :

3.7 **असम:** राज्य में सुरक्षा की स्थिति शांतिपूर्ण एवं नियंत्रण में है। सुरक्षा बलों द्वारा सोच-समझकर किए गए ऑपरेशनों से राज्य में आतंकवादी दलों की हिंसक गतिविधियों में काफी कमी आई है। सुरक्षा बलों ने भूमिगत तत्वों पर नैतिक वर्चस्व स्थापित किया है।

3.8 **नागालैंड :** राज्य में कुल मिलाकर हिंसा में कमी आई है लेकिन एन एस सी एन (के) एवं एन एस सी एन (के/के), जो एन एस सी सी एन (के) में फूट के बाद बना, गुप्तों के बीच आपसी झड़प लगातार जारी है क्योंकि दोनों ही गुट अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सेना एवं असम राइफल्स भूमिगत दलों पर नियंत्रण बनाए हुए हैं और इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सीज़फायर ग्राउंड रूल्स का पालन हो। युद्धविराम संबंधी मूल नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। नागा समस्या का स्थायी हल ढूंढने की प्रक्रिया जारी है।

3.9 **मणिपुर :** मणिपुर की सुरक्षा स्थिति हिंसात्मक घटनाओं में कमी के बावजूद लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। सेना एवं असम राइफल्स (ए आर) द्वारा ऑपरेशन जारी हैं। इम्फाल घाटी का गैर-अधिसूचित क्षेत्र हिंसात्मक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। कुकी एवं ज़ोमी भूमिगत गुप्तों के साथ ऑपरेशन बंद होने से (एसओएस) कुकी एवं ज़ोमी आबादी वाले क्षेत्रों में शांति बहाल हुई है और वे ऑपरेशन सस्पेंशन के मूल नियमों का अनुपालन कर रहे हैं।

3.10 **अरुणाचल प्रदेश :** यहां की स्थिति नियंत्रण में होने के बावजूद, एन एस सी एन (आई एम) एवं एन एस सी एन (के) के बीच इस समय चल रही वर्चस्व की लड़ाई के कारण तनावपूर्ण बनी हुई है। आसूचना रिपोर्टों से यह पता चला है कि म्यांमार से बाहर/में काडर एवं हथियारों/गोला-बारूदों को लाने ले जाने के लिए विद्रोही गुप्तों द्वारा इस क्षेत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और सुरक्षा बलों द्वारा एहतियाती ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

3.11 **त्रिपुरा और मिजोरम :** सुरक्षा स्थिति नियंत्रण में है। दोनों राज्यों में विधान सभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुए।

## सीमा पर स्थिति

3.12 **चीन के साथ द्विपक्षीय सम्बंध :** पिछले कुछ वर्षों से दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ है। समय-समय पर सैन्य संसाधनों के नियमित आदान-प्रदान के साथ-साथ अन्य राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैन्य स्तर पर रचनात्मक कार्य जारी हैं। मई 2013 में चीन के प्रमुख का भारत में आगमन तथा अक्टूबर

2013 में भारत के प्रधानमंत्री की चीन यात्रा वर्ष 2013 की महत्वपूर्ण घटनाएं रहीं। 50 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि चीन के प्रमुख और भारतीय प्रधानमंत्री एक ही वर्ष में एक-दूसरे के देशों की यात्रा पर गए। इसके अलावा, द्विपक्षीय बातचीत को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने भी एक दूसरे के देश की यात्रा की।

3.13 भारत चीन सहित अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण सम्बंध बनाना चाहता है। इसके लिए रचनात्मक बातचीत की नीति के साथ-साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति व सौहार्द बनाए रखना सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ-साथ वर्तमान और भावी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए बलों के आधुनिकीकरण में अवसंरचना का आवश्यक विकास और सेना को मुस्तैद रखने की कार्यवाई जारी है।

3.14 **वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल ए सी) पर स्थिति:** भारत-चीन सीमा पर स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। सीमा पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में भारत और चीन में मतभेद है। दोनों देश अपने-अपने मतानुसार निर्धारित की गई वास्तविक नियंत्रण रेखा तक गश्त लगाते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऐसे क्षेत्रों में चीन के गश्त दलों द्वारा किए गए अतिक्रमण के उल्लेखनीय मामले हॉट लाइनों, फ्लैग मीटिंगों और सीमा कार्मिक

**अक्टूबर 2013 में भारतीय प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान सीमा रक्षा सहयोग समझौते (बी डी सी ए) पर हस्ताक्षर करने से भारत-चीन के सम्बंधों में काफी सुधार हुआ है।**

बैठकों जैसी स्थायी प्रक्रिया के माध्यम से चीन के प्राधिकारियों के समक्ष उठाए गए हैं।

3.15 **सीमा रक्षा सहयोग समझौता (बी डी सी ए):** अक्टूबर 2013 में भारतीय प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के

दौरान सीमा रक्षा सहयोग समझौते (बी डी सी ए) पर हस्ताक्षर करने से भारत-चीन के सम्बंधों में काफी सुधार हुआ है। इस समझौते से यह पता चलता है कि भारत-चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति, स्थिरता और सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता को दोनों देशों ने स्वीकार किया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति को और खराब होने से बचाने के लिए यह करार एक महत्वपूर्ण कदम है।

3.16 **संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास 'हैंड-इन-हैंड 2013':** इस वर्ष के दौरान छेन्नाद्दू, चीन में आतंकवाद रोधी संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दोनों देशों के द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किया गया। पांच वर्ष के अंतराल के बाद संयुक्त अभ्यास दोबारा शुरू हुआ। इस अभ्यास से भारतीय सेना को पी एल ए की प्रशंसा हासिल हुई और दोनों सेनाओं को परस्पर लाभ भी हुआ।

3.17 **नेपाल:** भारत और नेपाल के बीच चल रहे रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में आपसी सैन्य संबंधों को कई क्षेत्रों में बढ़ाने के मुद्दे पर और अधिक बल दिया गया है। सितम्बर 2013 में भारत में बटालियन स्तर का पांचवां अभ्यास (सूर्य किरण-V) किया गया। चिकित्सा दलों, पैदल दलों के नियमित दौरे और

वरिष्ठ अफसरों द्वारा दौरे किए जा रहे हैं। अप्रैल 8-12, 2013 में सुरक्षा पर भारत-नेपाल द्विपक्षीय परामर्शी समूह (आई एन बी सी जी एस) की दसवीं बैठक बंगलुरु, भारत में आयोजित की गई, जिसमें आपसी हितों की रक्षा और सुरक्षा मामलों पर चर्चा हुई।

**3.18 भूटान :** भूटान के साथ अपने पुराने नजदीकी सम्बंधों को देखते हुए भारतीय सैन्य प्रशिक्षण टीम सक्रिय रूप से रक्षा सहयोग का कार्य कर रही है। वर्ष 2013-14 में हमारे प्रशिक्षण संस्थानों में रॉयल भूटान आर्मी और रॉयल भूटान गार्ड कार्मिकों को 450 रिक्तियां दी गईं।

**3.19 म्यांमार :** म्यांमार ने सैन्य नियंत्रण के अपने अनूठे मॉडल के साथ प्रजातांत्रिक स्वरूप की शुरुआत की है। पिछले एक वर्ष में हमारा रक्षा सहयोग और बढ़ा है। रक्षा सहयोग के रूप में हमने म्यांमार को सड़क निर्माण उपस्कर और वॉर गेमिंग सॉफ्टवेयर प्रदान किए हैं।

### मित्र राष्ट्रों के साथ संयुक्त अभ्यास (एफ एफ सी)

**3.20 मित्र राष्ट्रों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास** रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें एक दूसरे के साथ अनुभव बांटना, सैन्य ऑपरेशनों के बदलते तरीकों को समझना, मानवीयता के आधार पर सहायता करना और आपदा राहत सहित इंटर ऑपरैबिलिटी विकसित करना तथा संयुक्त ऑपरेशनों

की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाना शामिल है।

**3.21 भारतीय सेना मित्र राष्ट्रों के साथ निरंतर संयुक्त प्रशिक्षण/अभ्यास करती रहती है।** जनवरी 2013 से निम्नलिखित संयुक्त प्रशिक्षण/अभ्यास किए गए :

- स्पेशल फोर्सस ट्रेनिंग स्कूल (एस एफ टी एस) नाहन में 01 फरवरी से 29 मार्च 2013 तक सेशेल्स एस एफ के 20 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया।
- नौवां भारत मंगोलिया प्रशिक्षण/अभ्यास (नोमेडिक एलीफेन्ट) 11-23 जून 2013 तक मंगोलिया में आयोजित किया गया



(रिफ्लेक्स शूटिंग)

- एस एफ टी एस, नाहन में 09 सितंबर से 05 अक्टूबर, 2013 तक नाइजीरियन स्पेशल फोर्सस के 20 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया।



- पांचवां भारत नेपाल प्रशिक्षण/अभ्यास (सूर्य किरण) 23 सितंबर से 06 अक्टूबर 2013 तक पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया ।
- छठा भारत नेपाल प्रशिक्षण/अभ्यास (सूर्य किरण) 5 से 18 मार्च 2014 तक सलीझांडी, नेपाल में आयोजित किया गया ।
- एक्स बोल्ड कुरूक्षेत्र नामक यंत्रीकृत अभ्यास में लाइव फायरिंग को शामिल करने के लिए सिंगापुर के समाघात समूह स्तर पर इसे 1-31 मार्च 2014 तक बबीना, भारत में आयोजित किया गया ।



आपदा प्रबंधन/प्रतिक्रिया संबंधी गतिविधियों को देखते हुए

- भारत-पोलैंड एस एफ अभ्यास एच ए डब्ल्यू एस सोनमर्ग में 30 सितंबर से 19 अक्टूबर 2013 तक आयोजित किया गया ।
- भारत - तजाकिस्तान एस एफ अभ्यास 26 अक्टूबर से 8 नवंबर 2013 तक आगरा में आयोजित किया गया ।
- इसके अलावा, छठा भारत - सेशेल्स प्रशिक्षण/अभ्यास लिमिटये 2-14 दिसंबर 2013 तक माहे में आयोजित किया गया ।

## आधुनिकीकरण और उपस्कर जुटाना

3.22 प्रमुख सेना प्राप्तियों में नई क्षमताओं को तैयार करने और इन्वेन्ट्री में पाई गई उपस्करों की कमी को पूरा करने पर बल दिया जाता है। रक्षा प्रापण प्रविधि 2013 के लागू होने से स्वदेशीकरण को काफी प्रोत्साहन मिलेगा । सेना ने जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स (जी एस क्यू आर एस) तैयार करने, कांटेक्ट नेगोशिएशन कमेटी (सी एन एस) सेल की स्थापना करने और सौंपी गई वित्तीय शक्तियों के लिए एकीकृत वित्तीय सलाहकार (आई एफ ए) कैपिटल को शामिल करने और प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर एफ पी) सेल को सुदृढ़ करने जैसे कार्यों को सुगम बनाकर प्राप्ति ढांचे को सही दिशा देने का कार्य भी किया है । इन सभी उपायों से पूरी प्रणाली मजबूत और सक्षम हो गई है ।

3.23 वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, कुल 29 ठेके (जिसमें ओ एफ बी की तीन संविदाएं शामिल हैं) पूरे किए गए । जिन योजनाओं के ठेके किए गए थे उनका कुल मूल्य 6332.20 करोड़ ₹ था (जिसमें 6132.17 करोड़ ₹ की ओ एफ बी की योजनाएं शामिल हैं) और इनकी कुल लागत 764.41 करोड़ ₹ थी ।

3.24 चालू वित्त वर्ष यानि 2013-14 के दौरान कुल 11781.13 करोड़ ₹ की लागत वाले (ओ एफ बी ठेकों के 1632.17 करोड़ ₹ सहित) कुल 18 ठेके (जिसमें दो ओ एफ बी ठेके शामिल हैं) पूरे किए गए और 31 दिसंबर 2013 तक कुल व्यय 1265.26 करोड़ ₹ का हुआ ।

3.25 **यंत्रिकृत बल** : युद्ध क्षेत्र की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यंत्रिकृत बलों के आधुनिकीकरण का काम प्रगति पर है। इसके लिए नाइट फाइटिंग क्षमता, आधुनिक फायर नियंत्रण प्रणालियों और बेहतर पावर पैक्स आदि जैसे इन-सर्विस उपस्करों के अपग्रेडेशन पर जोर दिया जाता रहा है। इसके साथ ही भावी समाघात वाहन प्लेटफार्मों को अपने देश में ही विकसित करने की प्रक्रिया जारी है।

3.26 **आर्टिलरी** : आर्टिलरी उपस्कर को खरीदने के पीछे मुख्य कारण है कि इसे 155 मिमी कैलिबर में बदला जा सके ताकि निगरानी क्षमता बढ़े और लम्बी रेन्ज के वेक्टर्स को प्राप्त किया जा सके। रक्षा उपस्कर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड से इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपग्रेड की गई 155 मिमी गनों की मांग की गई है।

3.27 **इन्फैन्ट्री** : इन्फैन्ट्री सैनिक को आधुनिक बनाने का उद्देश्य उसकी घातक क्षमता को बढ़ाना और निजी सुरक्षा प्रदान करना है। इसके लिए बुलेट प्रूफ जैकेटों और बैलिस्टिक हेलमेट सहित आधुनिक असाल्ट राइफलों, कार्बाइन और एल एम जी को प्राप्त किया जा रहा है। विशेष बलों के लिए विशिष्ट उपस्कर भी प्राप्त किए जा रहे हैं।

3.28 **सेना हवाई रक्षा** : सेना हवाई रक्षा को अपनी गनों व मिसाइल प्रणालियों को अपग्रेड करने के लिए बड़े कदम उठा रही है। मौजूदा विन्टेज उपस्करों का स्थान

सुरक्षा बलों, आसूचना एजेंसियों, पुलिस, स्थानीय सिविल प्रशासन और आम जनता के बीच आपसी सहयोग से ऑपरेशनों में सुविधा हो गई है और जम्मू व कश्मीर राज्य में लगभग सामान्य स्थिति कायम करने में मदद मिली है।

ऐसे क्वालिटी अपग्रेड और इंडक्सन्स ले लेंगे जिन पर अभी काम चल रहा है। हवाई रक्षा कमान और रिपोर्टिंग प्रणाली की ऑटोमेशन परियोजना पर भी तेज़ी से काम चल रहा है।

3.29 **सामान्य उपस्कर** : विभिन्न सेनांगों के लिए विशिष्ट उपस्करों की खरीदारी के साथ-साथ हाई मोबिलिटी वाहन, मैटीरियल हैंडलिंग उपस्कर और रेल मूवमेन्ट के लिए महत्वपूर्ण रोलिंग स्टॉक को शामिल करने का काम भी चल रहा है। नवीनतम भंडारण सुविधाओं, क्षतिपूर्ति और लेखाकरण प्रणालियों से युक्त संभारिकी अधिष्ठापनाओं के आधुनिकीकरण का काम भी चल रहा है।

3.30 **डी आर डी ओ के साथ सहयोग** : सेना ने रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डी आर डी ओ) के साथ आपसी बातचीत को बढ़ाया है। गोलाबारूद की जरूरतों से संबंधित परियोजनाओं को वरीयता दी जा रही है जिससे हम आत्मनिर्भरता के करीब पहुंच सकें।

## राष्ट्रीय राइफल्स (आर आर)

3.31 दुर्गम क्षेत्रों, प्रकृति की कठोरताओं और प्रतिविद्रोहिता/आतंकवाद रोधी वातावरण की चुनौतियों के समक्ष अडिग रहने वाली राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू व कश्मीर में भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा बलों, आसूचना एजेंसियों, पुलिस, स्थानीय सिविल प्रशासन और आम जनता के बीच आपसी सहयोग से

ऑपरेशनों में सुविधा हो गई है और जम्मू व कश्मीर राज्य में लगभग सामान्य स्थिति कायम करने में मदद मिली है। बहुत से सफल सामरिक सैन्य ऑपरेशन किए गए जो विशिष्ट आसूचना पर आधारित थे और जिनके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया गया और उनसे बड़ी मात्रा में युद्ध संबंधी व संचारिकी सामान बरामद किया गया। बिना किसी मानवीय क्षति के यह संक्रियात्मक सफलता इस बल की व्यावसायिक उत्कृष्टता का प्रमाण है।

3.32 2014 में होने वाले लोकसभा व राज्यों की विधानसभा चुनावों के साथ-साथ 2014 में ही अफगानिस्तान से बाहरी क्षेत्रीय शक्तियों की निकासी को देखते हुए, आर आर को हमेशा चौकस व सतर्क रहने की आवश्यकता थी।

3.33 समय के साथ-साथ, आर आर ने सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है और खुद को जम्मू-कश्मीर की परिस्थितियों के अनुरूप तैयार कर लिया है। यह वर्ष भी कुछ अलग नहीं था जबकि इस बल ने न केवल आतंकवाद को काफी कम किया बल्कि स्थानीय जनता को राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करने के उद्देश्य से सिविल कार्रवाई कार्यक्रम के रूप में जम्मू व कश्मीर के लोगों को विपत्ति के समय हर प्रकार की सहायता भी प्रदान की। इस बल का प्रयास होगा कि वह राज्य से आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दे और जनता को, खासकर युवाओं को, राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए मार्गदर्शन करे। ऐसा करने के लिए पहले की तरह ही लोगों की

आकांक्षाओं पर खरा उतरना और मानवाधिकारों का किसी भी रूप में उल्लंघन न होना सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शी मापदंड होंगे।

## प्रादेशिक सेना (टी ए)

3.34 प्रधानमंत्री की टी ए दिवस परेड : प्रादेशिक सेना दिवस के अवसर पर 09 अक्टूबर 2013 को आर्मी परेड ग्राउंड दिल्ली कैंट में आयोजित प्रधानमंत्री की प्रादेशिक सेना दिवस परेड का निरीक्षण रक्षा राज्य मंत्री द्वारा किया गया था। इस परेड में दस मार्चिंग टुकड़ियों ने हिस्सा लिया जिसमें इन्फेन्ट्री (टी ए) यूनिटें, होम व हार्थ (टी ए) यूनिटें और विभागीय (टी ए) यूनिटों की तीन झांकियां थीं।

3.35 प्रादेशिक सेना भ्रातृसंघ की भारत के राष्ट्रपति से भेंट : प्रादेशिक सेना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में परम्परानुसार प्रादेशिक सेना के अफसरों, जे सी ओ, अन्य रैंकों और उनके परिजनों ने 10 अक्टूबर 2013 को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति से भेंट की।



प्रादेशिक सेना भ्रातृसंघ की भारत के राष्ट्रपति से भेंट

3.36 “मेरी पृथ्वी मेरा कर्तव्य” अभियान : “जी न्यूज़ मीडिया” द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान “मेरी पृथ्वी मेरा कर्तव्य” अगस्त 15-21, 2013 तक चलाया गया। इस अभियान में सभी आठों इकोलॉजिकल टॉस्क फोर्स बटालियनों ने भाग लिया और इस व्यापक वृक्षारोपण अभियान और जागरूकता कार्यक्रम को चलाया ।

### संयुक्त राष्ट्र मिशन

3.37 भारत सन् 1950 से संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन को सहयोग देता आ रहा है और एक बहुत बड़ा ट्रुप कंट्रीब्यूटर है । आज तक भारत विभिन्न शांति स्थापना मिशनों में लगभग 1,91,000 ट्रुपों को भेज चुका है । इस समय, छठे संयुक्त राष्ट्र मिशन में हमारे 6886 लोग शामिल हैं । हमारी प्रमुख उपलब्धियां आगे के पैराग्राफों में वर्णित हैं ।

3.38 मोनस्को : कांगो (1999 - आज तक) : डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो (डी आर सी) अफ्रीकन महाद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा देश है जो वर्ष 1960 में मिली आजादी के बाद भी लम्बे समय तक अशांति और अस्थिरता के दौर से गुजरा है। इस अवधि में वहां दो सिविल युद्ध और नस्लीय संघर्ष हुए । ट्रुप्स कंट्रीब्यूशन की बढ़ती मांग के कारण, भारत ने चार इन्फेन्ट्री बटालियन ग्रुपों ब्रिगेड सिग्नल कम्पनी और एक लेवल III अस्पताल के साथ इन्फेन्ट्री ब्रिगेड ग्रुप को नवम्बर 2004 से कांगो में तैनात किया । एक सेना विमानन फ्लाइट भी 2009 से मिशन एरिया में तैनात की गई है । भारतीय

ब्रिगेड डी आर सी के नार्थ किवू प्रांत में तैनात है जो कि सर्वाधिक विवादग्रस्त और विद्रोही ग्रुपों से उत्पीड़ित क्षेत्र है । कांगो में भारतीय ब्रिगेड के लिए ऑपरेटिंग कंडीशन बहुत चुनौतीपूर्ण, बंजर भूभाग से भरी और विषम जलवायु वाली है । मोनस्को अधिदेश को लागू करवाने में भारतीय ब्रिगेड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इसकी भरपूर सराहना की गई है ।

3.39 यूनीफिल:लेबनान (1998 - आज तक): यूनीफिल में भारतीय सेना ने सहायता के रूप में एक इन्फेन्ट्री बटालियन ग्रुप, लेवल I अस्पताल और स्टाफ अफसर भेजे हैं। भारतीय बटालियन को लगभग 100 वर्ग किलोमीटर के पहाड़ी इलाके में तैनात किया गया है जहां वह कुछ यूएन पोजीशनों और ब्लू लाइन पर अस्थायी प्रेक्षण चौकियों को संभालते हुए अपनी जिम्मेवारी के क्षेत्र में गहन ऑपरेशनल गतिविधियों में लगी हुई है। भारतीय टुकड़ी नियमित रूप से बड़ी संख्या में जनता की भलाई के लिए शिविर लगाती है जिसमें मेडिकल, डेंटल और पशु चिकित्सा शिविर शामिल हैं ताकि स्थानीय लोगों की मदद की जा सके और उनके दुख कम किए जा सकें ।

मोनस्को अधिदेश को लागू करवाने में भारतीय ब्रिगेड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इसकी भरपूर सराहना की गई है ।

3.40 यूएन मिस : साउथ सूडान (जुलाई 2011 - आज तक) : रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान के स्वतंत्र राज्य का गठन 09 जुलाई 2011 को एक जटिल और कमजोर



क्षेत्रीय परिवेश में हुआ। भारतीय सेना की टुकड़ियां इस समय (दो इन्फेन्ट्री बटालियन, एक फोर्स सिगनल कम्पनी और एक अस्पताल) यूएन मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिदेश की सहायता के लिए ऑपरेशनों का संचालन कर रही है। भारतीय टुकड़ियों की समय पर की गई दखल से, विद्रोही सहायक सैन्य समूहों (आर एम जी) और साउथ सूडान सेना के बीच झगड़े और अन्तर - ट्राइबल झगड़ों और विवादों के समाधान के दौरान, बहुत से लोगों की जानें बचाई गई। सात भारतीय शांति स्थापना कार्मिकों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायम रखने के लिए महान बलिदान दिया। मिशन की ऑपरेशनल क्षमता में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

**3.41 यू एन डी ओ एफ : गोलन हाइट्स-इस्त्राइल (जनवरी 2006 - आज तक) :** भारत ने गोलन हाइट्स में यू एन डी ओ एफ के भाग के रूप में एक संधारिकी दल तैनात किया है। सीरिया में सिविल अशांति के दौर में बहुत से विदेशी दल जैसे क्रोशिया, कनाडा, फिलिपिन्स पीछे हट गए थे, किंतु भारतीय टुकड़ी ने घोर अशांति के समय में भी मिशन क्षेत्र में काम जारी रखा। इस मिशन में फोर्स कमांडर एवं मिशन के प्रमुख के रूप में एक भारतीय जनरल अफसर कार्य कर रहे हैं।

### संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना के लिए केंद्र (सी यू एन पी के)

**3.42 शांति स्थापना में महिलाओं की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार :** यू एन वुमेन और सीयूएनपीके द्वारा संयुक्त रूप से फरवरी 6-7, 2013 को 'शांति स्थापना में महिलाओं की भूमिका' विषय पर एक

अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेनाध्यक्ष ने इस सेमिनार के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की और 6 फरवरी 2013 को प्रमुख व्याख्यान दिया।

**3.43 टेबल टॉप एक्सरसाइज: आई बी एस ए :** 26 से 29 नवंबर 2013 तक ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र (आर एस ए) के साथ टेबल टॉप एक्सरसाइज की गई। इसमें 15 भारतीय अफसरों के अलावा ब्राजील के 13 अफसरों एवं आर एस ए के 15 अफसरों ने भाग लिया।

**3.44 कम्बोडिया के लिए प्रशिक्षण दल :** आर सी ए एफ (रॉयल कम्बोडियन आर्मड फोर्स) के सदस्यों को शांति स्थापना प्रशिक्षण देने के लिए 07 से 19 अक्टूबर 2013 तक चार सदस्यों के एक प्रशिक्षण दल को कम्बोडिया में तैनात किया गया।

**3.45 अब तक कुल 19 प्रतिनिधि मंडलों ने इस केंद्र का दौरा किया।** इनमें से सीयूएनपीके को नेपाल, भूटान, सिंगापुर एवं जापान के सेनाध्यक्षों व किर्गिस्तान के माननीय रक्षामंत्री की मेजबानी करने का सम्मान प्राप्त है।

**3.46 संयुक्त राष्ट्र संघ मिलिटरी ऑब्ज़र्वर्स कोर्स (यू एन एम ओ सी) का आई टी एस, यू एन डी पी के ओ द्वारा प्रमाणीकरण :** इस केंद्र द्वारा संचालित यूनाइटेड नेशन्स मिलिटरी ऑब्ज़र्वर्स कोर्स (यू एन एम ओ सी) को चार वर्षों की अवधि के लिए इंटीग्रेटेड टेनिंग सर्विस, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति स्थापना ऑपरेशन्स विभाग (आई टी एस, यू एन डी पी के ओ), न्यूयार्क द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

## भारतीय नौसेना



आई एन एस विक्रान्त

**नौसेना** की सैन्य भूमिका का उद्देश्य ऐसे किसी हस्तक्षेप या कार्य का भय दिखाकर निवारण करना/रोकना है जो हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हो और लड़ाई होने की स्थिति में शत्रु को करारी मात देने की योग्यता रखना है।

4.1 भारतीय नौसेना (भा नौ) देश की सामुद्रिक संप्रभुता और असंख्य समुद्री क्रियाकलापों को संभव बनाने और उसकी गारंटी देने में प्रमुख भूमिका निभाती है। भारतीय नौसेना द्वारा अपनी चार भूमिकाओं अर्थात् सैन्य, राजनयिक, रक्षीदल और हितैषी कार्यों के माध्यम से इस दायित्व का निर्वहन किया जाता है। नौसेना की सैन्य भूमिका का उद्देश्य ऐसे किसी हस्तक्षेप या कार्य का भय दिखाकर निवारण करना/रोकना है जो हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हो और लड़ाई होने की स्थिति में शत्रु को करारी मात देने की योग्यता रखना है। नौसेना का बल प्रयोग के लिए तैनात किया जाना भी जैसा कि “ऑपरेशन विजय” और “ऑपरेशन पराक्रम” के दौरान प्रदर्शित किया गया था, भारतीय नौसेना के प्रमुख मिशन बने रहेंगे। नौसेना की रक्षी भूमिका का एक प्रमुख उद्देश्य तटवर्ती सुरक्षा और समुद्री डकैती रोधी उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है

4.2 भारत एक समुद्रवर्ती राष्ट्र है और व्यापार करने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था समुद्रों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। 90% से अधिक मात्रा के और 77% से भी अधिक मूल्य के हमारे व्यापार का परिवहन समुद्र मार्ग से किया जाता है। विश्व भर में नए बाजार तलाश कर रही तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार संबंधी ये आंकड़े भविष्य में और

ऊपर बढ़ेंगे। इससे आर्थिक विकास, जिसमें पोत-परिवहन, मत्स्यन, प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन निष्कर्षण तथा हमारी अपतटीय तथा तटवर्ती परिसंपत्तियों की सुरक्षा आदि शामिल हैं, के लिए समुद्रों का प्रयोग बढ़ेगा।

4.3 भारतीय नौसेना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय विदेश नीति के समर्थन में भारत की समुद्री शक्ति का प्रयोग करना है। नौसेना अन्य मित्र नौसेनाओं के साथ राय कायम करके, उन्हें भागीदार बनाकर, उपस्थिति दर्शाकर, भरोसा बनाकर तथा संयुक्त ऑपरेशनों में हिस्सा लेकर अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। नौसेना की हितैषी भूमिका के हिस्से के रूप में देश के भीतर और हित साधन के वैश्विक क्षेत्रों, दोनों में आपदा राहत ऑपरेशनों के लिए भारतीय नौसेना का उपयोग राष्ट्रीय नेतृत्व को विकल्प प्रदान करने के लिए किया जाता रहेगा।

4.4 भारतीय नौसेना से इस क्षेत्र में सुरक्षा, संरक्षा और स्थिरता से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए अधिकाधिक आग्रह किया जा रहा है। एक जिम्मेदार राष्ट्र और हितैषी समुद्री पड़ोसी के रूप में हिन्द महासागर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लागू करना, मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुँचाना हमारी अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं में सबसे

आगे रहेंगे। हिन्द महासागरीय क्षेत्र में पेचीदा समुद्री सुरक्षा माहौल के कारण भारतीय नौसेना के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उच्च स्तरीय ऑपरेशनल गति और

मुस्तैदी को हर समय बनाए रखे। बड़ी संख्या में किए गए संक्रियात्मक तैनातियों के अलावा, भारतीय नौसेना ने विदेशी मित्र राष्ट्रों की नौसेनाओं के साथ सफलतापूर्वक अभ्यास किए हैं। इन अभ्यासों से द्विपक्षीय संबंधों और हमारे व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने और अंतर-संक्रियात्मक विषयों को सरल और कारगर बनाने में मदद मिली है।

4.5 हिन्द महासागर क्षेत्र में और विशेष रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में समुद्री डकैती चिन्ता का बड़ा विषय रही है। 23 अक्टूबर 2008 के बाद से ही भारतीय नौसेना ने अपनी समुद्री डकैती-रोधी गश्तों के दौरान भारतीय और विदेशी मर्चेट पोतों पर होने वाले 40 हमलों को निष्फल करने का सराहनीय कार्य किया है। अदन की खाड़ी से परे समुद्र डकैती प्रभावित क्षेत्रों में हमारी लगातार उपस्थिति ने समुद्री क्षेत्र में इस खतरे से निपटने के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को दर्शाया है। हमारे विस्तारित होते हुए आर्थिक हितों की रक्षा करने की आवश्यकता और एक परिपक्व एवं जिम्मेदार क्षेत्रीय समुद्री शक्ति होने के नाते नेतृत्व संबंधी जिम्मेदारियों के चलते हमारे समुद्री हितों का संरक्षण करने की भारतीय नौसेना की भूमिका व जिम्मेदारी बढ़ती ही रहेगी। भारतीय युद्धपोत अदन की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त ट्रांजिट कॉरिडोर (आई

**अब तक भारतीय युद्धपोतों ने विभिन्न देशों के 2671 से अधिक मर्चेट पोतों, जिनमें 311 भारतीय ध्वज लगे पोत भी शामिल हैं, का सुरक्षित मार्गरक्षण किया है।**

आर टी सी) के आसपास गश्त कर रहे हैं। अब तक भारतीय युद्धपोतों ने विभिन्न देशों के 2671 से अधिक मर्चेट पोतों, जिनमें 311 भारतीय ध्वज लगे पोत भी शामिल हैं, का

सुरक्षित मार्गरक्षण किया है। इस मार्गरक्षी ऑपरेशनों का भरपूर लाभ उठाने के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत अन्य नौसेनाओं के युद्धपोतों के साथ मिलकर गश्त करते हैं।

4.6 निरंतर विकास और आत्मनिर्भरता के हमारे समग्र राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप भारतीय नौसेना ने स्वदेशीकरण कार्यक्रमों का तहेदिल से समर्थन किया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का केद्रबिंदु स्वदेशी युद्धपोत का निर्माण है। हमने देश में ही निर्मित पोतों और पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल करने को वरीयता दी है। इस समय जिन 45 पोतों और पनडुब्बियों का आर्डर दिया है, उन्हें भारतीय सार्वजनिक और निजी शिपयार्डों में ही बनाया जा रहा है।

## विदेश में ऑपरेशन

4.7 विदेश में तैनाती (ओ एस डी) भारतीय नौसेना के पोतों द्वारा ध्वज प्रदर्शन, मित्र राष्ट्रों के साथ बेहतर संबंध विकसित करने और विदेशी सहयोग को बढ़ाने के लिए विदेशों में उनकी तैनातियां की जाती हैं। वर्ष 2013 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विदेशी तैनातियां की गईं:-

(क) **पूर्वी बेड़े से विदेश में तैनाती** : पूर्वी बेड़े के पोत सतपुड़ा, रणविजय, शक्ति और किर्च मई से जून 2013 तक दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर में तैनात किए गए। इन पोतों ने सिंगापुर, वियतनाम (डेनांग), फिलीपीन्स (मनीला) तथा मलेशिया (पोर्ट क्लॉंग) स्थित बंदरगाहों का दौरा किया।

(ख) **पश्चिमी बेड़े से विदेश में तैनाती**: पश्चिमी बेड़े के पोत मैसूर, आदित्य, तरकश और तबर सितंबर 2013 में पारस की खाड़ी में तैनात किए गए। इस तैनाती के दौरान इन पोतों ने अस-शुवैख (कुवैत), पोर्ट मैसीद (कतर), दोहा (कतर), मीना रशीद (दुबई) और पोर्ट सुल्तान कबूस (मस्कट) का दौरा किया। विदेश में तैनाती के दौरान भारतीय नौसेना पोतों ने रॉयल नेवी ऑफ ओमान के साथ 'एक्सरसाइज नसीम-अल-बहार' में भाग लिया और कुवैती, कतरी तथा यू ए ई नौसेनाओं के साथ पैसेज अभ्यास (पैसएक्स) किए।

(ग) **आसियान देशों की समुद्री यात्रा अभियान**: नौचालन प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शिनी सितंबर 2012 से मार्च 2013 तक 192 दिन के बहुप्रशंसित आसियान देशों की समुद्री यात्रा अभियान पर रहा और इसने नौ आसियान देशों में 13 बंदरगाहों का दौरा किया।

(घ) **भारतीय नौसेना नौचालन पोत (आईएनएसवी) म्हादेई**: कमांडर अभिलाष टॉमी मार्च 2013 में आईएनएसवी म्हादेई में समुद्री मार्ग से विश्व की एकल समुद्रमार्गीय परिक्रमा करने वाले पहले

भारतीय बने। इस एकल समुद्रमार्गीय परिक्रमा के पूरा होने पर 06 अप्रैल 2013 को आईएनएसवी म्हादेई का समारोहपूर्वक स्वागत भारत के राष्ट्रपति द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया पर किया गया। इस बेजोड़ कारनामे को अंजाम देने के लिए इस अफसर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा कीर्ति चक्र देकर सम्मानित किया गया है।

(च) **प्रशिक्षण स्कवाड्रन की विदेश में तैनाती**: प्रथम प्रशिक्षण स्कवाड्रन के पोतों घड़ियाल, शारदा, तरंगिनी और सीजीएस वरुण को सितंबर से अक्टूबर, 2013 तक मॉरीशस और सेशेल्स में तैनात किया गया।

(छ) **समुद्रपारीय सर्वेक्षण**: आईएनएस जमुना को नवंबर 2012 से फरवरी 2013 तक केन्या और तंजानिया से परे सर्वेक्षण आपरेशनों तथा आईएनएस सर्वेक्षक को जनवरी से मार्च 2013 तक मॉरीशस से परे सर्वेक्षण आपरेशनों के लिए तैनात किया गया।

(ज) **सिडनी में अन्तर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा**: आईएनएस सहयाद्री ने सितम्बर 2013 में सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

4.8 **सेशेल्स, मॉरीशस और मालदीव से परे विशिष्ट आर्थिक जोन निगरानी तथा समुद्री डकैती-रोधी तैनाती**: पूर्वी अफ्रीकी तट, मॉरीशस, मालदीव और सेशेल्स के पास समुद्री डकैती की घटनाओं में बढ़ोतरी होने की वजह से संबंधित मेजबान सरकारों के अनुरोध पर भारतीय नौसेना पोतों तथा वायुयानों को उनके विशिष्ट आर्थिक जोन (ईईजी) में निगरानी के लिए भी तैनात किया जा रहा है।



**4.9 सोमालिया तट से परे समुद्री डकैती संबंधी संपर्क समूह (सीजीपीसीएस):** सोमालिया तट से परे समुद्री डकैती संबंधी संपर्क समूह (सीजीपीसीएस) वह मंच है, जो सोमालिया से होने वाली समुद्री डकैती मुद्दों से निपटता है और इस मामले पर आईएमओ को सिफारिशें देता है। भारत ने सितम्बर 2012 में सीजीपीसीएस की अध्यक्षता की। सीजीपीसीएस का 13वां पूर्ण सत्र 11 से 12 दिसम्बर 2012 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। बाद में भारत ने जनवरी 2013 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को अध्यक्षता सौंप दी।

## मुख्य अभ्यास

**4.10 ट्रोपेक्स-13:** वार्षिक थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडिनेस एक्सरसाइज (ट्रोपेक्स) पश्चिमी समुद्र-क्षेत्र में जनवरी 2013 के अंत से मार्च 2013 के आरंभ तक संचालित किए गए। इस अभ्यास में हथियारों से फायरिंग जलस्थलीय ऑपरेशन और सामरिक ऑपरेशन शामिल थे, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़ों ने भाग लिया।

**4.11 एम्फेक्स-13:** जल-स्थलीय अभ्यास (एम्फेक्स) भारत के पश्चिमी तट से परे जनवरी 2013 के मध्य से फरवरी 2013 के आरंभ तक आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में एक प्रशिक्षण चरण और एक सामरिक चरण शामिल था। इसके लिए टैंकों, टूप/आर्म्स तथा इन्फेन्ट्री ब्रिगेड की परिसम्पत्तियों के साथ-साथ 2000 से अधिक सैनिकों की तैनाती की गई।

**4.12 डीजीएक्स-13:** द एनुअल डिफेंस ऑफ गुजरात एक्सरसाइज (डीजीएक्स) अक्टूबर 2013 में उत्तरी अरब सागर में संचालित की गई जिसमें भारतीय

तटरक्षक बल, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

## विदेशी नौसेनाओं के साथ अभ्यास

**4.13 भारत-सिंगापुर अभ्यास (सिम्बेक्स-13):** सिंगापुर इंडिया मेरीटाईम बाईलेट्रल एक्सरसाइज (सिम्बेक्स) हर वर्ष बंगाल की खाड़ी या दक्षिण चीन सागर में संचालित किए जाते हैं। सिम्बेक्स 13 का आयोजन 16 से 23 मई 2013 तक दक्षिण चीन सागर में किया गया। इन चरणों में विभिन्न समुद्री ऑपरेशन शामिल थे, जिनमें सतह मुठभेड़, विजिट बोर्ड खोज और कब्जा प्रक्रियाएं, सामरिक अभ्यास, पनडुब्बी रोधी अभ्यास, इंटरएक्टिंग प्रेजेंटेशन आदि शामिल थे। भारतीय नौसेना पोतों सतपुड़ा और किर्च ने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया। आर एस एस स्टेडफास्ट और वेलिएंट (इंटीग्रल हेलीकॉप्टरों सहित), आर एस एस कंकरर (पनडुब्बी) और एम आर एयरक्राफ्ट फोकर 50 ने सिंगापुर नौसेना का प्रतिनिधित्व किया।

**4.14 भारत-श्रीलंका अभ्यास (स्लाइनेक्स-13):** प्रथम भारतीय नौसेना- नौसेना (श्रीलंकन नेवी) द्विपक्षीय अभ्यास (स्लाइनेक्स) 12 से 16 दिसम्बर 2005 तक संचालित किया गया था। इस वर्ष यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी में 4 से 7 नवम्बर 2013 तक किया गया। भारतीय नौसेना पोत तलवार (इंटीग्रल हेलीकॉप्टर सहित) तथा श्रीलंकाई नेवल पोत सागरा ने इस अभ्यास में भाग लिया।

**4.15 भारत-यूके नौसेना अभ्यास (कॉकण 13):** भारतीय नौसेना और रॉयल नौसेना ने 2004 से द्विपक्षीय अभ्यास के संबंध में संक्रियात्मक संपर्क स्थापित किए हैं। कॉकण-13 का अभ्यास 14 से 19 अक्टूबर, 2013 तक भारत के पश्चिमी तट से दूर किया गया। भारतीय नौसेना पोत दिल्ली ने इस अभ्यास में भाग लिया।

रॉयल नौसेना का प्रतिनिधित्व एचएमएस वेस्टमिनिस्टर ने किया।

**4.16 भारत-अमेरिका नौसेना अभ्यास (मालाबार-13):** भारतीय नौसेना (आईएन) और अमेरिकी नौसेना (यू एस एन) 1992 से 'मालाबार' नाम से द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन कर रही है। मालाबार के 17वें संस्करण का आयोजन 5 से 11 नवंबर 2013 तक भारत के पूर्वी तट से दूर आयोजित किया गया। यूएसएन का प्रतिनिधित्व यूएसएस मैककैपबेल और एक तटीय आधारित पी3सी ओरियन सामुद्रिक टोही विमान ने किया। भारतीय नौसेना पोत शिवालिक, रणविजय और टीयू 142 एम सामुद्रिक टोही विमान ने भारतीय नौसेना की ओर से भाग लिया।

**4.17 भारत-जापान अभ्यास (जिमेक्स-13) :** प्रथम भारत-जापान द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स का आयोजन जापान में योकोसुका से परे उरागा जलडमरूमध्य में 2012 में किया गया। जिमेक्स 13 की योजना 19 से 23 दिसंबर, 2013 तक चेन्नई से दूर बनाई गयी। जेएमएसडीएफ अरिआरके और संतोगिरी और भारतीय नौसेना पोत रणविजय, सतपुड़ा और कुठार ने इस अभ्यास में भाग लिया।

## हिन्द महासागर : प्रादेशिक तटवर्ती नौसेनाओं के साथ समन्वित गश्त

**4.18 म्यांमार नौसेना (एमएन) के साथ समन्वित गश्त (कॉर्पेट):** प्रथम भारतीय नौसेना-म्यांमार नौसेना का समन्वित गश्त अभ्यास 17 से 21 मार्च 2013 को ग्रेट कोको द्वीप, म्यांमार से परे आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना बारातंग और बाट्टीमाल्व और म्यांमार नौसेना पोत एमएन अंगजेया और बेइंगनौंग ने इस अभ्यास में भाग लिया।

**4.19 थाईलैंड के साथ समन्वित गश्त (कॉर्पेट):** इंडो-थाई कॉर्पेट के 16 वें-17वें चक्र का आयोजन अप्रैल और नवंबर 2013 में किया गया। भा नौ पोत बित्रा तथा एक भा नौ डॉर्नियर ने भारतीय नौसेना की ओर से और रॉयल थाई नौसेना की ओर से एचटीएमएस फुकेट/एचटीएमएस श्रीराचा और एक डॉर्नियर विमान ने इन कॉर्पेट का प्रतिनिधित्व किया।

**4.20 इंडोनेशिया के साथ समन्वित गश्त (कॉर्पेट):** भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्रवर्ती सीमा रेखा (आईएमबीएल) के साथ-साथ द्विवार्षिक समन्वित गश्त लगाते हैं। इंडो-इंडो कॉर्पेट के 21 वें चक्र का आयोजन मई 6 से 26, 2013 तक किया गया। भा नौ पोत महीश और बंगाराम के साथ-साथ एक भा नौ डॉर्नियर ने कॉर्पेट में भाग लिया। इंडोनेशियाई गश्त की ओर से आर पट्टीनुआस और एक सी ए एस ए-50 विमान ने प्रतिनिधित्व किया। 21 वें इंडो-इंडो कॉर्पेट का आयोजन सितंबर 6 से 27, 2013 तक किया गया। भारतीय नौसेना पोत कुंभीर के साथ-साथ एक भा नौ डॉर्नियर ने कॉर्पेट में भाग लिया। इंडोनेशिया की ओर से आर आई टीकू उमर और एक सी एस ए-50 विमान ने प्रतिनिधित्व किया।

## विदेशी नौसेनाओं को प्रशिक्षण

**4.21 प्रशिक्षण/परामर्श - दक्षिण अफ्रीका नौसेना (एसएएन):** एसएएन टाईप 209 पनडुब्बियाँ प्रचलित करता है, जो कि भारतीय नौसेना की शिशुमार वर्ग की पनडुब्बियों के समान है। भारतीय नौसेना ने एस ए एन पनडुब्बी कार्मिकों को 2005-2006 में बुनियादी पनडुब्बी प्रशिक्षण दिया। एसएएन से एसएएन पनडुब्बी शस्त्र के प्रशिक्षण के अनुरोध पर दो भारतीय नौसेना अफसरों को जुलाई 2013 में 6 माह के लिए दक्षिण अफ्रीका में प्रतिनियुक्त किया गया था।

**4.22 वियतनामी पीपल्स नेवी (पीपीएन) के लिए पनडुब्बी प्रशिक्षण:** वियतनाम अपनी नौसेना के लिए पनडुब्बियों का समावेश कर रहा है। पीपीएन ने भारतीय नौसेना से अपने कार्मिकों को बुनियादी पनडुब्बी प्रशिक्षण देने में सहयोग का अनुरोध किया है। पीपीएन के साथ लगभग तीन वर्षों की विस्तृत वार्ता के बाद 54 कार्मिकों के प्रथम बैच के लिए अक्टूबर, 2013 से आई एन एस सातवाहन में प्रशिक्षण शुरू किया गया। यह प्रशिक्षण 12 माह की अवधि का है।

**4.23 मॉरीशस को गोता सहायता:** गोतादल विशेष ऑपरेशनों और गोता लगाने से संबंधित पहलुओं में हिंद महासागर क्षेत्र (आरओआर) में तटीय नौसेना की क्षमता बढ़ाने में लगे हैं। भारतीय नौसेना दल को सितंबर 30 से 14 अक्टूबर, 2013 तक मॉरीशस टटरक्षक और पुलिस गोता दल के लिए पुनश्चर्या कमांडो और गोता प्रशिक्षण के आयोजन के लिए नियुक्त किया गया है।

## तटीय सुरक्षा

**4.24** 2009 में भारतीय नौसेना को समूची समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया था। जिसमें देश की तटीय सुरक्षा तथा अपतटीय सुरक्षा शामिल है। सभी मंत्रालयों/एजेंसियों तथा तटीय राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ आवश्यक संबंधों को मजबूत करने के लिए समन्वित प्रयास किए गए हैं, ताकि कारगर तटीय सुरक्षा प्रबंधन के लिए सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

**4.25** तटीय और अपतटीय क्षेत्र नौसेना पोतों और विमानों की नियमित निगरानी में रहते हैं। भारतीय नौसेना ने तटीय और अपतटीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए तीव्र अंतर्रोधी क्राफ्ट (एफआईसी)

और तत्काल सहायता जलयान (आईएसवी) को समावेश किया है। तटीय सुरक्षा की मांग को पूरा करने के लिए कुल 95 एफ आई सी का और भारत की पश्चिमी और पूर्वी तट से परे के तेल क्षेत्र विकास एरिया की सुरक्षा के लिए ओएनजीसी द्वारा 23 आई एस वी को शामिल किया जाएगा। समुद्री क्षेत्र जागरूकता (एमडीए) के विकास के लिए नेशनल कमान कंट्रोल कम्प्यूनिकेशन और इंटेलिजेंस नेटवर्क (एन सी<sup>3</sup> आई) को जनवरी 2014 तक पूरी तरह चालू करने की संभावना है। इसके अतिरिक्त तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए क्षमता और आधारभूत ढांचा विकास परियोजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

**4.26** सभी तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में तटीय सुरक्षा अभ्यास नियमित रूप से संचालित किए जा रहे हैं। राज्यों के साथ उन अभ्यासों को मिलाने के कारण इन अभ्यासों की जटिलता का स्तर और भी बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त सभी समुद्री हितधारकों को तटीय सुरक्षा संरचना की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने हेतु मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के साथ मिला लिया गया है। तटीय सुरक्षा अभ्यासों और एजेंसियों के बीच बढ़ते परस्पर प्रभाव ने तटीय सुरक्षा के क्षेत्र में बहुसमुद्री हितधारकों के बीच अन्तर-एजेंसी समन्वय सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सफल संयुक्त संक्रियाएं हमारी समुद्री तट रेखा से परे कई गैरकानूनी जलयानों की जाँच इसका ही परिणाम है। इसके अतिरिक्त भारतीय नौसेना समुदाय परस्पर क्रिया कार्यक्रमों के संचालन और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) और मैरीन पुलिस के प्रशिक्षण में भी सक्रिय रूप से लगी है।

**4.27 भारतीय नौसेना द्वारा चौकसी प्रयास:** भारतीय नौसेना द्वारा तट रेखा और हमारे द्वीपीय क्षेत्रों के आस-पास गश्त, तटीय और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए लगाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, अपतटीय विकास क्षेत्रों (ओ डी ए) की चौकसी भी बढ़ायी गयी है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों के लिए अनेक तटीय सुरक्षा ऑपरेशन और तटीय सुरक्षा अभ्यास चलाए गए थे। यह तटीय सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में सभी हितधारकों के बीच सहयोग, समन्वय तथा सामंजस्य विकसित करने में सहायक रहे हैं। इसके अतिरिक्त तटीय चौकसी ऑपरेशन भी भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक यूनिटों-दोनों द्वारा मध्य जून से सितंबर 2013 के अंत तक इस उद्देश्य से संचालित किए गए थे कि मानसून के दौरान निर्बाध तटीय चौकसी प्रदान की जा सके।

### **दूसरे देशों के साथ सहयोग**

**4.28 एम सी जी एस हुरावी के लिए उत्पाद सहयोग:** भारतीय नौसेना के हमारे समुद्री पड़ोसियों की क्षमता निर्माण के अभियान के अनुसरण में नौसेना डॉकयार्ड (विशाखापत्तनम) द्वारा 2013 में एम सी जी एस हुरावी को रीफिट और उत्पाद सहयोग प्रदान की गई।

**4.29 गश्ती पोत टोपाज के लिए उत्पाद सहयोग:** भारतीय नौसेना द्वारा 2005 से सेशेल्स सरकार के गश्ती पोत टोपाज के लिए उत्पाद सहयोग यथापेक्षित आधार पर प्रदान किया जा रहा है।

**4.30 जलराशिक (हाइड्रोग्राफिक) सहायता:** हाइड्रोग्राफिक के क्षेत्र में भारतीय नौसेना का उत्कृष्ट दर्जा होने से हमारे पोत इस क्षेत्र में विभिन्न देशों से

नियमित जलराशिक सर्वेक्षण कर रहे हैं। 2013 के दौरान जलराशिक सर्वेक्षण मॉरीशस, तन्जानिया और केन्या में/से परे किए गए थे।

### **नौसेना से नौसेना का विचार-विमर्श**

**4.31 स्टॉफ वार्ता:** स्टॉफ वार्ता के रूप में नौसेना से नौसेना स्तर की बातचीत, द्विपक्षीय सहयोग संबंधी पहलों का विकास करने और कार्यान्वयन करने का प्रभावी मंच प्रदान करता है। वर्ष 2013 में स्टॉफ वार्ता यूएसए, इजरायल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, जापान, मलेशिया, थाईलैण्ड, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, म्यांमार, फ्रांस और यूके के साथ की गई।

**4.32 हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आई ओ एन एस) ऑयन्स के उद्घाटन का आयोजन नई दिल्ली में 14 से 16 फरवरी, 2008 तक किया गया, जिसमें हिन्द महासागर क्षेत्र की नौसेनाओं के 35 नौसेनाध्यक्षों में से 22 ने भाग लिया। पाँच अन्य नौसेनाओं का प्रतिनिधित्व उनके उपाध्यक्षों द्वारा किया गया। नौसेनाओं द्वारा अपने शीर्ष स्तर पर व्यापक भागीदारी ने हिन्द महासागर क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था की सामूहिक आवश्यकता को दर्शाया है। ऑयन्स संक्रियात्मक सेमिनार और प्रारम्भिक कार्यशाला-2013 का आयोजन किया गया में 10 से 12 सितंबर, 2013 को किया गया। संगोष्ठी का विषय था, “हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए उभर रही नौसेनाओं की सहयोगात्मक सम्बन्ध में भूमिका और आकांक्षाएं।” इस सम्मेलन में 21 राष्ट्रों से आए 39 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।**

## विदेशी राष्ट्रों को परिसंपत्तियां उपहार में देना

4.33 **मालदीव को एएलएच:** सितंबर, 2012 में रक्षामंत्री की मालदीव यात्रा के बाद, उत्तरी द्वीप समूहों के विशिष्ट आर्थिक जोन को निगरानी कवर देने के लिए हनिमादु, मालदीव में एक नया एएलएच स्थापित करने का निर्णय लिया गया। एएलएच को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है और इसे जनवरी, 2014 में मालदीव में स्थापित किया जाएगा।

4.34 **मालदीव को अवतरण पोत की आपूर्ति:** मालदीव को 2014 की शुरुआत में एक प्रहार अवतरण पोत (एलसीए) दे दिया जाएगा।

4.35 **मॉरिशस को सर्वे मोटर बोट:** नौसेनाध्यक्ष ने 6 फरवरी, 2013 को पोर्ट लुईस, मॉरिशस में मॉरिशस सरकार को सर्वे मोटर बोट प्रदान किया।

## कमीशनिंग और डीकमीशनिंग

4.36 **नए पोतों और पनडुब्बियों की कमीशनिंग:** वर्ष के दौरान भारतीय नौसेना में कमीशन किए गए पोत भा नौ पो सरयू (अपतट गश्त पोत), त्रिकंड (फ्रिगेट), सुनयना (अपतट गश्त पोत) भा नौ पौ सुमेधा (अपतट गश्त पोत) और विमानवाहक पोत विक्रमादित्य थे।

4.37 भा नौ पो विक्रमादित्य को 16 नवम्बर, 2013 को सेवेरोडविंस्क, रूस में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। भारतीय समुद्री हितों का

भारत के पहला देशी विमानवाहक आई ए सी-1 (विक्रांत) का 12 अगस्त, 2013 को सी एस एल में जलावतरण किया गया। भारत के पोत निर्माण के प्रयास में विक्रांत का जलावतरण 'जलसंभार दृष्टि से मील का पत्थर' सिद्ध हुआ।

## देशी विमान वाहक आई ए सी (विक्रांत) का जलावतरण

4.41 भारत के पहला देशी विमानवाहक आई ए सी-1 (विक्रांत) का 12 अगस्त,

विस्तार संपूर्ण हिन्द महासागर में होने से, भा नौ पो विक्रमादित्य द्वारा उपलब्ध कराई गई समेकित वायुशक्ति से नौसेना क्षमता में बहुत अधिक योगदान मिलने की आशा है।

4.38 **भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन (आईएनएएस) 303 की कमीशनिंग:** भारतीय नौसेना का पहला मिग 29 के स्क्वाड्रन, आई एन ए एस 303 को 11 मई, 2013 को आई एन एस, हंसा, गोवा में कमीशन किया गया। एयरक्राफ्ट आई एन एस विक्रमादित्य से ऑपरेट होगा और इससे भारतीय नौसेना की समाघात क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

4.39 **आईएनएएस 322 की कमीशनिंग:** भारतीय नौसेना में पहली एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (एएलएच) स्क्वाड्रन आईएनएएस 322 को 12 नवंबर, 2013 को आई एन एस गरुड़, कोच्ची में कमीशन प्रदान किया गया। नौसेना ए एल एच को विभिन्न प्रकार के कार्यों, जिसमें लंबी दूरी की खोज और बचाव अभियान, विशेष हेलिकॉप्टर वाहित प्रचालनों और तटीय सुरक्षा के लिए सशस्त्र गश्त स्नाईपर ऑपरेशन शामिल हैं, में भी लगाया जाता है।

4.40 **पोतों की डीकमीशनिंग:** करीब 30 वर्षों तक देश की सेवा के बाद वर्ष 2013 में भा नौ पो तारागिरी, लिंइंडर श्रेणी के आखिरी पोत का डीकमीशनिंग किया गया था।





वाटरशेड माइलस्टोन-आई एसी 1 (विक्रान्त का कोच्चि में जलावतरण)

2013 को सी एस एल में जलावतरण किया गया। भारत के पोत निर्माण के प्रयास में विक्रान्त का जलावतरण 'जलसंभार दृष्टि से मील का पत्थर' सिद्ध हुआ। करीब 40,000 टन का विमानवाहक पोत बनाने वाला भारत दुनिया में पाँचवा ऐसा देश है। इस पोत को वर्ष 2018 में भारतीय नौसेना को सौंपे जाने की संभावना है।

## अरिहंत पर नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना

4.42 अगस्त 2013 में अरिहंत पोत पर सफलतापूर्वक छोटे आकार के नाभिकीय रिएक्टर को स्थापित करके हमारी नाभिकीय निवारण क्षमता को प्राप्त करने की दिशा में प्रमुख सफलता प्राप्त हुई। इस पनडुब्बी के समुद्री परीक्षण की शुरुआत हमारे लिए अगला मील का पत्थर सिद्ध हुई और इससे भारत दुनिया में नाभिकीय शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों को बनाने और प्रचालन करने वाला विश्व का केवल छठा देश बन गया। यह हमारे देश की नौसेना का "परमाणु क्षमता संपन्न नौसेना" बनने के बहुप्रतीक्षित स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और अब यह संक्रियात्मक वास्तविकता बन चुका है।



'आकाश में नजर'-पी-81 विमान

## भारतीय नौसेना में पी 8-1 और एडवांस्ड जेट प्रशिक्षण विमान का शामिल किया जाना

4.43 लंबी दूरी के समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध पद्धति (एल आर एम आर ए एस डब्ल्यू)- पी 81 एयरक्राफ्ट: 15 मई, 2013 को नौसेना में पहले आठ बोइंग पी-81 लंबी दूरी समुद्री टोही और पनडुब्बीरोधी युद्ध पद्धति के विमानों के आगमन के साथ ही भारतीय नौसेना विमानन को मजबूती मिली। दूसरा और तीसरा पी-81 एयरक्राफ्ट भी भारतीय नौसेना को नवंबर, 2013 में सौंपा गया शेष पाँच एयरक्राफ्ट भी अगले दो वर्षों में दे दिए जाएंगे। विमान समुद्री टोही, पनडुब्बी रोधी अभियान और इलेक्ट्रॉनिक आसूचना अभियान के लिए सेंसर से लैस हैं। विमान अत्याधुनिक सेंसर और अत्यधिक सक्षम सतह रोधी और पनडुब्बीरोधी हथियारों से पूरी तरह समाकलित है।

4.44 हाक एडवांस्ड जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट (एजेटी): 17 हॉक मेक 132 एडवांस्ड जेट ट्रेनरों (एजेटी) की सप्लाई के लिए भारतीय नौसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) बंगालुरु

के बीच 23 जुलाई 2010 को संविदा पर हस्ताक्षर किए गए। इस संविदा में जुलाई 2013 से जून 2016 तक 17 विमानों की डिलीवरी करनी है। भारतीय नौसेना में किरण विमान के बदले 5 हॉक मेक 132 विमान शामिल किए गए हैं ताकि भा नौ पायलटों की प्रशिक्षण अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

**4.45 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट (जी सैट-7):** 30 अगस्त 2013 को जी सैट-7 सैटेलाइट (रूक्मणी) को लांच करना भारतीय नौसेना और राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। 'रूक्मणी' के लांच होने के साथ ही, भारतीय नौसेना को हिन्द महासागर क्षेत्र (आईओआर) में एक महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा और नेट

केन्द्रिक ऑपरेशनों और रियल टाइम कम्यूनिकेशन में मदद मिलेगी।

**4.46 नामेक्सपो-13:** प्रथम नौसेना और सामुद्रिक प्रदर्शनी 23 से 27 सितम्बर 2013 तक कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोच्चि में आयोजित की गई प्रदर्शनी के दौरान भा नौ पो सतपुड़ा, सुदर्शिनी और काब्रा को कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में ही स्वदेशी पोत निर्माण के क्षेत्र में हुई उन्नति दर्शाने के लिए भा नौ के मैरीन कमांडो द्वारा एक संक्रियात्मक डेमो दिया गया। साथ ही नौसेना विमान द्वारा फ्लाई पास्ट और इसके अतिरिक्त नौसेना और सामुद्रिक विषयों पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया।



## भारतीय वायु सेना



वायुवाहित चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली (डब्लू ए सी एस) की रक्षा करते हुए दो एस यु-30 एम के आई

**भारतीय वायु सेना को भविष्य में एक ऐसा बहुआयामी बल बनाने की परिकल्पना की गई है जो भारत की भावी सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगा। वांतरिक्ष शक्ति का इस्तेमाल, भविष्य के छोटे और गहन युद्ध जीतने में निर्णायक सिद्ध होगा।**

5.1 भारतीय वायु सेना मौजूदा समय में एक ऐसे शक्तिशाली वांतरिक्ष बल के रूप में आकार ले रही है जिसने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की बदौलत लंबी पहुंच और बेहतर मारक क्षमता प्राप्त की है। भारतीय वायु सेना को भविष्य में एक ऐसा बहुआयामी बल बनाने की परिकल्पना की गई है जो भारत की भावी सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगा। वांतरिक्ष शक्ति का इस्तेमाल, भविष्य के छोटे और गहन युद्ध जीतने में निर्णायक सिद्ध होगा। मौजूदा बेड़ों के उन्नयन के साथ-साथ नए प्लेटफॉर्म और हथियार प्रणालियों के समावेशन से भारतीय वायु सेना संघर्ष के दायरे में आने वाले खतरों से निपटने और देश के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने में सक्षम बनेगी। भारतीय वायु सेना के आधुनिकीकरण से जुड़ी योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J वायुयानों के समावेशन से भारतीय वायु सेना की सामरिक पहुंच की क्षमता में भरपूर वृद्धि हुई है। Mi-17 V 5 हेलिकॉप्टरों के समावेशन से मध्यम (मीडियम) हेलिलिफ्ट क्षमता भी काफी बढ़ी है। मूल प्रशिक्षण वायुयान (बी टी ए) पिलाटस को शामिल करने से मूल उड़ान प्रशिक्षण के क्षेत्र में काफी बढ़ावा मिला है।

5.2 अत्याधुनिक भू एवं वायुवाहित वायु रक्षा सेंसरों तथा प्रणालियों के समावेशन से भारतीय वायु सेना ने

एकीकृत वायु कमान एवं नियंत्रण प्रणाली (आईएसीसी एस) का प्रयोग करते हुए समूचे भारतीय हवाई क्षेत्र से जुड़ी परिस्थितिजन्य व्यापक जागरूकता की क्षमता हासिल की है। संक्रियात्मक और तकनीकी आधारभूत ढांचे का आधुनिकीकरण प्रगति पर है जिससे अपेक्षित समाघात शक्ति प्रदान करने वाली संक्रियाओं को अंजाम देने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, आधुनिक सिम्युलेटर्स का उपयोग बढ़ाकर प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। राष्ट्र की सेवा में समर्पित 81 वर्ष के अपने गौरवशाली इतिहास की पृष्ठभूमि के साथ भारतीय वायु सेना समय के अनुरूप खुद को बदलने और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के कई संप्रभु विकल्प देश को मुहैया कराने के पथ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है।

### **वायुयानों का अर्जन और उन्नयन (अपग्रेड)**

5.3 लड़ाकू वायुयान अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर से लैस अतिरिक्त SU-30 MKI वायुयानों को संक्रियात्मक अवस्था में लाने से इस बेड़े की समाघात प्रभावकारिता बढ़ी है। मिग-29 बेड़े के लिए डिजाइन एवं विकास (डी एण्ड डी) चरण पूरा होने और मध्यवर्ती संक्रियात्मक क्लियरेंस के क्रम में अपग्रेड किए गए मिराज-2000 वायुयान की पहली उड़ान को अंजाम दिए जाने से मिग-29 और मिराज-2000 अपग्रेड कार्यक्रमों की दिशा में



बड़ी सफलता हासिल हुई है। हल्के समाघात वायुयानों (एलसीए) और मीडियम मल्टी-रोल समाघात वायुयानों (एमएमआरसीए) को निकट भविष्य में भारतीय वायु सेना में शामिल करने का काम सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

**5.4 एस यू-30 एम के आई वायुयान :** अतिरिक्त एस यू-30 एम के आई वायुयानों की डिलिवरी शुरू हो गई है। एस यू-30 एम के आई वायुयानों पर ब्रह्मोस मिसाइल लगाने के साथ-साथ मिसाइलों की खरीद के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं।



**5.5 जगुआर अपग्रेड :** जगुआर वायुयानों के एवियोनिक्स और इंजन अपग्रेड का काम शुरू किया जा रहा है।

## परिवहन वायुयान

**5.6 ए एन-32 बेड़े के अपग्रेड और सी-130 जे विशेष ऑपरेशन वाले वायुयानों तथा काफी भारी सामरिक परिवहन सी-17 वायुयानों के समावेशन की बढ़ती परिवहन बेड़ा भी बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है।**

सी-17 को शामिल किए जाने से संघर्ष के परिदृश्य में भारतीय वायु सेना की एयरलिफ्ट और हवाई आवागमन शक्ति में इजाफा हुआ है। इस क्षमता के बल पर शांतिकालीन हवाई संभारिकी, हवाई रख-रखाव और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत (एचएडीआर)/बाहरी क्षेत्र की आकस्मिकता (ओओएसी) से निपटने की शक्ति भी बढ़ेगी।

**5.7 सी-17 :** इस किस्म का पहला वायुयान 18 जून 2013 को भारत पहुंचा। सी-17 को शामिल किए जाने से संघर्ष के परिदृश्य में भारतीय वायु सेना की एयरलिफ्ट और हवाई आवागमन शक्ति में इजाफा हुआ है। इस क्षमता के बल पर शांतिकालीन हवाई संभारिकी, हवाई रख-रखाव और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत (एचएडीआर)/बाहरी क्षेत्र की आकस्मिकता (ओओएसी) से निपटने की शक्ति भी बढ़ेगी।

**5.8 अतिरिक्त सी-130जे :** पहली सी-130जे स्कवॉड्रन पूर्णतः संक्रियात्मक अवस्था में आ चुकी है। अतिरिक्त वायुयानों के लिए दिसंबर 2013 में एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन अतिरिक्त वायुयानों की खरीद से भारतीय वायु सेना की विशेष ऑपरेशनों, वायुवाहित हमलों और हवाई आवागमन से जुड़ी शक्ति और बढ़ेगी। यह वायुयान मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) ऑपरेशनों की दृष्टि से भी काफी बहुउपयोगी है।

**5.9 परिवहन बेड़े की संक्रियात्मक तैयारी :** भारतीय वायु सेना ने मार्च/अप्रैल 2013 में दो चरणों में अभ्यास

‘लाइववायर’ का संचालन किया। इस अभ्यास का एक बड़ा हिस्सा भारतीय वायु सेना की समाघात परिसंपत्ति की संक्रियात्मक हवाई गतिशीलता से जुड़ा था। परिवहन बेड़े ने इस दायित्व को अत्यंत प्रभावी ढंग से अंजाम दिया जिससे

भारतीय वायु सेना की क्षमता तीव्र संक्रियात्मक गतिशीलता के लिए और सुदृढ़ हुई। परिवहन बेड़े को मलेशियाई एयरलाइंस के लापता एम एच-370 वायुयान से जुड़े खोज एवं बचाव ऑपरेशन के काम में भी इस्तेमाल किया गया।

5.10 भारतीय वायु सेना की रोटरी विंग क्षमता में बदलाव का एक बड़ा दौर शुरू होने जा रहा है। एम आई-17वी 5 हेलिकॉप्टर के समावेशन से भारतीय वायु सेना की मीडियम हेलि-लिफ्ट क्षमता, विशेष तौर पर एवियोनिक्स, हथियार प्रणाली और उच्च तुंगता कार्य-निष्पादन के क्षेत्र में भरपूर वृद्धि हुई है। इसके अलावा भारतीय वायु सेना मौजूद हेलिकॉप्टरों जैसे कि एम आई-17 और एम आई-17 IV के उन्नयन (अपग्रेड) के लिए एक केस प्रोसेस कर रही है। इन सब के अलावा, एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (एएलएच) मार्क III, एकीकृत हथियार प्रणाली वाले रूपांतर के साथ पहले से ही समावेशन की प्रक्रिया में है।

5.11 जहां तक सैन्य हार्डवेयर के स्वदेशी विकास का संबंध है, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ए एल एच (ध्रुव) के सफल डिजाइन और विकास में अपनी उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन किया है। फिलहाल भारतीय वायु सेना के पास हल्का समाघात हेलिकॉप्टर (एलसीएच) है जो पूरी तरह एक नए डिजाइन का उदाहरण है। लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर (एलयूएच) एक और प्रोजेक्ट है जिसमें अच्छी प्रगति हुई है और भारतीय वायु सेना को उम्मीद है कि वह इन हेलिकॉप्टरों को 2020 तक अपने परिवार में शामिल कर लेगी।

सतह से हवा में मार करने वाली छोटी रेंज की मिसाइल (एसएएम), मध्यम रेंज की एस ए एम (एसएएम), न्यून स्तर पर तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता से जुड़ी मिसाइलों का समावेशन करके और इन हथियारों पर आधुनिक सेंसर लगाकर वायु रक्षा प्रणाली को और प्रबल बनाया जा रहा है।

5.12 **प्रशिक्षक वायुयान** : अप्रैल 2013 से मैसर्स पिलाटस, स्विटजरलैंड से पी सी-7 एम के-II वायुयानों की डिलिवरी शुरू होने और इन्हें तेजी से भारतीय वायु सेना में शामिल किए जाने से इसके मूल उड़ान प्रशिक्षण के कार्य को काफी बढ़ावा मिला।

## वायु रक्षा नेटवर्क

5.13 सतह से हवा में मार करने वाली छोटी रेंज की मिसाइल (एसएएम), मध्यम रेंज की एस ए एम (एसएएम), न्यून स्तर पर तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता से जुड़ी मिसाइलों का समावेशन करके और इन हथियारों पर आधुनिक सेंसर लगाकर वायु रक्षा प्रणाली को और प्रबल बनाया जा रहा है। भारतीय वायु सेना के सभी प्लेटफॉर्म और ग्राउंड सेंसरों के उन्नयन की योजना तैयार की गई है ताकि उन्हें चरणबद्ध तरीके से नेटवर्क आधारित ऑपरेशनों के लिए सक्षम बनाया जा सके।

5.14 **आकाश मिसाइल प्रणाली** : आकाश वायु रक्षा हथियार प्रणाली निम्न, मध्यम और उच्च तुंगता से हमला करने वाले वायुयानों के खिलाफ महत्वपूर्ण क्षेत्रों/महत्वपूर्ण स्थलों (वीए/वीपी) की रक्षा के लिए हर मौसम में एक कारगर वायु रक्षा प्रणाली है। आकाश प्रणाली के लिए मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलूरु के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे और स्कॉड्रन इन्हें कमीशन करने के लिए तैयार हैं।

5.15 **स्पाइडर लो लेवल क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली** : भारतीय वायु सेना अधिक महत्व वाली परिसंपत्तियों (हाई वैल्यू ऐसेट) (एचवीए) की सुरक्षा के लिए लो लेवल क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली खरीद रही

है। इसकी खरीद के लिए मैसर्स राफेल, इजरायल के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे।

**5.16 सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम रेंज की मिसाइल प्रणाली :** निम्न, मध्यम और उच्च तुंगता से हमला करने वाले वायुयानों के खिलाफ महत्वपूर्ण क्षेत्रों/महत्वपूर्ण स्थलों (वीए/वीपी) की रक्षा के लिए भारतीय वायु सेना सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम रेंज की मिसाइल प्रणाली खरीद रही है। इस प्रणाली की डिलिवरी 2014 में शुरू हो जाने की संभावना है।

## अंतरिक्ष सुरक्षा

**5.17 दुर्घटना से जुड़े आंकड़े :** भारतीय वायु सेना में 31 मार्च 2014 तक श्रेणी-I की 0.25 दुर्घटना दर (उड़ान के प्रत्येक 10000 घंटों में) दर्ज की गई है। लक्ष्य केंद्रित कार्यनीति और प्रतिबद्ध प्रयासों के बल पर दुर्घटना दर को 70 के दशक के शुरूआत के 1.84 के उच्च स्तर से कम करके वर्तमान दर तक नीचे लाने में सफलता मिली है। इन दुर्घटनाओं के पीछे मुख्य रूप से तकनीकी खराबियां (टीडी) और मानवीय चूक (वायुयान कर्मीदल) कारण रहे हैं।

**5.18 त्रुटि प्रबंधन संबंधी वायु सेना प्रणाली:** रिपोर्ट न की गई और असुरक्षित दुर्घटनाओं को दर्ज करने, इनका विश्लेषण करने और इन पर ध्यान देने के लिए एएफएसईएम (एयर फोर्स सिस्टम ऑन एरर मैनेजमेंट) का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे दुर्घटनाओं/घटनाओं को कम करने के लिए पूर्वानुमान संबंधी क्षमता विकसित करने और एहतियाती उपाय तय करने में मदद मिलती है। एएफएसईएम वर्जन 2.0 को काम में लाने से एएफएसईएम रिपोर्टों और विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई को ऑन-लाइन देखा जा सकता है। एएफएसईएम रिपोर्टों की विशिष्ट रिकॉर्डिंग के लिए वॉयस मेल प्रणाली भी सक्रिय है।

**5.19 पक्षी विज्ञान :** वायुयानों से टकराने वाले पक्षियों की प्रणालियों की पहचान करने के लिए भारतीय वायु सेना डी एन ए बार कोडिंग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रही है। हाल ही में डी आर डी ओ (डीआरडीओ) के अधीन काम कर रही एक प्रयोगशाला रक्षा शरीर-क्रिया विज्ञान एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (डिपास) से ये सेवाएं लेने के लिए एक पहल की गई है।

**5.20 अभ्यास आयरन फिस्ट :** भारतीय वायु सेना द्वारा 22 फरवरी 2013 को पोखरण में दिन से शुरू करके शाम और रात तक चले 'एक्सरसाइज आयरन फिस्ट' में अपनी वायु शक्ति का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेना के प्रमुख मौजूद थे। भारतीय वायु सेना ने अभ्यास के दौरान अपनी युद्धकालिक तैयारी और समाघात क्षमता का प्रदर्शन किया जिसमें विभिन्न लड़ाकू वायुयानों ने वास्तविक युद्ध क्षेत्र के टारगेट की एक समूची रेंज पर हवा से जमीन पर और हवा से हवा में अचूक तरीके से हथियार गिराए। शहरी भू-भाग में सैन्य ऑपरेशनों के लिए देश की क्षमता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से भारतीय वायु सेना के विशेष बल गरूड के जांबाजों के साथ संयुक्त ऑपरेशन में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो सदस्यों ने भी भाग लिया।

**5.21 'अभ्यास लाइववायर' :** मार्च-अप्रैल 2013 में एक अखिल-भारतीय परिदृश्य में 'एक्सरसाइज लाइववायर' नामक वायु सेना स्तर के एक अभ्यास का संचालन किया गया। इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायु सेना ने विभिन्न आकस्मिकताओं का कृत्रिम रूप तैयार करके एक अत्यंत नेटवर्कजन्य माहौल में युद्ध लड़ने की अपनी संकल्पनाओं का अभ्यास किया। भारतीय वायु सेना इस बात को प्रदर्शित और सिद्ध करने में सफल रही कि इसकी

मौजूदा समाघात परिसंपत्ति हमारे शत्रुओं के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है।



### अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण/अभ्यास

5.22 अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज-III (2013) : भारतीय वायु सेना के जगुआर वायुयान ने 3 से 11 अक्टूबर 2013 तक मसीरा, ओमान में रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान (आरएएफओ) के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 2013 में भाग लिया। आर ए एफ ओ के पास मौजूद वायुयानों में जगुआर, हॉक 203 और एफ-16 (सी एंड डी) शामिल हैं। इस अभ्यास से दोनों भागीदार बलों को ऑपरेशन, प्रक्रियाओं और हमलों से जुड़ी रणनीतियों के क्षेत्र में एक-दूसरे की संकल्पनाओं को समझने की दिशा में काफी मदद मिली।

5.23 संयुक्त योजना-निर्माण और ऑपरेशन : किसी भी भावी युद्ध के लिए संयुक्त ऑपरेशन सफलता का मूल मंत्र होते हैं और इस प्रकार ये सभी तीन सेनाओं के प्रशिक्षण/अभ्यासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं जिनसे एक-दूसरे के साथ ऑपरेशनों के लिए बेहतर तालमेल बिठाने में मदद मिलती है। वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 'योजना' तीनों सेना के साझा प्रशिक्षण के लिए माध्यम बनता है और इससे भारतीय वायु सेना हवाई क्षेत्र से जुड़े कार्यों को अंजाम देती है।

5.24 भारत-यू के संयुक्त अभ्यास 'अजेय वॉरियर', भारत-नाइजीरिया संयुक्त विशेष बल (एस एफ) प्रशिक्षण/अभ्यास, भारत-नेपाल संयुक्त अभ्यास "सूर्यकिरण-V" भारत-पोलैंड संयुक्त अभ्यास प्रशिक्षण, भारत-रूस संयुक्त अभ्यास "इंद्र-13" और भारत-ताजिकिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास कुछ ऐसे संयुक्त अभ्यास हैं जो मित्र राष्ट्रों के साथ संचालित किए गए। इन अभ्यासों में भारतीय वायु सेना के एम एल एच और हमलावर हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल व्यापक स्तर पर किया गया।

5.25 भारतीय वायु सेना-भारतीय नौसेना संयुक्त अभ्यास, गुजरात रक्षा अभ्यास (डीजीएक्स) और ट्रॉपेक्स अभ्यास हर वर्ष संचालित किए जाते हैं। हमारे देश की दोनों समुद्रतटीय सीमाओं (सीबोर्ड) की रक्षा के लिए समुद्री हवाई ऑपरेशनों को अंजाम देने में भारतीय वायु सेना की परिसंपत्तियों को व्यापक स्तर पर काम में लगाया जाता है। डी जी एक्स-13 का संचालन अक्टूबर 2013 में पश्चिमी समुद्रतटीय सीमा (सीबोर्ड) से लगे क्षेत्र में और ट्रॉपेक्स-14 का संचालन जनवरी-फरवरी 2014 में किया गया।

## बुनियादी ढांचा

5.26 न्योमा में एयरबेस का विकास : पूर्वी लद्दाख में संक्रियात्मक क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक कदम के रूप में भारतीय वायु सेना ने न्योमा में एक नए एयरबेस के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। इस निर्माण का उद्देश्य, भारतीय वायु सेना की मालसूची (इन्वेंट्री) पर रखे सभी किस्म के वायुयानों के ऑपरेशन के लिए एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड (ए एल जी) को उपयुक्त (फिट) बनाना है।

5.27 पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे का विकास : प्रधानमंत्री द्वारा 2008 में पूर्वी वायु कमान के जिम्मेदारी वाले क्षेत्र (ए ओ आर) में बुनियादी ढांचे

के विकास का काम शुरू करने के फैसले की घोषणा की गई थी। इसके परिणामस्वरूप निर्माण-कार्य की प्रगति की देख-रेख के लिए एक अधिकार-प्राप्त समिति गठित की गई और अरुणाचल प्रदेश में ए एल जी के विकास सहित बुनियादी ढांचे के विकास संबंधी विभिन्न निर्माण-कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदन प्रदान किया गया। पूर्वी वायु कमान ए ओ आर में ए एल जी और कुछ अन्य वायु सेना स्टेशनों में निर्माण-कार्य शुरू हो चुका है। इससे भारतीय वायु सेना की संक्रियात्मक क्षमता में वृद्धि होगी और अरुणाचल प्रदेश में नागर विमानन तथा पर्यटन को निश्चित तौर पर बढ़ावा मिलेगा।





## भारतीय तटरक्षक



**रा**जनीतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा एक अंतरिम तटरक्षक संगठन स्थापित किए जाने के लिए अनुमोदन देने पर भारतीय तटरक्षक 01 फरवरी, 1977 को अस्तित्व में आया। तटरक्षक अधिनियम, 1978 के विधान के साथ ही इस सेवा की एक स्वतंत्र संगठन के रूप में 19 अगस्त, 1978 को औपचारिक रूप से स्थापना हुई।

6.1 राजनीतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा एक अंतरिम तटरक्षक संगठन स्थापित किए जाने के लिए अनुमोदन देने पर भारतीय तटरक्षक 01 फरवरी, 1977 को अस्तित्व में आया। तटरक्षक अधिनियम, 1978 के विधान के साथ ही इस सेवा की एक स्वतंत्र संगठन के रूप में 19 अगस्त, 1978 को औपचारिक रूप से स्थापना हुई। भारतीय नौसेना से प्राप्त दो फ्रिगेटों और सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त पाँच गश्ती नौकाओं के साथ तटरक्षक ने 1978 में अपना सफर शुरू किया। अपनी स्थापना के समय से, इस सेवा ने शांति काल के दौरान उसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करने तथा युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के प्रयासों की अनुपूर्ति करने के लिए सतह और वायुवाहित दोनों ही प्रकार की व्यापक क्षमताएं हासिल की हैं।

6.2 **संगठन:** तटरक्षक की कमान और नियंत्रण नई दिल्ली स्थित महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक के द्वारा की जाती है। इस संगठन के गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर स्थित 5 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। ये क्षेत्रीय मुख्यालय भारत के तटवर्ती राज्यों में स्थित 13 तटरक्षक जिला मुख्यालयों के माध्यम से

भारत की संपूर्ण तटरेखा से लगे समुद्र में कमान और नियंत्रण संभालते हैं। इसके अलावा, खोज एवं बचाव कार्य तथा समुद्री निगरानी के लिए पोतों व विमानों की प्रभावी रूप से तैनाती करने हेतु विभिन्न सामरिक स्थानों पर 41 स्टेशन, 2 वायु स्टेशन, 06 एयर एंक्लेव और 01 स्वतंत्र एयर स्क्वाड्रन स्थापित किए गए हैं।

6.3 **कार्य तथा प्रकार्य:** तटरक्षक को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:-

- (क) समुद्री क्षेत्रों में कृत्रिम द्वीपों, अपतटीय टर्मिनलों, संस्थापनाओं तथा अन्य संरचनाओं और साधनों की सुरक्षा तथा संरक्षा सुनिश्चित करना।
- (ख) समुद्र में संकट के दौरान मछुआरों की सहायता करने सहित उनको संरक्षण प्रदान करना।
- (ग) ऐसे उपाय करना जो समुद्री पर्यावरण की संरक्षा एवं सुरक्षा तथा समुद्री प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए आवश्यक हों।
- (घ) तस्करी-रोधी अभियानों में सीमा-शुल्क तथा अन्य प्राधिकरणों की सहायता करना।
- (च) समुद्री क्षेत्रों में किसी समय लागू अधिनियमों के उपबंधों को प्रवर्तित करना।

(छ) समुद्र में जान और माल की सुरक्षा करने के लिए उपायों सहित अन्य मामलों पर कार्रवाई करना तथा यथानिर्दिष्ट वैज्ञानिक आंकड़ों का संग्रहण करना ।

(ज) भारतीय तटरक्षक की स्थापना के समय से इसे अतिरिक्त कार्य भी सौंपे गए हैं, जो इस प्रकार है:-

- (i) राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव समन्वय प्राधिकरण ।
- (ii) राष्ट्रीय तेल बिखराव की घटनाओं हेतु समन्वय प्राधिकरण ।
- (iii) अपतटीय तेल क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए समन्वय ।
- (iv) एशिया में क्षेत्रीय सहयोग समझौते के तहत समुद्री डकैती रोधी कार्रवाइयों में समन्वय के लिए भारत में केंद्र बिंदु ।
- (v) समुद्री सीमाओं के लिए अग्रणी आसूचना एजेंसी ।

6.4 **मौजूदा बल स्तर:** भारत के समुद्री क्षेत्रों की नियमित रूप से निगरानी करने के लिए भारतीय तटरक्षक के बेड़े में इस समय 46 पोत, 45 नौकाएं/होवरक्राफ्ट, 28 कमीशन न किए गए क्राफ्ट तथा 64 विमान हैं । वर्ष 2013-14 में (01 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2014 तक) एक अपतटीय गश्ती पोत

(ओपीवी), 5 तीव्रगामी गश्ती पोत (एफपीवी), 6 उपतटीय गश्ती पोत (आईपीवी), 6 वायु उपधान वाहन (एसीवी), 9 अंतर्रोधी नौकाएं (आईबी), 4 अंतर्रोधी क्रॉफ्ट (आईसी) और 7 डोर्नियर वायुयान भारतीय तटरक्षक के बेड़े में शामिल हुए हैं ।

## तटीय सुरक्षा

6.5 26/11 के बाद, भारतीय तटरक्षक को प्रादेशिक समुद्र में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में भी नामोदिष्ट किया गया है जिसमें वह समुद्र भी शामिल है जहां तटीय पुलिस द्वारा गश्त लगाई जाती है । महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक को कमांडर, तटीय कमान के रूप में भी नामोदिष्ट किया गया है और वे तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों के मध्य समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी हैं ।

6.6 तटरक्षक बल नौसेना के साथ समन्वय करके संपूर्ण तटीय रेखा की गश्त तथा चौकसी कर रहा है। समन्वित गश्तों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए 01 जनवरी, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक 16 तटीय सुरक्षा अभ्यास किए गए हैं ।

6.7 अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सामान्य गश्त के अलावा तटीय सुरक्षा के लिए तटरक्षक पोतों और वायुयानों की तैनाती बढ़ा दी गई है । तटीय सुरक्षा अभ्यासों के अलावा 01 जनवरी,

**समन्वित गश्तों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए 01 जनवरी, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक 16 तटीय सुरक्षा अभ्यास किए गए हैं ।**

2013 से 31 मार्च, 2014 तक तटरक्षक द्वारा हितधारकों के साथ समन्वय करके 38 तटीय सुरक्षा संक्रियाएं संचालित की गई हैं। तटरक्षक बल सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों के जरिए मत्स्य समुदाय के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखता है। 01 जनवरी, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के दौरान संकट चेतावनी ट्रांसमीटरों, रक्षा बोयाओं जैसे जीवनरक्षक उपकरणों के प्रयोग के बारे में जानकारी देने तथा समुद्र की ओर के खतरों की पूर्व चेतावनी देने के लिए 'आँख और कान' के रूप में कार्य करने के लिए कुल 659 सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

## महत्वपूर्ण लक्ष्य और उपलब्धियां

**6.8 पोर्ट ब्लेयर में तटरक्षक जिला मुख्यालय नं.-14 की स्थापना:** 18 दिसंबर, 2013 को पोर्ट ब्लेयर में तटरक्षक जिला मुख्यालय नं.-14 की स्थापना की गयी।

**6.9 तटरक्षक स्टेशनों की कमीशनिंग:** गोपालपुर (ओडिशा), पीपावाव(गुजरात) और कमोर्ता (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) में क्रमशः 26 फरवरी, 2013, 12 जुलाई, 2013 और 07 नवंबर, 2013 को तटरक्षक के तीन स्टेशनों को कमीशन किया गया।

**6.10 तटरक्षक स्टेशन का सक्रियण:** 27 फरवरी 2013 को निजामपतनम (आंध्र प्रदेश) में भारतीय तटरक्षक के एक स्टेशन को क्रियाशील किया गया और इसके वर्ष 2014 के प्रारंभ में कमीशन किए जाने की योजना है।

**6.11 अपतटीय गश्ती पोत(ओपीवी) की कमीशनिंग:** 21 मई, 2013 को एक अपतटीय गश्ती पोत, भारतीय तटरक्षक पोत वैभव को कमीशन किया गया।



21 मई, 2013 को महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक द्वारा भारतीय तटरक्षक पोत वैभव की कमीशनिंग

**6.12 तीव्रगामी गश्ती पोतों की कमीशनिंग:** भारतीय तटरक्षक पोत आदेश, भारतीय तटरक्षक पोत अभीक और भारतीय तटरक्षक पोत अभिनव नामक तीन तीव्रगामी गश्ती पोतों को क्रमशः 13 दिसंबर, 2013, 31 दिसंबर, 2013 और 15 जनवरी, 2014 को कमीशन किया गया।

**6.13 तीव्रगामी गश्ती पोतों (एफपीवी) का समावेशन:** भारतीय तटरक्षक पोत अभिराज और भारतीय तटरक्षक पोत अचूक नामक दो तीव्रगामी गश्ती पोतों को क्रमशः 04 मार्च 2014 और 28 मार्च 2014 को सेवा में शामिल किया गया और इनको शीघ्र ही कमीशन किया जाएगा।

**6.14 उपतटीय गश्ती पोतों (आईपीवी) की कमीशनिंग:** भारतीय तटरक्षक पोत राजकमल, भारतीय तटरक्षक पोत राजतरंग, भारतीय तटरक्षक पोत राजदूत, भारतीय तटरक्षक पोत रानी



अवंतीबाई, भारतीय तटरक्षक पोत राजवीर और भारतीय तटरक्षक पोत राजध्वज नामक छह उपतटीय गश्ती पोतों को क्रमशः 08 जनवरी, 2013, 11 फरवरी, 2013, 22 अप्रैल, 2013, 09 मई, 2013, 10 अगस्त, 2013 और 11 दिसंबर, 2013 को कमीशन किया गया ।

**6.15 वायु उपधान वाहनों(एसीवी) की कमीशनिंग:** एच-190, एच-191, एच-192, एच-194 और एच-193 नामक पांच वायु उपधान वाहनों को क्रमशः 19 फरवरी, 2013, 09 अप्रैल, 2013, 23 दिसंबर, 2013 और 13 फरवरी, 2014 को कमीशन किया गया ।

**6.16 वायु उपधान वाहन (एसीवी) का समावेशन:** 21 मार्च, 2014 को एच-195 नामक एक वायु उपधान वाहन को सेवा में शामिल किया गया और इसे शीघ्र ही कमीशन किया जाएगा ।

**6.17 अंतर्रोधी नौकाओं (आईबी) की कमीशनिंग:** सी-154, सी-402, सी-425, सी-403, सी-426, सी-404, सी-405 और सी-406 नामक आठ अंतर्रोधी नौकाओं को क्रमशः 22 फरवरी, 2013, 12 अप्रैल, 2013, 27 अप्रैल, 2013, 11 अगस्त, 2013, 19 सितंबर, 2013, 06 दिसंबर, 2013 और 17 फरवरी, 2014 को किया गया ।

**6.18 अंतर्रोधी नौका (आईबी) का समावेशन:** 19 फरवरी, 2014 को भारतीय तटरक्षक पोत सी-427 नामक एक अंतर्रोधी नौका को सेवा में शामिल किया गया तथा जिसका कमीशन शीघ्र किया जाना है ।

**6.19 अंतर्रोधी क्रॉफ्टों (आईसी) का समावेशन:** वर्ष 2013 के दौरान चार अंतर्रोधी क्रॉफ्टों (आईसी-307 से आईसी-310) को सेवा में शामिल किया गया ।

**6.20 वायुयानों का समावेशन:** वर्ष 2013 के दौरान सीजी-785, सीजी-786, सीजी-787, सीजी-788, सीजी-789 और सीजी-790 नामक छह डोर्नियर वायुयानों को सेवा में शामिल किया गया तथा एक डोर्नियर वायुयान फरवरी 2014 में भारतीय तटरक्षक के बेड़े में शामिल हुआ ।

## अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

**6.21 भारतीय तटरक्षक-जापान तटरक्षक की 12वीं उच्च स्तरीय बैठक:** पारस्परिक हितों के समुद्री मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और इन मुद्दों के निवारण हेतु एक सहयोगी दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए जापान तटरक्षक के साथ 12वीं उच्च स्तरीय बैठक के संबंध में महानिदेशक भारतीय तटरक्षक के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 20 से 24 जनवरी, 2013 के दौरान जापान का दौरा किया ।

**6.22 रिकैप, आईएससी, सिंगापुर की शासी परिषद की सातवीं वार्षिक बैठक:** भारतीय तटरक्षक, समुद्र में जलदस्युता और सशस्त्र डकैती से निपटने विषयक क्षेत्रीय सहयोग अनुबंध के संबंध में एशियाई सूचना सहभागिता केंद्र (रिकैप, आईएससी) को लगातार सहायता दे रहा है तथा उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है। 05 से 07 मार्च के दौरान सिंगापुर में रिकैप, आईएससी की 7वीं बैठक में भाग लेने के लिए उपमहानिदेशक

(संक्रिया एवं तटीय सुरक्षा) ने भारतीय तटरक्षक के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया ।

**6.23 भारतीय तटरक्षक और श्रीलंकाई तटरक्षक के बीच उच्च स्तरीय बैठक:** पारस्परिक सरोकार के समुद्री मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और एक सहयोगी दृष्टि कोण को विकसित करने के लिए महानिदेशक भारतीय तटरक्षक के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 09 से 14 जून, 2013 के दौरान कोलम्बो, श्रीलंका का दौरा किया ।



कोलम्बो, श्रीलंका में भारतीय तटरक्षक - श्रीलंकाई तटरक्षक के बीच उच्च स्तरीय बैठक

**6.24 भारतीय तटरक्षक और पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी के बीच उच्च स्तरीय बैठक:** पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी के साथ उच्च स्तरीय बैठक के



कराची, पाकिस्तान में भारतीय तटरक्षक और पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी के बीच उच्चस्तरीय बैठक

लिए महानिदेशक भारतीय तटरक्षक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 23 से 26 जून, 2013 के दौरान कराची का दौरा किया ।

**6.25 पट्टया, थाईलैंड में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 9वीं बैठक:** एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों (एचएसीजीएएम) की 9वीं बैठक में भाग लेने के लिए महानिदेशक भारतीय तटरक्षक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 28 से 30 अक्टूबर, 2013 के दौरान पट्टया, थाईलैंड का दौरा किया । एचएसीजीएएम एक शीर्ष स्तर का मंच है जो एशियाई क्षेत्र में सभी प्रमुख तटरक्षक एजेंसियों की बैठक को सुकर बनाता है ।

**6.26 समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया के सुदृढीकरण हेतु भारत-मालदीव-श्रीलंका त्रिपक्षीय सहयोग कार्यक्रम:** भारतीय तटरक्षक ने भारत मालदीव-श्रीलंका त्रिपक्षीय सहयोग कार्यक्रम के अधीन 25 नवंबर, 2013 से 06 दिसंबर, 2013 के दौरान मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) तेल प्रदूषण तत्परता, प्रतिक्रिया और सहयोग (ओपीआरसी) स्तर-1 एवं स्तर-2 पाठ्यक्रमों को आयोजित किया । प्रशिक्षण में मालदीव और श्रीलंका से आये पाँच-पाँच प्रतिभागियों ने भाग लिया । आईएमओ स्तर-1 एवं स्तर-2 की समाप्ति उपरांत, प्रशिक्षित विदेशी अधिकारियों ने 10 दिसंबर, 2013 को मुंबई के पास समुद्र में राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास के पाँचवें संस्करण में प्रेक्षक के रूप में भाग लिया । आईएमओ ओपीआरसी स्तर-1 एवं स्तर-2 प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक

संपूर्ण होने से तेल बिखराव प्रतिक्रिया में हमारे देश की स्थिति में, एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर के रूप में, अभिवृद्धि हुई है ।



भारत-मालदीव-श्रीलंका त्रिपक्षीय सहयोग कार्यक्रम

6.27 भारतीय तटरक्षक-जापान तटरक्षक की वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक और संयुक्त अभ्यास: भारतीय तटरक्षक के साथ उच्च स्तरीय बैठक और संयुक्त अभ्यास के लिए एडमिरल यूजी सेतो, कमांडेंट जापान तटरक्षक (जेसीजी) के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 12 से 15 जनवरी, 2014 के दौरान भारत का दौरा किया । इस संपर्क कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता महानिदेशक भारतीय तटरक्षक ने की । 13 जनवरी, 2014 को तटरक्षक मुख्यालय, दिल्ली



आईसीजी-जेसीजी के प्रतिनिधिमंडल की उच्च स्तरीय बैठक

में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान, दोनों तटरक्षक के प्रमुखों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा की । इस उच्च स्तरीय बैठक के उपरांत 14 जनवरी, 2014 को कोची में भारतीय तटरक्षक-जापान तटरक्षक का एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया ।

6.28 प्रमुख अभ्यानों का ब्योरा निम्नवत है:

क्र. सं.	विषय	प्रारंभ से	01 जनवरी, 2013 से 31 मार्च, 2013 तक
(i)	वर्जित वस्तुएं पकड़ी	510.244 करोड़ रुपए	6.5 करोड़ रुपए
(ii)	अनधिकृत मछली शिकार में लिप्त ट्रालरों को पकड़ना	1441 नौकाएं 12570 कर्मी	87 नौकाएं 523 Crew
(iii)	तस्करी पोतों को पकड़ना	123 नौकाएं 761 कर्मी	03 नौकाएं 29 कर्मी
(iv)	खोज एवं बचाव (एसएआर) मिशन	2770	485
(v)	खोज एवं बचाव (एसएआर) सार्टियां	3600	400
(vi)	जीवन बचाव	6330	672
(vii)	चिकित्सा निकासी	167	14
(viii)	तेल बिखराव घटनाओं में प्रतिक्रिया	86	01
(ix)	विदेश में तेल बिखराव की घटनाएं	01	—

## 6.29 खोज एवं बचाव

(क) **राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव की 12वीं बैठक, मुंबई मे:** 08 अगस्त, 2013 को तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय (पश्चिम), मुंबई में राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव (एनएमएसएआर) बोर्ड की 12वीं बैठक आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता महानिदेशक भारतीय तटरक्षक ने की और भारतीय खोज एवं बचाव क्षेत्र (एसआरआर) में खोज एवं बचाव (एसएआर) प्रणाली में सुधार लाने संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

(ख) **संकटग्रस्त यात्रियों का बचाव:** 08 जनवरी, 2013 को तटरक्षक जिला मुख्यालय नं.-8, हल्दिया को 'दिघा मोहना' समुद्री पुलिस स्टेशन से एक संदेश प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने दरियापुर लाईट के 4.6 समुद्री मील दक्षिण पूर्व की स्थिति में भूग्रस्त हुई फेरी लॉच "बसंत मोई" से संकटग्रस्त यात्रियों का बचाव करने का अनुरोध किया। सूचना मिलते ही, वायु उपधान वाहन (एसीवी) एच-188 को संकटग्रस्त यात्रियों का बचाव करने के लिए क्षेत्र में भेजा गया। भारतीय तटरक्षक वायु उपधान वाहन ने 125 यात्रियों (जिसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे) का बचाव किया।

(ग) **मछुवाही नौका "श्री राज" पर अग्नि की घटना:** 25 मार्च, 2013 को निगरानी उड़ान कर रहे तटरक्षक डोर्नियर वायुयान ने देखा कि ओखा के 86 समुद्री मील उत्तर-पश्चिम की स्थिति में मछुवाही नौका 'श्री राज' पर आग लग गयी

है। वायुयान ने अनन्य आर्थिक क्षेत्र में संक्रिया कर रहे भारतीय तटरक्षक पोत मीरा बेन को मार्गनिर्देशित किया। भारतीय तटरक्षक पोत ने नौका से 06 मछुवारों का बचाव किया।

(घ) **मछुवाही नौका 'बनदुर्गा' को सहायता:** 19 जून, 2013 को अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजैड) में गश्त करने के दौरान भारतीय तटरक्षक पोत राजकिरण को मछुवाही नौका 'बनदुर्गा' से अति उच्च आवृत्ति (वीएचएफ) पर एक संकट संदेश प्राप्त हुआ कि नौका, इंजन में खराबी के कारण डॉवाडोल होकर अनंतिम भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) को पार कर गयी है। अक्षम हुई नौका को भारतीय समुद्र में लाया गया और तत्पश्चात पोत के तकनीकी दल ने नौका के इंजन की खराबी को दूर कर दिया गया।

(च) **पोत 'एमवी एशियन एक्सप्रेस के कर्मियों का बचाव:** 12 जून, 2013 को एकीकृत मुख्यालय/रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने तटरक्षक मुख्यालय को सूचित किया कि 11 जून, 2013 को इंजन फेल होने के कारण कावार्थी द्वीप के 82 समुद्री मील दक्षिण की स्थिति में एक पोत 'एमवी एशियन एक्सप्रेस' संकटग्रस्त हो गया है। सूचना मिलने पर भारतीय तटरक्षक पोत वरुण और डोर्नियर वायुयान कोची से रवाना हुआ तथा पोत से 22 कर्मियों का बचाव कर लिया गया।

(छ) **राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव की छठी वर्कशाप एवं अभ्यास (एसएआरईएक्स-14):** भारतीय



तटरक्षक ने मुंबई में 19-20 मार्च, 2014 को छठे खोज एवं बचाव वर्कशाप एवं अभ्यास-2014 को आयोजित किया। 09 समुद्री राष्ट्रों से आये कुल 18 अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों ने प्रेक्षक के रूप में अभ्यास में भाग लिया। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बचाव एजेंसियों के सदस्यों और अन्य समुद्री हितधारकों ने भी अभ्यास में भागीदारी की।



राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव का छठा अभ्यास  
(सारेक्स-14)

(ज) पोन्नानी के पास अक्षम हुई मछुवाही नौका का बचाव: 01 जनवरी, 2014 को भारतीय तटरक्षक स्टेशन बेपूर (केरल) को 3 कर्मियों के साथ लापता हुई एक मछुवाही नौका की सूचना प्राप्त

हुई। सूचना मिलने पर, भारतीय तटरक्षक पोत, सी-404, जोकि नजदीकी क्षेत्र में तटीय गश्त कर रहा था, को लापता नौका का पता लगाने का निर्देश दिया गया। पोत ने असमर्थ हुई मछुवाही नौका को ढूँढ लिया तथा नौका को पोन्नानी लाया गया और उसे मछुवाही बंदरगाह तक खींच कर ले जाने के लिए अन्य मछुवाही नौका के सुपुर्द कर दिया गया।

(झ) नौका 'एमएफबी साहित्य' को सहायता: 02 फरवरी, 2014 को समुद्री बचाव उप केंद्र, गोवा को नौका 'एमएफबी साहित्य', जिस पर चौदह कर्मी थे, के सैलाबग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलने पर, भारतीय तटरक्षक पोत सी-148 को संकटग्रस्त नौका पता लगाने के लिए गोवा से रवाना किया गया। क्षेत्र में पहुँचने पर भारतीय तटरक्षक पोत द्वारा संकटग्रस्त नौका को मरमुगो बंदरगाह लाया गया और उसे मछुवाही बंदरगाह तक खींच कर ले जाने के लिए अन्य मछुवाही नौका के सुपुर्द कर दिया गया।





## रक्षा उत्पादन



आईसीजीएस रानी अवन्तीबाई का जलावतरण 9 मई, 2013 को किया गया था

**पि**छले वर्षों में इस विभाग ने आयुध निर्माणियों और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से विभिन्न रक्षा उपकरणों के लिए व्यापक उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं।

7.1 रक्षा उत्पादन विभाग (डी डी पी) की स्थापना नवंबर, 1962 में रक्षा के लिए आवश्यक हथियारों / प्रणालियों / प्लेटफार्मों / उपस्करों का उत्पादन करने के लिए व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से की गई थी। पिछले वर्षों में इस विभाग ने आयुध निर्माणियों और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से विभिन्न रक्षा उपकरणों के लिए व्यापक उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। विनिर्मित उत्पादों में हथियार एवं गोलाबारूद, टैंक, बख्तरबंद वाहन, भारी वाहन, लड़ाकू विमान एवं हेलिकॉप्टर, युद्ध पोत, पनडुब्बियां, प्रक्षेपास्त्र, गोलाबारूद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, विशेष मिश्र धातुएं और विशेष प्रयोजन वाले इस्पात शामिल हैं।

7.2 रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख संगठन हैं:

- आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ एफ बी)
- हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल)
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी ई एल)
- भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल)

- बी ई एम एल लिमिटेड (बी ई एम एल )
- मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)
- माझगांव डॉक लिमिटेड (एम डी एल)
- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जी आर एस ई)
- गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल)
- हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एच एस एल)
- गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डी जी क्यू ए)
- वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डी जी ए क्यू ए)
- मानकीकरण निदेशालय (डी ओ एस)
- योजना एवं समन्वय निदेशालय (डाइरेक्टोरेट आफ पी एण्ड सी)
- रक्षा प्रदर्शनी संगठन (डी ई ओ)
- राष्ट्रीय रक्षा पोत निर्माण अनुसंधान व विकास संस्थान (निर्देश)

7.3 रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से आयुध निर्माणियां और सार्वजनिक क्षेत्र के

रक्षा उपक्रम अपनी क्षमताओं को निरंतर आधुनिक और उन्नयित तथा अपनी उत्पादन रेंज को विस्तृत कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी अंतरण के माध्यम से बहुत से उत्पादों एवं उपस्करों का उत्पादन करने के अलावा इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास संबंधी पहलों के माध्यम से कई प्रमुख उत्पादों का विकास किया गया है।

7.4 कर पश्चात् लाभ सहित आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों का उत्पादन एवं कारोबार, क्रमशः सारणी सं0 7.1 व सारणी सं0 7.2 में दर्शाया गया है।

7.5 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणियों ने, नीति के रूप में, अपनी जरूरतों का बहुत सारा काम बाहर से करवाया है और पिछले वर्षों में एक व्यापक विक्रेता आधार विकसित किया है जिसमें भारी उद्योग के अलावा अनेक मध्यम और लघु उद्यम भी शामिल हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम और आयुध निर्माणी बोर्ड अपने विनिर्मित उपस्करों एवं उत्पादों में स्वदेशी मात्रा बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत हैं।

### **निजी क्षेत्र की भागीदारी**

7.6 जहां भी प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और स्वदेशीकरण करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। मई, 2001 में, रक्षा उद्योग क्षेत्र को जो कि अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था, लाइसेंस के अधीन 26 प्रतिशत तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित शत-प्रतिशत तक की भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया था। तथापि, जहां 26% से अधिक

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से देश को आधुनिक एवं नवोन्नत प्रौद्योगिकी मिलाने की संभावना हो, तो मामले-दर-मामले के आधार पर, ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन से उच्चतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमति दिए जाने के लिए निर्णय लिए जा सकते हैं। लाइसेंस के तहत हथियारों और गोलाबारूद का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी आई पी पी) अपने 4 जनवरी, 2002 के प्रेस नोट 2 (2002 श्रृंखला) द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर चुका है।

7.7 हथियारों और आयुधों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी आई पी पी) से प्राप्त सभी आवेदनों और आर्थिक कार्य विभाग (डी ई ए) की एफ आई पी बी इकाई से प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) के प्रस्तावों पर विचार करने तथा संबंधित विभागों के प्रस्तावों पर सिफारिशें देने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग में एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। यह समिति लाइसेंसशुदा कंपनियों द्वारा रक्षा उपस्करों के उत्पादन से संबंधित सभी मामलों अर्थात् स्वतः प्रमाणन के लिए आवेदनों, लाइसेंस के तहत विनिर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए अनुमति देने और लाइसेंस संबंधी शर्तों या सुरक्षा प्रावधानों के उल्लंघन आदि के कारण लाइसेंस रद्द करने पर भी विचार करती है। वर्तमान में, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय, थल सेना मुख्यालय, डी जी क्यू ए, डी जी ए क्यू ए, रक्षा विभाग, ओ एफ बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और बी ई एल जैसे विविध क्षेत्रों से सदस्यों सहित

संयुक्त सचिव (डी आई पी) इस स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं।

7.8 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी आई पी पी) ने 126 निजी कंपनियों को कई

प्रकार की रक्षा मदों के विनिर्माण के लिए 31 मार्च, 2014 तक 210 आशय-पत्र (एल ओ आई)/औद्योगिक लाइसेंस (आई एल) जारी किए हैं। अब तक 43 लाइसेंस प्राप्त कंपनियों ने उत्पादन आरंभ करने की सूचना दी है। रक्षा उद्योग क्षेत्र को, वर्तमान नीतियों के अनुसार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) के साथ भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोलने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में विभिन्न रक्षा उपकरणों के विनिर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में 31 मार्च, 2014 तक 30 एफ डी आई प्रस्तावों/संयुक्त उद्यमों को अनुमोदन दिया जा चुका है।

7.9 रक्षा उत्पादन विभाग ने लाइसेंसिंग प्रयोजनार्थ रक्षा उत्पादों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है जिसे औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी आई पी पी) जो औद्योगिक लाइसेंसिंग के लिए नोडल विभाग है, की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। रक्षा उत्पादों की सूची [www.dipp.nic.in](http://www.dipp.nic.in) 'निवेशकों के लिए' शीर्षक में 'निवेशक मार्गदर्शन' वाले अगले लिंक से देखी जा सकती है।

7.10 **भारतीय रक्षा उद्योग की निर्यात संबंधी रूपरेखा:** रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपकरणों तथा आयुध निर्माणी बोर्ड सहित

**आयुध निर्माणियां प्रयोक्ताओं की भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर अपनी आधारभूत संरचना को सतत रूप से उन्नयित करती रही हैं।**

भारतीय रक्षा उद्योग के निर्यातों का मूल्य वर्ष 2012-13 में 460.97 करोड़ रु0 था तथा 2013-14 में यह (अनंतिम रूप से) 635.45 करोड़ रु0 का है। निर्यात का यह रुझान उद्योग

द्वारा की गई बहुत अच्छी वृद्धि को दर्शाता है। रक्षा उत्पादों के लिए बड़े निर्यात वाले कुछ देश इस प्रकार हैं:- इटली, इजरायल, इक्वाडोर, रूस, अमरीका, यू ए ई, नामीबिया, श्रीलंका, मलेशिया, सेशेल्स, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया, यू के, इंडोनेशिया, मारीशस, नीदरलैण्ड, सूरीनाम, केन्या, नेपाल, बोत्सवाना और ओमान। निर्यात की गई कुछ रक्षा मदें इस प्रकार हैं:- डी जी सेट्स, रडार के लिए स्पेयर पार्ट, सेंसर रडार वार्निंग रिस्वीवर्स, हेलिकॉप्टर स्पेयर पार्ट, जगुआर स्पेयर पार्ट, मिग स्पेयर पार्ट, डोरनियर विमान स्पेयर पार्ट, फोर्जिंग्स आदि। निजी रक्षा उद्योग द्वारा निर्यात में काफी वृद्धि दिखाई गई है। निजी क्षेत्र की लगभग 10-12 कंपनियों ने रक्षा निर्यातों में योगदान दिया है। विभाग ने सेना के लिए साजो-सामान का निजी कंपनियों द्वारा निर्यात करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन ओ सी) जारी करने के लिए मानक प्रचालन कार्य प्रणाली (एस ओ पी) को अंतिम रूप दिया है।

## आयुध निर्माणी संगठन

7.11 इस समय आयुध निर्माणी बोर्ड की 39 निर्माणियां हैं। दो नई आयुध निर्माणियां - एक बिहार में नालंदा और यू पी में कोरबा में निर्माणाधीन हैं। इस समय आयुध निर्माणी बोर्ड में लगभग 93519 कार्मिक हैं। आयुध निर्माणियां प्रयोक्ताओं की भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर अपनी आधारभूत



संरचना को सतत रूप से उन्नयित करती रही हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान आयुध निर्माणी बोर्ड का कारोबार (टर्न ओवर) 11234 करोड़ रु० रहा (प्रोविजनल)।

7.12 आयुध निर्माणी बोर्ड ने सेनाओं को उपलब्ध कराए जाने वाले युद्धक क्षेत्र उपस्करों को अत्याधुनिक बनाने के लिए कई परियोजनाओं को शुरू किया है। सेनाओं द्वारा अपेक्षित कुछ महत्वपूर्ण हथियारों एवं गोलाबारूद संबंधी आत्मनिर्भरता में सुधार करने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड ने रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के साथ मिलकर कई अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। आयुध निर्माणी बोर्ड अपनी अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रही है ताकि इसे और अधिक कारगर बनाया जा सके।

7.13 प्रयोक्ताओं की दीर्घ अवधि एकीकृत अधिप्राप्ति नीति (एल टी आई पी पी) के आधार पर आयुध निर्माणी बोर्ड ने आयुध निर्माणियों में भावी अर्जन और समावेशन के लिए मोटे तौर पर प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों की पहले ही पहचान कर ली है। रक्षा मंत्रालय की प्रौद्योगिकी संदर्श और सक्षमता रोड मैप (टी पी सी आर) संबंधी दस्तावेजों का अध्ययन किया गया है और भावी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए कतिपय प्रौद्योगिकियों की पहचान कर ली गई है। आई आई टी, कानपुर की अनुसंधान सहायता से उन्नत आर्टिलरी गाइडेड शेल प्रणाली तथा डी आर डी ओ, रक्षा उपक्रमों और भारतीय उद्योग प्रौद्योगिकी भागीदारों के सहयोग से भावी काम्बेट सिस्टम अर्थात् एफ आई सी वी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

7.14 आयुध निर्माणी बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में उत्पादन मूल्य के संदर्भ में 85.3% का स्वदेशी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। महत्वपूर्ण

उपलब्धियां हैं - कमांडर हैच कंट्रोल यूनिट जो टी-90 टैंक का एक क्रिटिकल यूनिट है, का स्वदेशीकरण, टी-90 टैंक के 50 प्रकार के क्रिटिकल ऑप्टिकल कंपोनेंट का स्वदेशी उत्पादन, टी-90 टैंक के लिए 5 प्रकार के केबल हारनेस और ब्रिज लेइंग टैंक (बी एल टी) के लिए केबलों के सेट का स्वदेशी विकास रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से राकेट का स्वदेशी विकास शामिल है। आयुध निर्माणी बोर्ड की अन्य उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (i) प्रयोक्ता द्वारा शीतकालीन परीक्षणों के लिए जनवरी 2014 में ओ एफ बी गन 'धनुष' को तैनात किया गया था। इसके परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं।
- (ii) ओ एफ बी द्वारा निर्मित टी-72 संशोधित केमिस्ट्री बैरल का आरमर्ड कोर सेंटर एण्ड स्कूल, अहमदनगर में लाइफ साइकिल टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है।
- (iii) प्रौद्योगिकी अंतरण की उपलब्धता न होने के बावजूद आयुध निर्माणी आवड़ी ने सी वी आर डी ई (डी आर डी ओ) के सहयोग से एम बी टी अर्जुन के प्रथम इंजन की मरम्मत का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है।
- (iv) आयुध निर्माणी, दमदम ई एन एम एस: आई एस ओ : 51000 (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) पुरस्कार के लिए संस्तृत भारत का पहला सरकारी संगठन है।

7.15 **आधुनिकीकरण:** सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए ओ एफ बी ने कई चल रही स्वीकृत परियोजनाओं में क्षमता बढ़ाने की कार्रवाई की है। चल रही इन परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत 4571 करोड़ रु० है।

7.16 ओ एफ बी में प्रति कर्मचारी मूल्य का निर्गम (टर्न ओवर) 2007-08 में 6.4 से 2013-14 में 11.9 तक पहुंच गया है अर्थात् इसमें छह वर्ष की अवधि में 86% से अधिक की वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र के उद्योगों को एक वेंडर के रूप में भागीदार बनाकर समग्र

उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार उत्पादन बढ़ाने के लिए ओ एफ बी ने लगभग 5603 वेंडरों को पंजीकृत किया है।

7.17 पर्यावरण संरक्षण: 39 में से 37 आयुध निर्माणियां बी आई एस, एन क्यू ए क्यू एस आर, एन ओ आर एस के ई, वी ई आर टी ए एस जैसे विभिन्न सत्यापन निकायों से ई एम एस 14001:2014 के लिए पहले ही प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुकी हैं। शेष 2 निर्माणियां भी संगत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मानकों को पूरा करने पर संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई कर रही हैं।

## सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम (डी पी एस यू)

### हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)

7.18 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम है। लड़ाकू विमानों, प्रशिक्षक विमान और हेलिकाप्टरों जैसे उत्पादों के साथ इसने विमानन के क्षेत्र में अपने आप को भारतीय रक्षा सेनाओं के लिए व्यापक समाधान प्रदाता के रूप में स्थापित किया है। एच ए एल की लगभग 90% बिक्री भारतीय रक्षा सेनाओं के लिए होती है। एच ए एल के पूरे देश में स्थित 19 उत्पादन डिवीजन, 10

सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए ओ एफ बी ने कई चल रही स्वीकृत परियोजनाओं में क्षमता बढ़ाने की कार्रवाई की है। चल रही इन परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत 4571 करोड़ रु० है।

अनुसंधान एवं विकास केंद्र और 01 सुविधा प्रबंधन डिवीजन है। प्रमुख वायुयानों/हेलिकॉप्टरों की वर्तमान उत्पादन रेंज निम्नवत् हैं:- एस यू-30 एमकेआई बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान, हॉक – उच्च जेट प्रशिक्षक, हल्के लड़ाकू विमान (एल सी ए), मध्यवर्ती जेट

प्रशिक्षक (आई जे टी), डोर्नियर 228 – हल्के परिवहन वायुयान, ध्रुव (उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर), चेतक, चीता और चीतल हेलीकॉप्टर। कंपनी ने वर्ष 2013-14 में 15180 करोड़ रुपए का कारोबार किया।

7.19 वर्ष 2013-14 के दौरान एच ए एल की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :-

- (i) स्वदेश में ही डिजाइन एवं विकसित प्रमुख लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू विमान (एल सी ए) को 20 दिसंबर, 2013 को आरंभिक प्रचालन स्वीकृति मिल जाने से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है और आई ए एफ स्कवॉड्रन्स में शामिल किए जाने के चरण तक पहुंच गया है।
- (ii) भारतीय नौसेना ने एच ए एल द्वारा पूर्ण रूप से भारत में ही निर्मित हॉक उच्च जेट प्रशिक्षक को आई एन एस डेगा, विशाखापट्टनम में 6 नवंबर, 2013 को शामिल किया।
- (iii) मंगलग्रह आर्बिटर मिशन अंतरिक्ष यान 5 नवंबर, 2013 को आई एस आर ओ द्वारा छोड़ा गया था। एच ए एल ने पोलर सेटालाइट लांच व्हीकल (पी एस एल वी-सी25) के लिए सात प्रकार की रिवेटेड स्ट्रक्चरल असेम्बलीज तथा चार प्रकार के वेल्डेड प्रोपलेंट टैंकेंज की आपूर्ति करके इस

मिशन में योगदान दिया है। कंपनी ने आई एस आर ओ को बेयर सेटालाइट स्ट्रक्चर एवं डेक पैनल की भी सुपुर्दगी की है।

(iv) एच ए एल को सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में उत्कृष्टता एवं विशेष योगदान के लिए प्रतिष्ठित 'स्कोप' पुरस्कार से नवाजा गया है। एच ए एल, हैदराबाद को वर्ष 2011-12 के लिए रक्षा मंत्री का उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिल चुका है।

**7.20 भावी चुनौतियां:** एच ए एल रक्षा सेनाओं की भावी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं और भारतीय वायु सेना एवं अन्य रक्षा सेनाएं द्वारा नियोजित मध्यम बहु-भूमिका वाला लड़ाकू विमान (एम एम आर सी ए), बहु भूमिका वाला परिवहन विमान (एम टी ए), पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान (एफ जी एफ ए), भारतीय बहु-भूमिका वाले हेलीकॉप्टर (आई एम आर एच) और नौसेना बहु-भूमिका वाले हेलिकॉप्टर (एन एम आर एच) आदि जैसे अर्जनों में शामिल हो रहा है। एच ए एल के समक्ष प्रमुख चुनौतियों में से अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों को सशक्त बनाना भी एक चुनौती है, जिसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) एच ए एल ने अपने अनुसंधान एवं विकास के आधार को मजबूत बनाने के लिए, अपने सामान्य कार्यकलापों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए एक समग्र निधि बनाने का निश्चय किया है। देश में ही एरो-इंजन विकसित करने के लिए संयुक्त रूप से प्रारंभ किए गए प्रयास

**एच ए एल, वर्ष 2030 तक मानक श्रम घंटों के संदर्भ में अपने 50% तक के कार्य भार के बहिः स्रोतन (आउटसोर्सिंग) द्वारा एक सिस्टम इंटीग्रेटर के मुख्य विनिर्माता के स्थान पर सिस्टम इंटीग्रेटर की भूमिका में क्रमिक रूप से जाना चाहता है।**

में एच ए एल, डी आर डी ओ एवं बी एच ई एल के साथ मिलकर काम कर रहा है।

- (ii) नवोन्नत मैन्ड चेंबर वेल्डिंग (एम सी डब्ल्यू) शॉप का एच ए एल के उड़ीसा स्थित कोरापुट (सूनाबेड़ा) सुविधा केंद्र में 9 मई, 2013 को उदघाटन किया गया था। भारत एवं रूस ही ऐसे दो देश हैं जहां पर इस प्रकार की सुविधा है।
- (iii) पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान (एफ जी एफ ए) का प्रारंभिक डिजाइन चरण पूरा कर लिया गया है।
- (iv) बहु-भूमिका वाले परिवहन विमान (एम टी ए) का प्रारंभिक डिजाइन चरण पूरा कर लिया गया है और सभी रिपोर्टों (वित्त संबंधी पुस्तक को छोड़कर) को ग्राहक की स्वीकृति के लिए यू ए सी-टी ए में द्विभाषी रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- (v) हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एल सी एच) के समुद्री परीक्षण पूरे हो चुके हैं।
- (vi) वर्ष 2013-14 के दौरान 189 पेटेंट आवेदन प्राप्त हुए।

**7.21 एच ए एल, वर्ष 2030 तक मानक श्रम घंटों के संदर्भ में अपने 50% तक के कार्य भार के बहिः स्रोतन (आउटसोर्सिंग) द्वारा एक सिस्टम इंटीग्रेटर के मुख्य विनिर्माता के स्थान पर सिस्टम इंटीग्रेटर की भूमिका में क्रमिक रूप से जाना चाहता है।**

एच ए एल ने वर्ष 2013-14 के दौरान देश में 15 विक्रेता विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है। एच ए एल ने 5 लाख रुपए से अधिक की सभी निविदाओं के लिए ई-अधिप्राप्ति प्रणाली लागू कर दी है।

7.22 एच ए एल ने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एल सी एच), हल्के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (एल यू एच) उन्नत जगुआर डारिन-III और मिराज 2000 विमान का डिजाइन एवं विकास कार्य किया है। पहले आपूर्ति किए गए चेतक, चीता, चीतल एवं ए एल एच के साथ-साथ एल सी एच एवं एल यू एच के डिजाइन एवं विकास से एच ए एल भारतीय रक्षा सेनाओं के हल्के श्रेणी के हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में संपूर्ण स्वदेशी प्रदाता बन जाएगा। एच ए एल ने अब तक इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास से 15 प्रकार के और लाइसेंस के अधीन 14 प्रकार के विमानों का उत्पादन किया है।

7.23 **पर्यावरण संरक्षण** : पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के सभी प्रतिमानकों का कुशलतापूर्वक पालन किया जा रहा है। औद्योगिक बहिः-स्त्रावों का उपचार करने के लिए बहिःस्त्राव उपचार संयंत्रों (ईटीपी) का प्रयोग किया जा रहा है। एचएएल बेंगलूर के सुविधा प्रबंधन प्रभागों द्वारा केंद्रीय जांच गृह (सीटीएच) क्षेत्र में 500 किग्रा/दिन और 1000 किग्रा/दिन की क्षमता वाले दो बायो-गैस संयंत्र लगाए गए हैं। कंपनी प्रति वर्ष निर्माणी में एवं इसके आसपास वृक्षारोपण कर रही है और ऊर्जा लेखा परीक्षा के अनुवर्तन में ऊर्जा संरक्षण के कई उपायों को कार्यान्वित किया है जिसके परिणास्वरूप वर्ष 2013-14 के दौरान लगभग 10 लाख यूनिट ऊर्जा की बचत हुई है। नासिक यूनिट की छत पर 25 किलोवाट का एक सौर पॉवर संयंत्र चालू किया गया है और वर्ष 2014-15 के दौरान बेंगलूर में 100 किलोवाट का संयंत्र लगाने की योजना है।

### **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)**

7.24 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी ई एल) एक नवरत्न कंपनी है और इसकी स्थापना

1964 में रक्षा मंत्रालय के अधीन की गई थी। पूरे देश में फैली हुई 9 सामरिक व्यापार इकाइयां (एसबीयू) हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी का कारोबार 6180 करोड़ रुपए रहा है। यह कंपनी रडारों एवं हथियार प्रणालियों, सोनार, संचार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के क्षेत्र में बुनियादी क्षमताएं रखती है। वर्ष 2013-14 के दौरान, इसकी कुल बिक्री का 82 प्रतिशत भाग रक्षा क्षेत्र की आपूर्ति से प्राप्त हुआ है। गैर-रक्षा क्षेत्र में, बी ई एल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, टेबलेट पी सी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सोलार सैल और सेमीकंडक्टर डिवाइस का निर्माण करती है।

7.25 "गुणवत्ता नियंत्रण वर्ष" 2013-14 के दौरान, भारतीय गुणवत्ता सर्कल फोरम (क्यूसीएफआई) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में बी ई एल को छह सिगमा परियोजनाओं के लिए 12 स्वर्ण पदक मिले हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान, बी ई एल ने परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) के दोनों पैरामीटरों अर्थात् थल सेना के लिए यूएलएसबी एमके 2, पैसिव नाइट विजन डिवाइस (पीएनवीडी) और रडारों एवं अग्नि नियंत्रण प्रणालियों की समयबद्ध सुपुर्दगी देने में शतप्रतिशत सफलता हासिल की है।

7.26 **भावी चुनौतियां**: सामरिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारतीय रक्षा बाजार के परिदृश्य में तीव्र बदलाव हो रहा है। रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के निजी भागीदारी के लिए खुल जाने से, प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ गई है। इसके अलावा, ग्राहक की अपेक्षाएं भी मात्र उत्पादों तक सीमित न रहकर सिस्टम्स/मोबाइल प्लेटफार्मों तक पहुंच गई हैं। इसके कारण

सक्रिय अनुसंधान एवं विकास रणनीति के जरिए निरंतर वृद्धि बनाए रखने और रक्षा बाजार शेयर अपने पास रखने के संबंध में बीईएल के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। बी ई एल सुव्यवस्थित अनुसंधान एवं विकास संरचना युक्त एक प्रौद्योगिकी चालित कंपनी है जो अपने वार्षिक कारोबार का लगभग 6 से 8 प्रतिशत भाग अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करती है। रक्षा सेनाओं के लिए अपने उत्पादों या संयुक्त रूप से विकसित उत्पादों के लिए विभिन्न स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास (डीआरडीओ) प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा आईआईटी, आईआईएससी आदि जैसी ख्यातिप्राप्त अकादमिक संस्थाओं के साथ कंपनी का संबंध बहुत पुराना है। बीईएल प्रति वर्ष औसतन, लगभग 10 नए उत्पाद जारी कर रहा है। डिफेंस न्यूज, यूएसए द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बीईएल, रक्षा राजस्व में विश्व की 100 सर्वोच्च कंपनियों में से 69वें स्थान पर है। बहिःस्रोतन कार्यों में सुधार लाने के लिए कंपनी अधिप्राप्ति (उत्पादन एवं गैर-उत्पादन मर्दे), उप-संविदा तथा सेवाओं के लिए सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा शासित है। इनका समय-समय पर सरकारी दिशा-निर्देशों के साथ अद्यतन भी किया जाता है। बहिः स्रोतन को सुकर बनाने के लिए कंपनी ने अपनी सभी इकाइयों/एसबीयू में ई-अधिप्राप्ति का कार्यान्वयन एसएपी के एक हिस्से के रूप में किया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कुल बहिःस्रोतन 2368 करोड़ रूपए था।

7.27 बीईएल के उत्पाद बास्केट की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि इसके कारोबार का लगभग 85 प्रतिशत भाग स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों

से आता है। कंपनी ने प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य एवं क्षमता रूपरेखा (टीपीसीआर) के अनुरूप स्वदेशीकरण के लिए एक व्यापक पंचवर्षीय योजना तैयार की है।

7.28 **आधुनिकीकरण** : बीईएल उन्नत रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों के विनिर्माण में लगा हुआ है जहां न केवल उत्पादों की प्रौद्योगिकी बल्कि प्रोसेस भी तीव्रता से बदलती है। आधुनिकीकरण के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में आरएफ/एमडब्ल्यू सुपर संघटकों की सुविधा में विस्तार करना ,टी90 टैंकों के लिए स्टेबिलाइजर एवं ऑटोमेटिक लोडिंग गियर के लिए परीक्षण सुविधा, नियर फील्ड एंटीना विकास परीक्षण रेंज सुविधा इत्यादि शामिल हैं । वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए आधुनिकीकरण व्यय 258 करोड़ रूपए था।

7.29 बीईएल, गुणवत्ता विक्रेताओं के उपयुक्त विकास के जरिए, अपने उत्पादन आधार में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, बीईएल ने अपने विक्रेता आधार में पिछले वर्ष की तुलना में 6.5 प्रतिशत वृद्धि की है। कंपनी के पास एक अनुमोदित विक्रेता निर्देशिका (एवीडी) है एवं इसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है तथा कंपनी ने उत्पादों का बहिःस्रोतन एवं संयुक्त विकास, नामित उद्योग संवर्धन अधिकारियों के जरिए विक्रेताओं की मदद करना, वार्षिक विक्रेता बैठक, एमएसएमई से अधिप्राप्ति और ई-अधिप्राप्ति के कार्यान्वयन पर जोर देना इत्यादि जैसी कई पहलें की हैं।

7.30 **पर्यावरण संरक्षण** : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी प्रतिमानकों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। बीईएल के सभी प्रभाग आईएसओ-9001-2000



क्यूएमएस प्रमाणीकरण प्राप्त हैं। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष कंपनी द्वारा निर्माणी परिसर में और इसके आसपास वृक्षारोपण किया जाता है।

## भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल)

7.31 भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल), जोकि एक लघु रत्न श्रेणी-1 कंपनी है को, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1970 में निगमित किया गया था। टैंकरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र के विनिर्माण से शुरुआत करके बीडीएल नई पीढ़ी की एटीजीएम, सतह से हवा में मार करने वाली शस्त्र प्रणालियों, सामरिक महत्व के हथियारों, लांचरों, अंतर्जलीय हथियारों, डिफेंस और परीक्षण उपस्करों के विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। बीडीएल ने 3000 करोड़ रुपए मूल्य की इनवार मिसाइलों की सुपुर्दगी के लिए एक समझौते पर 19 अगस्त, 2013 को हस्ताक्षर किए हैं। बीडीएल की वर्तमान आर्डर बुकिंग की स्थिति लगभग 19,000 करोड़ रुपए है।

7.32 बीडीएल में उत्पादों के उन्नयन और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए संबंधित परीक्षण उपस्करों के विकास के लिए इन-हाउस डिजाइन एवं इंजीनियरी (डी एंड ई) प्रभाग है। संबंधित व्यापार क्षेत्रों में हो रही प्रौद्योगिकीय प्रगति से उत्पन्न होने वाली आगामी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होने के लिए बीडीएल ने अपने यहां एक संरचनागत आर एवं डी केंद्र स्थापित करने के लिए पहल की है।

7.33 बीडीएल ने अपने यहां विनिर्मित होने वाली एटीजीएम के स्वदेशीकरण के लिए कदम उठाए

हैं। कोनकर्स-एम, इनवार एटीजीएम और मिलान-2 टी जैसे उत्पादों का क्रमशः 90%, 65% एवं 71% स्वदेशीकरण हो चुका है। वर्ष 2013-14 के दौरान बीडीएल के विक्रेता आधार में पिछले वर्ष की तुलना में 12.4% की वृद्धि हुई है।

7.34 **आधुनिकीकरण** : आकाश मिसाइल के लिए नया असेंबली भवन स्थापित करना बीडीएल की प्रमुख आधुनिकीकरण योजना है। वर्ष 2013-14 के दौरान बीडीएल में आधुनिकीकरण पर 78.44 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की जाने वाली कुछ प्रौद्योगिकियां हैं :- मोटरों की रोबोटिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग उत्पादन लाइन में जॉब्स की ऑटोमेटिक लोडिंग एवं प्रोग्रेशन, थर्मल शॉक कैपेबिलिटी सहित मिसाइलों/उप प्रणालियों की हॉट एवं कोल्ड कंडीशनिंग का यूनिकीकरण/ऑटोमेशन इत्यादि।

## बीईएमएल लिमिटेड (बीईएमएल)

7.35 बीईएमएल, वर्ष 1964 में स्थापित, एक लघु रत्न कंपनी है, जो एनएसई एवं बीएसई की सूची में दर्ज है। बेंगलूर, मैसूर, कोलार गोल्ड फील्ड एवं पाल्लकाड़ में कंपनी के चार विनिर्माण परिसर हैं। इनमें 9 उत्पादन यूनिटें हैं जो खनन, निर्माण उपस्कर, रक्षा एवं एरोस्पेस उत्पादों तथा रेल एवं मेट्रो उत्पादों के डिजाइन, विनिर्माण, विपणन और बिक्री पश्चात सेल संबंधी कार्यों में लगी हुई हैं।

7.36 बीईएमएल ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 3254 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार एशिया, अफ्रीका एवं लेटिन अमेरिका के 58 से अधिक देशों में फैला हुआ है। वर्ष 2013-14 के दौरान 81 करोड़ रुपए का

निर्यात किया गया। बीईएमएल का रक्षा कारोबार मुख्य रूप से सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के अनुसार हाई मोबिलिटी वाहनों (एचएमवी) तथा बख्तरबंद रिकवरी वाहनों (एआरवी) का उत्पादन एवं आपूर्ति करना है।

7.37 नए एवं नवप्रवर्तनकारी उत्पादों का विकास करके तथा सर्वोत्तम वैश्विक प्रणालियों के साथ गठबंधन करके खनन एवं निर्माण क्षेत्र की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। घरेलू रेल एवं मेट्रो क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बीईएमएल अपनी उत्पादन क्षमता और अनुसंधान एवं विकास क्षमता में वृद्धि कर रहा है। स्वदेशीकरण और इन-हाउस आर एवं डी प्रयासों की सहायता से बीईएमएल, आयात पर निर्भर एचएमवी और एआरवी की आवश्यकता को पूरा करने पर काम कर रहा है।

7.38 **अनुसंधान एवं विकास पहल** : अनुसंधान एवं विकास के मुख्य कार्यकलापों में नए उत्पादों और डोजरों, डंपरों भूमि खोदने वाली मशीनों, लोडरों, ग्रेडरों तथा अन्य रक्षा एवं रेल उत्पादों के डिजाइन एवं विकास संबंधी कार्य शामिल हैं। इसमें विद्यमान उत्पादों के उन्नयन पर निरंतर काम करते हुए प्रौद्योगिकी आमेहन एवं स्वदेशीकरण भी शामिल हैं। रक्षा उपस्करों का अनुसंधान एवं विकास कार्य केजीएफ एवं बेंगलूर काम्प्लेक्स में किया गया है। कंपनी अपने कारोबार का लगभग 3 प्रतिशत भाग अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करती है जिसके परिणामस्वरूप नए उत्पादों का विकास हुआ है। विगत 5 वर्षों के दौरान, नए/उन्नतशील उत्पादों का कुल कारोबार में औसतन 25 प्रतिशत से भी अधिक योगदान रहा है। वैश्विक मानकों के अनुसार ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बदलती

प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों के अनुसार एक त्रिवर्षीय आर एवं डी योजना तैयार की गई है जिसमें तीनों वर्टिकल्स को शामिल किया गया है।

7.39 **स्वदेशीकरण** : बीईएमएल में खनन एवं निर्माण उत्पादों तथा रेल मेट्रो उत्पादों के संबंध में स्वदेशीकरण का स्तर 90 प्रतिशत से भी अधिक है। डीएमआरसी आरएस-6 एवं आरएस-8 (मेट्रो परियोजनाएं) के संबंध में मेट्रो कार के सभी इनपुट्स बीईएमएल के अपने हैं और इनमें सहयोगकर्ता द्वारा कोई भी आपूर्तियां नहीं की गई हैं। पीएमएस ब्रिज, एटीटी, विमान हथियार लोडर, 50टी ट्रेलर इत्यादि जैसे रक्षा उत्पादों के संबंध में स्वदेशीकरण की मात्रा शत-प्रतिशत है तथा हाई मोबिलिटी वाहन की मात्रा 75 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में और अधिक स्वदेशीकरण के लिए प्रयास जारी हैं।

7.40 बीईएमएल निरंतर रूप से अपनी उत्पादन सुविधाओं का आधुनिकीकरण अद्यतन प्रौद्योगिकी के साथ कर रहा है ताकि गुणवत्ता युक्त उत्पादों को निर्धारित समय के अंदर सुपुर्द किया जा सके। आधुनिकीकरण के इन कार्यक्रमों से प्रौद्योगिकी के उन्नयन, गुणवत्ता, लागत में कमी, प्रक्रिया में सुधार से रिवर्क में कमी, पर्यावरण एवं सुरक्षा के प्रतिमानकों के अनुपालन से, विनिर्माण क्षमता में विस्तार तथा निरंतर उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए अवरोध समाप्त करके उत्पादकता में बढ़ोतरी सुनिश्चित होती है।

7.41 भारतीय रेल द्वारा उपनगरीय कम्प्यूटिंग के लिए देश की प्रथम स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (एसएसईएमयू) के डिजाइन एवं विकास के लिए बीईएमएल को रक्षा मंत्री का 'डिजाइन प्रयास' पुरस्कार प्रदान किया गया है।

## मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)

7.42 मिधानि की स्थापना 1973 में रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थापना की गई थी ताकि विदेशी सहयोगियों से तकनीकी जानकारी के साथ जटिल क्षेत्रों के लिए विभिन्न उत्कृष्ट मिश्र धातुओं, टाइटेनियम मिश्र धातुओं, विशेष प्रयोजन वाले इस्पात आदि के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। तत्पश्चात, मिधानि ने रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों के राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों के लिए विभिन्न आकारों, मापों में उच्च कार्य निष्पादन मिश्र धातुओं की 105 से भी अधिक श्रेणियों का विकास, विनिर्माण किया व उनकी आपूर्ति की। मिधानि को नवंबर, 2008 में 'लघु रत्न श्रेणी-1' के दर्जे से नवाजा गया।

7.43 मिधानि ने गत वर्ष के 558.59 करोड़ रुपए के बिक्री कारोबार की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान 563.63 करोड़ रुपए का बिक्री कारोबार किया जो आज तक का सबसे अधिक है। गत वर्ष के दौरान 537.37 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी ने 555.04 करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किया। मिधानि ने एमआई-17 हेलीकॉप्टरों की आर्मरिंग के लिए 2 सैट कंपोजिट आर्मरपैनलों (सेरामिक-टाइटेनियम बाण्डेड एनकैप्सुलेटेड पैनल) का सफलतापूर्वक विनिर्माण किया तथा इन्हें वायु सेना 3 बीआरडी, चंडीगढ़ को सुपुर्द किया। प्रत्येक



सैट में विभिन्न आकार एवं साइज के 28 पैनल हैं। इन पैनलों को विनिर्मित करने की प्रौद्योगिकी डीएमआरएल, हैदराबाद द्वारा विकसित की गई थी।



7.44 अनुसंधान एवं विकास पहल : वर्ष 2013-14 में किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार नए श्रेणी के सामरिक अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए कई पहलें की गई हैं। नई श्रेणियों के विकास संबंधी कार्यकलाप प्रौसैसिंग एवं परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। वर्ष 2013-14 के लिए 6.5 करोड़ रुपए के व्यय लक्ष्य की तुलना में 9.90 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। क्षमता में वृद्धि करने के लिए, चरण वार आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत उच्च क्षमता वाले जटिल उपस्करों को लगाया जा रहा है। वर्ष 2013-14 के दौरान आधुनिकीकरण के लिए 60.00 करोड़ रुपए के पूंजी व्यय (सीएपीईएक्स) लक्ष्य की तुलना में 128.38 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

7.45 मिधानि में स्वदेशीकरण का उच्चतर स्तर प्राप्त करने पर जोर दिया जा रहा है। अपने उत्पादों की प्रोसेसिंग करते समय, शुद्ध निकेल, क्रोमियम, मालिबडेनम, कोबाल्ट आदि जैसी आयातित कच्ची सामग्री प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि ये सामग्रियां भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। इस वर्ष के दौरान, उत्पादन मूल्य में स्वदेशी मात्रा 388.53 करोड़ थी जो लगभग 70 प्रतिशत है। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों का पालन करने तथा अपने कारपोरेट मिशन को पूरा करने की दृष्टि से, कंपनी लगभग तीन वर्ष की समय सीमा में अपनी वर्तमान 4000 मीट्रिक

टन/वर्ष की क्षमता को 7000-8000 मीट्रिक टन/वर्ष करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।

### **माझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल)**

7.46 माझगांव डॉक लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रम शिपयार्डों में अग्रणी शिपयार्ड है, जो भारतीय नौसेना के लिए युद्धकपोतों एवं पनडुब्बियों के निर्माण में लगा हुआ है। अग्रिम श्रेणी के युद्धकपोतों और पनडुब्बियों के निर्माण की जटिलताओं की चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से शिपयार्ड में सभी क्षमताएं एवं सामर्थ्य हैं। इस कंपनी को 14 मई, 1960 को सार्वजनिक क्षेत्र के एक रक्षा उपक्रम के रूप में निगमित किया गया था। वर्ष 2012-13 में 2290.64 करोड़ रुपए के उत्पादन मूल्य की तुलना में वर्ष 2013-14 का उत्पादन मूल्य 2790 करोड़ रुपए है।

7.47 अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में बने रहने के लिए, एमडीएल, कुछ उपस्करों एवं मर्दों का मानकीकरण करने, एक ऐसी अधिप्राप्ति रणनीति तैयार करना जो पोतों एवं पनडुब्बियों की निर्माण अवधि के लिए उपयुक्त हो, उच्च ब्लॉक लेवल, निर्माण अवधि कम करने के लिए प्री-आउट फिटिंग्स, उत्पादकता में सुधार लाने के लिए ऑटोमेशन के स्तर में तात्कालिक व्यवस्था करने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने जैसे उपाय कर रहा है। एमडीएल एक पंचवर्षीय अनुसंधान एवं विकास योजना तैयार कर रहा है जिसमें यार्ड द्वारा इस अवधि के दौरान किए जाने वाले अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को दर्शाया गया है।

**माझगांव डॉक लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रम शिपयार्डों में अग्रणी शिपयार्ड है, जो भारतीय नौसेना के लिए युद्धकपोतों एवं पनडुब्बियों के निर्माण में लगा हुआ है।**

एमडीएल सहभागी अनुसंधान एवं विकास की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आईआईटी, वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान इत्यादि जैसी प्रतिष्ठित अकादमिक संस्थाओं के साथ गठबंधन करना चाहता है।

7.48 शिपयार्ड में निर्मित किए जा रहे पोतों एवं पनडुब्बियों की स्वदेशी मात्रा स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए एमडीएल प्रयासरत है। गत वर्षों में, शिपबोर्ड मशीनरी, उपस्करों एवं सामग्रियों का बड़ी मात्रा में स्वदेशीकरण किया गया है। हाल के वर्षों में, स्टेबिलाइजर्स, स्टीअरिंग गियर, सीवेज उपचार संयंत्र, अलवणीय जल जनरेटर्स, हेलीकॉप्टर लैंडिंग ग्रीड, शाफ्टिंग, स्टेम बॉस जैसे शिपबोर्ड उपस्करों का स्वदेशीकरण किया गया है। जीओएसटी प्रतिशत एनईएस 791 भाग 1 एवं भाग 3 विनिर्देशनों के अनुसार, अब तक आयात की गई इस्पात का भी स्वदेशीकरण किया जा चुका है। जहां तक निर्माणाधीन पी-15 बी विनाशकों का संबंध है, स्वदेशी संघटक की मात्रा 73 प्रतिशत तक रखने की योजना है।

7.49 **आधुनिकीकरण** : सामान की गुणवत्ता में वृद्धि करने और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए पोत निर्माण तथा पनडुब्बी निर्माण संबंधी अवसंरचना में क्रमिक रूप से बढ़ोतरी की गई है। माझगांव आधुनिकीकरण परियोजना (एमएमपी) लगभग पूरी होने वाली है। इस परियोजना के अंतर्गत नई वेट बेसिन एवं 300 टन की हैवी ड्यूटी गोलिएथ क्रेन लगाना शिपयार्ड की दो प्रमुख उपलब्धियां हैं। गोलिएथ क्रेन के साथ मॉड्यूल शॉप के संयोजन से मॉड्यूलर

निर्माण की एकीकृत संकल्पना अपनाने तथा युद्धपोतों एवं पनडुब्बियों की निर्माण अवधि प्रभावी रूप से कम करने में एमडीएल को सहायता मिलेगी।

### **गार्डन रीच शिबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)**

7.50 गार्डन रीच शिबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) सितंबर, 2006 से सार्वजनिक क्षेत्र की एक लघु रत्न श्रेणी-1 कंपनी है जो भारत की बढ़ती समुद्री जरूरतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है तथा एक अग्रणी पोत निर्माण यार्ड के रूप में पहचानी जाती है। इस समय जीआरएसई में, चार पनडुब्बीरोधी युद्धक कारवेट्स (पी 28 वर्ग), आठ लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, अपतटीय गश्ती जलयान और चार वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है। जीआरएसई ने मारीशस को अपतटीय गश्ती जलयान की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित निर्यात आर्डर भी प्राप्त किया है। इस पोत का जलावतरण 2 अगस्त, 2013 को किया गया था तथा सितंबर, 2014 में इसकी सुपुर्दगी की जाएगी। इस वर्ष में भारतीय तटरक्षक को दो अपतटीय गश्ती पोतों (आईपीवी) की सुपुर्दगी की गई थी। जीआरएसई ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 1550.83 करोड़ रुपए का कारोबार (वीओपी) (अनंतिम) किया जो अब तक का सर्वाधिक है।

7.51 **अनुसंधान एवं विकास पहल** : जीआरएसई की अनुसंधान एवं विकास नीति है जो बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित है। 01 अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए स्वदेशी उत्पादन मूल्य की मात्रा गत वर्ष 72.30 प्रतिशत की तुलना में 75.10 प्रतिशत है। पूरी की गई प्रमुख परियोजनाओं में 100 एम के ओपीवी के लिए हल कार्य का विकास

और स्वदेशी रूप से विकसित सिंगल लेन पोर्टेबल स्टील ब्रिज आईआरसी-6 का लोड परीक्षण शामिल है।

7.52 **आधुनिकीकरण** : जीआरएसई की आधुनिकीकरण योजना जिसका लक्ष्य मॉड्यूलर निर्माण संकल्पना सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत संरचना में वृद्धि करना है, को मई, 2013 को पूरा कर लिया गया है। चरण-2 के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत एकीकृत पोत निर्माण सुविधा, जीआरएसई को समर्थ बनाती है कि वह उन नवीनतम माड्यूलर पोत निर्माण प्रौद्योगिकी जिनमें प्री आउट फिटिंग के साथ 200 टन मेगाटनहल-ब्लॉकों को उपयोग में लाया जा सकता है, को उपयोग में लाते हुए पोतों का निर्माण कर सके। इससे पोत निर्माण में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी।



7.53 **वर्ष 2013-14 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित प्रकार से थी:**

- (क) दो जंगी पोत नामतः आईसीजीएस राजवीर और आईसीजीएस राजध्वज की सुपुर्दगी क्रमशः 16, जुलाई, 2013 और 30, अक्टूबर, 2013 को की गई ।
- (ख) यार्ड सं0-2092 और 2093 की, 24, अप्रैल, 2013 को, यार्ड सं0-2094 और 2095 की 30, अगस्त, 2013 को और यार्ड सं0- 2109 की 31, मार्च, 2014 को नौतल आधारशिला (कील लेइंग) रखी गई।



7.54 **पर्यावरण संरक्षण** : वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 के लिए मुख्य यार्ड में बिजली की खपत में 15.43 प्रतिशत की कमी की गई। शिपयार्ड में वन रोपण कार्यकलाप को सघन रूप से अपनाया जा रहा है। फैक्ट्री और इसके चारों ओर ही घनी हरित पट्टी है जिसमें नर्सरी, उद्यान और पौधे भी शामिल हैं। नए कारपोरेट कार्यालय के लिए वर्षा जल संचयन और ग्रीन बिल्डिंग संकल्पना को अपनाया गया है।

### गोवा शिपयार्ड लिमिटेड(जीएसएल)

7.55 वर्ष 1957 में एक छोटे बार्ज मरम्मत और निर्माण यार्ड के रूप में एक छोटी सी शुरुआत से विकास करते हुए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एक ऐसे प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धी शिपयार्ड की हैसियत तक आ पहुँचा है जो भारतीय नौसेना एवं तटरक्षक बल के लिए अपेक्षित उच्च प्रौद्योगिकी वाले अत्याधुनिक पोतों के स्वदेशी अभिकल्पन एवं उनका निर्माण करने में सक्षम है। वर्ष 2013-14 के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) का उत्पादन मूल्य 512.24 करोड़ रुपए है। कलेंडर वर्ष 2013 के दौरान गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने सितंबर, 2013 में भारतीय नौसेना को दूसरा ओपीवी सौंपा (पहले की सुपुर्दगी दिसंबर, 2012 में की गई थी) और तीसरा यान भी सुपुर्द किये जाने के लिए तैयार है। एक ओपीयू की सुपुर्दगी भारतीय तट रक्षक बल को की गई थी। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जुलाई, 2013 की एक मत्स्यन अनुसंधान यान, केन्द्रीय समुद्री मत्स्यन अनुसंधान संस्थान, कोच्ची को भी सौंपा है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को भी 4 शिप बर्थिंग पोन्टूनो की भी सुपुर्दगी की है।

7.56 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा अपने विभिन्न उत्पादों के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप करता है और पोत निर्माण की नई योजनाएं घरेलू (इन-हाउस) अभिकल्पना पर आधारित होती हैं। गोवा

शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पोतों के घरेलू रूप से विकसित डिजाइनों से देश को पोतों के डिजाइनों के आयात से बचाते हुए विदेशी मुद्रा की काफी बचत हुई है। देश की रक्षा आवश्यकताओं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रत्याशित मांग को पूरा करने की दृष्टि से नए प्लेटफार्म्स, ओपीवी, एएसडब्ल्यू, शैलो वाटर क्राफ्ट्स और इंटर सेक्टर क्राफ्ट के लिए (इन हाउस) अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप प्रगति पर हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अपने कारोबार संबंधी कार्यकलापों का विविधीकरण किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा शुरू की गई कुछ परियोजनाएं इस प्रकार से हैं: भारतीय नौसेना के लिए तट आधारित प्रशिक्षण सुविधा, भारतीय नौसेना के लिए जीआरपी सर्वे मोटर नौकाएं, स्टर्न गियर प्रणालियों की अधिष्ठापना और सेवा समर्थन।

7.57 **आधुनिकीकरण**: अपनी पोत निर्माण क्षमता को दोगुना करने के उद्देश्य से और माइन काउंटर मैजर वेसल्स (एमसीएमवी) के निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का आधुनिकीकरण कार्यक्रम 800 करोड़ रुपए के एक अनुमानित परिव्यय से 4 चरणों में निष्पादित किया जा रहा है। इस आधुनिकीकरण परियोजना का चरण 1 और 2 पूरा कर लिया गया है और अगले चरण के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है।

### हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल)

7.58 'सिंधिया शिपयार्ड लिमिटेड' की स्थापना वर्ष 1941 में की गई थी। वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा इसकी दो-तिहाई पूंजी (होल्डिंग्स) का अधिग्रहण किया गया था और इस शिपयार्ड को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के रूप में पुनर्नामित किया गया था। 1961 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, पोत परिवहन मंत्रालय के तहत एक पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व वाला उद्यम बन गया। यह शिपयार्ड जो भारतीय प्रायद्वीप

के पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश भारत में सामरिक रूप से अवस्थित है वह भारतीय सामुद्रिक, रक्षा और पोत निर्माण व पनडुब्बी मरम्मत और अपतट व उपतट संरचनाओं में तेल क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश का एक प्रमुख पोत निर्माण संगठन है। इस यार्ड को फरवरी, 2010 में रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया था।

7.59 पिछले पांच वर्षों के दौरान, एचएसएल ने 19 जलयानों की सुपुर्दगी की है जिसमें अंडमान और निकोबार प्रशासन को 150 यात्री वाले दो जलयान, संघ शासित क्षेत्र लक्षदीप को 700 यात्री वाला एक जलयान, मैसर्स गुडअर्थ मेरीटाइम लिमिटेड को 30,000 टन भार (डीडब्ल्यूटी) वाले ट्रेडर सीरीज के चार और 53,000 टन भार(डीडब्ल्यूटी) वाले डायमंड सीरीज बल्क कैरियर्स के तीन, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट को एक ऑयल रिकवरी एवं प्रदूषण नियंत्रण जलयान तथा दो 50 टन बोलार्ड पुल टग्स, भारतीय नौसेना को तीन 50 टन वाले बोलार्ड पुल टग्स, न्यू मेंगलोर पोर्ट ट्रस्ट को 32 टन बोलार्ड पुल टग्स और भारतीय तटरक्षक बल को एक गश्ती जलयान की सुपुर्दगी शामिल है। इस यार्ड में 8 हाईटेक ऑयल रिगों, (ओएनजीसी के लिए पांच, पुर्तगाल के



सुविधाओं का एक विहंगम दृश्य

लिए एक, माल्टा के लिए एक और अबन ऑफशोर लिमिटेड के लिए एक) और भारतीय नौसेना के लिए एक सबमैरीन की मरम्मत की गई।

7.60 **अनुसंधान एवं विकास पहल:** सर्वेक्षण जलयानों आदि के लिए इस यार्ड में स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल डिजाइन द्वारा कनसेप्ट डिजाइन के तहत 14000 डीडब्ल्यूटी से लेकर 27000 डीडब्ल्यूटी के टग्स, कारगो, जलयानों के लिए इन-हाउस डिजाइनों का विकास किया है। हाल ही में, डिजाइन विभाग को अविवा को 40 लाइसेंसों और ऑटोकैड-14 के 35 लाइसेंसों से पुनर्सज्जित किया गया है। विचाराधीन अवधि के दौरान इन अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर के लिए प्रशिक्षण का कार्य संतोषजनक ढंग से प्रगति पर है और इन लाइसेंसों को उपयोग में लाया जा रहा है।

7.61 **आधुनिकीकरण:** दिसम्बर, 2011 में रक्षा मंत्रालय ने एलपीडी परियोजना के तहत मशीनरी और आधारभूत संरचनाओं के पुर्नसज्जीकरण और प्रतिस्थापन (आरआरएमआई) के लिए 457.36 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आज की तिथि तक आरआरएमआई परियोजना से संबंधित कार्यकलापों की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा निम्नलिखित प्रकार से है:-

- (i) दिए गए आदेश - 40.66 करोड़ रुपए
- (ii) निविदा प्रक्रिया के तहत - 106.86 करोड़ रुपए

7.62 **वर्ष 2013-14 के दौरान प्रमुख उपलब्धियों और आवाडों का ब्यौरा:**

- (i) भारतीय तटरक्षक बल के लिए आईसीजीएस रानी आवंती बाई: पांच उपतटीय गश्ती पोतों (आईपीवी) की श्रृंखला के दूसरे पोत आईसीजीएस, रानी

आवंती बाई को 8 मई, 2013 को भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा गया। इस पोत को 9 मई, 2013 में कमीशन किया गया।



मैसर्स जीएमएल के लिए एमबी गुड डे

- (ii) मैसर्स गुडअर्थ मैरीटाइम लिमिटेड के लिए एमवी गुड डे: 53000 टन भार(डीडब्ल्यूटी) वाले कैरियर एमबी गुड डे, वीसी11139 जो 5 वाहक पोतों (कैरियर) की श्रृंखला में चौथा है, को 29 जुलाई, 2013 को मैसर्स वुड अर्थ मैरीटाइम लिमिटेड, चैन्नई को सौंपा गया था।
- (iii) 50 टन बोलाड पुल टग्स : भारतीय नौसेना के लिए तीन में से दो 50 टन वाले बोलाड पुल टग्स, वीसी 11163 (धीरज) और वीसी 11164 (साहस) की 24 दिसम्बर, 2013 को सुपुर्दगी की गई थी। तीसरे टग, वीसी 11162 (हिम्मत)

23 मार्च, 2013 को एचएसएल से खाना हुआ और 30, मार्च, 2014 को करवार पहुंचा।

- (iv) एचएसएल को 31, जनवरी, 2014 को कर्मचारी कल्याण और महिला सशक्तिकरण प्रयासों के लिए न्यू इंक लिजेंड, पीएसयू, शाइनिंग अवार्ड 2013 से नवाजा गया।



भारतीय नौसेना के लिए 50 टी बीपी टग्स

## **गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए)**

7.63 गुणता आश्वासन महानिदेशालय एक ऐसा गुणता आश्वासन संगठन है जो रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। गुणता आश्वासन महानिदेशालय थल सेना, नौसेना के लिए (नौसेना आयुधों के अलावा) आयातित एवं स्वदेशी दोनों प्रकार के सभी रक्षा भंडारों और उपस्करों और वायुसेना के लिए निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और आयुध निर्माणियों से अधिप्राप्त सामान्य उपभोक्ता मदों के लिए सेकेंड पार्टी गुणता आश्वासन के लिए उत्तरदायी है। अतः देश की रक्षा तैयारियों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

7.64 **संगठनात्मक ढांचा और कार्य:** गुणता आश्वासन महानिदेशालय संगठन ग्यारह तकनीकी निदेशालयों से संरचित है जिनमें से प्रत्येक निदेशालय एक भिन्न प्रकार के उपकरण श्रेणी के लिए जिम्मेवार है। कार्यात्मक उद्देश्यों के लिए तकनीकी निदेशालयों को दो स्तरों में संरचित किया गया है जिनमें उनके नियंत्रणालय और फील्ड स्थापनाएं शामिल हैं। इसके अलावा हथियारों और गोलाबारूदों की जांच करने के लिए जांच स्थापनाएं हैं।

### **7.65 उपलब्धियां :**

- (i) **स्टोर्स की गुणता आश्वासन:** वर्ष 2013-14 के दौरान गुणवत्ता सुनिश्चित किए गए स्टोर्स का मूल्य 20743 करोड़ रुपए है।
- (ii) **एनएबीएल प्रत्यायन:** गुणता आश्वासन महानिदेशालय की 34 अभिज्ञात प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं को एनएबीएल प्रत्यायन प्रदान किया गया है।

(iii) **आधुनिकीकरण:** अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले जांच उपकरणों की अधिप्राप्ति की गई है और उन्हें प्रूफ स्थापनाओं और जांच स्थापनाओं में कार्य पर लगाया गया है।

(iv) **प्रशिक्षण पहल:** गुणता आश्वासन रक्षा संस्थान (डीआईक्यूए) , गुणता आश्वासन महानिदेशालय के अधिकारियों और अन्य संगठनों के अधिकारियों को गुणता आश्वासन, प्रबंधन/ मानव संसाधन विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देता है। रक्षा उत्पादन विभाग (रक्षा मंत्रालय) में मनाए जा रहे गुणवत्ता वर्ष 2013-14 के दौरान गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के तीन अधिकारियों को स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए क्रेन फील्ड विश्वविद्यालय, यू के में भेजा गया था।

## **वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीएक्यूए)**

7.66 वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन एक नियामक प्राधिकरण है, जो हवाई शस्त्रास्त्र और मानवरहित विमान (यूएवी) सहित सैन्य विमानों के सहायक हिस्से पुर्जों और अन्य वैमानिकी साजो-सामान को उनके डिजाइन/ विकास/उत्पादन/मरम्मत और ओवरहाल/उन्नयन के दौरान गुणता आश्वासन और अंतिम स्वीकृति देता है। डीजीएक्यूए रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालयों, मुख्य संविदाकारों को रक्षा एयरो सामान के अर्जन और घरेलू विनिर्माण के विभिन्न चरणों में तकनीकी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ऐसे उत्पादों के आपूर्तिकर्ताओं के परिसर में यह सुनिश्चित करता है



कि उत्पाद और सेवाएं निर्धारित विनिर्देशितियों/मानकों के अनुरूप हों और गुणता प्रबंधन प्रणाली प्रभावी हो और इस प्रकार सैन्य विमानों/एयरबोर्न प्रणालियों की सुरक्षा में वृद्धि करता है। डीजीएक्यूए देश के विभिन्न भागों में अवस्थित 34 फील्ड स्थापनाओं/डिटैचमेंट स के एक नेटवर्क के माध्यम से अपने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय से कार्य करता है।

7.67 डीजीएक्यूए, प्रेक्षपास्त्र प्रणालियां गुणता आश्वासन एजेंसी(एमएसक्यूएए) और सामरिक प्रणालियां गुणता आश्वासन समूह(एसएसक्यूएजी) के लिए एक नोडल एजेंसी भी है। ये त्रिसेवा (डीजीएक्यूए, डीजीक्यूए और डीजीएनएआई) संगठन हैं, जो स्वदेशी प्रेक्षपास्त्रों के डिजाइन, विकास एवं उत्पादन के दौरान गुणता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं।

7.68 गुणता आश्वासन स्टोरों की उपलब्धियां: वर्तमान वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा गुणता कवरेज के साथ दिए गए स्टोरों की कीमत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
करोड़ रुपए में	14296	14898	14022	21803

**7.69 वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय के अंतर्गत आश्वासन कवरेज के तहत प्रमुख परियोजनाएं:**

- (i) एसयू-30 (एमकेआई) और एडवांस्ड जेट ट्रेनर (एचएडब्ल्यूके): मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) से लाईसेंस के तहत विनिर्माण

- (ii) एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच): विनिर्माण

- (iii) हल्का युद्धक विमान(एलसीएच): विकास

- (iv) हल्का युद्धक विमान(एलसीए): विनिर्माण

- (v) मध्यवर्ती जेट ट्रेनर (आईजेटी), हल्का युद्धक हेलीकॉप्टर (एलसीएच) और हल्का उपयोगी हेलीकॉप्टर(एलयूएच): विकास/विनिर्माण

- (vi) हवाई आयुध स्टोर्स: विनिर्माण

- (vii) घरेलू मिसाइलें: विकास/विनिर्माण

- (viii) एयर बार्न अर्ली वार्निंग रडार नियंत्रण प्रणाली (आईडब्ल्यू&सी): विकास

- (ix) वायु वाहित प्रयोगों के लिए भू-रडार प्रणालियां: विकास/विनिर्माण

- (x) विमान के लिए एरेस्टर बैरियर प्रणालियां : विनिर्माण

- (xi) वायुकर्मियों के लिए उड़ान के दौरान पहने जाने वाले वस्त्र : विकास/विनिर्माण

- (xii) सैनिक विमान में उपयोग के लिए टायर/ट्यूब्स: विकास/विनिर्माण

- (xiii) सैनिक विमान में उपयोग के लिए बैटरीज: विकास/विनिर्माण

7.70 वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा किए गए कुछ उपाय:

- (i) निरीक्षण नोट का कम्प्यूटरीकरण: संतोषप्रद गुणता आश्वासन जांचों के पश्चात स्टोरों की स्वीकृति के लिए वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा अब तक निरीक्षण नोट के मुद्रित फार्मों को प्रयोग में लाया जा रहा था।



इस कार्यकलाप का अब कम्प्यूटरीकरण कर लिया गया है और इस संबंध में विभिन्न फील्ड स्थापनाओं में उचित मार्गनिर्देश परिचालित किए गए हैं।

- (ii) फील्ड स्थापनाओं की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा: वैमानिकी गुणता महानिदेशालय की फील्ड स्थापनाओं में पहली बार वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय में से ही गठित क्रास फंक्शनल टीमों द्वारा कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा की गई है और व्यवसायिक दक्षता में वृद्धि करने के लिए सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाएगा।
- (iii) वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय का आईएसओ 9001 प्रमाणन वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय के आईएसओ-9001 प्रमाणीकरण प्राप्त करने की दिशा की ओर कार्रवाई शुरू की गई है।

### **मानकीकरण निदेशालय(डीओएस)**

7.71 मानकीकरण निदेशालय की स्थापना 1962 में रक्षा सेनाओं के भीतर मदों की तेज वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई थी। तदनुसार मानकीकरण महानिदेशालय का प्राथमिक उद्देश्य तीनों सेनाओं में उपस्करों और संघटकों में उभयनिष्ठा स्थापित करना है ताकि रक्षा सेवाओं की कुल मदसूची को कम करके न्यूनतम किया जा सके। निम्नलिखित द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास है:

- (क) विभिन्न मानकीकरण दस्तावेजों को तैयार करना।
- (ख) रक्षा सामान सूची का संहिताकरण।

**मानकीकरण निदेशालय की स्थापना 1962 में रक्षा सेनाओं के भीतर मदों की तेज वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई थी।**

(ग) प्रविष्टि नियंत्रण।

7.72 निदेशालय द्वारा अनुमोदित पंचवर्षीय रोल ऑन प्लान के अनुसार 305 नए मानक दस्तावेज और 1121 संशोधित दस्तावेज वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए जाने अपेक्षित थे। इन लक्ष्यों के प्रति 31मार्च, 2014 तक 165 नए मानक दस्तावेज और 764 संशोधित दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। इस निदेशालय ने 39,773 मदों को कूटबद्ध (कोडीफाइड) करने का एक लक्ष्य रखा है जिसके प्रति मार्च 31, 2014 तक 22306 मदों को कूटबद्ध कर लिया गया है और इस प्रकार आज की तिथि तक कूटबद्ध की गई मदों की कुल संख्या 5,56,008 हो गई है।

### **योजना और समन्वय निदेशालय**

7.73 रक्षा उत्पादन विभाग के तहत योजना और समन्वय निदेशालय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग, रक्षा उत्पादन विभाग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित कार्यकलापों के लिए एक केंद्रीय बिंदु है। यह विभिन्न देशों जिनके साथ भारत का रक्षा उत्पादन में सहयोग समझौता है, के साथ रक्षा उद्योग सहयोग से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

### **रक्षा प्रदर्शनी संगठन (डी ई ओ)**

7.74 रक्षा प्रदर्शनी संगठन का मुख्य कार्य भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा विकसित और विनिर्मित रक्षोन्मुखी उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में अभिवृद्धि करने के मूल दृष्टि कोण से देश और विदेश में

रक्षा प्रदर्शनियों का आयोजन और समन्वयन करना है। रक्षा प्रदर्शनी संगठन; प्रगति मैदान, नई दिल्ली में रक्षा पंडाल में स्थायी रक्षा प्रदर्शनी लगाए रखता है। इस प्रदर्शनी में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम (डीपीएसयू) आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीएक्यूए) अपने उत्पादों, नवाचारों और सेवाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं।

**7.75 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ);** रक्षा पैवेलियन प्रगति मैदान, नई दिल्ली में हर वर्ष 14 नवम्बर से 27 नवम्बर तक लगने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेले में, रक्षा पैवेलियन को पिछले 27 वर्षों के दौरान 8 स्वर्ण, 4 रजत, 3 कांस्य और एक विशेष प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

**7.76 एरो इंडिया:-** नौवां एरो इंडिया हवाई शो 06 फरवरी से 10 फरवरी, 2013 तक वायुसेना केन्द्र, येलाहंका, बेंगलोर में आयोजित किया गया था। इस एरो शो में 27 देशों से 352 विदेशी भागीदारों और 305 धरेलू प्रदर्शकों सहित कुल 650 प्रदर्शकों ने भाग लिया।

**7.77 डिफेंस एक्स्पोजे इंडिया 2014:** 8वीं रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन 6 फरवरी से 9 फरवरी, 2014 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया जिसमें 624 कंपनियों ने भाग लिया जिसमें से 368 विदेशी कंपनियां थीं।

**7.78 विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन:** भारतीय रक्षा उद्योग की निर्यात संभावना को बढ़ावा देने के दृष्टि कोण से रक्षा प्रदर्शनी संगठन विदेशों में लगने वाले प्रमुख रक्षा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में 'भारतीय पैवेलियन' लगाता है ताकि भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा निर्मित किए जा रहे रक्षा उत्पादों के लिए बाजार को विकसित किया जा सके। इस दौरान भारत ने लेटिन अमेरिका एरो एण्ड डिफेंस एक्जिजिशन (एलएएडी-2013), एमएकेएस-2013, इंटरनेशनल एविएशन एण्ड स्पेस सैलून, डिफेंस एण्ड सिक्युरिटी इक्यूपमेंट इंटरनेशनल एक्जिजिशन ( डीएसईआई-2013), टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केन्द्र, टोक्यो में एरोस्पेस इंडस्ट्री एक्जिजिशन (एएसईटी), 2013 और सियोल इंटरनेशनल एरोस्पेस एण्ड डिफेंस एक्जिजिशन (एडीईएक्स), 2013 में भाग लिया।

### **राष्ट्रीय रक्षा पोत निर्माण अनुसंधान एवं विकास संस्थान(निर्देश)**

**7.80:** राष्ट्रीय रक्षा पोत निर्माण अनुसंधान एवं विकास संस्थान (निर्देश) की स्थापना पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से चैलियम, कोझीकोड, केरल में की गई है। ऐसा विचार किया गया है कि यह संस्थान भविष्य के पोत निर्माण कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख केन्द्र होगा। निर्देश के अभिवृद्धि वाले क्षेत्र होंगे - अनुसंधान और विकास, पोत अभिकल्पन, प्रौद्योगिकी विकास, उद्योग सम्पर्क, प्रशिक्षण और परियोजना प्रबंध। निर्देश में रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम शिपयार्डों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, प्रमुख तकनीकी संगठनों/संस्थाओं आदि की सक्रिय भागीदारी होगी। रक्षा मंत्रालय, भारतीय

नौसेना, तटरक्षक बल के प्रतिनिधियों और सदस्यों के द्वारा कार्यस्थल (साइट) पर 40.52 एकड़ माप की रूप में शिपयार्डों के अध्यक्षों के साथ रक्षा मंत्री निर्देश आधारभूत संरचनाओं के मास्टर प्लान को अनुमोदित के संचालक मंडल के अध्यक्ष हैं। संचालक मंडल किया गया है।

### सारणी सं. 7.1

#### कार्य परिणाम

#### सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम और आयुध निर्माणी बोर्ड का उत्पादन एवं विक्रय मूल्य

(करोड़ रु. में)

पीएस यू का नाम	2011-12		2012-13		2013-14 (अंतिम)	
	उत्पादन मूल्य	विक्रय मूल्य	उत्पादन मूल्य	विक्रय मूल्य	उत्पादन मूल्य	विक्रय मूल्य
एचएएल	12693.19	14204.21	14201.82	14324.00	15296.00	15180.00
बीईएल	5793.58	5703.63	6290.00	6012.00	6140.00	6180.00
बीईएमएल	4077.19	3648.37	3359.70	3289.77	3201.32	3254.81
एमडीएल	2523.69	2262.87	2290.64	2404.69	2709.00	112.00
जीआरएसई	1293.80	546.33	1529.37	464.34	1550.83	1550.83
जीएसएल	676.40	269.70	506.62	844.13	512.24	1095.89
बीडीएल	992.94	959.12	1177.00	1074.71	1793.43	1829.86
मिधानि	496.00	509.01	537.37	558.59	555.04	563.63
एचएसएल	564.04	564.04	483.84	483.84	403.22	403.22
ओएफबी	12390.72	12390.72	11984.00	11984.00	11234.00	11234.00
<b>कुल</b>	<b>41501.55</b>	<b>41058.00</b>	<b>42360.36</b>	<b>41440.07</b>	<b>43395.08</b>	<b>41404.24</b>

### सारणी सं. 7.2

#### कर पश्चात लाभ

(करोड़ रु में)

पीएस यू का नाम	2011-12	2012-13	2013-2014 (अंतिम)
एचएएल	2539.43	2997.00	2735.00
बीईएल	829.90	890.00	853.00
बीईएमएल	57.25	79.87	0.00
एमडीएल	494.31	412.72	332.50
जीआरएसई	108.03	131.54	119.12
जीएसएल	82.80	15.57	-35.63
बीडीएल	234.96	288.40	308.18
मिधानि	68.45	82.52	72.58
एचएसएल	(-) 85.98	(-)55.17	(-)85.00
<b>कुल</b>	<b>4329.15</b>	<b>4842.45</b>	<b>4299.75</b>

## रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन



एल सी ए तेजस के लिए प्रारंभिक संक्रियात्मक स्वीकृति  
डीआरडीओ और भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम क्षण

# डीआरडीओ नवीनतम प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए निरंतर ध्यान केन्द्रित किए हुए है ताकि प्रणालियों को समकालीन रखा जा सके और इनकी तुलना विश्व की बेहतर प्रौद्योगिकियों से की जा सके

## पृष्ठभूमि

8.1 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास अंग है, जिसका गठन भारत की सशस्त्र सेनाओं के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान प्रदान करने के लिए किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी जब भारतीय सेना की तकनीकी विकास स्थापनाओं (टीडीई) एवं तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय (डीटीडीपी) को रक्षा विज्ञान संगठन में मिला दिया गया था। अस्सी के दशक के दौरान डीआरडीओ प्रणाली विकासकर्ता के रूप में उभरा जब इसने भारत के पहले मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) एवं एकीकृत मार्गनिर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी) के डिजायन का काम शुरू किया। नब्बे के दशक में डीआरडीओ ने हल्के लड़ाकू वायुयान (एलसीए) एवं इलैक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति (ईडब्ल्यू) प्रणालियों के विकास की शुरुआत की, जबकि रडार एवं सोनार विकास का कार्य जारी रहा। 2000 के दशक के प्रारंभ में डीआरडीओ ने अगली पीढ़ी की प्रणालियों को लांच किया और इसकी गतिविधियों ने सैनिकों के लिए जीवन सहायता प्रणालियों से लेकर परिष्कृत बेलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम तक वस्तुतः रक्षा

क्षेत्र की प्रत्येक जरूरतों को छुआ है। डीआरडीओ नवीनतम प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए निरंतर ध्यान केन्द्रित किए हुए है ताकि प्रणालियों को समकालीन रखा जा सके और इनकी तुलना विश्व की बेहतर प्रौद्योगिकियों से की जा सके। यह लगभग 7,600 वैज्ञानिकों और 10,000 तकनीकी कार्मिकों की समर्पित जन-शक्ति के सहयोग से प्राप्त हुआ है जिन्होंने नवीनतम प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों के विकास की चुनौतियों पर नियंत्रण पाने के लिए अथक कार्य किया है।

8.2 डीआरडीओ के अधिदेश में निम्नलिखित मुख्य गतिविधियाँ शामिल हैं :

- भारत की सशस्त्र सेनाओं के लिए उत्पादों, प्रणालियों एवं प्रौद्योगिकियों का डिजायन एवं विकास।
- अधिग्रहण एवं उत्पादन के संबंध में प्रौद्योगिकी के मामलों पर रक्षा मंत्री को सलाह प्रदान करना।
- भारतीय अकादमियों के साथ समन्वय कर देश में मजबूत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधार तैयार करना।



- परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित आधारभूत संरचना का निर्माण करना।

## संगठनात्मक संरचना

8.3 डीआरडीओ के प्रमुख रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं जो कि सचिव, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग और महानिदेशक, डीआरडीओ (म.नि. डीआरडीओ) भी हैं।

8.4 सितंबर 2013 में डीआरडीओ ने रामा राव समिति रिपोर्ट की अनुमोदित सिफारिशों पर कार्यान्वयन आरंभ किया। तदनुसार, डीआरडीओ का विकेन्द्रीकरण करके इसे सात प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक के प्रमुख एक अधिकार-प्राप्त महानिदेशक (म नि) हैं। वर्तमान में सात महानिदेशक (क्लस्टर) तथा पांच मुख्य नियंत्रक अनु.एवं वि. (मु. नि अनु.एवं वि) म.नि. डीआरडीओ को सहायता प्रदान करने के लिए हैं। सात म नि (क्लस्टर) हैं: म नि आयुध तथा समाघात इंजीनियरिंग प्रणालियां

(एसीई), पुणे, म नि वैमानिकी प्रणालियां (एयरो), बेंगलूरु; म नि मिसाइल तथा सामरिक प्रणालियां (एमएसएस), हैदराबाद; म नि नौसेना प्रणालियां तथा सामग्रियां (एनएस तथा एम) विशाखापट्टनम; म नि इलैक्ट्रॉनिक तथा संचार प्रणालियां (ईसीएम), बेंगलूरु; म नि सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी उपकरण एवं संगणक प्रणालियां (एमईडी तथा सीओएस), दिल्ली तथा म नि जैव विज्ञान (एलएस), दिल्ली।

8.5 छियालीस (46) प्रयोगशालाओं को संबंधित महानिदेशकों के अंतर्गत क्लस्टरबद्ध किया गया है। तालिका 8.1 में प्रत्येक म नि (क्लस्टर) के अंतर्गत आनेवाली प्रयोगशालाओं की सूची दी गई है।

## डीआरडीओ

8.6 नई दिल्ली स्थित डीआरडीओ मुख्यालय जो संगठन के सभी कार्यों का समन्वय कर सरकार और प्रयोगशालाओं के बीच जनसंपर्क का कार्य करता है। मुख्यालय में कॉरपोरेट निदेशालय हैं,

### तालिका सं. 8.1

तालिका 1 : संघटक प्रयोगशालाओं के साथ प्रौद्योगिकी क्षेत्र आधारित क्लस्टर रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, सचिव रक्षा अनु.एवं वि. एवं महानिदेशक डीआरडीओ महानिदेशक

आयुध एवं समाघात इंजीनियरी प्रणालियां	वैमानिकी प्रणालियां	मिसाइल एवं सामरिक प्रणालियां	नौसेना प्रणालियां एवं सामग्रियां	इलैक्ट्रॉनिक एवं संचार प्रणालियां	सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिक उपकरण एवं संगणक प्रणालियां	जैव विज्ञान
एआरडीई	एडीई	एसएसएल	एनएमआरएल	डेयर	अनुराग	डेबेल
सीफीज	एडीआरडीई	डीआरडीएल	एनपीओएल	डील	केयर	डीएफआरएल
डीटीआरएल	कैब्स	आईटीआर	एनएसटीएल	डीएलआरएल	एमटीआरडीसी	डिबेर
एचईएमआरएल	जीटीआरई	आरसीआई	डीएलजे	आईआरडीई	एसएजी	डिहार
पीएक्सई		टीबीआरएल	डीएमआरएल	लास्टेक	एसएसपीएल	डिपास
सीवीआरडीई		सीएचईएसएस	डीएमएसआरडीई	एलआरडीई	जेसीबी	डीआईपीआर
आरएंडडीई (ई)						डीआरडीई
सासे						डीआरएल
वीआरडीई						इनमास

जैसे - बजट, वित्त एवं लेखा (बीएफ तथा ए), बाह्य अनुसंधान एवं बौद्धिक संपदा अधिकार (ईआर एवं आईपीआर), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), कार्मिक, योजना एवं समन्वय (पी एंड सी), जनसंपर्क, राजभाषा आदि। कुछ ऐसे कॉर्पोरेट निदेशालय भी हैं जो साझेदार संगठनों के साथ विशिष्ट कार्यों को देखते हैं। ये निदेशालय हैं, सेनाओं के साथ संव्यवहार के लिए पारस्परिक-कार्रवाई निदेशालय (डीआईएसबी), औद्योगिक संपर्क एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन निदेशालय और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग निदेशालय ।

8.7 पुनर्संगठन के हिस्से के रूप में कुछ कॉर्पोरेट निदेशालयों का विलय कर उनके कार्यों को सरल और कारगर बनाया गया है। आईटी के कार्यों की देखरेख अब योजना एवं समन्वय द्वारा की जाएगी जबकि संसदीय कार्यों को निपटाने के लिए एक अलग निदेशालय (संसदीय कार्य निदेशालय, डीपीए), का गठन किया गया है। तीन नए समूह (ग्रुप) बनाए गए हैं अर्थात - भावी प्रौद्योगिकी प्रबंधन (एफटीएम) समूह, तकनीकी समन्वय समूह (टीसीजी) एवं अनुरूपण एवं मॉडलिंग केन्द्र (सैम सी)- जिसमें प्रत्येक की विशिष्ट क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं को सहायता/मार्गनिर्देशन में विशेष भूमिका है ।

8.8 कॉर्पोरेट निदेशालयों की गतिविधियों को देखने के लिए पाँच मुख्य नियंत्रक अनु.एवं वि.(मु. नि.अनु.एवं वि.) हैं । ये हैं : मु.नि. अनु.एवं वि. उत्पादन समन्वय एवं सेना संपर्क, (पीसी एवं एसआई); मु.नि. अनु.एवं वि. मानव संसाधन (एचआर); मु.नि. अनु.एवं वि. प्रौद्योगिकी प्रबंधन (टीएम); मु.नि. अनु.एवं वि. संसाधन एवं प्रबंधन और कार्यान्वयन (आर एवं एम

और इम्प) और मु.नि. अनु एवं वि. प्रणाली विश्लेषण एवं मॉडलिंग (सैम)।

## मानव संसाधन

8.9 डीआरडीओ मानव संसाधन प्रबंधन की गतिशील प्रणाली का अनुसरण करता है। विभिन्न परियोजना/कार्यक्रमों हेतु सभी श्रेणियों की जनशक्ति जरूरतों की एक जनशक्ति योजना बोर्ड (एमपीबी) द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। 31 मार्च 2014 के अनुसार, डीआरडीओ के कार्मिकों की कुल संख्या 25,642 है जिनमें से 7,574 रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा (डीआरडीएस), 9,696 रक्षा अनुसंधान एवं तकनीकी संवर्ग (डीआरटीसी) और 8,372 प्रशासन एवं संबद्ध संवर्ग में हैं। यह संगठन अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) एवं अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) की भर्ती, प्रोन्नति तथा कल्याण के लिए मार्गनिर्देशों का अनुपालन कर रहा है। डीआरडीओ में वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों की नियमित रूप से भर्ती विभिन्न भर्ती मोडों से की जाती है। प्रतिभा को आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी, आईआईटी (बीएचयू), आईएसयू धनबाद एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कैम्पस साक्षात्कार का संचालन करके भी लिया जाता है। पार्श्विक भर्ती के माध्यम से भी उच्चतर ग्रेडों में सीधी भर्ती की जाती है।

## बजट

8.10 डीआरडीओ देश के रक्षा बजट के लगभग 5.5% वित्तीय आबंटन के साथ कार्य करता है। लगभग 80% वित्तीय संसाधन मिशन मोड (एमएम) एवं स्टाफ परियोजनाओं में लगाए जाते हैं जिसका आउटपुट सीधे सेनाओं को जाता है ।

8.11 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (एफवाईपी) अवधि (2007-2012) के दौरान व्यय 42,322 करोड़ रु. रहा है। बारहवीं एफवाईपी अवधि (2012-2017) के दौरान वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कुल 9,884.94 करोड़ रु. की राशि रक्षा (अनु. एवं वि.) के लिए आबंटित की गई थी जिसमें 5,201.93 करोड़ रु. राजस्व शीर्ष एवं 4683.01 करोड़ पूँजीगत शीर्षों के अन्तर्गत आबंटित किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कुल 10,934.17 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है जिसमें से 5,672.57 करोड़ रु. राजस्व शीर्ष और 5,261.60 करोड़ रु. पूँजी शीर्ष के अन्तर्गत हैं।

### कार्यक्रम और परियोजनाएं

8.12 डीआरडीओ की परियोजनाओं को चार मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है - मिशन मोड (एमएम) सेना की तत्काल जरूरतों के आधार पर, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन (टीडी) परियोजनाएं जो डीआरडीओ की पहल पर होती हैं, एसएंडटी परियोजनाएं जो विशिष्ट कस्टमाइज्ड जरूरतों के लिए भावी प्रौद्योगिकियों एवं आधारभूत संरचना (आईएफ) परियोजनाओं के संबंध में है। इसके अतिरिक्त, एक नई श्रेणी अर्थात् उत्पाद सहायता (पीएस) को जोड़ा गया है जो हमारे उत्पादन साझेदारों की उत्पादन/टीओटी सहायता की जरूरतों को पूरा करने के लिए है।

8.13 31 मार्च, 2014 तक डीआरडीओ की 339 परियोजनाएं चल रही हैं जो लगभग 45,554.73 करोड़ रु. लागत की हैं। परियोजना लागत का 26% हिस्सा प्रयोक्ता द्वारा दिया जाता है। 223 परियोजनाएं पूरा होने के अंतिम चरण में हैं और तकनीकी/प्रशासनिक रूप से बंद किए जाने के

अधीन हैं। 339 सक्रिय परियोजनाओं में से 37 बड़ी परियोजनाएं (लागत  $\geq$  100 करोड़ रु.) जिनकी कुल लागत 36,613.89 करोड़ है जो इन सक्रिय परियोजनाओं का लगभग 85% है। 1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2014 की अवधि में कुल 1,651.59 करोड़ रु. की कुल लागत से 52 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त 13 परियोजनाएं जिनकी लागत 134.08 करोड़ रु. है, 2013-2014 में पूर्ण हो गई/बन्द कर दी गई।

8.14 वर्तमान समय में 12 प्रमुख कार्यक्रम सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं जिनकी लागत 32,019 करोड़ रु. है। इनमें से चार परियोजनाएं इन मिसाइलों के डिजाइन एवं विकास से संबंधित हैं: लंबी रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एलआरएसएएम), मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एमआरएसएएम) दृष्टि से परे की हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल (बीवीआरएएम) अस्त्र एवं पीजे-10 (ब्रह्मोस)/वैमानिकी के क्षेत्र में फ्लैगशिप परियोजनाएं हैं: हल्का लड़ाकू वायुयान (एलसीए) फेज 2, एलसीएएफ मैक-II, एलसीए नैवी फेज I, एलसीए नैवी मैक-II, वायुवाहित पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण (आईडब्ल्यू एवं सी), कावेरी इंजन, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), रूस्तम-II, एवं लड़ाकू वायुयान के लिए इलैक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति सुइट (ईडब्ल्यूएसएफए)।

8.15 डीआरडीओ की कुछ परियोजनाओं की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

**अग्नि-5 (ए5):** भारत की अंतर महाद्वीपीय सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल ए5 जो



अग्नि-5

अत्यधिक अचूकता के साथ अपेक्षित वारहेडों को गिराने में सक्षम है, का पिछले वर्ष प्रथम लांच की पुनरावृत्ति के साथ 15 सितम्बर 2013 को सफल परीक्षण किया गया और यह मिसाइल त्रिस्तरीय ठोस रॉकेट मोटर से शक्ति प्राप्त है और ऑटो लांच मोड में इसका प्रक्षेपण त्रुटिरहित रहा और इसने पाठ्यपुस्तक तरीके से अपने संपूर्ण प्रक्षेप-पथ का अनुसरण किया। मिसाइल प्रणाली की सभी प्रणालियों तथा उप-प्रणालियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। ए5 का दूसरा

भारत की 4000 कि.मी. रेंज की मिसाइल अग्नि 4 का 20 जनवरी 2014 को व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक लांच किया गया। ए4 नवीनतम उड्डयानिकी, पांचवी पीढ़ी के ऑनबोर्ड कंप्यूटर एवं वितरित वास्तुशिल्प से सुसज्जित है। यह तीसरा लगातार सफल परीक्षण था और विकासात्मक लांच की श्रेणी में अंतिम था। यह मिसाइल सेना में शामिल होने के लिए तैयार है और इसका क्रमिक उत्पादन जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा।

प्रक्षेपण सभी उप-प्रणालियों के प्रदर्शन में सामंजस्य को प्रमाणित करने के लिए खुले रेल मोबाइल लांचर से किया गया। इस सफलता के परिणामस्वरूप पूर्ण स्केल कैनिस्टर से पहला मिसाइल निष्कासन परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया जिसने वास्तविक रोड मोबाइल लांचर (आरएमएल) से शीत लांच क्षमता को साबित किया। इस परीक्षण ने सभी मिशन जरूरतों को पूरा किया गया। अग्नि-1, अग्नि-2 एवं अग्नि-3 पहले से ही सशस्त्र सेनाओं के शस्त्रागार में शामिल है जो इन्हें 3000 किमी की पहुँच प्रदान कर भारत को एक प्रभावी निवारक क्षमता प्रदान करती हैं ।

**अग्नि-4 (ए4):** भारत की 4000 कि.मी. रेंज की मिसाइल अग्नि 4 का 20 जनवरी 2014 को व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक लांच किया गया। ए4 नवीनतम उड्डयानिकी, पांचवी पीढ़ी के ऑनबोर्ड कंप्यूटर एवं वितरित वास्तुशिल्प से सुसज्जित है। यह तीसरा लगातार सफल परीक्षण था और विकासात्मक लांच की श्रेणी में अंतिम था। यह मिसाइल सेना में शामिल होने के लिए तैयार है और इसका क्रमिक उत्पादन जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा।

**कार्यक्रम एडी:** प्राक्षेपिकी मिसाइल हमलों के विरुद्ध एक सामरिक अस्त्र के रूप में डीआरडीओ द्वारा इंटरसेप्टर मिसाइल विकसित की जा रही हैं । कार्यक्रम एडी ने छह अन्तः वायुमंडलीय इंटरसेप्टर परीक्षणों और दो बाह्य-वायुमंडलीय इंटरसेप्टर उड़ान परीक्षणों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। विकसित इंटरसेप्टरों और सी4आई प्रणालियों का उड़ान



कार्यक्रम एडी

परीक्षणों के दौरान वास्तविक समय मूल्यांकन किया गया है। इंटरसेप्टर मिसाइलों के सुपुर्दगी योग्य संरूपण का विकास चल रहा है। पृथ्वी रक्षा वाहन (पीडीवी) का बुस्टर योग्यता परीक्षण पूरा कर लिया गया है और एक बुस्टर पीडीवी उड़ान के लिए तैयार है। वाहन की सभी प्रमुख उप-प्रणालियां प्रमाणित, एकीकृत की गई हैं और उड़ान परीक्षण के लिए तैयार हैं।

**सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल 'प्रहार':** ए डी कार्यक्रम के स्पिन ऑफ के तौर पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल (एस एस एम) का उड़ान परीक्षण किया

**डीआरडीओ द्वारा विकसित मध्यम दूरी (25 कि. मी.) की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एस ए एम) प्रणाली, आकाश निर्माणाधीन है और इसे भा. वा. से. और भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है।**

गया। उड़ान परीक्षण मूल्यांकनों के बाद प्रयोक्ताओं ने इस मिसाइल को सेना में शामिल करने की इच्छा जताई है। निकट भविष्य में प्रयोक्ताओं के साथ उड़ान परीक्षणों की योजना बनाई गई है।

**सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस:** यह समुद्री और जमीनी दोनों लक्ष्यों के खिलाफ जमीन, समुद्र, अंतरसमुद्र और हवा पर आधारित विविध प्लेटफार्मों से दागी जा सकने वाली एक सार्वत्रिक मिसाइल है। ब्रह्मोस की 2.8 मैक से ज्यादा की गति के साथ 290 कि. मी. रेंज है। सेना और नौसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के विभिन्न रूपांतर नौसेना युद्धपोतों और मोबाइल परिसरों पर तैनात किए गए हैं। यह शस्त्र प्रणाली पहले ही चार पोतों पर स्थापित की जा चुकी है और छह और पोतों पर भी स्थापना का काम चल रहा है। भारतीय सेना ने दूसरी रेजीमेंट को प्रचालित करने के लिए नियमित अभ्यास फायरिंग की है।

**आकाश मिसाइल प्रणाली (ए एम एस):** डीआरडीओ द्वारा विकसित मध्यम दूरी (25 कि. मी.) की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एस ए एम) प्रणाली, आकाश निर्माणाधीन है और इसे भा. वा. से. और भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है। डीआरडीओ उत्पादन एजेंजियों बी ई एल (आई ए एफ के लिए) और बीडीएल (भारतीय सेना के लिए) को सहायता प्रदान करने में जुटा हुआ है। आकाश मिसाइल प्रणाली (एएमएस) की दो स्क्वाड्रन सुपुर्द की जा चुकी

है और ये भारतीय वायुसेना (आई ए एफ) में शामिल की जा चुकी है। यह प्रणाली पूरी तरह प्रचालन में है और आई ए एफ द्वारा विभिन्न आंतरिक अभ्यासों में इस्तेमाल की जा रही है। सघन इलेक्ट्रॉनिक





अस्त्र

वारफेयर (ई डब्ल्यू) परिदृश्य में एएमएस के निष्पादन और कार्यात्मकता को परीक्षणों में प्रमाणित किया गया है। पहली बार मोबाइल टेलीमेट्रीप्रणाली के सुपुर्दगी योग्य रूपांतर को सफलतापूर्वक तैयार किया गया है। ये सभी उपस्कर गहन गुणता जांच से गुजरे हैं और इन्होंने सड़क संचलन परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। सेना एएमएस 'अकाश' के शस्त्र प्रणाली एकीकरण परीक्षण हेलिकाप्टर उड़ानों द्वारा किए गए और यह प्रणाली फायरिंग परीक्षणों के लिए तैयार है। ये सेना उपस्कर मान्य उड़ान परीक्षणों के बाद भारतीय सेना के सुपुर्द कर दिए जाएंगे।

**दृश्य क्षमता से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'अस्त्र':** अस्त्र सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों से जूझने और नष्ट करने के लिए विकसित की गई दृश्य क्षमता से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल (बी बी आर ए ए एम) है। इस शस्त्र प्रणालीको एस यू-30 एम के आई, भारतीय वायु सेना (भा. वा. से.) के मिराज 2000 और डीआरडीओ द्वारा विकसित हल्के लड़ाकू वायुयान (एलसीए) जैसे प्लेटफार्मों के लिए तैयार किया गया है। अप्रैल-मई, 2013 में केप्टिव

उड़ान परीक्षणों (सीएफटी-III) के सफलतापूर्वक पूरा होने से, अस्त्र की एसयू-30 एम के आई के साथ एवियोनिक इंटरफेसिंग प्रमाणित हो गई है। जनवरी 31, 2014 तक 2 एसयू-30 एम के आई वायुयान इस्तेमाल करके मिसाइल के साथ कुल 17 उड़ानों की गईं। विभिन्न प्रौद्योगिकियों और रडार की सटीकता के मूल्यांकनके लिए कुल 20 सफल अनुरूपक लांच किए गए। एसयू- 30 एमकेआई वायुयान में प्रयोग के लिए अस्त्र के ब्लास्ट-ट्यूब विन्यास के लिए उपयुक्त एक नया अस्त्र लांचर डिजाइन एवं विकसित किया गया है। उड़ानयोग्य ऑन-बोर्ड-कम्प्यूटर (ओबीसी), विद्युत आपूर्ति नियमन इकाई (पीएसआरयू) और डाटा लिंक रिसीवर के साथ, सीएफटी-III परीक्षणों के लिए दो अस्त्र मीट्रिक मिसाइलें तैयार की गई थीं। मेक-II नोदन प्रणाली विकास के अधीन है। अप्रैल, 2014 में मिसाइलों के पहले एयर लांच परीक्षणों के लिए परियोजना की कार्रवाई प्रगति पर है।

**लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एलआरएसएएम):** लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एलआरएसएएम) डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आई एआई), इजरायल का संयुक्त विकास कार्यक्रम है। मार्गदर्शन के लिए अंतिम प्रावस्था और प्रारंभिक/बीच रास्ते अद्यतनीकरण के लिए सक्रिय रडार सीकर तथा ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर के प्रयोग के साथ इसकी 70 कि. मी. रेंज है। यह शस्त्र प्रणाली भारतीय नौसेना के तीन पोतों को बड़ी संख्या में विभिन्न हवाई खतरों का सामना करने के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। दो पोतों के लिए शस्त्र नियंत्रण प्रणाली, रडार तथा वर्टिकल लांच इकाई सुपुर्द कर दिए गए हैं। पहले पोत पर ऑन बोर्ड अधिष्ठापन पूरा हो गया है। अगस्त

2013 के दौरान होम-ऑन-टारगेट (हॉट) उड़ान परीक्षण किए गए।

**मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एमआरएसएम):** मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एमआरएसएम) आई ए आई इजरायल के साथ संयुक्त विकास कार्यक्रम के रूप में डीआरडीओ द्वारा हाथ में लिए गए प्रमुख मिशन मोड कार्यक्रमों में से एक है। विभिन्न उप प्रणालियों एवं मुख्य घटकों का डिजायन पूरा कर लिया गया है।

**हेलिना :** हेलिना उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर (एएलएच) के लिए 7 जमा किमी वाली तीसरी पीढ़ी की टैंकरोधी निर्देशित मिसाइल (ए टी जी एम) है। मिसाइल प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण उप प्रणालियां तैयार कर ली गई हैं और भू उड़ान परीक्षणों द्वारा इसके उड़ान निष्पादन का मूल्यांकन कर लिया गया है। एएलएच से स्वतंत्र बैलिस्टिक परीक्षण भी किया जा चुका है। हेलिना के जमीन-से-जमीन पर प्रारंभिक परीक्षण सितंबर 2013 में किए गए। हेलिना अग्नि नियंत्रण प्रणाली (एफसीएस) के हेलिकॉप्टर परीक्षण दिसंबर 2013 में किए गए। हेलिना के लिए नोदन प्रणालियों का परीक्षण भी किया जा चुका है। पुनः विन्यासित मिसाइल प्रणाली के उड़ान परीक्षण किए जा चुके हैं जिसने पुनः डिजायन किए गए नोदन, वायुगतिक और नियंत्रण निष्पादनों को प्रमाणित किया है। 7 किमी पर रिपीट कंट्रोल निष्पादन और लॉक ऑन बिफोर लांच (एलओबीएल) निर्देशित

**एलसीए तेजस भा. वा. से. की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजायन तथा विकसित किया गया भारत का पहला स्वदेशी बहु-भूमिका वाला लड़ाकू वायुयान है। वायुयान के लिए प्रारंभिक प्रचालन स्वीकृति (आई ओ सी-II) 20 दिसंबर को हासिल की गई थी जो कि डीआरडीओ के इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर है।**

निष्पादनता स्थापित कर ली गई है। हेलिकॉप्टर लांच के लिए आशोधित नोदन विन्यास की उपयुक्तता सुनिश्चित करते हुए आउटबोर्ड और इनबोर्ड स्टेशनों, दोनों के लिए एएलएच से हेलिना सेपेरेशन उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं।

**नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल (एनजीएआरएम):** जमीन पर स्थित विविध रडार लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजायन की गई एयर लांच्ड मिसाइल के विकास के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। एसयू-30 एम के आई वायुयान से 100 मी. से 15 किमी की लांच ऊचाईयोंसे इसकी 15-100 कि. मी. की इंटरसेप्शन रेंज है। उप-प्रणालियों की प्रारंभिक डिजायन समीक्षा (पीडीआर) और मिशन समीक्षा पूरी हो चुकी है। रॉकेट मोटर निर्माण के साथ हार्डवेयर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

**हल्का लड़ाकू वायुयान (एलसीए) तेजस:** एलसीए तेजस भा. वा. से. की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजायन तथा विकसित किया गया भारत का पहला स्वदेशी बहु-भूमिका वाला लड़ाकू वायुयान है। वायुयान के लिए प्रारंभिक प्रचालन स्वीकृति (आई ओ सी -II) 20 दिसंबर को हासिल की गई थी जो कि डीआरडीओ के इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर है। 27 दिसंबर, 2013 को तेजस ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया, जहां इसने 500वीं उड़ान भरी।

सीमित श्रृंखला उत्पादन वायुयान में आखिरी अर्थात् एल एस पी 8 ने मार्च 31, 2013 को अपनी पहली उड़ान भरी। मार्च 31, 2014 तक एलसीए द्वारा कुल 2519 उड़ान परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं। ऐनवेलप एक्सपेंशन तथा वेपन रिलीज परीक्षण भी सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। सुपुर्दगी के विभिन्न माध्यमों में 25 एलबीएस अभ्यास बम और 1000 एलबीएस बम रिलीज किए गए, इस तरह आई ओ सी जरूरतों को पूरा किया गया। तेजस ने पोखरण में होने वाले आयरन फीस्ट - 2013 में भाग लिया और इसी मिशन में स्विंग रोल क्षमता अर्थात् लेजर निर्देशित बम (एलजीबी) फायरिंग और उसके बाद आर 73 ई मिसाइल फायरिंगका व्यापक प्रदर्शन किया। तीनतेजस वायुयानों ने एयरो इंडिया 2013 में भाग लिया और प्रशंसनीय सफलता हासिल की।

**एल सी ए नौसेना :** एल सी ए नौसेनिक प्रोटोटाइप (एन पीआई) का परीक्षण अक्टूबर 2013 से दोबारा शुरू किया गया। एल सी ए एन पी 2 प्रणाली एकीकरण के अधीन है। एल सी ए नौसेना के परीक्षण के लिए बनाई जा रही तट आधारित परीक्षण सुविधा (एबीटीएफ) पूरा होने के करीब है।

**ए ई डब्ल्यू एवं सी कार्यक्रम :** स्वदेशी वायुवाहित शीघ्र चेतावनी एवं नियंत्रण (ए ई डब्ल्यू एवं सी) प्रणाली कार्यक्रम में कई प्रणालियों नामतः लक्ष्यों की खोज तथा ट्रैकिंग के लिए इलेक्ट्रोनिकली स्कैन्ड लंबी दूरी के निगरानी ऐरे रडार, मित्रों और शत्रुओं की पहचान के लिए सेकेंडरी निगरानी रडार, एलओएस तथा सैटकॉम डाटा लिंक तथा सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए प्रणालियों का डिजायन एवं विकास समाहित है। डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित इन प्रणालियों का भू-



ए ई डब्ल्यू एवं सी प्रणाली

परीक्षण, उड़ान वैधीकरण और ए ई डब्ल्यू एवं सी वायुयान पर एकीकरण किया गया जिन्हें विशेषरूप से इस प्रयोजन के लिए परिवर्तित किया गया है। मिशन प्रणाली को कार्यात्मक रूप से वायुयान के साथ इंटरफेस कर दिया गया है और सभी प्रणालियों का परीक्षण किया गया। दो वायुयानों का प्रयोग करते हुए 100 से भी अधिक उड़ाने पूरी की जा चुकी हैं। परियोजना का कार्य प्रगति पर है और प्रणाली सत्यापन तथा मान्यकरण परीक्षण संतोषजनक रूप से आगे बढ़ रहा है।

**मध्यम तुंगता की लंबी क्षमता वाला यू ए वी रूस्तम-II: रूस्तम - II** को इलेक्ट्रॉनिक बारफेयर, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक तथा सिंथेटिक अपरचर रडार (ईओ एवं एसएआर) पेलोडों को ढोते हुए 24 घंटे की सहनशक्ति के साथ 30000 फीट तुंगता पर काम करने के लिए डिजायन किया जा रहा है। यह 350 कि. ग्रा. वजन तक विविध प्रकार के अन्य पेलोड ढो सकता है। भू नियंत्रण स्टेशन (जी सी एस) और अन्य उप-प्रणालियों का भी विकास किया जा रहा है। रूस्तम-II एक प्लेटफार्म है जिसे सेना, नौसेना और भा. वा. से. के लिए आसूचन, निगरानी ओर टोह मिशनों को अंजाम देने के लिए डिजायन किया गया है। इसकी मिशन अपेक्षाओं में सतत वृहत् क्षेत्र



मध्यम तुंगता की लंबी क्षमता वाला यू ए वी रूस्तम-II

की कवरेज देने के अलावा छोटे लक्ष्यों की पहचान में सक्षम होना है। पहला एयरफ्रेम प्रणाली एकीकरण के अधीन है। इंजन एकीकरण पूरा कर लिया गया है और नवंबर 2013 में ग्राउंड रन आयोजित किए गए। रूस्तम उड़ान नियंत्रण कम्प्यूटर (आर एफ सी सी) सॉफ्टवेयर कोड कर लिया गया है और लैंडिंग गियर एकीकृत किया जा रहा है। कम गति के टैक्सी परीक्षण मार्च 2014 में आयोजित किए गए और इसकी पहली उड़ान जुलाई 2014 को की जानी है।

**अभ्यास:** उच्च गति वाला एक्सपेंडेबल हवाई लक्ष्य (हीट) शस्त्र प्रणालियों के अभ्यास के लिए कम लागत में खतरे का यथार्थवादी परिदृश्य प्रदान करता है। हीट-अभ्यास डीआरडीओद्वारा विकसित किया जा रहा उच्च गति का मानवरहित एक्सपेंडेबल हवाई लक्ष्य है। पहली परीक्षणात्मक उड़ान ने लांच ओर विन्यास क्षमताओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। 25-30 मिनट की सहनशक्ति वाले अभ्यास को सेंसर के साथ फिट किया जाएगा और यह जीपीएस सक्षम है। इसमें ऑन

बोर्ड प्रवर्तक, एक उड़ान नियंत्रण कम्प्यूटर और एक मिस-डिस्टेंस संकेतक लगा होगा। सभी तीनों सेनाओं ने युद्धसंचालन योग्य एक्सपेंडेबल हवाई लक्ष्य (मीट) के लिए अपनी जरूरत बता दी है। इंजन प्रवर्तकों और जीसीएस को ऑटो-पायलट से एकीकृत करके तथा मिशन के समय का सटीक विश्लेषण करके अनुरूपण पूरा कर लिया गया है। सभी लाइन रिप्लेसेबल इकाईयों को एकीकृत कर लिया गया है। सी जी, एम आई और बूस्टर थ्रस्ट संरेखण को भी पूरा कर लिया गया है। दो लक्ष्य क्लोस्ड लूप में लांच किए जाने के लिए तैयार हैं जिनमें से एक लक्ष्य का उड़ान परीक्षण अक्टूबर 2013 में पूरा किया गया।

**एयरोस्टेट:** आकाशदीप के सफल प्रदर्शन के बाद, 450 कि. मी. परिधि जो कि आकाशदीप के वर्तमान 110 कि. मी. परिधि निगरानी ट्रैक से लगभग चार गुणा है, को ट्रैक करने के लिए एक एयरोस्टेट प्रणाली, नक्षत्र का विकास किया जा रहा है। यह निगरानी प्रणाली 4.5 कि. मी. की ऊंचाई तक ऊपर उठ सकती है। इसकी पेलोड क्षमता 1 टन और आयतन 17,000 क्यूबिक मीटर है

**मुख्य युद्धक टैंक 'अर्जुन':** अर्जुन एमबीटी मेक-II के विकास और उत्पादन की योजना कई उन्नत विशेषताओं और प्रणाली सुधारों को शामिल करते हुए मेक-II के अनुवर्तन/अनुक्रम में बनाई गई थी। चेसिस और ऑटोमोटिव प्रणाली, उन्नत रनिंग गियर प्रणाली और टरेट शस्त्र प्रणाली में सुधार किए गए हैं। इनमें से कुछ को अर्जुन एमबीटी मेक-II प्रोटोटाइप के साथ एकीकृत किया गया है और प्रयोक्ताओं द्वारा परीक्षणों को मान्यता दे दी गयी है। मिसाइल फायरिंग परीक्षण का प्रथम फेज पूरा हो गया है।





एमबीटी अर्जुन

**केटापल्ट गन प्रणाली:** भारतीय थलसेना के तोपखाना निदेशालय ने डीआरडीओ को अर्जुन मेक-1 चेसिस पर 130 एमएस केटापल्ट गन प्रणाली को विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस दिशा में डीआरडीओ द्वारा हासिल किए गए मील के पत्थरों में व्यवहार्यता अध्ययन और परीक्षण मूल्यांकन के आधार पर अर्जुन एमबीटी टैंक में परिवर्तन, मेक-11 में सुधारों के बाद विकासात्मक परीक्षण मूल्यांकन शामिल हैं।

**मल्टी बैरल रॉकेट लांचर (एमबीआरएल) प्रणाली-पिनाका मेक-11 :** डीआरडीओ द्वारा विकसित



केटापल्ट गन प्रणाली

पिनाका शस्त्र प्रणाली सभी मौसमों के लिए उपयुक्त, इनडायरेक्ट फायर फ्री फ्लाइंग तोपखाना रॉकेट प्रणाली है जोकि विविध जमीनी लक्ष्यों को निष्प्रभावी करने में सक्षम है। दो रेजिमेंटों के लिए उत्पादन का कार्य विभिन्न एजेंसियों नामतः आयुध निर्माणियों में गोला-बारूद; मैसर्ज बीईएमएल, बेंगलूरु में लोडर एवं रेप्लेनिशमेंट वाहन; मैसर्ज टाटा पावर तथा मैसर्ज एल एंड टी में लांचर और बैटरी कमांड पोस्ट का कार्य चल रहा है। पहली दो रेजिमेंटों के लिए लांचर और अन्य भू-सहायता प्रणालियों का उत्पादन पूरा हो चुका है। विद्यमान पिनाका रॉकेटों की रेंज को 39 कि.मी. से 60 कि.मी. तक बढ़ाने के लिए पिनाका मेक-11 रॉकेट के विकास का जिम्मा लिया गया है। संरचनात्मक और भू-अनुकंपन परीक्षण तथा मोटर ट्यूब्स की लाइनिंग पूरे कर लिए गए हैं। कॉस्ट मोटर के बैच प्रूफ के लिए स्थिर परीक्षण आयोजित किए जा चुके हैं। तीन स्टेबिलाइजर एसेम्बली ने एकीकरण के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है। नवम्बर 2013 में आयोजित तीसरे गतिशील परीक्षण के आयोजन के लिए सात उड़ान हार्डवेयर तैयार किए गए थे।

**उन्नत खींची गई तोपखाना गन प्रणाली (एटीएजीएस):** डीआरडीओ ने भारतीय सेना के तोपखाने के लिए 155m/52cal उन्नत खींची गई तोपखाना गन प्रणाली के डिजाइन और विकास का कार्य अपने हाथों में लिया है। गन संरचना, स्वचलन और नियंत्रण प्रणाली के उप-प्रणाली स्तर डिजाइन, प्रलेखन और समीक्षा को पूरा कर लिया गया है। पूर्वानुमानित प्राक्षेपिक हल का पता लगाया गया है, आयुध और रिकाइल प्रणाली के सभी घटकों का डिजाइन और समीक्षा को पूरा कर लिया



गया है। गन बैरल के लिए निर्माण संविदा निकाली गई है।

#### **मानवरहित भू वाहन:**

डीआरडीओ ने एनबीसी रेकी, सुरंगका पता लगाने और निगरानी पेलोड के लिए एक

टेली-संचालित और स्वायत्त मानवरहित खोजी वाहन के डिजाइन और विकास के लिए एक परियोजना को हाथ में लिया है। इस परियोजना में इस्तेमाल प्रौद्योगिकियां वाहन गतिकी, ऊर्जा प्रबंधन, मिशन पेलोड, मेनिपुलेटर, पथ योजना, स्थानीकरण, तार द्वारा खींचना, अवगम, मानव मशीन मेकेनिकल अंतरापृष्ठ/संचालक कंसोल यूनिट (एचएमएमआई/ओसीयू) हैं। इस वाहन ने 5 किमी. रेंज के लिए खोजी बीएमपी के टेलीसंचालन को प्रदर्शित किया है। 20 कि. मी. प्रति घंटा की अधिकतम गति से मंत्रा-एस के संचालन के लिए तार द्वारा खींचने की क्षमता को भी प्रदर्शित किया गया है। निगरानी पेलोड मिशन का मानवरहित संचालन कर लिया गया है। रिमोट संचालन के लिए एनबीसी सेंसरों को आशोधित किया गया है और एनबीसी पेलोड एकीकरण को पूरा कर लिया गया है। रियल टाइम माइन डिटेक्शन एलगोरिथम का विकास भू-वेधी राडार (जीपीआर) सेंसर, स्वायत्त मार्गनिर्देशन मापदण्ड के उपयोग से विकास और परीक्षण किया गया है।

#### **46 मी. सैन्य भार श्रेणी (एमएलसी) 70 मॉड्यूलर**

**ब्रिज:** इस परियोजना का उद्देश्य 14मी. से 46मी. तक की विविधता वाली रिक्तियों के लिए एकल अवधि में डाले जाने के लिए एक 46मी. एमएलसी-70 मॉड्यूलर

**डीआरडीओ ने एनबीसी रेकी, सुरंगका पता लगाने और निगरानी पेलोड के लिए एक टेली-संचालित और स्वायत्त मानवरहित खोजी वाहन के डिजाइन और विकास के लिए एक परियोजना को हाथ में लिया है।**

ब्रिज का विकास करना है। 46मी. एमएलसी-70 मॉड्यूलर ब्रिज उच्च गतिशीलता वाले सेवाधीन वाहनों पर आधारित होगा। आज की तारीख तक, एक आदिप्रारूप (प्रोटोटाइप) को कार्यान्वित किया गया है।

प्रयोक्ता समर्थित तकनीकी परीक्षण (यूएटीटी) और एमबीटी अर्जुन के साथ सजीव भार परीक्षण भी किया गया है। निष्पादन में तीव्रता लाने के लिए प्रणाली के एक और आदिप्रारूप (प्रोटोटाइप) का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

#### **उड़ान घूर्णन इंजन (एफआरई):**

निशांत यूएवी पर उड़ान परीक्षणों के लिए 15 घूर्णन इंजन के विकास/निर्माण के उद्देश्य से उड़ान घूर्णन इंजन (यूएवी के लिए) के विकास का जिम्मा लिया गया है। परियोजना की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं: प्रथम दो इंजनों यानि एफआरई-1 और एफआरई-2 ने 150 घंटों से अधिक की क्षमता परीक्षा पूर्ण कर ली है। दो उड़ान परीक्षण (कुल 05 घंटे) सेमिलाक से अन्तरिम उड़ान अनुमति के बाद किए गए थे। एफआरई-1 और एफआरई-2 में निष्पादन में सुधार किए गए थे। एफआरई-3 और एफआरई-4 इंजनों के भू-परीक्षण भी किए गए थे और सभी उत्पादन और परीक्षण दस्तावेज स्वीकार्यता के लिए सेमिलाक को सौंप दिए गए हैं। देश में पहली बार 55 एचपी वांकल टाईप इंजन को स्वदेशी तरीके से डिजाइन और विकसित किया गया है।

#### **उन्नत टारपीडो रक्षा प्रणाली 'मारीच':**

टारपीडो रक्षा प्रणाली में खींची जाने वाली ऐरे, खींचा जाने वाला

डिकाय, हल (आवरण) लगा हुआ सोनार अंतरापृष्ठ, बढ़ने योग्य, विंच और डिकाय लांचर शामिल हैं। यह प्रणाली अपनी ओर आने वाले आधुनिक और पुराने टॉरपीडो के संसूचन, खोज प्रलोभन, भ्रमित और लुभाने में सक्षम है। दो उत्पादन ग्रेड प्रणालियों को दो नौसेना पोतों के बोर्ड के ऊपर पूरी तरह से प्रचालन में लाया गया है।

**पोत से छोड़ा जाने वाला उच्च भार टॉरपीडो 'वरुणास्त्र':** पोत से छोड़े जाने वाले पनडुब्बीरोधी उच्च भार इलैक्ट्रिकल टारपीडो ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। परियोजना ने अपना विकास चक्र पूरा कर लिया है और चार प्रयोक्ता समर्थित परीक्षणों के साथ सभी तकनीकी परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित कर लिए गए हैं। अनेक प्रयोक्ता मूल्यांकन परीक्षण (यूईटी) 2013-14 में आयोजित किए गए थे और सभी गतिशील पैरामीटरों को साबित किया गया था।



पोत से छोड़ा जाने वाला उच्च भार टॉरपीडो  
'वरुणास्त्र'

**उन्नत हल्के वजन का टॉरपीडो (एएलडब्ल्यूटी):** उन्नत हल्के वजन का टॉरपीडो (एएलडब्ल्यूटी) पोत और वायुवाहित अनुप्रयोगों दोनों के लिए डीआरडीओ

द्वारा अपने हाथ में ली गई एक परियोजना है। एएलडब्ल्यू के लिए घूर्णक और स्थायी विंग वायुयान लांच प्लेटफार्म हैं। छह गतिशील परीक्षण वर्ष के दौरान पूरे किए गए। होमिंग प्रणाली के प्रारंभिक स्थायी परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं। वाहन स्थिरीकरण परीक्षण प्रगति पर हैं और 120 कि.वाट बैटरी के विकास का सफल परीक्षण किया गया है। अभ्यास टारपीडो संरूपण के लिए आवश्यक सभी घटक तैयार हैं। अभ्यास टॉरपीडो को 60 किलो वॉट मोटर और 70 किलोवॉट बैट्रियों के साथ एकीकृत किया गया है।

**वायु स्वतंत्र प्रणोदन (एआईपी):** यह पनडुब्बियों के लिए ईंधन सैल वायु स्वतंत्र प्रणोदन (एआईपी) के लिए एक भू-आधारित आदिप्रारूप (प्रोटोटाईप) है। उत्पादन पूर्व फर्श मॉडल (पीपीएफएम) हार्डवेयर प्रणाली, पीपीएफएम के लिए नियंत्रण प्रणाली और पीपीएफएम जांच हेतु 300 किलो वाट अनुरूपक भार सुविधा से संबद्ध गतिविधियां इस वर्ष पूरी कर ली गई हैं। हाइड्रोजन उत्पादन आदिप्रारूप (प्रोटोटाईप) का भी एकीकरण और परीक्षण किया जा चुका है।

**एलटास:** पनडुब्बियों का पता लगाने और वर्गीकरण के लिए उन्नत हल्का खींचा जाने वाला ऐरे सोनार (एलटास) एक दक्ष पता लगाने वाली प्रणाली है। रिसीवर प्रणाली के निष्पादन को प्रमाणित करने वाले परीक्षण नवम्बर 2013 में भा.नो.पो. शारदा पर ऑन बोर्ड आयोजित किए गए थे। प्रणाली का विकास और प्रयोगशाला एकीकरण जनवरी 2014 में पूरा किया गया था।

**उशुस पनडुब्बी सोनार अनुरूपक (सिमुलेटर):** परियोजना का उद्देश्य पनडुब्बी विद्यालयों के लिए दो उशुस सोनार अनुरूपकों का विकास और आपूर्ति करना है, ताकि अपने सभी प्रचालन मोड और रिजाइम

में सोनार के सर्वोत्तम और प्रभावी उपयोग के लिए उशुस सोनार प्रचालकों के प्रशिक्षण में मदद की जा सके। उशुस सोनार अनुरूपक (सिमुलेटर) प्रथम चरण में भा.नो.पो. सातवाहन; पूर्वी नौसेना कमान (ईएनसी) विज्ञाग और आईएनएस वज्रबाहु, पश्चिमी नौसेना कमान (डब्ल्यूएनसी), मुम्बई में प्रशिक्षण के लिए स्थापित और सौंपा गया है। चरण-II का विकास और स्थापन 2013 में पूर्वी और पश्चिमी नौसेना कमान पर किया जा चुका है।

**मोहिनी:** डीआरडीओ ने प्रौद्योगिकी प्रदर्शन (टीडी) परियोजना 'मोहिनी' का जिम्मा लिया है जिसमें मोबाइल प्रलोभन, रॉकेट लांच प्रलोभन, पनडुब्बी से फायर किया गया प्रलोभन, मोबाइल प्रलोभन और रॉकेट लांच प्रलोभन को लांच करने के लिए एकीकृत पोत लांचर और बचने के तरीकों के अनुरूपक (सिमुलेटर) अध्ययन के लिए प्रणाली मूल्यांकन सॉफ्टवेयर का विकास शामिल हैं।

### **इलैक्ट्रॉनिक समर्थित उपाय (ईएसएम) प्रणाली**

**वरुण:** यह एक आधुनिक ईएसएम प्रणाली है, जो अन्तरावरोधन, संसूचन, अनेक फ्रीक्वेंसी बैंड पर एलपीआई राडार के साथ पल्सड, सीडब्ल्यू, कुशल पीआरएफ;फ्रीक्वेंसी कुशल राडारों का वर्गीकरण और पहचान करने में सक्षम है। निर्मित मॉडल को एक नौसेना प्लेटफार्म के बोर्ड पर स्थापित किया गया है और इसकी सफल समुद्री स्वीकार्यता के बाद कड़े प्रयोक्ता परीक्षणों के अधीन है। प्रणाली को फ्लीट ईवनिंग 2013 के दौरान "सर्वश्रेष्ठ ईडब्ल्यू निपुणता" पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा 18 वरुण के लिए उत्पादन आर्डर प्रगति पर है।

**समुद्रिका :** डीआरडीओ ने नौसेना कर्मचारी गुणवत्ता आवश्यकताओं (एनएसक्यूआर) के अनुसार विभिन्न

प्लेटफार्मों के लिए बनी सात ईडब्ल्यू प्रणालियों के समूह के स्वदेश में ही विकास की जिम्मेदारी ली है। नौसेना ने इन प्रणालियों के आगे उत्पादन और अधिष्ठापन के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। सभी सात प्रणालियों के लिए पीडीआर पूरी कर ली गई है। पहचाने गए प्लेटफार्मों पर प्रणाली स्थापन संभाव्यता अध्ययन और आरएफ मैपिंग किए गए हैं। सभी प्रणालियों के संरूपण को अंतिम रूप दे दिया गया है और उप-प्रणालियों का विकास प्रगति पर है।

**गिरिशक्ति:** भारतीय सेना डीआरडीओ प्रौद्योगिकियों के साथ "खरीदो भारतीय" श्रेणी के अधीन पर्वतीय भूभाग (हिमशक्ति) के लिए एकीकृत ईडब्ल्यू प्रणाली के प्रापण की प्रक्रिया में है। जैमर अंतरावरोधी मोबाइल (जेआईएम) स्टेशन के लिए लक्ष्य खोजी प्रणाली का विकास पूरा कर लिया गया है। रडार खण्ड में कोर प्रणाली प्रौद्योगिकी मॉड्यूल जिसमें होमोडाईन आरएक्स, क्वाड सुपरहेट आरएक्स, डिजिटल आरएक्स सम्मिलित हैं, को एकीकृत किया गया है।

### **अंतरिक्षवाहित इलेंट प्रणाली के लिए कौटिल्य:**

कार्यक्रम कौटिल्य में स्वदेशी लघु उपग्रह पर एकीकरण के लिए इलैक्ट्रॉनिक आसूचना (इलेंट) पेलोड का विकास शामिल है। इलेंट पेलोड के लिए प्रारंभिक डिजायन समीक्षा (पीडीआर) और विस्तृत डिजायन समीक्षा पूरी कर ली गई हैं। इसरो के साथ आधार-रेखा डिजायन समीक्षा भी पूरी की जा चुकी है। प्रणाली संभाव्यता अध्ययन भी पूरा किया जा चुका है और प्रणाली संरूपण को अंतिम रूप दिया जा चुका है। हार्डवेयर का विकास प्रगति पर है।

**हिमराज:** प्रणाली का कार्य दुश्मनों के रडार ट्रांसमिशन का 70 मेघाहर्टज से 40 गिगाहर्टज बैंड तक पता लगाना, बाधित करना, मॉनीटर करना और विश्लेषण करना शामिल है। अति महत्वपूर्ण उप प्रणाली के प्रणाली डिजाइन एवं विकास के लिए डीआरडीओ जिम्मेदार है और भू-आधारित चल (मोबाइल) ईएलआईएनटी प्रणाली (जीबीएमईएस) जिसका उत्पादन बीईएल में किया जा रहा है, के लिए इंजीनियरी प्रणाली के छांटे गये संदर्भ संस्करण के कार्यान्वयन के लिए डीआरडीओ जिम्मेदार है। पूरी प्रणाली संरूपण (कनफिग्रेशन) को अंतिम रूप दे दिया गया है और इंजीनियर प्रणाली का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

**ईडब्ल्यू सुईट:** एलसीए के लिए उन्नत किस्म के ईडब्ल्यू सुईट के विकास का कार्य, डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय, इजराइल के बीच एक संयुक्त विकास कार्यक्रम के रूप में विकासाधीन है। प्रणाली को तेजस पीवी 1 वायुयान में स्थापित किया है और भू-स्वीकार्य (अनुमोदित) परीक्षण (जीएटी) पूरा हो गया है।

**मिग-29 विमान के लिए आंतरिक ईडब्ल्यू प्रणाली:** डीआरडीओ ने मिग-29 के लिए एक अत्याधुनिक एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्धशीर्ष प्रणाली (युईडब्ल्यूएस) को विकसित किया है। यह प्रणाली रिसेप्शन और जैमिंग दोनों के लिए चारों तरफ से दिग संरक्षण और उच्च यथार्थ दिशात्मक क्षमता प्रदान करती है।

**एमएलएच पर ईडब्ल्यू सुईट -एमआई-17:** एमआई-17 में ईडब्ल्यू आत्म रक्षा सुईट विकसित एवं एकीकृत है। हेलीकॉप्टर में बीडीएल-सीएमडीएस सहित एकीकृत

**डीआरडीओ ने 100 किमी दूरी और मल्टीमोड संचालन के साथ लड़ाकू वायुयानों के लिए उड़ान नियंत्रण रडार के विकास की जिम्मेदारी ली है।**

रडार चेतावनी रिसिवर (आरडब्ल्यूआर) एवं मिसाइल सदृश चेतावनी प्रणाली (एमएडब्ल्यूएस) है। यह प्रणालियां उनके संदर्भित प्रकार्यात्मक पैरामीटरों के सत्यापन के लिए अलग-अलग उड़ानों का मूल्यांकन करती थी और साथ ही एकीकृत मोड में भी मूल्यांकन करती थी। परिक्षणों के पश्चात प्रणाली के एमआई-17 हेलिकॉप्टरों के पूरे बेडे के लिए प्रस्तावित किया गया।

**मध्यम शक्ति रडार (एमपीआर 'अरुद्ध'):** उपभोक्ता अर्थात् कसौली में स्थित भारतीय वायु सेना (आईएएफ)।



एमपीआर अरुद्ध

(युजर) के लिए प्रोटोटाइप रडार को विकसित और प्रदर्शित किया गया।

**सक्रिय विद्युतिय स्कैन ऐरे रडार (ईईएसएआर) 'उत्तम':** डीआरडीओ ने 100 किमी दूरी और मल्टीमोड संचालन के साथ लड़ाकू वायुयानों के लिए उड़ान नियंत्रण रडार के विकास की जिम्मेदारी ली है। स्वदेशी टीआर मॉडल के साथ प्रोटोटाइप सक्रिय छिद्र

(ऐपचर) ऐरे एंटीना यूनिट (एएयू) का कार्यान्वयन एवं अशांकन पूरा हो गया है। विभिन्न एल्गोरिथ्म विधियों एवं अग्नि नियंत्रण रडार के



संकेतो के मान्यकरण के लिए मेकेनिकल स्केन्ड एरे संरूपण (एमएसए) उच्च स्तरिय प्लेटफार्म पर उड़ान योग्य रडार प्रोसेसर और एक्साइटर, - रिसीवर का कार्यान्वयन एवं परीक्षण किया जाएगा। वायु - वायु उप मोड़ों के लिए सॉफ्टवेयर का विकास किया गया।

**कमांडर की गैर-पेनौरेमिक (गैर विशालदर्शी) टीआई साइट:** टी-72, टी-90 और बीएमपी- II के लिए कमांडर टीआई मेक -II साइट के लड़ाकू वाहनों के लिए कमांडर साइट आधारित थर्मल इमेजिंग (टीआई) के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण के लिए ओएफबी और बीईएल ने स्वीकृति दे दी है।

**इलैक्ट्रो ऑप्टिकल अग्नि नियंत्रण प्रणाली:** छः इलैक्ट्रो - ऑप्टिकल अग्नि नियंत्रण प्रणाली (ईओएन 51) को कार्यान्वित कर लिया गया है और नौसेना को सुपुर्द कर दिया गया।

**हल्के भार वाले पोर्टेबल लेजर लक्ष्य (टारगेट) डेजीग्नेटर:** डीआरडीओ द्वारा विकसित हल्के भार वाले पोर्टेबल लक्ष्य डेजीग्नेटर (LWPLTD) को एएसआर के अनुकूल पाया गया और इसे मेसर्स बीईएल को उत्पादन एजेसी के रूप में सेवा के साथ मिलाने की सिफारिश की गयी।

**वाहन माउंटेड उच्च शक्ति लेजर निर्देशित उर्जा प्रणाली -“आदित्य”:** इस प्रणाली का कार्य आरपीवी/यूएवी/डीआरओएनई से हुई संरचनात्मक हानि के कारणों का पता लगाना है और आवश्यक बीम नियंत्रण प्रौद्योगिकियों से इलैक्ट्रो-ऑप्टिकल प्रणालियों, CO<sub>2</sub> गैस डायनेमिक लेजर स्रोत को निष्क्रिय करना है।

**सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो (एसडीआर):** परियोजना का कार्य समर्थ; अंतः प्रचालनीय

नेटवर्क विकसित करना है और आधुनिक सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो (एसडीआर) भारतीय नौसेना के लिए दोनों चल एवं स्थिर सेनाओं को वायरलेस (बेतार) सुरक्षित संचार क्षमता प्रदान करना है। आवश्यक सॉफ्टवेयर संचार वास्तुकला (एससीए) परिचालन वातावरण और रेडियो प्रबंधन कार्यत्मकता को शामिल कर तीन एसडीआर - एनसी प्रोटोटाइप (2वी/यूएचएफ चैनल) और तीन एसडीआर - टीएसी प्रकार्यात्मक प्रोटोटाइप (2वी/यूएचएफ चैनलों) को विकसित किया गया। एएम,एफएम, लिंक-II एवं सुरक्षित कम डाटा दर (64 के बी) की तरंगों को विकासक समृद्ध परीक्षणों तक ले जाया गया। दो एसडीआर -एआर प्रोटोटाइप हार्डवेयर माड्यूल एवं चेसिस कार्यान्वित कर लिए गये है। एएम की पोर्टिंग एवं एफएम की तरंग पूरी हो गई है और उड़ान परीक्षण के सत्यापन के लिए सेमीलेक में पहुँचाया गया है। बेसबैंड एवं आरएफ मॉडल के साथ दो व्यक्ति-पैक एसडीआर चेसिस और बेसबैंड मॉडल के साथ दो हैंड हैल्ड एसडीआर चेसिस का कार्यान्वयन कर लिया गया है। यूएचएफ चल तदर्थ नेटवर्क (एमएएनईटी) तरंग सहित तीन एसडीआर-टीएसी रेडियो को एकीकृत किया गया और कार्य बेंच पर आईपी आधारित एप्लीकेशनों के लिए आईपी गेटवे का परीक्षण किया गया।

**एस- बैंड हब एवं भू सेटकॉम टर्मिनल:** परियोजना में चार प्रकार के सुरक्षित एमएसएस टर्मिनल (एस्सेसरिज के साथ) डिजायन एवं विकास शामिल है यानी हैंडहेल्ड सेटकॉम टर्मिनल (एचएसटी) मैन-पैक सेटकॉम टर्मिनल (एमएसटी), सेटकॉम संदेश टर्मिनल (एसएमटी) एवं एसओटीएम टर्मिनल (एसटी)। साथ ही इसमें उपभोक्ता (यूजर) टर्मिनल के प्रभावी नेटवर्क के लिए आवश्यक



आरएफ के साथ प्रचलित प्रायोगिक डील हब के संवर्धन के साथ एवं स्केबल बेसबैंड हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर शामिल है। सभी चारों संरूपण का डिजायन पूरा हो गया है जबकि सॉफ्टवेयर माड्यूलस एवं हार्डवेयर कार्यान्वयन का विकास प्रगति पर है।

**समुद्रीय क्षेत्र जागरूकता (एमडीए) एवं समुद्रीय प्रचालन जानकारी प्रणाली (एमओकेएस) के लिए अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर एवं सुरक्षा समाधानों का विकास:** समुद्रीय स्थितिपरक जागरूकता के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग एवं सुरक्षा समाधानों का विकास किया गया। सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग को नियोजित किया गया और इसका प्रचालन किया गया। संचार के लिए सुरक्षा समाधान का डिजायन एवं विकास संस्थान में किया गया और उत्पादन एजेंसी को सौंप दिया गया। मुख्य नौसेना की गतिविधियों में नियोजित इन प्रणालियों का परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने समुद्र और तटवर्ती स्थापनाओं दोनों में संतोषजनक प्रदर्शन किया।

**टीएसी 31 एकीकरण के लिए प्रौद्योगिकियां :** विभिन्न टीएसी 31 प्रणालियों के एकीकरण के लिए प्रौद्योगिकियों एवं सोल्युशनों को इस्तेमाल करना जिसका उद्देश्य युद्धक्षेत्र कमांडरों को 'सेना गुणक (मल्टीप्लायर)' प्रदान करना है, को विकसित किया गया। ओपी गतिविधियों के दौरान इन प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित किया गया और इसे भारतीय सेना द्वारा सराहा गया। उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण पूरा हो गया है।

**साइबर सुरक्षा समाधानों के लिए प्रौद्योगिकियां :** उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुरक्षा समाधानों के उपलब्ध कराने के लिए

ज्यादातर प्रौद्योगिकियों को विकसित किया गया। सामरिक और रणनीति वातावरण में सरकारी मानकों सहित प्रणालियों को बड़ी संख्या में विकसित और निर्धारित कर नियोजित किया गया ।

**एयरो इंजिन अनुप्रयोगों के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड और वेनस:** डीआरडीओ ने उन्नत एयरो इंजिन में इस्तेमाल के लिए जटिल कुलिंग चैनल सहित उच्च दबाव टरबाइन ब्लेड (एचपीटीबी) और उच्च दबाव टरबाइन वेन्स (एचपीटीवी) के लिए एकल क्रिस्टल कास्टिंग प्रक्रिया विकसित की है।

**उन्नत कंचन कवच:** डीआरडीओ ने बड़े मापक गतिक उर्जा गोलाबारूद से सुरक्षा में वृद्धि के लिए एमबीटी अर्जुन मेक-II के लिए उन्नत कंचन कवच को डिजायन एवं विकसित किया। नये कवच में उन्नत सामग्री का इस्तेमाल किया गया और बिना भार में वृद्धि के नया डिजायन बनाया गया। मेक-I और मेक-II के डिजायन निर्माण में कवच माड्यूल को दोहराया गया और इन माड्यूलों पर उपभोक्ता परीक्षण किये गये ।

**टाइटेनियम स्पांज:** प्रतिवर्ष 500 टन व्यवसायिक टाइटेनियम स्पांज के लिए डीआरडीओ, वीएसएससी द्वारा संयुक्त रूप से संयन्त्र लगाया गया और मेसर्स केरला मिनरल एवं मेटल्स लिमिटेड (केएमएमएल) छावरा, कोलम, केरल, लगातार 3.5 एमटी बैच में टाइटेनियम स्पांज का उत्पादन कर रहा है। मई 2013 के दौरान एयरोस्पेस शुद्धता के टाइटेनियम स्पांज के पहली खेप की आपूर्ति मिधानी, हैदराबाद को की गई थी। इसी क्रम में एयरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम स्पांज की अगली खेप वीएसएससी की गई।

**एआई20डी एयरो-इंजन का जीवन विस्तार:** भारतीय वायुसेना में डीआरडीओ एवं आरसीएमए (इंजन), कोरापुट के सहयोग से एएन-32 वायुयान के एयरो इंजन के लिफ्टिंग समीक्षा के लिए वर्गीकृत कार्यप्रणाली को स्थापित करने का कार्य लिया है। कुल तकनीकी जीवन (टीटीएल) का परिशोधन उड़ान समय का 300,000 एच अतिरिक्त उत्पादन होना चाहिए।

**ज्वाला मंदक वायु कर्मीदल उत्तरजीविता जैकेट:** कुल 2700 ज्वाला मंदक वायुकर्मीदल उत्तर जीविता जैकेटों (एफआरएसजे), जिन्हें भारतीय वायुसेना की सभी साधारण उड़ानों में बाह्य वस्त्र की तरह पहनाने के लिए भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया है।

**ज्वाला मंदक एंटीजी सूट:-** एंटी जी सूट एक काऊटर प्रेशर गारमेंट है जो लड़ाकू पायलटों द्वारा शरीर के पेट और अंदरूनी हिस्सों के ऊपर पहना जाता है। इन को उच्च निष्पादन वायुयान के लिए स्वीकृत किया गया और इन्हें भारतीय वायु सेना में शामिल किया जा रहा है।

**ज्वाला मंदक दस्ताने:** ज्वाला मंदक द्विसामग्री दस्ताने, जिसके पीछे की तरफ और हथेली की तरफ एफआर मेटा आर्मिड फ्रेबिक से बने दस्ताने हैं, जो ज्वाला मंदक और कटने फटने से बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं। दस्तानों के दो संस्करण विकसित किये गये हैं और भारतीय वायुसेना में 10550 जोड़ी दस्तानों को शामिल किया गया है।

**सक्रिय कार्बन स्पेंडर (एसीएस) कोटेड सीबीआरएन सूट (मेक V):** डीआरडीओ ने एनबीसी योजना में कार्मिकों की प्रभावी सुरक्षा के लिए सीबीआरएन के उन्नत संस्करण को विकसित किया। एसीएस प्रक्रिया तकनीक को इकट्ठे उत्पादन के लिए उद्योगों को हस्तांतरित की गई और उपभोक्ता द्वारा आवश्यक 6.5 लाख सूटों की आवश्यकता को

पूरा करने के लिए स्वदेशी सूटों का विकास किया जा रहा है।



सीबीआरएन सूट (मेक-v)

**परमाणु जैविक एवं रासायनिक (एनबीसी) रक्षा कार्यक्रम:** 10 डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से 12 मिशन मोड परियोजनाएं और 24 विज्ञान और तकनीकी परियोजनाएं शामिल हैं और एकेडमी और उद्योगों के साथ मजबूत अंतःफलक है। उत्पाद और प्रौद्योगिकियां, एनबीसी वातावरण में सेना के ऑपरेशन में संवेदना बचाव और बल को विकसित करती हैं। सेना की संपूर्ण एनबीसी सूची में और उपभोक्ता परीक्षणों के विभिन्न स्तर पर ज्यादातर स्वदेशी उत्पादों का विकास किया गया। इस कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद और प्रौद्योगिकियां हैं:- एनबीसी रेकी वाहन, चल शुद्धिकरण प्रणाली, एकीकृत फील्ड शेल्टर, एनबीसी सूट, खतरे की पूर्व सूचना देने वाला सॉफ्टवेयर, निर्वात बैग, पोर्टेबल गैस क्रोमेटोग्राफ, आटोमेटिक केमिकल एंजेट डिटेक्शन, वैयक्तिक बचाव उपकरण, एटीडोट्स (प्रतिकारक), जैव संवेदक इत्यादि



नॉरमोबेरिक्स हिपोक्सिया चैम्बर



एन बी सी विसंदूषण प्रणाली

हैं। 2013 के दौरान एनबीसी कार्यक्रम में कुछ उपलब्धियां शामिल हैं:-फुलाने वाले एनबीसी शेल्टर के प्रोटोटाइप की तत्परता, सीएमई पूणे स्थित बहुदेशिय शुद्धिकरण प्रणाली और उन्नत फिटमेट टेस्टर का यूएटीटी, युएटीटी के लिए निर्यात बैग की तत्परता और एसएडब्ल्यू ई-नोज का एकीकरण।

**नॉरमोबेरिक हाइपोक्सिया चैम्बर:** शारिरिक दशा के अनुकूल के लिए कम या समय न होने पर उच्च तुंगता पर आधुनिक सैन्य अभियानों में अक्सर तेजी से कार्मिकों की तैनाती आवश्यक होती है। नॉरमोबेरिक हाइपोक्सिया चैम्बर को हाल ही के

तरीकों में से एक तेजी से ऊंचाई के अनुकूलन के रूप में इंटरमिटेन्ट हाइपोक्सिक एक्सपोजर (आईएचई) प्रदान करने के लिए विकसित किया गया।

**हवाई यातायात नियंत्रक संज्ञानात्मक एवं गैर-संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली:** भारतीय वायुसेना की मांग पर, संज्ञानात्मक कौशल पर आधारित हवाई यात्रायात नियंत्रक संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली की परियोजना का विकास किया गया। संज्ञानात्मक कार्य विश्लेषण से हवाई यातायात के नियंत्रण में शामिल संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की पहचान को लगभग 96 वरिष्ठ हवाई यातायात नियंत्रकों ने पूरा किया। वर्गीकरण बोर्ड के परिणामों के साथ-साथ प्रशिक्षण प्रदर्शन के पूर्वानुमान के लिए परीक्षण मान्य थे। वर्तमान में यह संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली वायुसेना अकादमी, हैदराबाद में स्थापित है।

### 8.16 प्रौद्योगिकी पहलें

चल रहे मिशन मोड परियोजना गतिविधियों के अतिरिक्त, डीआरडीओ ने कई प्रौद्योगिकी विकसित कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं: जिसमें ये शामिल हैं -

- **सीएचईएसएस (CHESS) की स्थापना,** उच्च उर्जा प्रणाली एवं विज्ञान केंद्र - जो निर्देशित उर्जा शस्त्र (डीईडब्ल्यू) एप्लीकेशन के लिए उच्च शक्ति लेजर एवं उच्च शक्ति माइक्रोवेव प्रणालियों के विकास पर कार्य करेगा।

- राष्ट्रीय इंजिन मिशन का लांच: एमबीटी एवं अन्य प्लेटफार्म के लिए उच्च शक्ति आईसी इंजिन के विकास के लिए।
- डीआरडीओ - अकादमी औद्योगिक सहयोग का एक नया प्रारूप-मद्रास अनुसंधान पार्क, आईआईटी में अनुसंधान एवं नवाचार केन्द्र (आरआईसी) की स्थापना जो कि अनु.एवं नवा.केन्द्र में तैनात डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को समर्थ बनाएगा कि वे साथ में स्थित उद्योगों के समन्वय में आईआईटी संकाय के साथ कार्य करें।

### 8.17 निगमित पहलें

**सेनाओं की पारस्परिक क्रिया:** सेनाओं के आयुध में स्वदेशी प्रणालियों की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से डीआरडीओ ने सेनाओं के साथ निरंतर पारस्परिक क्रिया की एक प्रणाली शुरू की है। इस ओर किए गए परिरक्षित प्रयास कई प्रणालियों के प्रवेश, जिनमें दिन-रात देखने, टी-72 टैंकों के लिए एकीकृत अग्नि संसूचन तथा उन्मूलन प्रणाली (आईएफडीएसएस), ई/एफ बैंड वायु सह सतह चौकसी रडार रेवथी तथा ईडब्ल्यू प्रणाली शक्ति इत्यादि शामिल हैं, के प्रवेश के लिए डीएसी के अनुमोदन को ले लिया गया है। सेना की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डीआरडीओ द्वारा तीसरी पीढ़ी की टैंकरोधी निर्देशित मिसाइल (एटीजीएस) के विकास के लिए डीएसी का अनुमोदन भी मांगा गया है। कई उत्पादों को डीआरडीओ द्वारा निर्मित या डीआरडीओ प्रौद्योगिकी पर आधारित खरीद (भारतीय) के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। सेनाओं के साथ प्रत्येक तिमाही में पारस्परिक कार्रवाई बैठकें आयोजित की गई हैं और सेनाओं की आवश्यकताओं के संबंध में स्वदेश में विकास के विषयों के बारे में बताने के लिए सभी

प्रयास किए जा रहे हैं। उत्पादन के लिए अनुमोदित डीआरडीओ उत्पादों का संचित मूल्य करीब 1.6 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। प्रयोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डीआरडीओ द्वारा अपने हाथ में लिए जाने वाली परियोजनाओं की एक व्यापक सूची बनाने हेतु विभिन्न डीआरडीओ समूहों और प्रयोक्ताओं के साथ सेनाओं की एलटीआईपीपी का विश्लेषण और इन पर चर्चा की गई है।

**उद्योग अंतरापृष्ठ:** भारत और विदेशी देशों में डीआरडीओ द्वारा भारत और विदेशी देशों में विकसित गैर-सुरक्षा अतिसंवेदनशील प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए डीआरडीओ ने 'त्वरित प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और व्यावसायीकरण (एटीएसी)' कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसके द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के 12 लाइसेंसिंग करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इतिहास में पहली बार डीआरडीओ द्वारा विकसित एक प्रौद्योगिकी विस्फोटक खोजी किट (ईडीके) को डीआरडीओ-फिक्की-एटीएसी कार्यक्रम द्वारा भारत से मैसर्स क्रो एंड कंपनी अमरीका को अंतरित किया गया था।

**अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां:** डीआरडीओ ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया जैसे कि लेटिन अमेरिकन ऐयरोस्पेस एवं डिफेंस (एलएएडी-2013), ब्राजील; रक्षा एवं सुरक्षा उपस्कर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी (डीएसईआई-2013), लंदन, यू.के; बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वायु प्रदर्शनी 2014, बहरीन और रक्षा प्रदर्शनी 2014, नई दिल्ली। सियोल अंतर्राष्ट्रीय वायुआकाश और रक्षा प्रदर्शनी (एडीईएक्स-2013), कोरिया, में भारत ने डीआरडीओ द्वारा डिजायन और विकसित किए गए अपने नवीनतम अत्याधुनिक शस्त्र प्रणालियों, प्लेट फार्मों, सेंसरों, सूचना प्रणालियों इत्यादि का प्रदर्शन किया।



**अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** डीआरडीओ का लक्ष्य विश्वभर में उपलब्ध सर्वोत्तम रक्षा प्रौद्योगिकी के साथ साझेदारी विकसित करना है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकिय शक्ति बढ़ाना और निर्यात नियमन से संबंधित विषयों को सुलझाने के लिए रक्षा अनुसंधान, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और परामर्श के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में डीआरडीओ व्यस्त है। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी में विकसित और मजबूत औद्योगिक आधार वाले मित्र देशों के साथ सहयोग के नए आयाम खोजे गए हैं। 2013 में डीआरडीओ ने रूस, इजराइल, अमरीका, बेलारूस, चेक रिपब्लिक, यू.के., सिगांपुर दक्षिण कोरिया, कनाडा, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, स्वीडन, हंगरी, बुल्गारिया, यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और ब्राजील के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की हैं। 'सूक्ष्मजैविकीय और विकिरण चिकित्सा खोज और बचाव के रक्षा पहलुओं' के क्षेत्र में सहयोग से अनुसंधान के लिए हंगरी के साथ अक्टूबर 2013 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यू.के. गृह कार्यालय के साथ फरवरी 2013 में सीबीआरएन सुरक्षा सहयोग पर भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

**बाहरी अनुसंधान (ईआर):** अपने विरोधियों के ऊपर देश के उत्कर्ष को बनाए रखने में मदद हेतु बाहरी अनुसंधान के लिए तेईस एस एवं टी प्रणोदन क्षेत्रों की पहचान की गई है। विकसित प्रौद्योगिकियां डीआरडीओ की विभिन्न लम्बी एवं कम अवधि की परियोजनाओं और कार्यक्रमों का आधार बनती हैं। प्रथम ईआर सारांश जो कि 2008-2011 के दौरान पूरा किया गया 136 परियोजनाओं के परिणाम को दर्शाता है, जिसे रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा जारी किया गया था। जनवरी 2013 से मार्च

2014 की अवधि के दौरान 26.5 करोड़ रु. की लागत से नई परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। ये परियोजनाएं फोटोटोनिक, उन्नत उच्च ऊर्जा पदार्थ, नेटवर्क सुरक्षा, जैविक विज्ञान, संसर नेटवर्क, गणितीय मॉडलिंग और अनुरूपण (सिमुलेशन) के क्षेत्र में हैं। 466 से अधिक परियोजनाएं विभिन्न विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी, महाविद्यालयों, अनु एवं वि. संस्थानों और सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में चालू हैं। डीआरडीओ के महत्व और संबद्धता के विभिन्न क्षेत्रों में 397 से अधिक सम्मेलन/संगोष्ठियां प्रायोजित की गईं। अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन केन्द्र (आरआईसी), आईआईटी मद्रास अनुसंधान पार्क, चेन्नई, को 14 करोड़ रु. से अधिक की लागत की ग्यारह निर्देशित अनुसंधान परियोजनाएं मंजूर की गई थीं। परियोजनाओं के संचालन के लिए आरआईसी, ईआर एवं आईपीआर और आईआईटी मद्रास के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

**बौद्धिक संपदा अधिकार:** डीआरडीओ के नवप्रवर्तनों को विधिक सुरक्षा प्रदान करने के अनुसरण में इलैक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रुमेंटेशन, पदार्थों, जैव-चिकित्सा विज्ञान, खाद्य प्रौद्योगिकी इत्यादि के क्षेत्रों को सम्मिलित करने वाले उत्पादों/प्रक्रियाओं पर इक्कट्टा करने के लिए 203 आईपीआर आवेदन (विदेशी देशों में 4 शामिल) संसाधित किए गए। जनवरी 1, 2013 से मार्च 31, 2014 की अवधि के दौरान 32 पेटेंट (विदेशों में 13 शामिल) प्रदान किए गए। इसके अलावा नौ प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) और तीन डिजायन भारत में पंजीकृत किए गए। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के बीच आईपीआर जागरूकता के प्रचार के प्रयास में विभिन्न प्रयोगशालाओं में इस अवधि के दौरान पांच आईपीआर जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं/पेटेंट क्लिनिक आयोजित की गईं।



## 8.18 पुरस्कार

**पद्म पुरस्कार:** डीआरडीओ की उपलब्धियों की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तब उजागर हुई, जब इस वर्ष डीआरडीओ ने कई वार्षिक पद्म पुरस्कार अपने नाम किए। पूर्व डीआरडीओ प्रमुख डॉ. वी.

के. सारस्वत, ब्रह्मोस के सीईओ डॉ. ए शिवथानु पिल्लै को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जबकि रक्षामंत्री के वर्तमान वैज्ञानिक सलाहकार श्री अविनाश चन्दर को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ये तीनों वैज्ञानिक सामरिक एवं कूटनीतिक दोनों मिसाइल प्रणालियों के विकास में शामिल रहे हैं।

**आर्यभट्ट अवार्ड:** डॉ. विजय कुमार सारस्वत को ऐस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार मिसाइल एवं एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उनके जीवनपर्यन्त योगदान एवं देश में अंतरिक्षयानिकी के विकास की ओर उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया।

**एएसआई रॉकेट्री पुरस्कार:** डीआरडीओ के वैज्ञानिक एवं आरसीआई के निदेशक जी सतीश रेड्डी को प्रतिष्ठित एएसआई रॉकेट्री एवं संबंधित प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

**डीआरडीओ पुरस्कार:** वर्ष 2012 के लिए प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण कोटि के योगदान के लिए रक्षा मंत्री द्वारा डीआरडीओ पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार 14 विशिष्ट

पूर्व डीआरडीओ प्रमुख डॉ. वी.के. सारस्वत, ब्रह्मोस के सीईओ डॉ. ए शिवथानु पिल्लै को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जबकि रक्षामंत्री के वर्तमान वैज्ञानिक सलाहकार श्री अविनाश चन्दर को पद्म श्री से सम्मानित किया गया।

श्रेणियों में डीआरडीओ के 43 व्यक्तिगत वैज्ञानिकों/टीम एवं आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में डीआरडीओ के प्रयासों को और मजबूत करने में उनके विशिष्ट योगदान करने के लिए अन्य क्षेत्रों से डीआरडीओ के साझेदारों को दिया गया।

**डीआरडीओ जीवन पर्यन्त उपलब्धि पुरस्कार:** डॉ. ईश्वर भगीरथ राव को इलैक्ट्रॉनिक, संचार एवं इलैक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति प्रणालियों के क्षेत्रों में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया।

**प्रौद्योगिकी नेतृत्व पुरस्कार:** श्री एसएस सुदंरम, डीएस एवं मु.नि. अनु.एवं वि. (ईसीएस): डॉ. के. डी. नायक, डीएस एवं मुनि अनु.एवं वि.(एमईडी एवं सीओएस) एवं डॉ. वीजी सेकरन, डीएस एवं निदेशक (एएसएल) को उनके संबंधित क्षेत्रों में उनके विशिष्ट योगदान एवं विभिन्न वैज्ञानिक टीमों में विशिष्ट नेतृत्व प्रदान करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

**उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डीआरडीओ पुरस्कार:** यह पुरस्कार डॉ. वी.जी सेकरन एवं उनकी टीम को अग्नि-5 में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। श्री अनिल एम दातार, ओएस एवं निदेशक (एआरडीई) एवं उनकी टीम को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लांचिंग प्रणाली के लिए भी यह पुरस्कार दिया गया।

**अग्रणी (पाथ ब्रेकिंग) अनुसंधान एवं उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी के लिए डीआरडीओ पुरस्कार:** डॉ. एस क्रिस्टोफर, डीएस एवं निदेशक (कैब्स) एवं

उनकी टीम को आईडब्ल्यू एंड सी प्रणालियों से जुड़े उनके विशिष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त डॉ. देवराज सरोहा, वैज्ञानिक जी, टीबीआरएल एवं उनकी टीम को मल्टी-ईएफपी वारहेड के डिजाइन के लिए विस्फोटक परिणत प्रक्षेपणास्त्र (ईएफपी) प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया।

**रक्षा प्रौद्योगिकी स्पिनऑफ पुरस्कार:** एनएच1ए बनिहाल टनल, जे एवं के पर, अवधाव के खतरे को कम करने के लिए अवधाव नियंत्रण संरचनाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु हिम एवं अवधाव अध्ययन स्थापना (सासे), चंडीगढ़ को रक्षा प्रौद्योगिकी स्पिनऑफ पुरस्कार दिया गया।

**अकादमी उत्कृष्टता पुरस्कार:** प्रोफे. तपन कुमार घोषाल, प्रोफेसर विद्युत इंजीनियरी, जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता एवं प्रोफे. राजाराम नगप्पा, उच्च अध्ययन का राष्ट्रीय संस्थान, बेंगलूरु को डीआरडीओ से संबंधित विकास में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया।

**रक्षा प्रौद्योगिकी अवशोषण पुरस्कार:** एनएमआरएल द्वारा विकसित फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल स्टेक उत्पादन प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक अवशोषण करने के लिए मेसर्स थर्मैक्स पुणे को दिया गया। एनपीओएल से अपेक्षित प्रौद्योगिकी अवशोषण कर लोचपूर्ण टोड सेंसर अरे विकसित करने के लिए मेसर्स केल्ट्रान कंट्रोल्स, अरूर, केरल को दिया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, 15 वैज्ञानिकों को वार्षिक पुरस्कार, आत्मनिर्भरता में उत्कृष्टता के लिए 7 अग्नि पुरस्कार एवं उत्तम कॉरपोरेट सेवाओं के लिए तीन अवार्ड थे।

**8.19 सूचना का अधिकार (आरटीआई):** डीआरडीओ में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू कर दिया गया है और यह प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है। डीआरडीओ मुख्यालय में स्थित आरटीआई प्रकोष्ठ में सभी गतिविधियों को मॉनीटर करने के लिए सॉफ्टवेयर (आरटीआई एपीपी प्रणाली) को लगाया गया है। आरटीआई प्रकोष्ठ ने संगठन के लिए आर टी आई नीतियों को कार्यान्वित किया है और क्षेत्रवार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के द्वारा सभी प्रयोगशालाओं से सीपीआईओ/सीएपीआईओ को प्रशिक्षित किया है। मानक प्रचालन प्रक्रिया के रूप में सीपीआईओ के लिए दिशा निर्देश पर एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है एवं सभी को तत्काल संदर्भ हेतु वितरित की गई है।

**8.20 राजभाषा की पहलें:** संगठन अपनी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में राजभाषा के इस्तेमाल के लिए कर्मठतापूर्वक कार्य कर रहा है। डीआरडीओ राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए प्रयोगशालाओं को निधि आबंटित करता है। डीआरडीओ की ज्यादातर प्रयोगशालाएं गृह-पत्रिका का प्रकाशन करती हैं और हिंदी पखवाड़ा मनाती हैं। 31 मार्च 2014 तक डीआरडीओ प्रयोगशालाओं द्वारा 119 राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं, 44 राजभाषा गृह पत्रिकाओं को प्रकाशित किया गया है। डीआरडीओ प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं के सभी हिंदी अधिकारियों/वरिष्ठ हिंदी सहायकों/हिंदी सहायकों के लिए पांच अभिमुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

दिसंबर 2013 में डेसीडॉक में डीआरडीओ द्वारा हिंदी पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया और विभिन्न क्षेत्रों के हिन्दी में शोध पत्रों को शामिल करते हुए 11 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं।

8.21 डीआरडीओ ने अपने 55वें वर्ष की शुरुआत में सामरिक हथियार, परमाणु शक्ति युक्त पनडुब्बियों, लड़ाकू विमान और मुख्य युद्ध टैंकों और सोनार की इलैक्ट्रानिक प्रणालियां, रडार और इलैक्ट्रानिक युद्धशीर्ष को उपलब्ध कराने के संदर्भ में भारत को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में उच्चतम स्थान पर

पहुँचाने का गौरव प्राप्त किया है। ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी प्रणालियों का संचालन करने से हमारे औद्योगिक आधार मजबूत होंगे, आर्थिक विकास में वृद्धि होगी और तकनीकी प्रधानता प्राप्त होगी। इन सभी के योगदान से विश्व पटल पर भारत की स्थिति सुदृढ़ बनेगी।



## अंतर-सेवा संगठन



राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय



**सेना** इंजीनियर सेवा 12,000 करोड़ रु. से अधिक वार्षिक बजट के साथ सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी सरकारी आधारभूत संरचना विकास एजेंसी है । यह सशस्त्र सेनाओं को इंजीनियरी सहायता प्रदान करती है और उसके द्वारा उनकी संक्रियात्मक तैयारी में योगदान दिया जाता है

9.1 निम्नलिखित अंतर सेवा संगठन सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं:-

- (i) सेना इंजीनियर सेवा
- (ii) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा
- (iii) रक्षा संपदा महानिदेशालय
- (iv) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय
- (v) जनसंपर्क निदेशालय
- (vi) सेना क्रय संगठन
- (vii) सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड
- (viii) सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग
- (ix) राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय
- (x) विदेशी भाषा विद्यालय
- (xi) इतिहास प्रभाग
- (xii) रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय
- (xiii) रक्षा सेवा स्टॉफ महाविद्यालय
- (xiv) रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय

## सेना इंजीनियर सेवा

9.2 सेना इंजीनियर सेवा 12,000 करोड़ रु. से अधिक वार्षिक बजट के साथ सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी सरकारी आधारभूत संरचना विकास एजेंसी है ।

यह सशस्त्र सेनाओं को इंजीनियरी सहायता प्रदान करती है और उसके द्वारा उनकी संक्रियात्मक तैयारी में योगदान दिया जाता है । सेना इंजीनियर सेवा धावन पथ, हेंगरों, रडार सुविधाओं, नौसैनिक डॉकयार्डों, घाटों, समुद्री ढांचों, ब्लास्ट पेनों, गोला-बारूद डिपो इत्यादि के रूप में संक्रियात्मक आधारभूत संरचना के सृजन और अनुसंधान के माध्यम से युद्ध प्रयास में योगदान देती है । सेना इंजीनियर सेवा परम्परागत भवनों के साथ-साथ अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास एवं औद्योगिक सुविधाओं, परिष्कृत कार्यशाला शेडों, मेगा अस्पताल परियोजनाओं को निष्पादित कर रही है । अपनी स्वदेशी डिजाइन और परामर्श कार्य सुविधाओं के साथ सेना इंजीनियर सेवा छावनी योजना और विपुल जल एवं बिजली आपूर्ति तथा स्वच्छता इंजीनियरी जैसी उपयोगी सेवाओं की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । सशस्त्र सेनाओं के अतिरिक्त सेना इंजीनियर सेवा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन और सीमा सड़क संगठन को निर्माण सेवाएं मुहैया कराती है ।

9.3 सेना इंजीनियर सेवा शांतिकाल में राष्ट्र निर्माण और आपदा न्यूनीकरण में भी योगदान देती है । सेना इंजीनियर सेवा के कार्मिक भुज भूकंप और सुनामी तथा लेह एवं उत्तराखंड में बादल फटने के पश्चात

पुनर्वास के दौरान सबसे आगे थे । इसके अतिरिक्त सेना इंजीनियर सेवा के कार्मिकों को समय-समय पर विभिन्न संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के अंतर्गत निर्माण इंजीनियर कंपनियों के भाग के रूप में तैनात किया गया (पूर्वोत्तर में आधारभूत संरचना के विकासार्थ, सेना इंजीनियर सेवा में बड़ी परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने का पुनः बीड़ा उठाया है) है ।

9.4 सेना इंजीनियर सेवा को विशेष रूप में हमारे देश के उत्तरी पूर्वोत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों / इलाकों में सैनिकों के लिए आवास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के सृजन को सुनिश्चित करने का ही कार्य नहीं बल्कि उस क्षेत्र के पूर्ण विकास में सहायता का भी कार्य सौंपा गया है।

## 9.5 चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाएं

(क) **केन्द्रीय आयुध डिपो (सीओडी) आगरा और जबलपुर का आधुनिकीकरण:-** आधुनिकीकरण योजना में गोदामों के लिए वृहत आकार आधुनिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग (पी ई बी) ढांचों (सबसे बड़ा आकार 198 मीटर 54 मी.) में पुराने गोदाम शेल्टर्स में बदलाव शामिल है। इन ढांचों में मैकेनाइज्ड हैंडलिंग उपस्कर और अत्यंत सकरा पथ (वी एन ए) ट्रैक्स के साथ भंडारों की आधुनिक स्टेकिंग और पुनः प्राप्ति प्रणाली है। आधुनिक सुविधाएं जैसे ऊंची इन्वेट्री भंडारण प्रणाली, गोदाम प्रबंधन साफ्टवेयर, अग्नि-शमन व्यवस्था और पहुंच नियंत्रण इस परियोजना के भाग हैं। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक भवनों और ओटीएम आवास/एस्कोर्ट लाइनों को भी निर्मित किया जा रहा है ।

(ख) **उच्च तुंगता क्षेत्र (एचएए) आवास:** उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में डिजाइन और निर्माण तकनीक के विधि को तैयार करने के लिए सैन्य टुकड़ियों के आवास और जीवन दशाओं में सुधार के लिए प्रायोगिक परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है। शीत और ग्रीष्म के पश्चात परिसंपत्तियों का परीक्षण मूल्यांकन पूरा हो चुका है ।

(ग) **पूर्वी कमान में आधारभूत संरचना विकास:**

(i) सीसीएस ने पूर्वी खेत्र में 2016-17 में पूरा होने की संभावित तारीख के साथ आधारभूत संरचना विकास के लिए अनुमोदन प्रदान किया है । उपर्युक्त निर्माण कार्यों को डीडब्ल्यूपी-2007 के अनुसार सेना इंजीनियर सेवा द्वारा निष्पादित किया जा रहा है । कार्य क्षेत्र में सैन्य टुकड़ियों के लिए स्थायी रक्षा और आवास, सड़कों, रेल लाइनों के माध्यम से संचार नेटवर्क, संक्रियात्मक ट्रैक्स/प्राणी ट्रैक्स, गोदाम/भंडार, आवास और अन्य सामरिक अवसंरचना शामिल है ।

(ii) वर्तमान में नौ-निर्माण कार्यों के निष्पादन सहित साथ कुल 89 निर्माण कार्य प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं ।

9.6 **पूरी की गई महत्वपूर्ण परियोजनाएं :-** इस वर्ष के दौरान पूरे किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में निम्नलिखित है:-

(क) दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन बटालियन के लिए केएलपी

(ख) सेना अस्पताल (आर एंड आर) स्थित कार्डियों थोरासिक वैसकुलर साइंस सेंटर (सी टी वी एस)

(ग) नोएडा में तटरक्षक के लिए आवासीय परिसर

(घ) एसटीपी शंकर विहार

(ङ.) कवचित रेजीमेंट, इंफैंट्री बटालियन और मध्यम रेजीमेंट के लिए ओटीएम आवास

(च) बेस अस्पताल और सैन्य अस्पताल के लिए ओ टी एम आवास

#### 97. मुख्य पहल

(क) **14 कोर एओआर में राज्य पीडीडी से हाइडल बिजली शक्ति की टेपिंग:-** सेना इंजीनियर सेवा के दृढ़ और निरंतर प्रयासों से कारगिल और इसकी सात सेटलाइट स्टेशनों के लिए समर्पित बिजली आपूर्ति अर्जित की गयी है ।

(ख) 03 कोर जोनों में उन्नत अवतरण स्थलों (ए एल जी) का उन्नयन किया गया है ।

(ग) सभी सेना इंजीनियर सेवा विरचनाओं में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-भुगतान कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(घ) ई-निविदा:-ई-निविदापोर्टल [www.eprocuremes.gov.in](http://www.eprocuremes.gov.in) का सृजन किया गया है और यह एन आई सी सर्वर पर उपलब्ध है।

(ङ.) रक्षा में विरासत संसाधन: रक्षा में विरासत

संसाधनों के लिए संरक्षण संबंधी नीति के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है और इनको विरचनाओं को जारी किया जा रहा है।

### सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (ए एफ एम एस)

9.8 सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में (एएफएमएस) सेना, नौसेना और वायुसेना की चिकित्सा सेवाएं और महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा शामिल है । प्रत्येक चिकित्सा सेवा लेफ्टिनेंट जनरल अथवा समतुल्य रैंक के महानिदेशक, चिकित्सा सेवा (डी जी एम एस) के अधीन है । महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा रक्षा मंत्रालय के चिकित्सा सलाहकार हैं और चिकित्सा सेवा सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हैं । सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के कार्मिकों में सेना चिकित्सा कोर (ए एम सी), सेना चिकित्सा कोर (गैर-तकनीकी), सेना दंत चिकित्सा कोर (ए डी सी) और सैन्य नर्सिंग सेवा (एम एन एस) के अफसर शामिल हैं । देश भर में 130 सशस्त्र सेना अस्पताल हैं । मेडिकल अफसरों, डेंटल अफसरों एवं एमएनएस अफसरों तथा एएमसी (एनटी) की प्राधिकृत नफरी क्रमशः 6165, 651, 4600 एवं 368 है ।

9.9 हमारे देश की सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा युद्ध-क्षेत्र में तैनाती के समय अर्द्ध-सैनिक संगठनों के कार्मिकों, देश के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय पुलिस/आसूचना बलों समेत सशस्त्र सेना कार्मिकों एवं उनके परिवारों को समर्पित एवं भरोसेमंद चिकित्सा देख-

हमारे देश की सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा अर्ध सैनिक संगठनों के कार्मिकों सहित सशस्त्र सेना कार्मिकों एवं उनके परिवारों को समर्पित एवं भरोसेमंद चिकित्सा देख-रेख प्रदान करने का विशिष्ट रिकार्ड रखती है।

रेख प्रदान करने का विशिष्ट रिकार्ड रखती है। इसके अतिरिक्त यह भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों एवं देश में जरूरतमंद सिविलियनों को भी चिकित्सा देख-रेख सुविधा प्रदान करती है ।

9.10 ए.एफ.एम.एस. के संसाधन सभी तीनों सेनाओं में कार्यभार के अनुसार फैले हैं । सभी एम.आई. कक्षाओं सिविल बे, स्टेशन चिकित्सा देख-रेख केन्द्र तथा विशेषज्ञ ओपीडी वर्ष 2012 में देश भर में 130 सैन्य अस्पतालों तथा बहुत सी नॉन बेड यूनिटों में ओपीडी कार्यभार लगभग 1,38,59,000 लाख था । अस्पताल दाखिलों में पिछले वर्ष संपूर्ण देश में सैन्य अस्पतालों में 7,08,000 से अधिक रोगियों को दाखिल किया गया था और उनका इलाज किया गया था ।

### वर्ष के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय/ गतिविधियां:

9.11 (I) एएफएमएस (फेज-II) में जनशक्ति की वृद्धि: 407 चिकित्सा अफसरों, 25 दंत चिकित्सा अफसरों और 684 एमएनएस अफसरों सहित 3530 चिकित्सा कार्मिकों को शामिल करने हेतु एएफएमएस में जनशक्ति के संवर्धन के फेज-II को अनुमोदित किया गया है ।

#### (II) ए.एफ.एम.एस. में कमीशन:

(क) सिविल स्रोतों से एस.एस.सी: वर्ष 2013 में सिविल स्रोतों से 42 महिलाओं सहित 178 डाक्टरों को अल्प सेवा कमीशन (एस.एस.सी.) प्रदान किया गया ।

(ख) ए.एफ.एम.सी. कैडेटों को कमीशन प्रदान करना: वर्ष 2013 के दौरान ए.एफ.एम.सी से 108 कैडेटों को इस प्रकार कमीशन प्रदान किया गया:

- (i) पीसी - 47
- (ii) एस.एस.सी. - 61

(ग) विभागीय स्थायी कमीशन (ए एम सी/एन टी): वर्ष 2013 के दौरान ए.एम.सी. (एन.टी) के 32 एसएससी अफसरों को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया ।

(घ) पी.बी.ओ.आर. को ए.एम.सी (एनटी) में पीसी/एसएससी: वर्ष में 2013 के लिए रिक्तियों के लिए ए.एम.टी (एनटी) में पीबीओआर को 10 एसएससर और 5 पीसी प्रदान किए गए ।

(III) मानद परामर्शदाता/सलाहकार की नियुक्ति: सशस्त्र सेनाओं की संपूर्ण चिकित्सा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञताओं में सुविख्यात सिविलियन डाक्टरों की सेवा आवश्यकता, परामर्शदाता की विशेषज्ञता और मुफ्त सेवा उपलब्ध कराने की उनकी इच्छा के आधार पर उन्हें विभिन्न स्थानों पर मानद परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

(IV) सशस्त्र सेनाओं में एच.आई.वी.-एड्स: सशस्त्र सेनाओं में एचआईवी/एड्स नियंत्रण के लिए एएफएमएस एड्स नियंत्रण संगठन (एसीओ) नोडल संस्था है । इस संगठन ने सशस्त्र सेनाओं में एचआईवी नियंत्रण में एक उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की है । सशस्त्र सेनाओं में नियंत्रण रणनीतियों के कड़े कार्यान्वयन से एच आई वी पॉजिटिव मामलों में बड़ी गिरावट आई है जिससे पता चलता है कि यह महामारी रूक रही है । वर्ष 2012 एक विशेष वर्ष था क्योंकि एचआईवी/एड्स के कारण होने वाली मृत्यु अथवा अशक्तता के किसी मामले की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(V) सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय (ए एफ एम सी), पुणे: सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे में दाखिला लेने के लिए आवेदन-पत्र संबंधी प्रक्रिया को पहली बार पूर्णतः ऑनलाइन किया गया। वर्ष 2013 में 130 (105 छात्र और 25 छात्राएं) विद्यार्थियों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया। इसके अतिरिक्त मित्र पड़ोसी देशों से 06 प्रायोजित विद्यार्थियों को भी दाखिला दिया गया।

(VI) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (ए एफ एम एस) का आधुनिकीकरण:

(क) मुख्यालय आईडीएस (चिकित्सा) ने सशस्त्र सेनाओं के लिए टेलीमेडीसिन की तीन स्तरीय परिकल्पना की है।

(ख) मुख्य भूमि तृतीय चिकित्सा नौसेना अस्पतालों के लिए टेलीलिंक पोतों की परियोजना प्रगति पर है। इस परियोजना के पूरा होने पर तृतीय चिकित्सा भूमि आधारित अस्पतालों के विशेषज्ञों/नौसेना सुपर विशेषज्ञों की राय और सुविज्ञता का पोतों/पनडुब्बियों पर सवार/सुदूर अवस्थिति में स्थित अस्पतालों में लाभकारी रूप में उपयोग किया जाएगा।

(ग) विष विज्ञान प्रयोगशाला:- दहन गैसों, अल्कोहल और मादक द्रव्यों जैसे विदेशी पदार्थों की उपस्थिति के लिए वायुयान चालकों से शव-परीक्षा जैविकीय नमूनों के मूल्यांकन के लिए 3.6 करोड़ रु. की लागत से आई ए एम बंगलौर में आधुनिक विष विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई। यह भारत में प्रथम विष विज्ञान प्रयोगशाला है और इस प्रयोगशाला के माध्यम से मिलने वाली जानकारी भारतीय वायु सेना में उड़ान सुरक्षा के लिए लाभकारी होगी।

(घ) सीटीवीएस प्रकोष्ठ: सेना अस्पताल (आर एंड आर) दिल्ली छावनी स्थित 200 बेडों की क्षमता वाले कार्डियों थोरासिक वैसकुलर सर्जरी (सीटीवीएस) केन्द्र के लिए 'अत्याधुनिक' चिकित्सा उपस्करों की चरणबद्ध अधिप्राप्ति में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के कार्यालय में सी टी वी एस प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

दहन गैसों, अल्कोहल और मादक द्रव्यों जैसे विजातीय पदार्थों की उपस्थिति के लिए वायुयान चालकों से शव-परीक्षा जैविकीय नमूनों के मूल्यांकन के लिए 3.6 करोड़ रु. की लागत से आई ए एम बंगलौर में आधुनिक विष विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई। यह भारत में प्रथम विष विज्ञान प्रयोगशाला है

(ड.) उच्च प्रयोजन, परिष्कृत 'अत्याधुनिक' चिकित्सा उपस्करों की वार्षिक अधिग्रहण योजनाओं एएपी के माध्यम से अधिप्राप्ति की गई है जिनके बारे में चरणबद्ध आधुनिकीकरण टेम्प्लेटों के रूप में 2006-07 में विचार किया



गया था जो वर्तमान में सेना अस्पतालों के विशेषीकृत और गंभीर चिकित्सा उपस्कर प्रोफाइल के अभूतपूर्व संवर्द्धन के रूप में विकसित हुई है। वार्षिक अधिग्रहण योजनाओं (एएपी) के प्रारंभ से 700 करोड़ रु. की लागत से चिकित्सा उपस्करों की चरणबद्ध तरीके से अधिप्राप्ति की गई है जिसमें 256 स्लाइस सी टी स्कैन्स-02, 16 स्लाइस सी टी स्कैन्स-38, एमआरआई स्कैन्स-15, पेट स्कैन्स-05 कार्डियाक कैथेटरिजेशन लैब-06 स्लीप लैब्स-13, होलमियम याग लेजर-10, पूर्णतः स्वचालित रेडियो असंक्राम्य जांच-06, लेपरोस्कोपिक सर्जरी सैट्स-33 इत्यादि शामिल हैं। अत्याधुनिक अल्ट्रा विशेषीकृत लीवर ट्रांसपोर्ट केन्द्र, अस्थिमज्जा प्रतिरोपण केन्द्रों, कोकलियर इंफ्लान्ट केन्द्रों, अनुर्वरता के इलाज के लिए सहायक प्रजनक प्रौद्योगिकी केन्द्र, डी एन ए लैब और मल्टीपल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट केंद्रों की स्थापना ने सेना अस्पतालों की सुविधाओं को देश में उपलब्ध श्रेष्ठ सुविधाओं के समतुल्य ला दिया है। अधिप्राप्त महत्वपूर्ण उपस्करों में कार्डियक कैथेटरराइजेशन लैब, ईकोकार्डियोग्राफी मशीन-3डी, इन्द्रा एओर्टिक बैलून पम्प, आई सी यू वेन्टीलेटर्स और काम्प्रेहेन्सिव मॉनीटरिंग साल्यूशंस शामिल हैं।

#### (VII) मित्र देशों को प्रदत्त विदेश सहायता:-

- (क) भारत और मालदीव गणराज्य के बीच रक्षा सहयोग के भाग के रूप में एक स्पाइरोमीटर, एम्ब्यूलेटरी होल्डर मॉनीटर मालदीव स्थित एम एन डी एफ अस्पताल को प्रदान किया गया है। वर्तमान में 1 न्सी टी स्कैन तथा 1 एम आर आई मशीन एम एन डी एफ अस्पताल को उपहार में देने के लिए अधिप्राप्त की जा रही है।
- (ख) डेंगू महामारी से मुकाबला करने के लिए निकारागुआ को मानवीय सहायता के भाग के रूप में 8,82,185/-रुपए की लागत की मेडिकल सामग्री राहत के रूप में 24 घंटों की अल्प सूचना पर भेजी गई थी।
- (ग) फिलीपींस को भी आपदा राहत सहायता भेजी गई थी जिसमें 9,38,986 रुपए की लागत की मेडिकल सामग्री राहत के रूप में 24 घंटों की अल्प सूचना भेजी गई थी।

#### (VIII) अस्पतालों का आधुनिकीकरण/उन्नयन

- (क) कमान अस्पताल (दक्षिणी कमान) पुणे के नए तकनीकी एवं ओ टी एम आवास का रक्षा मंत्री द्वारा शिलान्यास किया जाना: रक्षा मंत्री ने 18 जून, 2013 को कमान अस्पताल (दक्षिणी कमान) पुणे के नए आधुनिक बहुमंजिलें तकनीकी और ओटीएम आवास का शिलान्यास किया। यह परियोजना 2016 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

- (ख) **आईएनएचएस नवजीवनी कमीशनिंग:** यह अस्पताल दिसंबर, 2012 में अधिष्ठापित किया गया है ।
- (IX) **अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप:** पुणे में फरवरी, 2013 में हुई सशस्त्र सेना चिकित्सा अनुसंधान समिति (एएफआरएमसी) की 51 वीं बैठक के दौरान 10 करोड़ रूपए की लागत से 119 अनुसंधान परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था।
- (X) **एएफएसएस अस्पतालों में विदेशी नागरिकों का उपचार:** भारत सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही मैत्रीभाव के एक उपाय के तौर पर अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांगला देश और मालदीव जैसे देशों के सशस्त्र सेना कार्मिकों को एएफएमएस अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं दी जाती है ।
- (XI) **श्रेष्ठ कमान अस्पताल के लिए रक्षा मंत्री ट्राफी:** वर्ष 2013 के लिए कमान अस्पताल (मध्य कमान) लखनऊ ने 'सशस्त्र सेनाओं में श्रेष्ठ कमान अस्पताल' के लिए स्पृहणीय 'रक्षा मंत्री ट्राफी' प्राप्त की ।

## रक्षा सम्पदा महानिदेशालय

9.12 रक्षा सम्पदा महानिदेशालय, नई दिल्ली, 62 छावनियों में रक्षा भूमि और नागरिक प्रशासन के प्रबंधन से संबंधित सलाहकार और कार्यपालक का कार्य करता है । यह महानिदेशालय, वर्तमान में जम्मू, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और जयपुर स्थित छह प्रधान निदेशालयों के माध्यम से कार्य करता है ।

यह प्रधान निदेशालयों के माध्यम से कार्य करता है । ये प्रधान निदेशालय बारी-बारी से कई फील्ड कार्यालयों जैसे कि रक्षा सम्पदा कार्यालयों, सहायक रक्षा सम्पदा कार्यालयों और छावनी बोर्डों जैसे कार्यालयों को देश के चारों ओर फैले छावनी बोर्डों और रक्षा भूमियों के दैनंदिन प्रबंधन का कार्य सौंपता है ।

9.13 रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व में देश भर में लगभग 17.54 लाख एकड़ रक्षा भूमि है जिसका प्रबंधन तीनों सेनाओं और अन्य संगठनों जैसे कि आयुध निर्माणी बोर्ड, डीआरडीओ, डीजीक्यूए, सीजीडीए आदि द्वारा किया जाता है । सेना के नियंत्रण और प्रबंधन में सर्वाधिक अर्थात् 14.14 लाख एकड़ भूमि है और इसके बाद वायु सेना और नौसेना के पास क्रमशः 1.40 लाख एकड़ और 0.44 लाख एकड़ भूमि है । अधिसूचित छावनियों के अंदर लगभग 1.57 लाख एकड़ रक्षा भूमि है और शेष लगभग 16.00 लाख एकड़ भूमि छावनियों से बाहर है।

9.14 महानिदेशालय ने सभी रक्षा भूमि का कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। सभी रक्षा भूमि का सर्वेक्षण कार्य और सीमांकन और रक्षा भूमि पर नियंत्रण और प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए रिकार्डों का डिजीटाइजेशन का कार्य चल रहा है ।

9.15 रक्षा संपदा विभाग सशस्त्र सेनाओं के लिए रिहायशी आवासों और भूमि को किराए पर लेने/ अर्जित करने का कार्य भी करता है । जम्मू व कश्मीर में अचल सम्पत्ति का अर्जन जे एंड के आरएआईजी अधिनियम, 1968 के अधीन किया जाता है ।

9.16 रक्षा सम्पदा महा-निदेशालय, रक्षा मंत्रालय की ओर से छावनियों में नागरिक प्रशासन के नियंत्रण, मानीटरी और निरीक्षण के लिए भी उत्तरदायी है। भारत में 62

छावनियां हैं। ये छावनियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित 19 राज्यों में स्थित हैं। छावनी बोर्ड 'बॉडी कार्पोरेट' होते हैं जो केन्द्रीय सरकार के समग्र नियंत्रण में और छावनी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कार्य करते हैं। छावनी बोर्डों के आधे सदस्य निर्वाचित होते हैं। स्टेशन कमांडर छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इन निकायों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण और नियंत्रण मध्यवर्ती स्तर पर जनरल आफिसर्स कमांडिंग इन चीफ और प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा द्वारा और उच्चतम स्तर पर रक्षा सम्पदा महानिदेशालय के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है।

9.17 केन्द्रीय सरकार उन छावनी बोर्डों को जो वित्तीय घाटे में होते हैं, सहायता अनुदान के जरिये वित्तीय सहायता मुहैया कराती है ताकि वे बजट को संतुलित कर सकें। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान छावनियों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु 20.69 करोड़ रुपए प्रदान करने के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान घाटे वाले छावनी बोर्डों को 225.69 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था।

**रक्षा सम्पदा महा-निदेशालय, रक्षा मंत्रालय की ओर से छावनियों में नागरिक प्रशासन के नियंत्रण, मानीटरी और निरीक्षण के लिए भी उत्तरदायी है।**

9.18 प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए छावनी बोर्ड प्राथमिक विद्यालय चलाते हैं। कई छावनी बोर्ड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और इंटरमीडिएट/जूनियर

महाविद्यालय भी चला रहे हैं। छावनी बोर्डों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों की कुल संख्या 197 है।

9.19 छावनियों और आसपास की आम जनता को चिकित्सीय सेवाएं मुहैया करने के लिए छावनी बोर्ड 40 अस्पताल, जिनमें 1360 बेड हैं, और 39 डिस्पेंसरियां चला रहे हैं।

## **मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय**

9.20 मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना मुख्यालयों और अंतरसेवा संगठनों के मुख्यालय कार्यालयों को सिविलियन जनशक्ति और अवसंरचनात्मक सहयोग मुहैया कराता है। मुख्य प्रशासन अधिकारी (सी ए ओ) और नदेशक (सुरक्षा) का कार्य भी करते हैं।

9.21 मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय निम्नलिखित सात प्रभागों के द्वारा अपना कार्य करता है:

(क) **प्रशासन विभाग:** यह प्रभाग सेना मुख्यालयों और अंतर सेवा संगठनों में कार्यरत लगभग

12,000 सिविलियन कार्मिकों को प्रशासनिक ढांचा प्रदान करता है।

(ख) **कार्मिक एवं विधिक प्रभाग:** कार्मिक प्रभाग तीनों सेना मुख्यालयों और 27 अंतर सेवा संगठनों में तैनात सिविलियन कार्मिकों की लगभग 200 ग्रेडों में तैनाती सहित कैडर प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग अदालती मामलों को देखता है।

(ग) **जनशक्ति योजना और भर्ती प्रभाग:** यह प्रभाग सशस्त्र बल मुख्यालय संवर्ग / काडर बाह्य पदों के विभिन्न प्रवर्गों पर भर्ती, अनुकंपा के आधार पर नियोजन, विभिन्न ग्रेडों के भर्ती नियमों को तैयार करना/ में संशोधन करना, संवेदनशील संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों के चरित्र और पूर्ववृत्त की दोबारा जांच, एएफएचक्यू सिविलियन कैडरों की कैडर समीक्षा/पुनर्गठन और वेतन आयोगों से संबंधित कार्यों आदि के लिए उत्तरदायी है।

(घ) **वित्त और सामग्री प्रभाग:** यह प्रभाग अंतर सेवा संगठनों को सामग्री संबंधी सहयोग प्रदान करता है जिसमें कार्यालय उपकरणों, भंडारों, फर्नीचर, लेखा सामग्रियों और सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की अधिप्राप्ति और प्रोवीजनिंग शामिल है।

(ड.) **संपदा और निर्माण कार्य प्रभाग:** यह प्रभाग सशस्त्र सेना मुख्यालयों में तैनात सेना अफसरों के रिहायशी आवासों के लिए सम्पदा संबंधी

कार्य करता है और रक्षा मुख्यालयों में प्रमुख निर्माण कार्यक्रमों का समन्वय करता है।

(च) **विभागीय अनुशासन, समन्वय और कल्याण प्रभाग:** यह प्रभाग एएफएचक्यू सिविलियन संवर्ग कर्मचारियों के अनुशासनिक मामलों को देखता है। इसके अतिरिक्त यह प्रभाग रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय के भीतर और संयुक्त सचिव (प्रशि.) और मु.प्र. अधिकारी के लिए समन्वय, राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामले, आफिस काउंसिल, महिला प्रकोष्ठ, खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यकलाप विभागीय कैंटीन, एएमए की नियुक्ति, रक्षा सिविलियन चिकित्सा सहायता निधि (डीसीएमएफ) आदि जैसे कल्याणकारी कार्यकलापों का भी संचालन करता है। ई-गवर्नेंस का कार्यान्वयन, इलेक्ट्रॉनिक डाटाप्रोसेसिंग और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय का लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) और वेबसाइट के रखरखाव से संबंधित मामले इस प्रभाग के क्षेत्र में आते हैं। रक्षा मंत्रालय (पुस्तकालय) के प्रशासन के साथ-साथ पुस्तकों के चयन और उनकी अधिप्राप्ति के लिए राष्ट्रीय रक्षा निधि अनुदान प्राप्त करने संबंधी कार्य/जवाबदेही और इस उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश जारी करने का कार्य भी इस प्रभाग को सौंपा गया है।

(छ) **रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण (डीएचटीआई):** सेना मुख्यालयों और अन्तर सेवा संगठनों में

तैनात सिविलियन कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के तत्वाधान में कार्यरत रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान देखता है। तीनों सेनाओं के अफसरों के लिए कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रमों का भी संचालन किया जाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान, सिविलियन और सेना कार्मिकों दोनों के लिए रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अपने परिसर में 139 पाठ्यक्रमों और विभिन्न फील्ड स्थापनाओं में 15 अतिरिक्त पाठ्यक्रमों का संचालन किया गया/किया जाना है।

**9.22 सुरक्षा कार्यालय:** सुरक्षा कार्यालय, रक्षा मंत्रालय सुरक्षा क्षेत्र के अंतर्गत वास्तविक सुरक्षा प्रदान करने, प्रवेश पर नियंत्रण करने, सुरक्षा भंग न होने देने और आग न लगने देने के लिए जिम्मेदार है।

## जनसम्पर्क निदेशालय

9.23 जनसम्पर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेनाओं तथा रक्षा मंत्रालय के अधीन अंतर - सेवा संगठनों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की महत्वपूर्ण घटनाओं, कार्यक्रमों, उपलब्धियों तथा मुख्य नीतिगत निर्णयों के बारे में मीडिया तथा जनता को सूचना प्रसारित करने के लिए एकमात्र प्राधिकृत एजेंसी है। इस निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके देश भर में 25 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो मीडिया सहायता एवं सेवाएं प्रदान करते हैं ताकि प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो सके। यह नियमित रूप से साक्षात्कार,

प्रेस कांफ्रेंस और प्रेस दौरे आयोजित करके नेतृत्व और रक्षा मंत्रालय तथा सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विनिमय को भी सुकर बनाता है।

9.24 गत वर्षों की भांति इस निदेशालय ने मीडिया के लोगों के लिए उनकी रक्षा विषयों के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए 19 अगस्त, 2012 से 18 सितंबर, 2013 तक रक्षा संवाददाता पाठ्यक्रम का आयोजन किया। संपूर्ण देश से 30 पत्रकारों, जिनमें 5 महिलाएं थीं, ने एक महीने तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम में भाग लिया।

9.25 यह निदेशालय सशस्त्र सेनाओं के लिए 13 भाषाओं में पाक्षिक पत्रिका 'सैनिक समाचार' प्रकाशित करता है। इस निदेशालय का प्रसारण अनुभाग सैनिकों के लिए 40 मिनट का कार्यक्रम तैयार करता है जिसका प्रसारण सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के लिए आकाशवाणी से प्रतिदिन किया जाता है। इसका फोटो अनुभाग रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण घटनाओं की फोटोकवरेज उपलब्ध कराता है। फोटो अनुभाग के फोटो अभिलेखागार को डिजीटाइजेशन करने का प्रयास किया जा रहा है।

9.26 यह निदेशालय गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़ी सभी मीडिया सुविधाओं का भी प्रबंध करता है एवं राजपथ पर परेड का आंखों देखा हाल प्रसारित करता है। निदेशालय द्वारा लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह, संयुक्त कमांडर्स कान्फ्रेंस एवं प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित एनसीसी रैली और



राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह जैसी महत्वपूर्ण सूचीबद्ध घटनाओं को भी यथोचित प्रचार किया गया ।

9.27 कोच्चि में भारत के प्रथम विमान वाहक आईएनएस विक्रान्त को लांच किए जाने का व्यापक प्रचार किया गया था। प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया दोनों की एक चालीस सदस्यीय प्रेस पार्टी को इस कवरेज के लिए कोच्चि ले जाया गया था ।

9.28 इस निदेशालय ने जून, 2013 में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिक बाढ़ के समय प्रभावित क्षेत्रों में मीडिया संचलनों का समन्वय करने तथा सुविधा प्रदान करने के लिए मोबाइल यूनिटों की स्थापना की । इसने कई मीडिया व्यक्तियों को देहरादून, केदारनाथ, गोचारंद और अन्य बुरी तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विमान से ले जाने में सहायता की ताकि वे अपने प्रथम अनुभवों के आधार पर सशस्त्र बलों द्वारा किए गए बड़े स्तर पर बचाव और राहत संक्रियाओं 'राहत' के बारे में रिपोर्ट दे सकें ।

9.29 नई दिल्ली में हुई थल, नौसेना, आन्तरिक सुरक्षा और रक्षा प्रणाली पर एक द्विवार्षिक प्रदर्शनी डीफैक्सपो इंडिया के 8वें संस्करण को डीपीआर ने उपयुक्त प्रचार-प्रसार प्रदान किया जिसमें 30 देशों की 624 कंपनियों ने भाग लिया ।

### **सेना क्रय संगठन (एपीओ)**

9.30 रक्षा मंत्रालय के सेना क्रय संगठन को रक्षा बलों के उपभोग के लिए सूखे राशन की अधिप्राप्ति

एवं समय पर विभिन्न प्रकार के फूड स्टफस की आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है । यह संगठन चावल व गेहूं भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीदता है और चीनी का आवंटन चीनी निदेशालय द्वारा विभिन्न चीनी मिलों को आवंटित लेवी कोटे में से किया जाता है । दालें, पशु, राशन, खाद्य तेल एवं वनस्पति एवं दुग्ध उत्पाद जैसे अन्य सामान केंद्रीय एवं राज्य सार्वजनिक उपक्रमों एवं राष्ट्रीय/राज्य स्तर के सहकारी उपभोक्ता/विपणन परिसंघों से खरीदे जाते हैं। मिल्क पाउडर, बटर और घी भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता डेयरी परिसंघ के सदस्यों से खरीदे जाते हैं । मिल्क पाउडर, बटर और घी भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता डेयरी परिसंघ के सदस्यों से खरीदे जाते हैं । चाय एवं डिब्बाबंद सामान जैसे सब्जियां, फल, जैम, दूध, मांस एवं मछली, काफी, अंडा पाउडर, रेडी टू ईट भोजन (एमआरई) आदि निजी पार्टियों सहित पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से खरीदे जाते हैं । सेना क्रय संगठन सशस्त्र सेनाओं के लिए ऐसे पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से रिटार्ट पाउच में सब्जियां व चिकन करी भी खरीदता है जिनके पास प्रौद्योगिकी होती है।

### **सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड**

9.31 सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड (एसएससीबी) तीनों सेनाओं में विभिन्न खेलकूद गतिविधियों का आयोजन एवं समन्वय करता है । एसएससीबी के तत्वाधान में 18 खेलों में चार टीमों (आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स) की अंतर-सैन्य चैंपियनशिप आयोजित की जाती है और राष्ट्रीय चैंपियनशिप/खेलों में भाग लेने के लिए सेनाओं की

टीम के चयन हेतु 12 खेलों के लिए ट्रायल आयोजित किए जाते हैं ।

9.32 सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड को स्पोर्ट्स अकादमी ऑफ एक्सेलेन्स की स्थापना और प्रबंधन के लिए 31

अगस्त, 2013 को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ ।

9.33 **राष्ट्रीय चैंपियनशिप:** इस वर्ष सेना ने लगभग सभी राष्ट्रीय चैंपियनशिपों में अपने वरिष्ठ खिलाड़ी दलों को शामिल किया, सेना टीमों ने फैसिंग, इक्वेस्ट्रियन, वाटर पोलों, ड्राइविंग, जिम्नास्टिक (आर्टिस्टिक), जिमनास्टिक (एक्रोबैटिक), जिमनास्टिक (ट्रमपोलाईन और टम्बलिंग), हैंडबाल, कुश्ती (ग्रीकोरोमन), टाइक्वॉ, एथलिटिक्स, क्वार्किंग और केनोडिंग, वुशु, रोइंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती और ताईक्वाडो क्रास कन्ट्री, कबड्डी और जूडो में उपविजेता रही। सेना ने लगातार दूसरे वर्ष, वर्ष 2013 की 67 वीं संतोष राष्ट्रीय फुटबाल चैंपियनशिप जीती ।

9.34 **मादक औषध सेवन पर नियंत्रण:** सेना खेलकूद से डोपिंग के खतरे को हटाने के लिए, सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड ने नेशनल एन्टी डोपिंग एजेंसी (एन ए डी ए) के साथ मिलकर अंतर सेवा स्तर पर एन्टी डोपिंग की शुरुआत की है ।

9.35 **सशस्त्र सेना खेलकूद औषध केन्द्र (ए एफ एस एम सी):-** गोरपडी, पुणे स्थित सशस्त्र सेना खेलकूद औषध केन्द्र सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड

**सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड को स्पोर्ट्स अकादमी ऑफ एक्सेलेन्स की स्थापना और प्रबंधन के लिए 31 अगस्त, 2013 को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ ।**

के अंतर्गत कार्य करता है जो सेना खिलाड़ियों को निष्पादन के लिए वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है । इस वर्ष तीनों सेनाओं के खिलाड़ियों के हित के लिए ए एफ एस एम सी द्वारा दो 'फिजिकल कंडीशनर' पाठ्यक्रम और एक

मसौर पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था । कुल 100 विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम में भाग लिया और सभी आवेदक इस पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हुए।

9.36 **सर्वोत्तम सेना खेलकूद टीम**

(क) सर्वोत्तम सेना टीम-सेना रेड टीम ने अंतर-सेना चैंपियनशिप में सर्वाधिक अंक हासिल किये जिसके लिए उसे रक्षा सेवा संपूर्ण चैंपियनशिप में सर्वाधिक अंक हासिल किये जिसके लिए उसे रक्षा सेवा संपूर्ण 'चैंपियनशिप ट्राफी' 2012-13 से नवाजा गया था ।

(ख) तीनों सेनाओं में से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिपों में प्रदर्शन के आधार पर उत्कृष्ट सेना खिलाड़ी का चयन किया जाता है । शूटर एम सी सी ओ-? ओमकार सिंह को 2 वर्ष 2012-13 के लिए 'उत्कृष्ट सेना खिलाड़ी' से नवाजा गया था ।

**सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो विभाग**

9.37 सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो विभाग (एएफएफपीडी) मूल रूप से सेना मुख्यालयों और

अन्य रक्षा संगठनों के प्रक्षेपण, प्रशिक्षण फिल्मों की अधिप्राप्ति और वितरण, फोटो निर्माण, कला कार्य इत्यादि के लिए उत्तरदायी है। रक्षा मंत्रालय के सभी समारोहों और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के फोटो और विडियोग्राफी का कार्य भी ए एफ एफ पी डी को सौंपा जाता है।

9.38 वर्तमान में, 27 प्रशिक्षण फिल्में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें 8 फिल्में 31 मार्च, 2014 तक पूर्ण हो जाएंगीं, 12 फिल्में पूर्व निर्माण तक और 7 फिल्में पूर्व-निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं। अधिकतर फिल्मों की अवधि लगभग से 30 से 40 मिनटों की है और जिन्हें हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रस्तुत किया जाता है।

9.39 ए एफ एफ पी डी के पास पुरानी फिल्मों और फोटो का बड़ा संग्रह है, बड़ी ऐतिहासिक महत्ता वाला ये सामान अंग्रेजों से विरासत में प्राप्त हुआ जो केन्द्रीय रक्षा फिल्म पुस्तकालय के इस प्रभाग द्वारा संरक्षण और अनुरक्षण किया जाता है। इन फिल्मों में द्वितीय विश्व युद्ध के विभिन्न मोर्चों पर और परेडों में, समारोहों में, वैयक्तिक और प्रशिक्षण कार्य-कलापों इत्यादि में भारतीय सेनाओं के फिल्मों का चित्रण है।

9.40 इस प्रभाग का केन्द्रीय रक्षा फिल्म पुस्तकालय (सी डी एफ एल) विभिन्न इकाइयों/निकायों/प्रशिक्षण स्थापनाओं/कमानों में उनकी विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए प्रशिक्षण फिल्मों के वितरण के लिए जवाबदेह है। इस वर्ष के दौरान सेना/नौसेना/वायुसेना की विभिन्न इकाइयों/निकायों को

200 डीवीडी जारी/लोन पर दी गई।

9.41 इस प्रभाग की चल सिनेमा इकाई (एम सी यू) दुर्गम क्षेत्रों के सैनिकों को वृत्त-चित्र फिल्मों/संस्कृति पर, पारिवारिक विकास पर न्यूज पत्रिकाओं और अन्य सम-सामयिक विषयों पर प्राप्ति/वितरण करता है। इस वर्ष के दौरान एल सी यू रक्षा स्थापनाओं को लगभग 64 सी डी/डी वी डी (16 विषयों पर) लोन आधार पर जारी कर चुका है।

## राष्ट्रीय रक्षा कालेज

9.42 राष्ट्रीय रक्षा कालेज रक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्था है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध-नीति शिक्षा का एक उत्कृष्ट केन्द्र है। इस कालेज में प्रशिक्षण के लिए भारतीय और विदेशी सशस्त्र बलों के ब्रिगेडियर/समकक्ष पदधारित तथा प्रशासनिक सेवा के निदेशक और उससे उच्च अफसर नामित किए जाते हैं। नामित अधिकारियों को ग्यारह माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मुख्य केन्द्र बिंदु राष्ट्रीय सुरक्षा होता है जिसमें सभी घरेलू क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के सभी आयाम शामिल होते हैं जिससे भावी नीति निर्धारकों को राष्ट्रीय रणनीति की योजना बनाने के लिए आवश्यक बहुविध आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य वैज्ञानिक और संगठनात्मक पहलुओं की व्यापक समझ प्राप्त करने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि मिल सके। पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन के कैम्पस, लेक्चर/पैनल विचार-विमर्श, युद्ध-नीतिक अभ्यास गेम, युद्ध क्षेत्र भ्रमण, अनुसंधान कार्यकलाप / थीसिस लिखना एवं सेमिनार सम्मिलित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के

लिए इस पाठ्यक्रम के लिए छह अध्ययन कैम्पसूल आयोजित किए जाते हैं ।

9.43 एनडीसी के 54 वें पाठ्यक्रम में कुल 100 अधिकारी समाविष्ट थे जिनमें सेना (40), नौसेना (6), वायुसेना (12), सिविल सेवा (16), मित्र देशों से (26) समाविष्ट थे। 11 महीनों का यह पाठ्यक्रम 6 जनवरी, 2014 को समाप्त हुआ ।

## विदेशी भाषा विद्यालय

9.44 विदेशी भाषा विद्यालय हमारे देश का एक ऐसा अनुपम संस्थान है जैसा और कहीं नहीं है जहां पर एक ही छत के नीचे बहुत सी विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हों । यह भारत में वर्ष 1948 से विदेशी भाषा पढ़ाने का एक अग्रणी संस्थान है । इस समय यह सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को 18 विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देने में संलग्न है । यह भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों, जैसे कि विदेश मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय, केन्द्रीय पुलिस संगठन अर्थात् बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी आदि की आवश्यकता की पूर्ति करता है । इसके अलावा सिविलियन विद्यार्थियों को भी प्रवीणता प्रमाण-पत्र उन्नत डिप्लोमा और दुभाषिया पाठ्यक्रमों में निर्धारित सरकारी नियमों के अनुसार प्रवेश दिया जाता है।

9.45 एसएफएल में अरबी, बहासा इंडोनेशिया, बर्मी चीनी, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, रूसी, स्पेनी, तिब्बती और सिंहाला विदेशी भाषाएं नियमित आधार पर तथा जापानी और थाई आदि अल्पकालिक पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाई जाती है ।

9.46 एसएफएल द्वारा प्रवीणता पाठ्यक्रम, उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दुभाषिया पाठ्यक्रम और अल्पकालिक पाठ्यक्रम/कैम्पसूल पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं ।

9.47 दुभाषिया पाठ्यक्रम एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है। इसके लिए सशस्त्र सेनाओं, रक्षा मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय और अन्य सरकारी विभागों द्वारा विद्यार्थी प्रायोजित किए जाते हैं। यह पाठ्यक्रम अपने विद्यार्थियों को दुभाषिए और अनुवाद के उच्च दक्षता कार्य में निपुणता प्रदान करता है । यह एक अत्यंत विशिष्ट पाठ्यक्रम है जिसके समान भारत में अन्यत्र कोई पाठ्यक्रम नहीं है । विदेशी भाषा विद्यालय में सिंहाली, भाषा, इंडोनेशिया, बर्मी, पश्तो, पाक उर्दू, थाई और तिब्बती जैसे सामरिक महत्व की भाषाएं राजनीतिक - सैन्य दृष्टिकोण से पढ़ाई जाती है ।

9.48 अल्पकालिक पाठ्यक्रम विशेषकर नामोदिष्ट सैन्य अताशे और संयुक्त राष्ट्र संघ मिशनों पर भेजे जा रहे अफसरों के लिए अथवा प्रयोक्ता संगठन की विशिष्ट जरूरत के अनुसार, आवश्यकतानुसार आयोजित किए जाते हैं ।

9.49 एसएफएल, अन्य रक्षा संस्थाओं, नामतः राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे और सेना शिक्षा कोर प्रशिक्षण केन्द्र एवं कालेज, पंचमढी का नियंत्रक संगठन है जहां विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती है । यह परीक्षाओं का आयोजन करता है और सफल उम्मीदवारों को डिप्लोमा भी जारी करता है । भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए इस संस्थान द्वारा आयोजित उन्नत डिप्लोमा परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है ।

9.50 वर्ष 2013-14 के दौरान एसएफएल ने विभिन्न देशों के लिए नामोदिष्ट डीए/एमए को संबंधित विदेशी भाषाओं अर्थात अरबी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और रूसी में प्रशिक्षण दिया ।

## इतिहास प्रभाग

9.51 पहले ऐतिहासिक अनुभाग के रूप में जाने वाले इतिहास प्रभाग की स्थापना 26 अक्टूबर, 1953 को स्वतंत्रता के समय से आज भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए सैन्य आपरेशनों के इतिहास को संकलित करने हेतु की गई थी । आज तक इसने जम्मू तथा कश्मीर में आपरेशनों का इतिहास 1947-48, आपरेशन पोला, आपरेशन विजय (गोवा), भारत के सैन्य परिधान, वीरता की कहानियां, 1965 का भारत पाक युद्ध एक इतिहास, आदि सहित 20 खंड संकलित व प्रकाशित किए हैं । इस प्रभाग ने द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 में भारतीय सशस्त्र सेना के आधिकारिक इतिहास को आठ खंडों में पुनर्मुद्रित भी किया है । संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना मिशनों में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा चलाए गए ऑपरेशनों को भी संकलित किया गया है और इनमें कांगों में संयुक्त राष्ट्र संघ ऑपरेशनों में भारतीय सशस्त्र सेनाओं का इतिहास, सीएफआई अथवा कोरिया में भारतीय सैनिक 1953-54, ऑपरेशन शांति (भारतीय सैनिक मिश्र में) और वृहत जिम्मेदारी (इंडो-चाइना में शांति के लिए लड़ाई) शामिल है । कुछ प्रकाशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किए गए हैं । इस समय, यह प्रभाग वीरता की कहानियां भाग III तथा भारत के युद्ध स्मारक शीर्षक वाली दो पुस्तकों पर काम कर रहा है।

9.52 इतिहास प्रभाग, रक्षा मंत्रालय और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अनुसंधान, अभिलेख और संदर्भ कार्यालय के रूप में भी कार्य करता है। इसे रक्षा मंत्रालय, तीनों सेना मुख्यालयों और विभिन्न यूनिटों से सैन्य मामलों से संबंधित विविध अभिलेख और संक्रियात्मक अभिलेख नियमित आधार पर संरक्षण तथा इस्तेमाल के लिए प्राप्त होते हैं । यह प्रभाग इस समय अभिलेखों का डिजीटाइजेशन करने में लगा हुआ है ।

9.53 इस प्रभाग का हेराल्डिक प्रकोष्ठ तीनों सेना मुख्यालयों और रक्षा मंत्रालय को समारोह संबंधी सभी मामलों जैसे नई स्थापनाओं के नामकरण और अधिग्रहण, बैजो और कलगियों का डिजाइन बनाने और स्मृति चिन्हों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है ।

9.54 विभागीय पुस्तकालय में कुछ दुर्लभ पुस्तकें, आवधिक पत्रिकाएं और सैन्य महत्व के विदेशी प्रकाशनों सहित पांच हजार से अधिक पुस्तकें हैं। पिछले एक वर्ष में पुस्तकालय में 600 और पुस्तकें आई हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों की उपलब्धता की जानकारी के लिए पुस्तक-सूची को डिजीटाइज करने का भी प्रयास किया जा रहा है ।

## रक्षा प्रबंधन कालेज (सीडीएम)

9.55 रक्षा प्रबंधन कालेज तीनों सेनाओं का एक प्रबंधन कालेज है जो तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों, अर्धसैनिक बलों रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को संकल्पनात्मक, निर्देशात्मक और कार्यात्मक रक्षा प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है। इसके साथ-साथ कालेज बहुतायत में सिविलियनों



और विदेशी शिष्टमंडलों को रक्षा प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करता है। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक 'उच्चतर रक्षा प्रबंधन' शिक्षा और 'सैन्य मामलों में क्रांति' की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, रक्षा प्रबंधन कालेज ने वर्तमान प्रशिक्षण अवसंरचना के प्रति आशीर्वाद है और प्रतिवर्ष में लगभग 500 अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। रक्षा प्रबंधन कालेज ने भारतीय सशस्त्र सेना के सभी स्तरों में पाठ्यक्रम/प्रबंधन शिक्षा के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपीएस) के तदानुकूल कैप्सूल भी विकसित किये हैं। ये प्रबंधन विकास कार्यक्रम बड़ी संख्या में मित्र देशों के साथ भी साझा किया जाता है। एक जनवरी, 2013 से 31 मार्च 2014 रक्षा प्रबंधन कालेज द्वारा एक उच्चतर रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम, दो वरिष्ठ रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम, दस प्रबंधन विकास कार्यक्रम और कई विदेशी कैप्सूल पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। एचडीएलसी के प्रतिभागियों को सेना मुख्यालय द्वारा एक प्रोजेक्ट पाठ्यक्रम भी प्रायोजित किया जाता है और पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने वालों को उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंध निष्णात (एमएमएस) की डिग्री प्रदान की जाती है।

## रक्षा सेवा स्टाफ कालेज

9.56 वेलिंग्टन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कालेज एक सशस्त्र सेना प्रशिक्षण संस्थान है जो तीनों सेनाओं और केन्द्रीय सिविल सेवाओं के चयनित अफसरों के लिए स्टाफ पाठ्यक्रम संचालित करता है। इसके अतिरिक्त, मित्र राष्ट्रों के रक्षा अधिकारियों को भी कालेज द्वारा संचालित स्टाफ कोर्स में शामिल किया जाता है। रक्षा सेवा स्टाफ कालेज से पास होने वाले अफसरों को

चेन्नई विश्वविद्यालय रक्षा और सामरिक अध्ययन में विज्ञान स्नातकोत्तर की उपाधि दी जाती है। तीनों सेनाओं के अफसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टाफ पाठ्यक्रम की क्षमता को चरणबद्ध ढंग से बढ़ाकर 500 करने हेतु सम्मिलित प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए योजनाबद्ध प्रशिक्षण अवसंरचनाएं पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। तथापि, विवाहित आवास परियोजना के लिए अफसरों को निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके वर्ष 2015 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इन सब बातों के होते हुए भी, विद्यमान अवसंरचनाओं का इष्टतम उपयोग करते हुए, चाले स्टाफ कोर्स (69 वां स्टाफ कोर्स) की संख्या बढ़ाकर 445 कर दी गई है जिसमें विदेशी मित्र राष्ट्रों के 32 अफसर शामिल हैं। रक्षा सेवा स्टाफ कालेज ने 'डीप ब्लू वार गेमिंग पैकेज फॉर एयर ऑप्स' और सैंड माडल रूमस के डिजीटाइजेशन के द्वारा प्रशिक्षण उपकरणों के आधुनिकीकरण में उल्लेखनीय प्रगति की है।

## रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय

9.57 रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय, तीनों सेना मुख्यालयों, अंतर सेवा संगठनों और अन्य सम्बद्ध रक्षा स्थापनाओं में योजना एवं नीति निर्धारण से संबंधित विषयों पर साहित्य उपलब्ध करवाता है। सामान्य पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा, इसे रक्षा तथा संबद्ध विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त है। वर्ष के दौरान इस पुस्तकालय ने 1725 पुस्तकें खरीदीं और 129 पत्रिकाएं/आवधिक पत्रिकाएं तथा 29 समाचार पत्र मंगवाएं।



## भर्ती एवं प्रशिक्षण



राष्ट्रीय नौसेना अकादमी में पासिंग आउट परेड

**संघ** लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी में प्रवेश के लिए वर्ष में दो बार प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है। उम्मीदवार 10+2 परीक्षा पास करने पर या 12वीं कक्षा में पढ़ते हुए प्रतियोगिता में बैठने के पात्र हैं।

10.1 सशस्त्र सेनाएं सेवा, बलिदान, देशभक्ति और हमारे देश की मिली-जुली संस्कृति का प्रतीक हैं। सशस्त्र सेनाओं में भर्ती स्वैच्छिक है और भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय का हो, सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के योग्य है बशर्ते कि वह निर्धारित शारीरिक, चिकित्सा और शैक्षिक मानदंडों पर खरा उतरता हो।

10.2 सशस्त्र सेनाओं में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अफसरों की भर्ती : सशस्त्र बलों में कमीशन प्राप्त अफसरों की भर्ती मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है जो इसके लिए निम्नलिखित दो अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करता है :

(क) **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) और नौसेना अकादमी (एन ए):** संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी में प्रवेश के लिए वर्ष में दो बार प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है। उम्मीदवार 10+2 परीक्षा पास करने पर या 12वीं कक्षा में पढ़ते हुए प्रतियोगिता में बैठने के पात्र हैं। संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात सफल उम्मीदवारों को सैन्य चयन बोर्ड (एस एस बी) द्वारा आयोजित पांच दिवसीय साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। चिकित्सीय

रूप से स्वस्थ पाए जाने एवं एन डी ए की मेरिट सूची में आने वाले सफल उम्मीदवार आवेदन के समय दिए गए विकल्प के अनुसार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अथवा नौसेना अकादमी में प्रवेश पाते हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण के लिए संबंधित सेना अकादमियों में भेजा जाता है।

(ख) **संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सी डी एस ई) :** संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष में दो बार किया जाता है। विश्वविद्यालयों के स्नातक अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले छात्र इस परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को एस एस बी साक्षात्कार एवं चिकित्सा जांच के लिए उपस्थित होना होता है। मेरिट लिस्ट में आने वाले उम्मीदवारों को स्थायी कमीशन के लिए भारतीय सैन्य अकादमी/वायुसेना अकादमी एवं नौसेना अकादमी में 18 महीने का आधारभूत सैन्य प्रशिक्षण एवं अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसर (एस एस सी ओ) बनने के लिए अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओ टी ए) में 11 महीने का सैन्य प्रशिक्षण लेना होता है। एस एस सी ओ 10 वर्ष की अवधि तक सेवा कर सकता है जिसे 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि वे 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर



स्थायी कमीशन के लिए अथवा 5 वर्ष की सेवा पूरी होने पर सेवा छोड़ने का विकल्प ले सकते हैं, जिस पर अलग-अलग मामले के आधार पर विचार किया जाता है।

## सेना

10.3 संघ लोक सेवा आयोग के जरिए प्रवेश के अलावा नीचे बताए तरीकों से भी सेना में कमीशन प्राप्त अफसरों की भर्ती की जाती है:-

(क) **10+2 तकनीकी प्रवेश योजना (टी ई एस) :** जिन उम्मीदवारों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में कुल मिलाकर न्यूनतम 70% अंकों के साथ सी बी एस ई/आई सी एस ई/राज्य बोर्ड की 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे 10+2 (टी ई एस) के तहत कमीशन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एस एस बी में सफल रहने तथा चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने पर वे प्रशिक्षण अकादमी (गया) में एक वर्ष का बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण लेते हैं और तत्पश्चात स्थायी कमीशन प्राप्त करने से पूर्व संबंधित शाखाओं में तीन वर्ष का इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। कमीशन प्रदान किए जाने के बाद उन्हें उस सेनांग/सेवा का एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें उन्हें कमीशन दिया गया है।

(ख) **विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) :-** अधिसूचित इंजीनियरी शाखाओं के अंतिम वर्ष से पूर्व के विद्यार्थी विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के तहत सेना के तकनीकी सेनांगों में कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र अभ्यर्थियों

को सेना मुख्यालय द्वारा तैनात स्क्रीनिंग टीमों द्वारा कैम्पस साक्षात्कार के जरिए चुना जाता है। इन अभ्यर्थियों को एस एस बी और मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना होता है। सफल अभ्यर्थियों को भारतीय सैन्य अकादमी (आई एम ए) देहरादून में एक वर्षीय कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण लेना होता है। इस प्रवेश के माध्यम से कमीशन मिलने पर कैडेट एक वर्ष की पूर्व-दिनांकित वरिष्ठता के भी हकदार होते हैं।

(ग) **तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) :** सेना शिक्षा कोर के लिए इंजीनियरी की अधिसूचित शाखा के इंजीनियरी ग्रेजुएट, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंक योग वाले पोस्ट ग्रेजुएट एवं कृषि/सैन्य फार्म के लिए डेयरी में एम एससी धारक उम्मीदवार इस प्रवेश के माध्यम से स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। एस एस बी और चिकित्सा बोर्ड के पश्चात अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को कमीशन प्रदान किए जाने से पूर्व भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में एक वर्ष का कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण लेना अपेक्षित है। इस प्रवेश के माध्यम से कमीशन मिलने पर कैडेट एक वर्ष की पूर्व-दिनांकित वरिष्ठता के हकदार होते हैं।

(घ) **अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी) प्रवेश :** अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी) प्रवेश योजना, पात्र तकनीकी स्नातकों/स्नातकोत्तरों को तकनीकी सेनांगों में भर्ती कराती है। एस एस बी और चिकित्सा बोर्ड के बाद अंतिम रूप से चुने गए अभ्यर्थियों को ओ टी ए, चेन्नई में 49 सप्ताह का कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण



पूरा होने पर उन्हें अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में प्रवेश दिया जाता है। इस प्रवेश के माध्यम से आए अभ्यर्थी भी कमीशन प्राप्त होने पर एक वर्ष की पूर्व-दिनांकित वरिष्ठता के हकदार हैं।

(च) **एन सी सी (विशेष प्रवेश योजना) :** न्यूनतम 'बी' ग्रेड का एन सी सी 'सी' प्रमाण-पत्र और स्नातक परीक्षा में 50% अंक पाने वाले विश्वविद्यालय स्नातक इस योजना के माध्यम से अल्प सेवा कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तृतीय वर्ष में पढ़ने वाले छात्र भी इस प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते उन्होंने पहले दो वर्षों में न्यूनतम 50% समग्र अंक प्राप्त किए हों। ऐसे उम्मीदवारों को साक्षात्कार में चयन होने की स्थिति में 50% समग्र अंक प्राप्त करने होंगे अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ओ टी ए में प्रवेश लेने के समय उम्मीदवारों के पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए अथवा तृतीय वर्ष में पढ़ रहे छात्रों को ओ टी ए में प्रशिक्षण आरंभ होने की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर डिग्री प्रस्तुत करनी होगी। इन कैडेटों को एस एस बी द्वारा अयोजित साक्षात्कार के पश्चात मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच के लिए बुलाया जाता है। योग्यता संबंधी अपेक्षाएं पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य स्तर पर एन सी सी ग्रुप मुख्यालयों के माध्यम से आवेदन करना होता है। संबंधित ग्रुप मुख्यालयों द्वारा स्क्रीनिंग के बाद एन सी सी महानिदेशालय योग्य कैडेटों के आवेदन पत्र रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय स्थित भर्ती निदेशालय को भेजता है।

(छ) **जज एडवोकेट जनरल प्रवेश :** एल एल बी में न्यूनतम 55% कुल अंकों सहित विधि स्नातक और 21 से 27 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्ति जज एडवोकेट जनरल शाखा के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र उम्मीदवारों को सीधे ही सेवा चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और तत्पश्चात् उनकी चिकित्सा जांच की जाती है। यह एक अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रवेश है जिसमें योग्य उम्मीदवार बाद में स्थायी कमीशन का चुनाव कर सकते हैं।

(ज) **अल्पकालिक सेवा कमीशन (महिला) :** पात्र महिला उम्मीदवारों को महिला विशेष प्रवेश योजना के माध्यम से सेना में अल्प सेवा कमीशन अफसर के रूप में भर्ती किया जाता है। वैद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर कोर, इंजीनियर्स, सिग्नल, सेना शिक्षा कोर, सेना आयुध कोर, सेना आपूर्ति कोर, सैन्य आसूचना कोर, जज एडवोकेट जनरल शाखा और सेना वायु रक्षा में कमीशन प्रदान किया जाता है। महिलाओं को तीन क्षेत्रों (स्ट्रीम) अर्थात् गैर-तकनीकी स्नातक, तकनीकी और स्नातकोत्तर/विशेषज्ञ में दस वर्ष की अवधि के लिए अल्प सेवा कमीशन की पेशकश की जाती है, जिसे पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर और चार वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में भारत सरकार ने महिला अफसरों को 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सेना शिक्षा कोर एवं जज एडवोकेट जनरल शाखा में स्थायी कमीशन का विकल्प प्रदान किया है। अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि 49 सप्ताह है। अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला (तकनीकी)

प्रविष्टि के लिए अधिसूचित शाखाओं में बी ई/बी टेक के उत्तीर्ण अथवा अंतिम वर्ष/सेमेस्टर के छात्र आवेदन करने के पात्र हैं। इसके पश्चात सीधे एस एस बी साक्षात्कार एवं चिकित्सा जांच होती है। हालांकि गैर-तकनीकी स्नातक शाखाओं के लिए आवेदकों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से आवेदन करना अपेक्षित है और लिखित परीक्षा के बाद एस एस बी साक्षात्कार के लिए आना होता है जैसा कि अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त पुरुष अफसरों के मामले में किया जा रहा है। गैर-तकनीकी शाखा की 20% आबंटित सीटें एन सी सी 'सी' प्रमाणपत्र धारित उन महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं जिन्होंने स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 'बी' ग्रेड एवं 50% अंक योग प्राप्त किया हो। आवेदन एन सी सी निदेशालय, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) के माध्यम से भेजे जाएंगे जैसा कि पुरुष अफसरों के मामलों में किया जा रहा है। जज एडवोकेट जनरल शाखा के लिए न्यूनतम 55% अंक प्राप्त करने वाले विधि स्नातकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जिन्हें सीधे एस एस बी साक्षात्कार के लिए भेजा जाता है। सेवा कार्मिकों की जो विधवाएं पात्रता संबंधी निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं, वे आयु में 4 वर्ष की छूट के लिए पात्र हैं और उनके लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में 5% (तकनीकी और गैर-तकनीकी, प्रत्येक शाखा में 2.5%) सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला (तकनीकी), एन सी सी प्रविष्टि

एवं जज एडवोकेट जनरल शाखाओं के लिए लिखित परीक्षाओं से छूट है और इनके लिए सीधे अतिरिक्त भर्ती महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) को आवेदन करना होगा। अधिसूचना एस एस सी डब्ल्यू (तकनीकी) के साथ वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाएगी।

(झ) **सैन्य प्रवेश :** जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर एवं अन्य रैंकों (जे सी ओ एवं ओ आर) की अफसर संवर्ग में भर्ती सेना चयन बोर्ड के माध्यम से निम्नलिखित तरीके से की जाती है :-

- (i) **सेना कैडेट कॉलेज (ए सी सी) प्रवेश:** 10+2 परीक्षा पास किए हुए 20-27 वर्ष के आयु वर्ग में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके पात्र अन्य रैंक (ओ आर) नियमित कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों की एस एस बी और चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्क्रीनिंग होती है। सफल उम्मीदवारों को सेना कैडेट कॉलेज विंग, देहरादून में तीन वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसकी समाप्ति पर उन्हें स्नातक डिग्री मिलती है। इसके बाद आई एम ए देहरादून में एक वर्ष का कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है।
- (ii) **विशेष कमीशन प्राप्त अफसर प्रवेश (एस सी ओ) योजना :** इस प्रवेश योजना के तहत सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र प्राप्त (कक्षा

10+2 पैटर्न) 30-35 वर्ष आयु समूह के जे सी ओ/एन सी ओ/अन्य रैंक एस एस बी और चिकित्सा बोर्ड की स्क्रीनिंग के बाद कमीशन के लिए पात्र हैं। उन्हें ओ टी ए, गया में एक वर्ष का कमीशन पूर्व प्रशिक्षण लेना होता है। मूल पदोन्नति एवं कार्यकारी पदोन्नति के नियम नियमित अफसरों की भांति ही हैं। इन अफसरों को यूनिटों में सब यूनिट कमांडर/क्वार्टर मास्टर और विभिन्न अतिरिक्त रेजिमेंट ल रोजगार नियुक्तियों में मेजर रैंक तक के पदों पर नियुक्त किया जाता है। ये अफसर लगभग 20-25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 57 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। इस योजना से न केवल जे सी ओ/एन सी ओ/अन्य रैंक की कैरियर संभावनाओं में सुधार होता है बल्कि सेना में अफसरों की कमी को पूरा करने में भी काफी हद तक सहायता मिलती है।

(iii) **स्थायी कमीशन (विशेष सूची) (पी सी एस एल) :-** इस प्रवेश के अंतर्गत 42 वर्ष तक की आयु एवं न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र (10+2 पद्धति) पास जे सी ओ/एन सी ओ/अन्य रैंक के कार्मिक एस एस बी एवं चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्क्रीनिंग के बाद कमीशन के पात्र होते हैं। आई एम ए में चार सप्ताह का अनुकूलन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें स्थायी

कमीशन (विशेष सूची) प्रदान किया जाता है।

10.4 भर्ती : वर्ष 2013 के दौरान अफसर के रूप में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती का ब्यौरा नीचे सारणी सं. 10.1 में दिया गया है।

**सारणी 10.1**

क्रम सं.	एकादमी	एंट्री	प्रवेश
1.	एन डी ए	सेना	617
		नौसेना	120
		वायुसेना	211
		<b>कुल</b>	<b>948</b>
2.	आई एम ए	आई एम ए (डी ई)	487
		ए सी सी	168
		एस सी ओ	124
		पी सी (एस एल)	55
		<b>कुल</b>	<b>834</b>
3.	ओ टी ए	एस एस सी (एन टी)	181
		एस एस सी डब्ल्यू (एन टी)	46
		एस एस सी डब्ल्यू (टी)	37
		एन सी सी	84
		एन सी सी (डब्ल्यू)	12
		जी ए जी	14
		जी ए जी (डब्ल्यू)	6
		<b>कुल</b>	<b>380</b>
4.	तकनीकी प्रविष्टियां	यू ई एस	83
		एस एस सी (टी)	149
		10+2 टी ई एस	347
		टी जी सी	288
		<b>कुल</b>	<b>867</b>
		<b>कुल योग</b>	<b>3029</b>

10.5 चयन केंद्र, उत्तर की स्थापना : सरकार की मंजूरी से रोपड़ (पंजाब) में चयन केंद्र, उत्तर के अधीन दो सेवा चयन बोर्ड (एस एस बी) की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

10.6 जूनियर कमीशनप्राप्त अफसर एवं अन्य रैंक (जे सी ओ/ओ आर) की भर्ती : सेना में ग्यारह जोनल भर्ती कार्यालय, दो गोरखा भर्ती डिपो, एक स्वतंत्र भर्ती कार्यालय एवं 59 सेना भर्ती कार्यालय हैं और इसके अलावा 47 रेजीमेंटल केन्द्र भी हैं जो अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में रैलियों के माध्यम से भर्ती करते हैं। सेना में जे सी ओ/ओ आर की भर्ती खुली रैली प्रणाली के माध्यम से की जाती है। जे सी ओ/ओ आर की भर्ती के लिए पहले रैली स्थल पर उम्मीदवारों की प्रारंभिक परीक्षा, संबंधित दस्तावेजों की जाँच, शारीरिक योग्यता की परख, शारीरिक माप एवं चिकित्सा जांच की जाती है। इसके बाद हर प्रकार से पात्र उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा ली जाती है। अंतिम तौर पर चुने गए सफल उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए संबंधित प्रशिक्षण केन्द्रों पर भेजा जाता है। एक भर्ती वर्ष में देश के प्रत्येक जिले को वर्ष में एक बार अवश्य कवर करने के प्रयास किए जाते हैं।

10.7 भर्ती रैलियां: भर्ती वर्ष के दौरान, 122 भर्ती रैलियां आयोजित की गई थीं जिसमें 54,146 उम्मीदवारों को 25 मार्च 2014 तक भर्ती किया गया।

भर्ती वर्ष के दौरान, 122 भर्ती रैलियां आयोजित की गई थीं जिसमें 54,146 उम्मीदवारों को 25 मार्च 2014 तक भर्ती किया गया।

उपद्रव वाले क्षेत्रों में आयोजित 14 रैलियों, जिसमें कुल 3221 रंगरूटों की भर्ती हुई, समेत अल्प विकसित क्षेत्रों में भी रैलियों का आयोजन किया गया।

#### 10.8 कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा (सी बी ई टी):

(क) आरंभ में नर्सिंग सहायक (एन ए) ट्रेड कॉमन प्रवेश परीक्षा (सी ई ई) के लिए पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा का स्थान लेने के लिए विकसित सी बी ई टी सॉफ्टवेयर का सभी भर्ती मुख्यालय क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। सी बी ई टी के फायदे इस प्रकार हैं:-

- (i) संपूर्ण पारदर्शिता
- (ii) प्रयोक्ता अनुकूलता
- (iii) अफसरों के पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन बोर्ड की जरूरत नहीं होती जिससे मूल्यावान जनशक्ति की बचत होती है।
- (iv) छद्मवेशधारण को रोकती है।
- (v) तुरंत परिणाम देती है।
- (vi) सूचना का अधिकार (आर टी आई) अधिनियम का अनुपालन करने वाली

ख) सी बी ई टी प्रयोगशाला की वर्तमान प्रगति: वर्तमान में सैनिक नर्सिंग सहायक श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने के लिए 11 सी बी ई टी प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं।

**10.9 सैन्य अस्पतालों व रेजिमेंटल केन्द्रों पर बायो-मिट्रिक प्रणाली लगाया जाना :** सैन्य अस्पताल व रेजिमेंटल केन्द्र, छद्मवेशधारण व फर्जी भर्ती को रोकने की दृष्टि से सै अ व रै के ऑटोमेशन के लिए प्रमुख लिंक है। इसके अंतर्गत इन्टरनेट सुविधा से लैस टर्मिनलों की स्थापना और बायो-मिट्रिक यंत्र लगाया जाना सम्मिलित है। सभी सैन्य अस्पतालों और रेजिमेंटल केन्द्रों में बायो-मिट्रिक यंत्र लगाए जाने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं।

## नौसेना

**10.10 नौसेना में भर्ती सभी नए एवं मौजूदा पोतों, पनडुब्बियों, विमानों एवं तटीय स्थापनाओं को अनुकूलतम स्तर पर प्रभावशाली ढंग से जनशक्ति तैनात करने की जरूरत के आधार पर की जाती है।** नौसेना में भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। भर्ती किए गए कार्मिकों की संख्या पात्र आवेदकों (पुरुष और महिला) जो लिखित परीक्षा, सेवा चयन बोर्ड (एस एस बी) साक्षात्कार, डॉक्टरी जांच में उत्तीर्ण हो सकें और योग्यता-सूची में उनकी सापेक्ष स्थिति पर निर्भर होती है। लिंग/धर्म/जाति/पंथ के आधार पर भर्ती में अथवा अन्य किसी समय कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

## भारतीय नौसेना में अफसरों की भर्ती

**10.11 भर्ती का तरीका :** भारतीय नौसेना की भर्ती प्रणाली सुव्यवस्थित, पारदर्शी, द्रुत और उम्मीदवारों के अनुकूल प्रक्रिया है। भारतीय नौसेना में भर्ती दो तरीकों

से की जाती है, अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग भर्ती और संघ लोक सेवा आयोग के अलावा भर्ती :

(क) **संघ लोक सेवा आयोग भर्ती:** संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) और भारतीय नौसेना अकादमी (आई एन ए) में स्थायी कमीशन (पी सी) अफसरों के रूप में भर्ती के लिए वर्ष में दो बार एक परीक्षा का आयोजन करता है। 10+2 (पी सी एम) परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अथवा 12वीं कक्षा में पढ़ रहे उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के पात्र होते हैं। लिखित परीक्षा के बाद संघ लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों की छंटाई करता है। इसके उपरांत उम्मीदवारों को बेंगलूर, भोपाल और कोयम्बटूर में स्थित सेवा चयन बोर्डों के पास भेजा जाता है। अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों के परिणाम संघ लोक सेवा आयोग को अंतिम मेरिट-सूची तैयार करने हेतु भेजे जाते हैं। मेडिकल रूप से फिट अर्हक उम्मीदवारों को मेरिट-सूची के आधार पर एन डी ए/आई एन ए में नियुक्ति के लिए सूचित किया जाता है। एन डी ए/आई एन ए में प्रशिक्षण पूरा होने पर नौसेना कैडेटों को नौसेना समुद्री प्रशिक्षण के लिए कोच्चि में प्रशिक्षण पोतों पर भेजा जाता है। स्नातक विशेष भर्ती योजना के लिए संघ लोक सेवा आयोग वर्ष में दो बार संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सी डी एस ई) का आयोजन करता है। बी टेक डिग्री स्नातक भी इस परीक्षा में बैठने के पात्र होते हैं। सफल उम्मीदवारों को नौसेना अनुकूलन पाठ्यक्रम (एन ओ सी) के लिए केरल के एझिमाला में स्थित भारतीय नौसेना अकादमी में शामिल किया जाता है।



- (ख) **संघ लोक सेवा आयोग के अलावा भर्ती:** गैर-यू पी एस सी प्रवेश के माध्यम से की जाने वाली भर्तियां स्थायी कमीशन (पी सी) और अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस एस सी) दोनों के लिए होती हैं। इस प्रकार की भर्तियों के लिए रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (नौसेना) में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तथा उनकी छंटाई की जाती है। तत्पश्चात छंटे गए उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए भेजा जाता है। उसके बाद रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों की एक मेरिट सूची बनाई जाती है। नौसेना की निम्नलिखित शाखाओं/संवर्गों के लिए सेवा चयन बोर्डों के साक्षात्कारों के माध्यम से गैर-यू पी एस सी भर्ती की जाती है।
- (i) **एग्जीक्यूटिव:** विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) के माध्यम से अल्पकालिक सेवा कमीशन एवं कार्यपालक (जी एस)/हवाई यातायात नियंत्रण/कानून/संभारिकी/नौसैनिक अस्त्र निरीक्षणालय (एन ए आई)/जल संवर्गों/पायलट/प्रेक्षक के लिए अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस एस सी) योजनाएं एवं संभारिकी/कानून/एन ए आई संवर्गों के लिए स्थायी कमीशन।
- (ii) **इंजीनियरी (नौसेना वास्तुकारों सहित):** विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के माध्यम से अल्प सेवा कमीशन विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस), विशेष नौसेना वास्तुकार प्रवेश योजना (एस एन ए ई एस) और एस एस सी (ई) योजनाओं के माध्यम से है। स्थायी कमीशन 10+2 (कैडेट प्रवेश योजना) के माध्यम से है।
- (iii) **वैद्युत इंजीनियरी:** विश्वविद्यालय प्रवेश योजना और एस एस सी (एल) योजनाओं के माध्यम से अल्प सेवा कमीशन तथा 10+2 (कैडेट प्रवेश योजना) योजना के माध्यम से स्थायी कमीशन में प्रवेश।
- (iv) **शिक्षा शाखा :** इस शाखा के लिए स्थायी कमीशन और अल्प सेवा कमीशन योजनाएं मौजूद हैं।
- (ग) **10+2 (कैडेट प्रवेश योजना):** यह योजना भारतीय नौसेना की कार्यपालक, इंजीनियरी और वैद्युत शाखाओं में स्थायी कमीशन के लिए है। इस योजना के तहत 10+2 (पी सी एम) अर्हताप्राप्त उम्मीदवार सेना चयन बोर्ड के माध्यम से चुने जाने के पश्चात बी टेक पाठ्यक्रम के लिए भारतीय नौसेना अकादमी में भेजे जाते हैं। इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें भारतीय नौसेना में कार्यपालक, वैद्युत और इंजीनियरी शाखाओं में स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है।
- (घ) **विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस):** अगस्त 2005 से यू ई एस अल्पकालिक सेवा कमीशन के रूप में पुनरारम्भ की गई है। सातवें और आठवें सेमेस्टर के इंजीनियरी छात्र नौसेना की एग्जीक्यूटिव एवं तकनीकी शाखाओं में प्रवेश के पात्र हैं। एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) और कमान मुख्यालयों से नौसेना चयन दल उम्मीदवारों को छंटने के लिए पूरे देश में ए आई सी टी ई द्वारा अनुमोदित इंजीनियरी कॉलेजों का दौरा करते हैं। अखिल भारतीय मैरिट के आधार पर छंटे गए उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। इसके पश्चात सफल उम्मीदवारों की

डाक्टरी जांच की जाती है। अंतिम चयन, सेवा चयन बोर्ड साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अखिल भारतीय मेरिट के आधार पर होता है।

**10.12 महिला अधिकारी:** नौसेना की एग्जीक्यूटिव शाखा (पर्यवेक्षक, ए टी सी, विधि 7 संभारिकी), शिक्षा शाखा एवं इंजीनियरी शाखा के नौसेना वास्तुकला संवर्ग में अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस एस सी) अधिकारी के रूप में महिलाओं का प्रवेश हो रहा है।

**10.13 एस एस अधिकारियों को स्थायी कमीशन:** रक्षा मंत्रालय ने एग्जीक्यूटिव शाखा (विधि संवर्ग), शिक्षा शाखा एवं इंजीनियरी शाखा (नौसेना वास्तुकला) के अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारियों, पुरुषों तथा महिलाओं दोनों को स्थायी कमीशन प्रदान करना आरंभ किया है।

**10.14 एन सी सी के माध्यम से भर्ती:** न्यूनतम 'बी' ग्रेडिंग सहित स्नातक डिग्री परीक्षा में 50% अंक वाले एन सी सी 'सी' प्रमाण-पत्र धारक विश्वविद्यालय स्नातकों को नौसेना में नियमित कमीशन प्राप्त अफसरों के रूप में भर्ती किया जाता है। इन स्नातकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा में बैठने से छूट दी गई है और उनका चयन केवल एस एस बी साक्षात्कार के माध्यम से ही किया जाता है। वे सी डी एस ई कैडेटों के साथ ही नौसेना अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम (एन ओ सी) के लिए नौसेना अकादमी में प्रवेश लेते हैं।

**10.15 विशेष नौसेना वास्तु-शिल्प प्रवेश योजना:** सरकार ने हाल ही में 'विशेष नौसेना वास्तुकार प्रवेश योजना' (एस एन ई ए एस) के तहत भारतीय नौसेना

में अल्प सेवा कमीशन अफसरों के रूप में नौसेना वास्तुकार अफसरों को भर्ती किए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। नौसेना को शक्ति प्राप्त दल आई आई टी खड़गपुर, आई आई टी चेन्नई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कोचिन (सी यू एस ए टी) और आंध्र विश्वविद्यालय, जिनमें बी टेक (नौसेना वास्तुशिल्प) पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है, के कैम्पस साक्षात्कारों के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन करने हेतु दौरा करता है। चुने हुए उम्मीदवारों की निकटतम मिलिटरी अस्पताल में मेडिकल जांच की जाती है और उपयुक्त पाए जाने पर प्रशिक्षण के लिए उनका चयन किया जाता है।

## नाविकों की भर्ती

**10.16 भर्ती का तरीका:** नौसेना में भर्ती उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार 'भर्ती योग्य पात्र पुरुष आबादी की राज्यवार मेरिट पर अखिल भारतीय आधार पर' की जाती है। राज्य विशेष से भर्ती हुए कार्मिकों की संख्या उन पात्र उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर होती है जो लिखित परीक्षा, शारीरिक फिटनेस टेस्ट और डॉक्टरी जांच तथा मेरिट में उनकी अपनी-अपनी स्थिति के अनुरूप होती है। जाति/पंथ अथवा धर्म के आधार पर रिक्तियों का कोई कोटा नहीं होता है। पात्र वालंटियर्स से आवेदन-पत्र मंगवाने हेतु सभी प्रमुख राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार-पत्रों और रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित किये जाते हैं। बहुत से स्कूलों/कॉलेजों और जिला सैनिक बोर्डों में भी प्रचार सामग्री भेजी जाती है। स्थानीय प्रशासन ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान चलाता है।

10.17 **भर्ती की किरमैं:** नाविकों की भर्ती के लिए विभिन्न प्रविष्टियां इस प्रकार हैं (प्रत्येक प्रविष्टि के सामने दर्शाई गई शैक्षिक योग्यताओं के साथ) :-

- (क) आर्टिफिसर अप्रेंटिस (ए ए) - 10+2 (पी सी एम)
- (ख) सीनियर सैकेन्डरी रंगरूट (एस एस आर) - 10+2 (साइंस)
- (ग) मैट्रिक भर्ती रंगरूट (एम आर)-रसोइया स्टीवार्ड एवं संगीतकार की भर्ती के लिए मैट्रिकुलेशन
- (घ) गैर-मैट्रिक रंगरूट (एन एम आर), टोपास नौसैनिकों (सफाईवाला) की भर्ती के लिए-कक्षा VI
- (च) सीधी भर्ती (उत्कृष्ट खिलाड़ी)



चिलका में प्राथमिक नौसेना नाविक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण

## भारतीय वायुसेना अफसरों की भर्ती

10.18 भारतीय वायुसेना में अफसरों के चयन की नीति पूरी तरह मेरिट पर आधारित है और सभी भारतीय नागरिक इसमें भाग ले सकते हैं। प्रौद्योगिकी आधारित

सेना होने के नाते भारतीय वायुसेना कार्मिकों की भर्ती के लिए अपने उच्च मानकों को बरकरार रखती है।

10.19 **अफसरों का प्रवेश :** संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) और संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सी डी एस ई) प्रविष्टियां अफसर संवर्ग के लिए प्रमुख फीडर हैं। अफसर संवर्ग में गैर-संघ लोक सेवा आयोग प्रविष्टियां हैं: अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस एस सी) (पुरुष एवं महिला) उड़ान, एन सी सी भर्ती (पुरुषों के लिए स्थायी कमीशन), ग्राउंड ड्यूटी अफसर (जी डी ओ सी) (गैर-तकनीकी), (पुरुषों के लिए स्थायी कमीशन), एयरमैन भर्ती (एयर वॉरियर्स के लिए स्थायी कमीशन), अल्पकालिक सेवा कमीशन (तकनीकी) (पुरुष और महिला), और अल्पकालिक सेवा कमीशन (गैर तकनीकी) (पुरुष एवं महिला)।

10.20 **सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती :** भारतीय वायुसेना में उड़ान शाखा (पायलट), वैमानिकी इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स), वैमानिकी इंजीनियरिंग (यांत्रिकी), शिक्षा, प्रशासन, संचारिकी, लेखा एवं



उड़ान प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षु पायलट कैडेटों में प्रतिभा को निखारते हैं।

मौसम विज्ञान शाखाओं के लिए भर्ती सेवा चयन बोर्डों/वायुसेना चयन बोर्डों के माध्यम से की जाती है।

#### 10.21 विश्वविद्यालय प्रवेश

**योजना:** इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में अंतिम / अंतिम वर्ष से पूर्व वर्ष के विद्यार्थी विश्वविद्यालय प्रवेश

योजना के अंतर्गत वायुसेना की तकनीकी शाखाओं में स्थायी कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में भर्ती होने के पात्र हैं।

**10.22 सेवा प्रविष्टि योजना:** इस प्रवेश के अंतर्गत न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा (तकनीकी एवं गैर तकनीकी ट्रेड) पूरी कर चुके 36-42 वर्ष आयु वर्ग वाले सार्जेंट एवं उससे ऊपर के रैंक वाले सेवारत कार्मिक, जिनकी न्यूनतम शिक्षा योग्यता 10+2 है, यूनिट स्तर पर स्क्रीनिंग के पश्चात वायुसेना चयन बोर्ड परीक्षा एवं चिकित्सा जांच किए जाने पर कमीशन के पात्र हैं। तकनीकी ट्रेडों के सैन्य कार्मिकों को तकनीकी शाखा में भर्ती किया जाता है एवं गैर-तकनीकी ट्रेडों के कार्मिकों को ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में भर्ती किया जाता है।

**10.23 महिला अफसरों की भर्ती:** पात्र महिलाओं को भारतीय वायुसेना की उड़ान, वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिक्स), वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी), शिक्षा, प्रशासन, संभारिकी, लेखा और मौसम विज्ञान शाखाओं में अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अफसरों के रूप में भर्ती किया जाता है।

भारतीय वायुसेना की करियर वेबसाइट [www.careerairforce.nic.in](http://www.careerairforce.nic.in) को जून 2012 से एक सक्रिय वेबसाइट के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है ताकि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकें। यह वेबसाइट 2013-14 में सरकारी वेबसाइटों में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली 20 वेबसाइटों में शामिल है।

**10.24 राष्ट्रीय कैडेट कोर के माध्यम से भर्ती:** न्यूनतम 'बी' ग्रेडिंग के एन सी सी 'ग' प्रमाणपत्र धारक एवं स्नातक स्तर पर 50% अंक प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय स्नातकों को सेवा चयन बोर्डों के माध्यम से चयन करके भारतीय नौसेना एवं वायुसेना में नियमित

कमीशनप्राप्त अफसरों के रूप में भर्ती किया जाता है।

**10.25 भारतीय वायुसेना की करियर वेबसाइट [www.careerairforce.nic.in](http://www.careerairforce.nic.in) को जून 2012 से एक सक्रिय वेबसाइट के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है ताकि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकें। यह वेबसाइट 2013-14 में सरकारी वेबसाइटों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले 20 वेबसाइटों में शामिल है। वायुसेना सामान्य प्रवेश परीक्षा (ए एफ सी ए टी) चक्र 02/2013 के लिए कुल 1,46,462 आवेदन जमा किए गए थे।**

**10.26 नए वायु सेना चयन बोर्डों (ए एफ एस बी) की स्थापना:** भारतीय वायुसेना के लिए दो अतिरिक्त ए एफ एस बी हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

**10.27 एयरमैन की भर्ती:** भारतीय वायुसेना के एयरमैन संवर्ग में अनुसूचित चयन परीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय मैरिट आधार पर भर्ती की जाती है। जाति, पंत, धर्म या समुदाय के भेदभाव बिना देश के अर्हता प्राप्त सभी नागरिकों का इस परीक्षा में स्वागत है। अनुसूचित परीक्षा के अतिरिक्त दूरदराज स्थित क्षेत्रों/कम आवेदन वाले क्षेत्रों/सीमावर्ती क्षेत्रों/

विद्रोहग्रस्त एवं पहाड़ी तथा देश के द्वितीय क्षेत्रों के युवाओं को एयरमैन के रूप में भारतीय वायुसेना में नियुक्ति का अवसर प्रदान करने के लिए भर्ती रैलियां आयोजित की जाती हैं।

**10.28 सिविलियनों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण :-** भारतीय वायुसेना सिविलियन एक बहुत बड़ा कार्यबल है एवं भारतीय वायुसेना के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों/लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायुसेना में नियुक्त सिविलियनों के लिए अभी तक प्रवेश प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी, इसी लिए भारतीय वायुसेना में नियुक्ति होने वाले सिविलियन क्लर्कों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। इनको भारतीय वायुसेना एवं सिविल प्रशासन के सूक्ष्म भेदों से परिचित कराना एवं उनके कौशल को बढ़ाना तथा उनके भीतर पेशेवर होने की भावना जगाना इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है। इस पाठ्यक्रम को भारतीय वायुसेना मुख्यालय प्रशिक्षण कमांड के संरक्षण में जलाहली वायुसेना स्टेशन के अधीन संचालित किया जाएगा।

**10.29 भारतीय वायुसेना के वायुसेना अधिकारियों के लिए कैप्सूल पाठ्यक्रम :** सिविल प्रशासन में प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात होने वाले वायुसेना अधिकारी के लिए सिविल प्रशासन पर कैप्सूल पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। अधिकारियों को आचरण नियमावली, अनुशासनत्मक कार्यवाही, अदालतों/कैट के मामलों की देखरेख, वेतन संरचना एवं एम ए सी पी, शास्ति का अर्थिक प्रभाव, छुट्टी नियमावली एवं जे सी एम से संबंधित मामलों की जानकारी देना इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। अधिकारियों ने इस पाठ्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। इस प्रकार के तीन कार्यक्रम वार्षिक रूप में संचालित किए जाते हैं।

**10.30 बेसिक ट्रेनर विमान पीसी-7 एम के-II को शामिल करना :** भारतीय वायुसेना में पिलाटस पी सी-7 एम के-II के शामिल किए जाने के साथ ही उड़ान प्रशिक्षण पैटर्न ने एक नया प्रतिमान हासिल कर लिया है। बेसिक ट्रेनर विमान ने अपनी कार्य पद्धति तथा विकसित ऑनबोर्ड एविऑनिक्स तथा नेविगेशन प्रणाली से प्रशिक्षण की दिशा को बदल कर रख दिया है। बेसिक ट्रेनर विमान के रूप में यह विमान, लड़ाकू, परिवहन अथवा हेलिकाप्टर समेत सभी क्षेत्रों के भावी पायलटों के लिए एक ठोस आधार बनेगा।

**10.31 करियर संभावना में सुधार :** विभिन्न सेवाकालीन कोर्सों में अफसरों के निष्पादन में योग्यता को बढ़ावा देने के लिए प्लेसमेंट / नियुक्तियों के लिए योग्यता आधारित चयन के दौरान पाठ्यक्रमों में अधिकारियों के निष्पादन को उचित महत्व दिया जाता है। इससे अधिकारियों के व्यवसायिक सैन्य शिक्षा (पी एम ई) में उल्लेखनीय सुधार होगा।

## भारतीय तटरक्षक

**10.32 अफसरों की भर्ती :-** तटरक्षक संगठन में अफसरों की भर्ती वर्ष में दो बार की जाती है। तटरक्षक में सहायक कमांडेंटों की रिक्तियों का विज्ञापन रोजगार समाचार तथा प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में दिसंबर/जनवरी एवं जून/जुलाई के महीने में प्रकाशित किया जाता है। भर्ती के लिए आयु सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पांच वर्ष तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाती है। अफसरों को निम्नलिखित शाखाओं में भर्ती किया जाता है :-



(क) सामान्य ड्यूटी: 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत बारहवीं कक्षा के स्तर तक गणित एवं भौतिकी पढ़े हुए 21 से 25 वर्ष की आयु वाले सभी पुरुष/महिला स्नातक अभ्यर्थी, सामान्य ड्यूटी शाखा में अफसर के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ख) महिलाओं के लिए सामान्य ड्यूटी (अल्पकालिक सेवा नियुक्ति योजना) : शिक्षा की 10+2+3 शिक्षा पद्धति में 12वीं कक्षा तक गणित और भौतिकी सहित स्नातक उपाधि वाली महिला उम्मीदवार, जो 21-25 के आयु वर्ग के बीच हों, सामान्य ड्यूटी शाखा में अफसर के लिए आवेदन करने की पात्र हैं।

(ग) सामान्य ड्यूटी (पायलट/नौचालन): स्नातक के दौरान गणित एवं भौतिकी विषयों में बैचलर डिग्री रखने वाले 19-27 वर्ष की आयु के पुरुष/महिला अभ्यर्थी, सामान्य ड्यूटी (पायलट/नौचालन) शाखा में अफसर के लिए आवेदन करने के पात्र हैं ।

(घ) सामान्य ड्यूटी (वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस अल्प सेवा प्रविष्टि): 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण महिला/पुरुष जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को नागर विमानन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सी पी एल) रखते हैं और जिनकी आयु 19-27 वर्ष के बीच है, वे सी पी एल अल्पकालिक सेवा प्रविष्टि के तहत अफसर के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(च) तकनीकी शाखा: 21-30 आयु वर्ग के इंजीनियरिंग डिग्रीधारी (नौसेना वास्तुशिल्प / यांत्रिकी / इलेक्ट्रिकल / दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक / डिजाइन / उत्पादन वैमानिकी / नियंत्रण इंजीनियरिंग) अथवा समकक्ष योग्यता वाले पुरुष तकनीकी शाखा में अफसर के लिए आवेदन करने के पात्र हैं ।

10.33 अफसरों का चयन: अफसरों जनरल ड्यूटी/जनरल ड्यूटी पायलट/नौचालन/सी पी एल धारक (अल्पकालिक सेवा नियुक्ति), महिला अल्पसेवा नियुक्ति और तकनीकी शाखा में अफसरों का चयन तटरक्षक चयन बोर्ड के माध्यम से किया जाता है ।

10.34 अधीनस्थ अफसरों को अफसर के रूप में शामिल किया जाना: चयन प्रक्रिया के अनुसार 48 वर्ष तक की आयु के उत्कृष्ट अधीनस्थ अफसरों को सामान्य ड्यूटी और तकनीकी शाखा में सहायक कमांडेंट के रूप में शामिल किया जाता है।

10.35 अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों (पी बी ओ आर) की भर्ती: पी बी ओ आर की तटरक्षक में भर्ती वर्ष में दो बार की जाती है । दिसम्बर/जनवरी एवं जून/जुलाई माह में तटरक्षक में पी बी ओ आर की रिक्तियों का विज्ञापन रोजगार समाचार और प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। पी बी ओ आर निम्नलिखित शाखाओं में भर्ती किए जाते हैं :-

(क) यांत्रिक: मैट्रिक पास करने के बाद यांत्रिकी/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग

में तीन वर्षीय डिप्लोमाधारी 18-22 वर्ष की आयु के पुरुष उम्मीदवार यांत्रिक के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ख) **नाविक (सामान्य ड्यूटी):** गणित एवं भौतिकी विषयों सहित इंटरमीडिएट/10+2 पास 18-22 वर्ष की आयु के पुरुष उम्मीदवार नाविक (सामान्य ड्यूटी) के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ग) **नाविक (घरेलू शाखा):** 18-22 वर्ष की आयु के मैट्रिक पास पुरुष उम्मीदवार नाविक (घरेलू शाखा) के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

## रक्षा सेवाओं के लिए प्रशिक्षण

10.36 रक्षा क्षेत्र की बहुत-सी संस्थाएं एक दूसरे के साथ समन्वय करके कार्य करती हैं। कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं का निम्नलिखित पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है :-

### सैनिक स्कूल

10.37 सैनिक स्कूल केंद्र एवं राज्य सरकारों के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किए गए थे। ये सैनिक स्कूल सोसायटी के समग्र नियंत्रण में चलते हैं। इस समय देश के विभिन्न भागों में कुल 25 सैनिक स्कूल हैं। मैनपुरी (उत्तर प्रदेश) में एक सैनिक स्कूल तथा राजस्थान में दो अन्य स्कूलों को आरंभ करने के प्रस्ताव को अनुमोदन मिल चुका है।

10.38 सैनिक स्कूलों का उद्देश्य बेहतर पब्लिक

स्कूल शिक्षा को आम आदमी तक पहुंचाना, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और सशस्त्र सेनाओं के अफसर संवर्ग में मौजूद क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए शैक्षिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार किए जाने के प्रमुख उद्देश्य के अनुरूप इन स्कूलों से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने वाले कैडेटों की संख्या में वृद्धि का रुझान दिखाई दिया है। जुलाई 2013 के एन डी ए कोर्स में 21 सैन्य स्कूलों के 112 कैडेटों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी में प्रवेश लिया।

10.39 सैनिक स्कूल लड़कों को छठी एवं नौवीं कक्षाओं में प्रवेश देते हैं। प्रवेश वर्ष की 01 जुलाई को कक्षा छठी के लिए उनकी उम्र 10-11 वर्ष एवं कक्षा नौवीं के लिए 13-14 वर्ष होनी चाहिए। प्रवेश प्रत्येक वर्ष जनवरी मास में आयोजित अखिल भारतीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में योग्यताक्रम (मेरिट) के आधार पर दिया जाता है।

10.40 सैनिक स्कूल सोसाइटी ने उत्कृष्ट शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनके परिणामस्वरूप बोर्ड और एन डी ए के परिणामों में उच्चतर वृद्धि हुई है। आज की तारीख में रक्षा सेनाओं के 8200 से अधिक अफसर सैनिक स्कूलों से पढ़े हुए हैं।

### राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (आर एम एस)

10.41 देश में पांच मिलिट्री स्कूल कर्नाटक में बेलगाम व बंगलौर, हिमाचल प्रदेश में चैल एवं राजस्थान में

अजमेर और धौलपुर में स्थित है। धौलपुर में स्थापित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इनमें से नवीनतम है। ये स्कूल सी बी एस ई से संबद्ध है। ये स्कूल लड़कों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके रक्षा सेनाओं में भर्ती होने के लिए तैयार करते हैं।

10.42 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एक साझी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लड़कों को प्रवेश देते हैं। उम्मीदवारों की चार विषयों अर्थात् अंग्रेजी, गणित, बुद्धिमत्ता एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा ली जाती है। आर एम एस में 67% सीटें जूनियर कमीशंड अफसरों/अन्य रैंक के बच्चों के लिए एवं 20% सीटें कमीशनप्राप्त अफसरों तथा शेष 13% सिविलियनों के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।

### राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए)

10.43 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) तीनों सेवाओं की एक प्रमुख संस्था है जहां सभी तीन सेवाओं के कैडेटों को उनसे संबंधित कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण अकादमियों में प्रवेश से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों की कमी तथा इस कमी को दूर करने के लिए परिणामी तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एन डी ए में एक अतिरिक्त स्क्वाड्रन अर्थात् 16वें स्क्वाड्रन की स्थापना को मंजूरी मिलने के साथ ही

**भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों की कमी तथा इस कमी को दूर करने के लिए परिणामी तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एन डी ए में एक अतिरिक्त स्क्वाड्रन अर्थात् 16वें स्क्वाड्रन की स्थापना को मंजूरी मिलने के साथ ही एन डी ए की प्रवेश क्षमता को हाल ही में 1800 कैडेट से बढ़ाकर 1920 कैडेट कर दिया गया है।**

एन डी ए की प्रवेश क्षमता को हाल ही में 1800 कैडेट से बढ़ाकर 1920 कैडेट कर दिया गया है। भवन निर्माण में कुछ अतिरिक्त वर्ष लगने के कारण अंतरिम उपाय के रूप में 120 कैडेटों के आवास के लिए पी फैब्रिकेटेड आवास का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2015 तक कैडेटों की प्रवेश क्षमता 2400 तक बढ़ाने के लिए 4 स्क्वाड्रन वाले एक अतिरिक्त बटालियन (5वें वटालियन) की स्थापना पर कार्य चल रहा है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भविष्य की तकनीक के आगमन से सामंजस्य बढ़ाने के लिए कल के सैन्य अधिकारियों को सक्षम बनाने के लिए एन डी ए कैडेटों के अकादमिक स्तर को भी ऊंचा उठाया जा रहा है।

### राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आर आई एम सी)

10.44 राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आर आई एम सी) की स्थापना चयनित लड़कों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) एवं नौसेना अकादमी (एन ए वी ए सी) में प्रवेश के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 1922 में की गई थी। वर्ष में दो बार (जनवरी एवं जुलाई) बिना आरक्षण अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रत्येक सत्र में 25 कैडेटों को प्रवेश दिया जाता है।

10.45 आर आई एम सी के लिए लड़कों का चयन राज्य सरकारों के माध्यम से आयोजित

एक लिखित-सह-मौखिक परीक्षा के द्वारा किया जाता है। संबंधित राज्यों के लिए सीटें जनसंख्या के आधार पर आरक्षित की जाती हैं। कॉलेज, लड़कों को कक्षा VIII में प्रवेश देता है।

### **भारतीय सैन्य अकादमी (आई एम ए), देहरादून**

10.46 वर्ष 1932 में स्थापित भारतीय सैन्य अकादमी, (देहरादून) का उद्देश्य सेना में अफसरों के रूप में शामिल होने वाले व्यक्तियों के बौद्धिक, नैतिक एवं शारीरिक गुणों का पूर्णतः विकास करना है। भारतीय सैन्य अकादमी में प्रविष्टि के विभिन्न माध्यम इस प्रकार हैं :-

- (क) एन डी ए से स्नातक होने पर।
- (ख) सेना कैडेट कॉलेज से, जो आई एम ए का ही एक विंग है, स्नातक होने पर।
- (ग) सीधी भर्ती स्नातक कैडेट, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करके सैन्य चयन बोर्ड द्वारा चुने जाते हैं।
- (घ) तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) के लिए।
- (च) इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंतिम/अंतिम से पूर्व वर्ष के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय प्रविष्टि योजना (यू ई एस) के अंतर्गत।
- (छ) 10+2 तकनीकी प्रविष्टि योजना (टी ई एस) के माध्यम से।

10.47 आई एम ए मित्र देशों के जेंटलमैन कैडेटों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

### **अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओ टी ए), चेन्नई**

10.48 वर्ष 1963 में स्थापित अफसर प्रशिक्षण स्कूल (ओ टी एस) के 25 वर्ष पूरे होने पर 01 जनवरी 1988 को इसे अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओ टी ए) नाम दिया गया। वर्ष 1965 से पहले इसका मुख्य कार्य इमरजेंसी कमीशन प्रदान करने के लिए जेंटलमैन कैडेटों को प्रशिक्षित करना था। 1965 के बाद अकादमी ने अल्प सेवा कमीशन के लिए कैडेटों को प्रशिक्षित करना आरंभ किया है।

10.49 21 सितम्बर 1992 से सेना में महिला अफसरों के प्रवेश के पश्चात ओ टी ए से हर वर्ष लगभग 100 महिला अफसर सेना सर्विस कोर, सेना शिक्षा कोर, जज एडवोकेट जनरल विभाग, इंजीनियर्स कोर, सिग्नल तथा इलैक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल कोर में कमीशन प्राप्त करती हैं।

10.50 ओ टी ए निम्नलिखित के लिए कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करती है :-

- (क) स्नातकों के लिए अल्प सेवा कमीशन (गैर तकनीकी)
- (ख) स्नातकों के लिए अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी)
- (ग) स्नातक/स्नातकोत्तर महिला कैडेटों के लिए अल्प सेवा कमीशन (महिला)

### **अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओ टी ए), गया**

10.51 3 दिसम्बर 2009 को सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी सी एस) ने गया, बिहार में दूसरी अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओ टी ए) स्थापित किए जाने के

प्रस्ताव को अनुमोदित किया। 18 जुलाई 2011 से इस अकादमी में प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। वर्तमान में 305 कैडेट ओ टी ए गया में प्रशिक्षण ले रहे हैं। क्रमिक रूप से इसकी क्षमता बढ़ाकर 750 जेंटलमैन कैडेटों की कर दी जाएगी ।

### **सेना युद्ध कॉलेज, महू**

10.52 15 जनवरी 2003 को सेना युद्ध कॉलेज के नाम से पुनर्नामकरण किया गया पूर्ववर्ती समाघात कॉलेज इंफेन्ट्री स्कूल में से सृजित किया गया था और 01 अप्रैल 1971 को इसे स्वतंत्र संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था । एक अग्रणी संस्थान के रूप में अफसरों को सामरिक प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ सेना युद्ध कॉलेज सामरिकी एवं संभारिकी के क्षेत्रों में नई संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण कार्य करता है ।

### **जूनियर लीडर्स विंग (जे एल डब्ल्यू), बेलगांव**

10.53 बेलगांव में जूनियर लीडर्स विंग सब यूनिट लेवल टेक्टिकल और विशेष मिशन तकनीकों में जूनियर अफसरों, जे सी ओ एवं एन सी ओ को प्रशिक्षण देता है ताकि वे भीषण तनाव और दबाव में विभिन्न क्षेत्रों में सौंपे गए संक्रियात्मक मिशनों तथा युद्ध एवं शांतिकाल में अपनी उप-यूनिटों की कमान और प्रशासन प्रभावी रूप से संभाल सकें। यह सेना, अर्ध सैनिक बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों और विदेशी मित्र देशों के अफसरों और एन सी ओ को कमांडो प्रकार की संक्रियाओं में प्रशिक्षण देती है ताकि उन्हें सभी प्रकार के क्षेत्रों और संक्रियात्मक परिवेश में या

तो विशेष मिशन समूहों का हिस्सा बनाया जा सके अथवा स्वतंत्र मिशनों का नेता बनाया जा सके।

### **जूनियर लीडर्स अकादमी (जे एल ए), बरेली**

10.54 प्रशिक्षण के लिए और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जे एल ए, रामगढ़ और जे एल ए, बरेली का समामेलन कर दिया गया है। यह संस्था प्रतिवर्ष 4212 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

### **उच्च तुंगता युद्धपद्धति स्कूल (एच ए डब्ल्यू एस), गुलमर्ग**

10.55 इस विद्यालय का उद्देश्य उच्च तुंगता (एच ए) की पर्वतीय युद्धपद्धति से जुड़े सभी पहलुओं में चुने गए कार्मिकों को प्रशिक्षित करना तथा ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों में युद्ध तकनीक विकसित करना है। एच ए डब्ल्यू एस अफसरों, जे सी ओ तथा एन सी ओ के लिए पाठ्यक्रमों की दो श्रृंखलाएं-पर्वतीय युद्धपद्धति (एम डब्ल्यू) तथा शीतकालीन युद्धपद्धति (डब्ल्यू डब्ल्यू), क्रमशः सोनमर्ग तथा गुलमर्ग में चलाता है। प्रशिक्षण की अवधि सामान्यतः जनवरी से अप्रैल तक (डब्ल्यू डब्ल्यू सीरीज़) तथा मई से अक्टूबर तक (एम डब्ल्यू सीरीज़) होती है। इस स्कूल से प्रशिक्षित कार्मिकों ने माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा तथा सं रा अमरीका की माउंट मैकिनले जैसी विश्व की कुछ प्रमुख चोटियों पर चढ़ने में सफलता पाई है।

### **प्रतिविद्रोहिता तथा जंगल युद्ध पद्धति स्कूल (सी आई जे डब्ल्यू), वीरांगटे**

10.56 सी आई जे डब्ल्यू अधिकारियों तथा जे सी



ओ/एन सी ओ के लिए प्रतिविद्रोहिता तकनीकों तथा असमिया, बोडो, नागामीज, मणिपुरी/तंगखुल भाषाओं के पाठ्यक्रम आयोजित करता है तथा विद्रोहपूर्ण क्षेत्रों में भेजने से पहले सभी यूनिटों के लिए तैनाती पूर्व प्रशिक्षण (पी आई टी) भी आयोजित करता है।

## प्रतिविद्रोहिता तैनाती-पूर्व प्रशिक्षण युद्ध स्कूल

10.57 सी आई जे डब्ल्यू स्कूल की सीमित क्षमता तथा विशिष्ट संक्रियात्मक परिस्थितियों व यूनिटों के संचलन में आने वाली प्रशासनिक समस्याओं के कारण यह आवश्यक समझा गया कि यूनिटों को उनके संक्रिया क्षेत्रों के निकट ही प्रशिक्षण दिया जाए। सेना के संसाधनों में से ही उत्तरी कमान की ओर जाने वाली यूनिटों के लिए खेरू, सरोल एवं भालरा में तथा असम तथा मेघालय की ओर संचलन करने वाली यूनिटों के लिए ठाकुरबाड़ी में और कोर युद्ध स्कूल स्थापित किए गए हैं। प्रतिविद्रोहिता प्रशिक्षण के साथ-साथ ये स्कूल विशेषकर उत्तरी कमान में यूनिटों को नियंत्रण रेखा तथा उच्च तुंगता के संबंध में उनकी भूमिका के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं।

## इन्फैंट्री स्कूल, महू

10.58 इन्फैंट्री स्कूल भारतीय सेना का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है। इन्फैंट्री स्कूल में यंग आफिसर्स पाठ्यक्रम, प्लैटून वेपन पाठ्यक्रम, मोर्टार पाठ्यक्रम, एंटी टैंक एण्ड गाइडेड मिसाइल पाठ्यक्रम, मीडियम मशीन गन एवं आटोमैटिक ग्रेनेड लॉन्चर (जे/एन) पाठ्यक्रम, सेक्शन कमांडर्स

पाठ्यक्रम, आटोमैटिक डेटा प्रोसेसिंग पाठ्यक्रम, स्नाइपर पाठ्यक्रम तथा सपोर्ट वेपन पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। यह संस्थान केवल इन्फैंट्री के ही नहीं बल्कि अर्ध सैनिक बलों एवं सिविल पुलिस संगठनों के साथ-साथ अन्य सेनांगों एवं सेनाओं के अफसरों, जे सी ओ एवं अन्य रैंकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

## सामग्री प्रबंधन कॉलेज

10.59 यह कॉलेज अक्टूबर 1925 में किरकी में स्थापित भारतीय सेना आयुध कोर (आई ए ओ सी) अनुदेश स्कूल की परम्परा को आगे बढ़ा रहा है। बाद में फरवरी, 1939 में इस स्कूल को दोबारा आई ए ओ सी प्रशिक्षण केंद्र नाम दिया गया और इसे जबलपुर में इसके मौजूदा स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। जनवरी 1950, में आई ए ओ सी स्कूल का नाम सेना आयुध कोर (ए ओ सी) स्कूल कर दिया गया। ए ओ सी स्कूल का नाम फिर से बदलकर सामग्री प्रबंधन कॉलेज (सी एम एम) रख दिया गया और 1987 में इसे जबलपुर विश्वविद्यालय (रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय) से संबद्ध कर दिया गया। 1990 में सी एम एम स्वायत्तशासी हो गया। यह कॉलेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में 'सरकारी कॉलेज' के रूप में भी पंजीकृत है। इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) का अनुमोदन भी प्राप्त है।

10.60 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के तहत गठित एक स्वायत्तशासी निकाय नेशनल असेसमेन्ट एंड एक्रिडिटेशन काउंसिल (एन ए ए सी) ने कॉलेज को पांच सितारा (उच्चतम) मान्यता प्रदान की है। कॉलेज, भारतीय सेना में आयुध सपोर्ट प्रबंधन संबंधी कार्यों में लगे ए ओ सी के सभी रैंकों

और सिविलियनों को आवश्यक संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह सभी सेनांगों तथा सेवाओं के चयनित अफसरों, जे सी ओ तथा अन्य रैंकों को भी यूनिट प्रशासन और सामग्री प्रबंधन संबंधी नियंत्रण का प्रशिक्षण प्रदान करता है।

## **तोपखाना स्कूल, देवलाली**

10.61 तोपखाना स्कूल, देवलाली विज्ञान की विविध उपशाखाओं और तोपखाना युद्धपद्धति प्रणाली सिखाने वाला शैक्षणिक केन्द्र है जो हवाई प्रेक्षण चौकी ड्यूटी के लिए पायलटों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ अफसरों, जे सी ओ तथा एन सी ओ को तोपखाना हथियारों और प्रणाली का तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त भारतीय तथा विदेशी तोपखाना उपस्कर सिद्धांतों की समीक्षा, अध्ययन और परीक्षण भी किया जाता है।

10.62 स्कूल ने भारतीय सेना के कई अफसरों, जे सी ओ तथा एन सी ओ के साथ-साथ मित्र देशों के कई अफसरों और कार्मिकों को भी वर्ष के दौरान प्रशिक्षण प्रदान किया है।

## **सेना हवाई रक्षा कॉलेज, गोपालपुर**

10.63 सेना हवाई रक्षा कॉलेज (ए ए डी सी) पहले अक्टूबर 1989 तक तोपखाना स्कूल देवलाली की एक विंग के रूप में कार्य करता था, जब इसे तोपखाने की मुख्य शाखा से हवाई रक्षा तोपखाना के अलग होने से पूर्व गोपालपुर लाया गया। यह कॉलेज वायुरक्षा तोपखाना के कार्मिकों, अन्य सेनांगों और मित्र देशों के

सशस्त्र बलों के कार्मिकों को वायु रक्षा संबंधी विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

10.64 ए ए डी सी अनेक पाठ्यक्रम चलाता है। इनमें से कुछ हैं-लांग गनरी स्टाफ कोर्स (अफसर), युवा अफसर कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति कोर्स, वरिष्ठ कमान हवाई रक्षा कोर्स, लांग गनरी स्टाफ कोर्स, जूनियर कमीशंड अफसर/नॉन कमीशंड अफसर, तकनीकी अनुदेशक फायर नियंत्रण कोर्स, वायुयान पहचान कोर्स, यूनिट अनुदेशक और चालक दल आधारित प्रशिक्षण और ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग कोर्स।

## **सेना सेवा कोर (ए एस सी) केन्द्र एवं कॉलेज, बंगलौर**

10.65 बंगलौर में सेना सेवा कोर केन्द्र एवं कॉलेज की स्थापना के लिए 01 मई 1999 को सेना सेवा कोर केन्द्र (दक्षिण) और सेना यांत्रिक परिवहन स्कूल को बंगलौर में ए एस सी केन्द्र के साथ मिला दिया गया। यह विविध विषयों जैसे संभारिकी प्रबंधन, परिवहन प्रबंधन, केटरिंग, ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग इत्यादि में अफसरों, जूनियर कमीशंड अफसरों, अन्य रैंकों और अन्य सेनांगों और सेवाओं, सेना सेवा कोर के रंगरूटों को मूलभूत और उन्नत प्रशिक्षण देने वाला एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है।

10.66 1992 से ए एस सी कॉलेज संभारिकी एवं संसाधन प्रबंधन में डिप्लोमा/डिग्री प्रदान करने के लिए रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से संबद्ध किया गया है।

## सेना शिक्षा कोर प्रशिक्षण कॉलेज एवं केन्द्र, पंचमढ़ी

10.67 ए ई सी प्रशिक्षण कॉलेज एवं केन्द्र, पंचमढ़ी सशस्त्र सेनाओं में शैक्षणिक प्रशिक्षण देने वाला एक उत्कृष्ट रक्षा संस्थान है। यह बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध एक स्वायत्तशासी कॉलेज भी है जिसे अपने कोर्सों और डिग्रियों की रूपरेखा तैयार करने, उनको संचालित करने, परीक्षा लेने और डिग्री प्रदान करने की शैक्षणिक और प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त हैं।

10.68 मानचित्र शिल्प विभाग ए ई सी अफसरों और भारतीय सेना के सभी सेनांगों और सेवाओं के अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों (पी बी ओ आर), अर्ध सैनिक बलों और मित्र देशों के कार्मिकों के लिए 10 सप्ताह का मैप रीडिंग अनुदेशक कोर्स चलाता है।

10.69 2-सप्ताह लंबा यूनिट शिक्षा अनुदेशक (यू ई आई) पाठ्यक्रम भारतीय सेना के सभी सेनांगों और सेवाओं के अन्य रैंकों को अपनी यूनिटों में सक्षम शिक्षा अनुदेशक बनने के लिए प्रशिक्षित करता है।

10.70 देशी भाषा विंग (एफ एल डब्ल्यू), जो ए ई सी प्रशिक्षण कॉलेज व केन्द्र के तीन प्रभागों में से एक है, न केवल सशस्त्र सेनाओं में अपितु राष्ट्रीय शैक्षणिक परिवेश में भी विदेशी भाषा प्रशिक्षण का एक अग्रणी संस्थान है। इसकी दो डिजिटाइज्ड भाषा प्रयोगशालाएं हैं जो 20-20 छात्रों को प्रशिक्षण देती हैं।

## मिलिट्री संगीत विंग, पंचमढ़ी

10.71 मिलिट्री संगीत विंग (एम एम डब्ल्यू) की स्थापना ए ई सी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर, पंचमढ़ी के एक भाग के रूप में अक्टूबर 1950 में तत्कालीन कमांडर-इन-चीफ (बाद में फील्ड मार्शल) जनरल के

एम करियप्पा, ओ बी ई के संरक्षण में की गई थी। इसके पास 200 से भी अधिक सैन्य संगीत रचनाओं का समृद्ध खजाना है। इसने भर्ती हुए बैंडमैनों, पाइपर्स या ड्रमर्स को प्रशिक्षण देने के लिए भिन्न-भिन्न श्रेणियों के पाठ्यक्रमों के माध्यम से, भारत में मिलिट्री संगीत का उच्च स्तर बनाए रखने में विशिष्टता हासिल की है।

## रिमाउंट और पशुचिकित्सा कोर केन्द्र तथा स्कूल, मेरठ

10.72 मेरठ स्थित रिमाउंट और पशुचिकित्सा कोर (आर वी सी) केन्द्र तथा स्कूल का उद्देश्य सभी सेनांगों और सेवाओं के अफसरों और अफसरों से नीचे के रैंक के सभी कार्मिकों को पशु प्रबंधन तथा पशुचिकित्सा से जुड़े विभिन्न पहलुओं के विषय में प्रशिक्षण देना है। संस्थान में अफसरों के लिए ग्यारह कोर्स तथा पी बी ओ आर के लिए छह कोर्स चलाए जाते हैं।

## सेना खेलकूद संस्थान (ए एस आई), पुणे

10.73 भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेता तैयार करने के उद्देश्य से देश में विभिन्न स्थानों पर चुने हुए विषयों में सेना खेलकूद केन्द्रों के साथ-साथ पुणे में एक सेना खेलकूद संस्थान की स्थापना की गई है। आधुनिक आधारभूत सुविधाओं एवं उपस्करों के साथ-साथ भोजन, रहन-सहन, विदेशी दौरो एवं विदेशी प्रशिक्षकों के अधीन प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त निधि की व्यवस्था की गई है।

## शारीरिक प्रशिक्षण सेना स्कूल, पुणे

10.74 शारीरिक प्रशिक्षण सेना स्कूल (ए एस पी टी) पहला ऐसा संस्थान है जो यूनिटों और सब यूनिटों में

शारीरिक प्रशिक्षण देने के संबंध में सेना कार्मिकों को सुव्यवस्थित तथा व्यापक प्रशिक्षण दे रहा है। यह सेना में खेल-कूद का स्तर सुधारने और शारीरिक प्रशिक्षण में मनोरंजन को शामिल करके उसे पूर्ण बनाने की दृष्टि से खेल-कूद का बुनियादी प्रशिक्षण भी देता है। इन पाठ्यक्रमों में सैन्य और अर्धसैनिक बलों के और अफसर, जे सी ओ और अन्य रैंक तथा मित्र देशों के सेना कार्मिक भाग लेते हैं। ए एस पी टी ने राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान के सहयोग से पी बी ओ आर के लिए बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, बॉस्केटबाल, तैराकी और जीवनरक्षा, जूडो और योग पाठ्यक्रमों में छह सम्बद्ध खेलकूद पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं।

### **समाघात सेना विमानन प्रशिक्षण स्कूल (सी ए ए टी एस) नासिक रोड**

10.75 समाघात सेना विमानन प्रशिक्षण स्कूल (सी ए ए टी एस) की स्थापना मई, 2003 में नासिक रोड में की गई थी। इसका उद्देश्य विमान चालकों को विमानन कौशल तथा विभिन्न युद्ध संक्रियाओं में विमानन यूनितों के रख-रखाव में प्रशिक्षित करना, विमानन अनुदेशकों को मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एस ओ पी) के विकास में प्रशिक्षित करना तथा जमीनी बलों के सहयोग से विमानन सामरिकी सिद्धांत के विकास में सेना प्रशिक्षण कमान की मदद करना है। स्कूल में चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम हैं - प्री-बेसिक पायलट पाठ्यक्रम, बेसिक सेना विमानन पाठ्यक्रम, प्री-क्वालिफाइड उड़ान अनुदेशक पाठ्यक्रम, विमानन अनुदेशक हेलिकॉप्टर पाठ्यक्रम, हेलिकॉप्टर कंवर्शन ऑन-टाइप, उड़ान कमांडर्स पाठ्यक्रम तथा नव उपस्कर पाठ्यक्रम।

### **मिलिट्री इंजीनियरी कॉलेज (सी एम ई), पुणे**

10.76 पुणे स्थित मिलिट्री इंजीनियरी कॉलेज (सी एम ई) एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है जहां इंजीनियरी कोर, अन्य सेनांगों और सेवाओं, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बलों व पुलिस कार्मिकों और सिविलियनों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा मित्र देशों के कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कॉलेज बी-टेक और एम-टेक डिग्रियां देने के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। सी एम ई द्वारा चलाए जाने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्सों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) की मान्यता भी प्राप्त है।

### **सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मैकेनिकल इंजीनियरी कॉलेज (एम सी ई एम ई), सिकंदराबाद**

10.77 एम सी ई एम ई का कार्य सिविलियनों सहित, ई एम ई के सभी रैंकों को इंजीनियरी, शस्त्र प्रणालियों तथा उपस्कर के विभिन्न विषयों में और खास तौर से उनके रख-रखाव, मरम्मत और जांच के संबंध में, तकनीकी शिक्षा देना तथा वरिष्ठ, मध्यम और पर्यवेक्षक स्तरों पर प्रबंध और सामरिक प्रशिक्षण देना है। एम सी ई एम ई में सभी रैंकों के 1760 कार्मिकों (सभी रैंक) को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। यहां अफसरों के लिए 13 कोर्स और पी बी ओ आर के लिए 61 कोर्स चलाए जाते हैं।

10.78 कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण (सी बी टी) पैकेज और डिजिटल चार्ट भी विकसित किए गए हैं जिनमें 'एम सी ई एम ई' में पढ़ाए जाने वाले उपस्कर के

इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक भाग की कार्यप्रणाली, मरम्मत, रखरखाव, सर्विसिंग पहलुओं और सही प्रयोग की विस्तृत तकनीकी जानकारी मौजूद है ।

### **मिलिट्री पुलिस कोर केन्द्र और स्कूल, बंगलौर**

10.79 स्कूल का उद्देश्य अफसरों और पी बी ओ आर को कानून, जांच-पड़ताल, यातायात नियंत्रण आदि से जुड़ी मिलिट्री और पुलिस ड्यूटियों के बारे में प्रशिक्षित करना है । वर्तमान में अफसरों के लिए चार और पी बी ओ आर के लिए चौदह कोर्स चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों की कुल संख्या 910 है ।

### **सेना विमानवाहित प्रशिक्षण स्कूल, आगरा**

10.80 सेना विमानवाहित प्रशिक्षण स्कूल (ए ए टी एस) पहले सेना हवाई यातायात सहायता स्कूल (ए ए टी एस एस) कहलाता था। सभी विमानवाहित प्रशिक्षण को एक ही एजेन्सी के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से सेना वायु परिवहन सहायता स्कूल का नाम बदलकर 15 जनवरी 1992 से सेना विमानवाहित प्रशिक्षण स्कूल कर दिया गया।

### **दूरसंचार इंजीनियरिंग मिलिट्री कॉलेज (एम सी टी ई), महु**

10.81 एम सी टी ई, मऊ सिग्नल अधिकारियों को समाधात संचार, इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति, संचार इंजीनियरी, कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी, रेजीमेंटल सिग्नल

संचार एवं गूढ़ भाषा के संबंध में प्रशिक्षित करता है। पांच प्रशिक्षण संकायों एवं विंगों के अलावा, कॉलेज के पास एक प्रशासनिक विभाग है जो स्टाफ एवं विद्यार्थियों को प्रशासनिक एवं संचारिक सहायता प्रदान करता है तथा एक अवधारणात्मक अध्ययन प्रकोष्ठ है जो संचार सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने का काम कराता है। कॉलेज में एक आधुनिक और पुस्तकों से भरापूरा पुस्तकालय तथा एक खुद का प्रिंटिंग प्रेस भी है। प्रशिक्षणार्थियों को एक औपचारिक परिवेश में अध्ययन एवं प्रशिक्षण का मौका दिया जाता है ताकि वे वर्तमान एवं भावी कार्यों के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं से परिपूर्ण हो सकें ।

### **सैन्य आसूचना प्रशिक्षण स्कूल और डिपो (एम आई एन टी एस डी), पुणे**

10.82 सैन्य आसूचना प्रशिक्षण स्कूल और डिपो (एम आई एन टी एस डी) भारतीय सेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों के सभी रैंकों को आसूचना प्राप्ति, जवाबी आसूचना और सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख संस्था है । स्कूल मित्र देशों की सेनाओं के कार्मिकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है । राजस्व आसूचना विभाग के सिविलियन अफसरों को भी इस संस्था में प्रशिक्षण दिया जाता है । यह स्कूल एक बार में सभी सेनांगों के 90 अफसरों, 130 जूनियर कमीशन प्राप्त/गैर कमीशन प्राप्त अफसरों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है। स्कूल प्रतिवर्ष लगभग 350 अफसरों और 1100 जूनियर कमीशंड अफसरों/गैर कमीशन अफसरों को प्रशिक्षण देता है ।



## **इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिक इंजीनियरी स्कूल (ई एम ई), वड़ोदरा**

10.83 ई एम ई स्कूल अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम तथा पी बी ओ आर के लिए डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र स्तर के पाठ्यक्रम चलाता है। मित्र देशों के अनेक अफसर और पी बी ओ आर ई एम ई स्कूल में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में भाग ले रहे हैं।

## **सैन्य विधि संस्थान, कामठी**

10.84 सैन्य विधि संस्थान की स्थापना शिमला में की गई थी। 1989 में संस्थान को कामठी स्थानांतरित कर दिया गया। स्कूल की चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ सेना के सभी सेनांगों और सेवाओं के अफसरों को व्यापक विधिक शिक्षा प्रदान करना है। यह स्कूल सैन्य और संबद्ध विधि के क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान, विकास और प्रचार का कार्य भी करता है।

## **कवचित कोर केन्द्र एवं स्कूल, अहमदनगर**

10.85 1948 में प्रशिक्षण विंग, रिक्लूट प्रशिक्षण केन्द्र और कवचित कोर डिपो और रिकार्ड को अहमदनगर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां पहले से ही लड़ाकू वाहन स्कूल कार्यरत था और इन सभी को मिलाकर कवचित कोर केन्द्र एवं स्कूल और कवचित कोर रिकार्ड

बना दिया गया। इसमें छह विंग हैं - कवचित युद्ध पद्धति स्कूल, तकनीकी प्रशिक्षण स्कूल, बेसिक ट्रेनिंग रेजिमेंट, ड्राइविंग एवं मेंटिनेंस रेजिमेंट, ऑटोमोटिव रेजिमेंट आयुध एवं इलैक्ट्रॉनिकी रेजिमेंट हैं जो इन विषयों में विशेषीकृत प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

## **विदेशी सेना कार्मिकों का प्रशिक्षण**

10.86 भारतीय सैन्य स्थापनाओं में प्रशिक्षण पाने के लिए विदेशी सेनाओं की बढ़ती हुई दिलचस्पी के चलते पड़ोसी देशों, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशियाई गणतंत्र (सी ए आर), अफ्रीकी महाद्वीप और कुछ विकसित देशों के सेना कार्मिकों को भारत में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुछ शाखाओं में भारतीय अफसर भी विकसित देशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

10.87 विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार विकासशील और अल्पविकसित देशों को सहायता उपलब्ध करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकासशील देशों के कार्मिक सैन्य संस्थाओं में निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। विकसित पश्चिमी देश भी अपने अफसरों को पारस्परिक आधार और प्रशिक्षण और अन्य सम्बद्ध प्रभारों की लागत के भुगतान के आधार पर इन संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं।

## भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास तथा कल्याण



'रोजगार हेतु अपेक्षित दक्षताएं' पर सी आई आई संगोष्ठी में भाग लेते हुए

**केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय** भारत सरकार का एक शीर्ष निकाय है जो भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण हेतु सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है ।

11.1 भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग देश में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं कल्याण हेतु विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम बनाता है । विभाग के दो प्रभाग, अर्थात् पुनर्वास एवं पेंशन हैं और इसके तीन संबद्ध कार्यालय हैं जिनके नाम केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय, महानिदेशालय (पुनर्वास) (डीजीआर) तथा केन्द्रीय संगठन, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना हैं । केन्द्रीय सैनिक बोर्ड भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण और कल्याण निधियों के प्रशासन हेतु भी उत्तरदायी होता है । केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की उसके कार्य करने में सहायता हेतु 32 राज्य सैनिक बोर्ड (आरएसबी) और 386 जिला सैनिक बोर्ड (जैडएसबी) हैं, जो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होते हैं । पुनर्वास महानिदेशालय का कार्यालय सेवानिवृत्ति से पहले/बाद का प्रशिक्षण, पुनःरोजगार और स्व-रोजगार इत्यादि जैसी विभिन्न नीतियों/योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। पुनर्वास महानिदेशालय की सहायता हेतु 5 कमानों में से प्रत्येक कमान में एक-एक पुनर्वास क्षेत्र निदेशालय (डीआरजेड) है । ईसीएचएस भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है।

## कल्याण

11.2 **केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, सचिवालय** : केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय भारत सरकार का एक शीर्ष निकाय है जो भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण हेतु सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है । भूतपूर्व सैनिकों की कल्याण योजनाओं को राज्यों की राजधानियों में स्थित राज्य सैनिक बोर्डों और जिला स्तर पर स्थित जिला सैनिक बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है । इन राज्य सैनिक बोर्डों/जिला सैनिक बोर्डों की स्थापना का खर्च केन्द्र और राज्यों द्वारा वहन किया जाता है । विशेष दर्जे वाले राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के संबंध में निधि के वित्त-पोषण का पैटर्न 75:25 है और अन्य राज्यों के संबंध में यह 60:40 है ।

## सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष

11.3 रक्षा सेवा बजट के अलावा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की कल्याणकारी योजनाओं को धन प्रदान करने के लिए एक प्रमुख स्रोत है। इस समय एएफएफडीएफ की मूलनिधि 254.05 करोड़ रु. है । इस वर्ष समेकित

प्रयास करते हुए अब तक 28.00 लाख रुपए एकत्रित किए गए हैं ।

11.4 सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) की मूलनिधि से अर्जित ब्याज में से 92.5 का इस्तेमाल भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है तथा 7.5 ब्याज को एएफएफडीएफ मूलनिधि में पुनः जोड़ दिया जाता है ।

### **रक्षा मंत्री विवेकाधीन निधि (आरएमडीएफ)**

11.5 आरएमडीएफ के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक/आश्रितों को उनकी चिह्नित व्यक्तिगत आवश्यकताओं, जैसेकि निर्धनता अनुदान, संतान शिक्षा अनुदान आदि के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है । वर्ष 2013-14 के दौरान आरएमडीएफ के अंतर्गत 21.82 करोड़ रु. की राशि संवितरित की गई है ।

11.6 **प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस):** भूतपूर्व सैनिकों तथा भूतपूर्व भारतीय तटरक्षकों के आश्रित प्रतिपाल्यों/विधवाओं को उच्च तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा में सहयोग के लिए इस योजना को वर्ष 2006 में आरम्भ किया गया था। भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं के प्रतिपाल्यों को इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 4000 छात्रवृत्तियां दी जाती है । इस योजना का वित्त-पोषण राष्ट्रीय रक्षा निधि से किया जाता है । छात्रवृत्ति की राशि इस प्रकार है :

(क) लड़कों के लिए 2000/- रु. प्रतिमाह (वार्षिक रूप से देय)

(ख) लड़कियों के लिए 2,250/- रु. प्रतिमाह (वार्षिक रूप से देय)

11.7 इस योजना की शुरुआत से अब तक भारतीय नियामक निकायों जैसेकि एआईसीटीई, एमसीआई आदि से विधिवत् रूप से मान्यताप्राप्त भारत में व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले छात्रों को 118.5 करोड़ रु. की राशि संवितरित की गई है । वर्ष 2013-14 के दौरान प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 19337 छात्र लाभ प्राप्त कर चुके हैं और इसके अंतर्गत 40.89 करोड़ रु. की राशि संवितरित की गई है ।

### **अन्य कल्याणकारी योजनाएं**

11.8 **गंभीर रोगों के लिए वित्तीय सहायता :** गैर-पेंशनभोगी पीबीओआर तथा अफसरों को क्रमशः खर्च का 90 और 75% तक अथवा अधिक-से-अधिक 1,25,000/- (हृदय रोग आदि के लिए) तथा 75,000/-रु. (डायलिसिस और कैंसर के लिए) प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है । यह योजना नेपाल में भारतीय सेना भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन (आईईडब्ल्यूओएन) पर भी लागू है और वर्ष 2013-14 के दौरान नेपाल अधिवासी भूतपूर्व सैनिकों को 1.35 करोड़ रु. संवितरित किए गए हैं ।

11.9 **पैराप्लेजिक पुनर्वास केन्द्र (पीआरसी) :** पैराप्लेजिक तथा टेट्राप्लेजिक भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए संचालित स्वायत्त संस्थानों, पीआरसी किरकी तथा मोहाली को उनकी देखरेख/ स्थापना हेतु क्रमशः प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष 14,600/- रु. के अलावा 9,60,750/- रु. तथा 4,34,375/- रु. का वार्षिक

अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। दोनों पीआरसी को 34.46 लाख रु. की राशि संवितरित की गई है।

**11.10 युद्ध स्मारक हॉस्टल (डब्ल्यूएमएच) :** ऐसी युद्ध

विधवाओं/युद्ध निशक्तों, जिनकी

मृत्यु/निशक्तता युद्ध/युद्ध जैसी संक्रियाओं के कारण हुई हो, को क्रमशः 1350/-रु. तथा 675/-रु. प्रतिमाह प्रति बच्चा डब्ल्यूएमएच अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 30.91 लाख रु. (आरोप्य) तथा 12.29 लाख रु. (गैर आरोप्य) की राशि संवितरित की गई है।

**11.11 सेंट डंस्टन ओर्गेनाइजेशन :** दृष्टिहीन सैनिकों, नौसैनिकों और वायुसैनिकों के लिए सेंट डंस्टन ओर्गेनाइजेशन दृष्टिहीनता के दुःख को कम करने में सहायता देने और दृष्टिहीन भूतपूर्व सैनिकों को उपचारांत देखभाल के अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है ताकि वे समाज में बदली हुई परिस्थिति में अपने को ढाल सकें। इस संगठन को प्रतिवर्ष 14 लाख रु. जारी किए जाते हैं।

**11.12 मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में सीटों में आरक्षण:** वर्ष 2013-14 के लिए केएसबी सचिवालय को भारत सरकार के नामिती के रूप में रक्षा कार्मिकों के प्रतिपाल्यों के लिए कुछ सीटें आबंटित की गई हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान 21 एमबीबीएस सीटें तथा 03 बीडीएस सीटें आबंटित की गई हैं।

## पुनर्वास

**11.13 पूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू) का प्रमुख कार्य पूर्व सैनिकों का पुनर्वास/पुनःस्थापन करना**

**पुनर्वास महानिदेशालय को सेवानिवृत्त होने वाले / सेवानिवृत्त कार्मिकों को दूसरे कैरियर के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।**

है। प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेनाओं से करीब 60,000 कार्मिक सेवानिवृत्त होते हैं अथवा सक्रिय सेवा से कार्यमुक्त होते हैं। इनमें से अधिकांश 35 से 45 वर्ष के कम आयु ब्रैकेट में सेवानिवृत्त होते हैं और

अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए इन्हें दूसरे कैरियर की आवश्यकता होती है। ये कार्मिक राष्ट्र निर्माण के लिए उपलब्ध अत्यधिक अनुशासित, सुप्रशिक्षित और कर्तव्यनिष्ठ प्रतिभावान पूल होते हैं। इस लक्ष्य को निम्नलिखित रीति से प्राप्त किया जा सकता है :-

- (क) भूतपूर्व सैनिकों को पुनःरोजगार ढूंढने में सहायता करना और इन्हें नए कौशल प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण देना जिससे वे नए रोजगार/जॉब के लिए तैयार हो सकें।
- (ख) सरकारी / अर्धसरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सतत प्रयास करना।
- (ग) कॉरपोरेट सेक्टर में भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियुक्तियां प्राप्त करने में सहायता के लिए सक्रिय कार्रवाई करना।
- (घ) स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से नौकरियां उपलब्ध करवाना।
- (ङ) उद्यमी योजनाओं में सहायता करना।

## प्रशिक्षण कार्यक्रम

**11.14 पुनर्वास महानिदेशालय को सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कार्मिकों को दूसरे कैरियर के लिए**



तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चूंकि प्रशिक्षण का उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों का नागरिक जीवन में पुनर्वास करना है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पब्लिक/प्राइवेट और कॉरपोरेट सेक्टर की आवश्यकताओं के अनुरूप सतत समीक्षा की जाती है।

## अफसर प्रशिक्षण

11.15 भूतपूर्व सैनिक (अफसर) के प्रशिक्षण के लिए पुनर्वास महानिदेशालय तीन माह अवधि के मॉड्यूलर मेनेजमेंट तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से लेकर छह माह के व्यावसायिक प्रबंधन कार्यक्रम जैसे पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रशिक्षण वर्ष 2013-14 के लिए नए पाठ्यक्रम जैसेकि सिक्स सिगमा के माध्यम से व्यावसायिक उत्कृष्टता, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, परियोजना प्रबंधन पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है।

## जेसीओ/अन्य रैंक और समकक्ष प्रशिक्षण

11.16 जेसीओ/ओआर तथा समकक्ष के लिए विविध क्षेत्रों में एक वर्ष तक की अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन देशभर में फेले सरकारी/अर्ध-सरकारी तथा निजी संस्थानों में किया जाता है। ये पाठ्यक्रम जेसीओ/ओआर के लिए निःशुल्क आयोजित किए जाते हैं। सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की उद्योग, पुनः-नियुक्ति क्षमता और सैन्य मुख्यालयों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है। प्रशिक्षण वर्ष 2013-14 के लिए अधिक महत्व वाले पाठ्यक्रमों सहित बहुत से नए पाठ्यक्रम जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर नियोजनीयता अवसर हैं, आयोजित किए गए हैं।

## भूतपूर्व सैनिक प्रशिक्षण

11.17 इस योजना के अंतर्गत राज्य सैनिक बोर्डों को अपने-अपने राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित कराने के लिए निधियां आबंटित की जाती है। यह योजना मुख्यतः ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए है जो सेवा में रहने के दौरान पुनर्वास प्रशिक्षण की सुविधा का लाभ नहीं ले पाए थे। इस योजना में भूतपूर्व सैनिक की विधवा/एक आश्रित को भी शामिल किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह पाठ्यक्रम निःशुल्क है और प्रत्येक प्रशिक्षु को 1000 रु. प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दी जाती है। वर्ष 2013-14 के दौरान 662 अफसरों, 27,004 जीसीओ/ओआर और 179 भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षित किया गया है।

11.18 सरकारी नौकरियों में आरक्षण : केन्द्रीय सरकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवाओं में निम्नलिखित आरक्षण उपलब्ध कराती है :

- (क) समूह 'ग' पदों में 10% और समूह 'घ' पदों में 20%
- (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में समूह 'ग' में 14.5% और समूह 'घ' में 24.5%
- (ग) अर्ध-सैनिक बलों में सहायक कमांडेंट के 10% पद
- (घ) रक्षा सुरक्षा कोर में 100%

11.19 भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सिफारिश की है कि सरकारी नौकरियों में तत्कालीन समूह 'घ' पदों के 20% आरक्षण को समूह 'ग' में अंतरित किया जाए और समूह 'ग' में उपलब्ध 10% आरक्षण को समूह 'ख' में अंतरित किया जाए, क्योंकि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की

सिफारिश के अनुसार समूह 'घ' पदों को समाप्त कर दिया गया है ।

11.20 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श पर भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने 18 मार्च, 2013 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया है जिसमें 01 फरवरी, 2006 से, पूर्व रंगरूटों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा दिया गया है ।

11.21 **स्थापन** : विभाग द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के रूप में मूल्यवान मानव संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में कोरपोरेट सैक्टर में जागरूकता बढ़ाने तथा कॉरपोरेट/प्राइवेट सैक्टर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार अवसरों को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य के लिए लगातार प्रयास करना लाभदायक रहा है । 52607 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार मिला है । कुछ प्रमुख स्थापनों के ब्यौरे निम्नालिखित हैं:

(क) **सुरक्षा एजेंसियां** : पुनर्वास महानिदेशालय भूतपूर्व सैनिक संचालित निजी सुरक्षा एजेंसियों, कम्पनियों और भूतपूर्व सैनिक निगमों को, विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने के लिए, पैनलबद्ध/प्रायोजित करता है । यह योजना सेवानिवृत्त अफसरों को अच्छे स्वरोजगार अवसर प्रदान करती है तथा सेवानिवृत्त जेसीओ/ओआर तथा समकक्ष को उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार अवसर प्रदान करती है । वर्ष 2013-14 के दौरान 53414 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान कुल मिलाकर 338 सुरक्षा एजेंसियां पैनलबद्ध की गई हैं ।

(ख) **अफसरों को रोजगार** : वर्ष 2013-14 के दौरान, 696 अफसरों का स्थापन किया गया है ।

### 11.22 रोजगार निदेशालय

(क) सुरक्षा एजेंसी योजना की सुचारु तथा पारदर्शी कार्य-प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने जुलाई 2012 में पुनर्वास महानिदेशालय में पैनलबद्ध सुरक्षा एजेंसियों की कार्य-प्रणाली के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं । इन दिशा-निर्देशों में जनवरी 2013 में और संशोधन किए गए हैं । ये दिशा-निर्देश वेबसाइट [www.desw.gov.in](http://www.desw.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

(ख) सुरक्षा एजेंसियों को पैनल में शामिल करने और प्रायोजन के ब्यौरे को पुनर्वास महानिदेशालय की वेबसाइट [www.dgrinidia.com](http://www.dgrinidia.com) पर सभी हितधारकों की सूचना के लिए तथा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए नियमित रूप से अपलोड किया जा रहा है ।

11.23 **ईएसई सुरक्षा गार्डों के लिए कुशलता श्रेणी का अपग्रेडेशन** : पुनर्वास महानिदेशालय ने सुरक्षा गार्डों की मूलभूत मजदूरी को उनके कुशलता सैट के अनुसार किए जाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ कार्रवाई आरम्भ की है । नया राजपत्र लागू हो गया है जिसमें बिना शस्त्र वाले सुरक्षा गार्डों को जिन्हें पहले 'अकुशल (अनस्किल्ड)' श्रेणी में रखा जाता था, अब उन्हें अपग्रेड करके 'अर्ध-कुशल (सेमी स्किल्ड)' श्रेणी में रखा गया है । इसी प्रकार, शस्त्र सहित सुरक्षा गार्डों का दर्जा बढ़ाकर 'अर्द्ध-कुशल (सेमी स्किल्ड)' से 'कुशल (स्किल्ड)' श्रेणी कर दिया गया है ।

## स्वरोजगार की योजनाएं

11.24 सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के पुनर्वास तथा पुनःस्थापन के लिए अनेक स्वरोजगार योजनाएं तैयार की हैं। पुनर्वास महानिदेशालय ने कोल इण्डिया लिमिटेड और कोयला संबंधित सहायक कंपनियों के साथ अपने समझौता ज्ञापन को 12 दिसम्बर 2013 को संशोधित किया है। वर्तमान में 61 भूतपूर्व सैनिक कंपनियां कोयला संबंधी विभिन्न सहायक कंपनियों में कोयले की ढुलाई कर रही हैं। विभिन्न कोयला संबंधी विभिन्न सहायक कंपनियों से 13 नई भूतपूर्व सैनिक कोयला कम्पनियों की मांग मिली है और इसके लिए प्रायोजन की कार्रवाई चल रही है। वर्ष 2013-14 में कोयला टिप्पर योजना में कुल मिलाकर 58 विधवाओं/निशक्त सैनिकों को लाभ मिला है। पुनर्वास महानिदेशालय ने इस वर्ष के दौरान विभिन्न तेल उत्पाद एजेंसियों के आबंटन के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं/आश्रितों को 194 पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए हैं। आईओसीएल तथा बीपीसीएल के कम्पनी स्वामित्व एवं कम्पनी संचालित (कोको) के रिटेल आउटलेट रक्षा सेनाओं के कमीशन प्राप्त अफसरों को सम्पूर्ण भारत में कोको योजना के अंतर्गत रिटेल आउटलेटों के प्रबंधन के लिए रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। पुनर्वास महानिदेशालय ने कोको योजना के लिए 891 भूतपूर्व सैनिकों (अफसर) को प्रायोजित किया है।

11.25 **मदर डेरी दुग्ध बूथ और फल एवं सब्जी (सफल) दुकानें:** भूतपूर्व सैनिक जेसीओ/ओआर समकक्ष के लिए यह योजना एक अच्छे लाभ वाली समय पर खरी उतरी स्वरोजगार योजना है। वर्ष 2013-14 के दौरान इस योजना से 258 जेसीओ/ओआर समकक्ष लाभान्वित हुए हैं।

11.26 **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों (अफसर) द्वारा सी एन जी स्टेशन का प्रबंधन:** योजना को हाल ही में संशोधित किया गया है। नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव को शामिल करते हुए योजना के कार्य-क्षेत्र को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ाया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान इस योजना से 123 भूतपूर्व सैनिक (अफसर) लाभान्वित हुए हैं।

11.27 **सेना अधिशेष श्रेणी-वी 'बी' वाहनों का आबंटन:** भूतपूर्व सैनिक और सेवा के दौरान मृत रक्षा कार्मिकों की विधवाएं, सेना अधिशेष श्रेणी-वी 'बी' वाहनों के आबंटन हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं। कुल मिलाकर 122 भूतपूर्व सैनिकों का पंजीकरण पुनर्वास महानिदेशालय में किया गया।

11.28 **प्रचार और जागरूकता अभियान :** जागरूकता फैलाने और रक्षा सेना कार्मिकों द्वारा दिए गए बलिदान को याद करते हुए टी.वी. सीरीज "सारे जहाँ से अच्छा" के 13 धारावाहिक पूरे हो गए हैं और इनका प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा।

11.29 पुनर्वास महानिदेशालय ने जो 06 फरवरी, 2014 से प्रगति मैदान नई दिल्ली में एक चार दिवसीय डैफएक्सपो-2014 वैश्विक प्रदर्शनी में भाग लिया। पुनर्वास महानिदेशालय ने भूतपूर्व सैनिकों के रूप में अपने प्रशिक्षित और अनुशासित मानव संसाधन का प्रदर्शन किया जिन्हें कारपोरेट सेक्टर और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सार्थक ढंग से रोजगार दिया जा सकता है।

## स्वास्थ्य देखभाल

11.30 भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) की शुरुआत 01 अप्रैल, 2003 से हुई थी। इस योजना का अक्टूबर, 2010 में पुनः विस्तार किया गया। ईसीएचएस का उद्देश्य

भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को ईसीएचएस पोलीक्लिनिकों के नेटवर्क के माध्यम से गुणवत्ता वाली चिकित्सा मुहैया करना है। सैनिक चिकित्सा सुविधाएं तथा सिविल पैनलबद्ध/सरकारी अस्पताल पूरे देश में फैले हुए हैं। इस योजना

को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की तर्ज पर बनाया गया है और इसका वित्त-पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह प्रयास है कि पैनलबद्ध अस्पतालों का उपयोग करके नकदीरहित उपचार सुनिश्चित किया जाए।

11.31 ईसीएचएस पोलीक्लिनिक बहिःरोगी चिकित्सा मुहैया कराने के लिए बनाए गए हैं जिनमें परामर्श, आवश्यक जांच और औषधियों की व्यवस्था शामिल है। विशिष्ट परामर्श, जांच, अंतरंग चिकित्सा (अस्पताल में भर्ती करना) सैन्य अस्पतालों, सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता के माध्यम के साथ-साथ ईसीएचएस में पैनलबद्ध सिविल चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं।

11.32 क्षेत्रीय केन्द्र : कुल मिलाकर 28 क्षेत्रीय केन्द्र देशभर में फैले हुए हैं। भारत सरकार ने अब तक नेपाल में 06 पोलीक्लिनिकों सहित कुल मिलाकर 432 ईसीएचएस पोलीक्लिनिक संस्वीकृत किए हैं। इनमें से 388 पोलीक्लिनिकों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

इस योजना के अंतर्गत कुल 45,86,889 लाभार्थी हैं। योजना में 929 सिविल अस्पताल पैनलबद्ध हैं और उपर्युक्त सभी अस्पतालों ने ईसीएचएस लाभार्थियों को नकदीरहित उपचार मुहैया कराने के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

## वर्तमान स्थिति

11.33 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार 31,72,358 आश्रितों के साथ-साथ कुल मिलाकर 14,14,531 भूतपूर्व सैनिक पेंशनभोगियों ने योजना में अपना नाम दर्ज करवाया है। इस योजना के अंतर्गत कुल 45,86,889 लाभार्थी हैं।

योजना में 929 सिविल अस्पताल पैनलबद्ध हैं और उपर्युक्त सभी अस्पतालों ने ईसीएचएस लाभार्थियों को नकदीरहित उपचार मुहैया कराने के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में ईसीएचएस रोगियों के चिकित्सा उपचार पर 966.93 करोड़ रु. खर्च किए गए।



ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक : शकूरबस्ती का उद्घाटन

11.34 (क) ऑन-लाइन बिल प्रोसेसिंग : सरकार ने फरवरी 2012 में 05 प्रमुख क्षेत्रीय केन्द्रों अर्थात् दिल्ली, चंडीमन्दिर, पुणे, हैदराबाद और त्रिवेंद्रम में एक बिल प्रोसेसिंग एजेंसी (यूटीआई-आईटीएसएल) का प्रयोग करते हुए 'ऑन-लाइन बिल प्रोसेसिंग' की स्वीकृति जारी की है। पांच और क्षेत्रीय केन्द्रों अर्थात्

कोलकाता, कोच्चि, जयपुर, जालन्धर और लखनऊ को 'ऑन-लाइन' बिल प्रोसेसिंग शुरू करने के लिए फरवरी 2013 में स्वीकृति जारी की गई थी और इसे कार्यान्वित कर दिया गया है। 'ऑन-लाइन' बिल प्रोसेसिंग से प्रोसेसिंग समय में कमी आई है और इसीलिए अब पैलनबद्ध अस्पतालों के बिलों के भुगतान में बहुत तेजी आई है। इससे अपेक्षित पारदर्शिता भी आई है। शेष 18 क्षेत्रीय केन्द्रों पर 'ऑन-लाइन' बिलिंग के विस्तार के लिए अनुमोदन दे दिया गया है।

(ख) **क्षेत्रीय केन्द्रों तथा पोलीक्लिनिकों में कार्य की शुरुआत :** 28 क्षेत्रीय केन्द्रों और 388 पोलीक्लिनिकों में कार्य की शुरुआत हो गई है। केवल 38 पोलीक्लिनिक शेष हैं जिनको अभी शुरू किया जाना है। सभी पोलीक्लिनिकों के चालू करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।

(ग) **ईसीएचएस नेपाल :** नेपाल में नेपाल अधिवासित गोरखा (एनडीजी) भूतपूर्व सैनिकों को ईसीएचएस सुविधाओं के लिए शामिल किया गया है। सरकार ने काठमांडू, पोखरा और धारन में तीन ईसीएचएस पोलीक्लिनिकों को संस्वीकृति दी है जिनमें उपर्युक्त प्रत्येक स्थान पर एक मोबाइल क्लीनिक को इसके साथ लगाया जाएगा ताकि नेपाल के दूरवर्ती हिस्सों में निवास करने वाले ईसीएचएस लाभार्थियों को स्वास्थ्य देखभाल का लाभ दिया जा सके।

(घ) **पोलीक्लिनिक भवनों के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन:** पोलीक्लिनिक भवनों के निर्माण के लिए 203 स्थानों पर भूमि का अर्जन किया गया है। 134 स्थानों पर निर्माण-कार्य पूरा हो गया है और 28 स्थानों पर निर्माण विभिन्न चरणों में जारी है। सभी स्थानों पर भवन निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने का उद्देश्य है ताकि

प्रत्येक पोलीक्लिनिक को निर्दिष्ट क्षमता से सुसज्जित किया जा सके जिससे इसका कार्य-करण इष्टतम स्तर पर शुरू हो सके।

(ङ) **सिविल चिकित्सा सुविधाओं को पैलन में शामिल करना :** 174 नए अस्पतालों को ईसीएचएस में पैलनबद्ध किया गया है जिससे समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले पैलनबद्ध अस्पतालों की कुल संख्या 929 हो गई है।

(च) **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी):** आईसीटी का प्रयोग करके ईसीएचएस में चिकित्सा सुविधा में सुधार के लिए एक विस्तृत अध्ययन किया गया है। यह प्रयास है कि ईसीएचएस के सर्वाधिक हिस्सों को संचालित किया जाए जिससे इस योजना में सक्रियता बढ़ेगी और पारदर्शिता में भी वृद्धि होगी। अब तक 264 पोलीक्लिनिकों ने अपने दिन-प्रति-दिन के कार्यकलापों में स्वचालन कर लिया है।

(छ) **चिकित्सा उपकरणों के मानक :** पोलीक्लिनिकों के लिए 18 दिसम्बर, 2012 को उपकरणों के मानकों में संशोधन किया गया और नए मानकों के अनुसार उपकरणों की अधिप्राप्ति करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है।

(ज) **अधिप्राप्तियां :** अभी तक 182 जनरेटर्स (30 केवीए) की अधिप्राप्ति की गई है। पावर बैंक-अप के लिए सभी पोलीक्लिनिकों में एक 30 केवीए जनरेटर है। हाल में स्वीकृत की गई नई ईसीएचएस पोलीक्लिनिकों के लिए 77 एम्बुलेंसों की अधिप्राप्ति की गई। 105 और एम्बुलेंसों की अधिप्राप्ति की कार्रवाई चल रही है।

(झ) **ईसीएचएस के लिए अतिरिक्त जनशक्ति:** देशभर में फैले ईसीएचएस के नेटवर्क के लिए 1,709



स्टाफ की अतिरिक्त जनशक्ति की संस्वीकृति की गई है। इससे सेनानियों तथा उनके आश्रितों को गुणवत्तापरक चिकित्सा लाभ मुहैया कराने के संदर्भ में ईसीएचएस पोलीक्लिनिकों के कार्य निष्पादन में सुधार होगा।

(ज) **ईसीएचएस की टोलफ्री हेल्पलाइन** : सदस्यता, उपचार तथा रोजगार से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए सभी ईसीएचएस सदस्यों को ईसीएचएस टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-114-115 उपलब्ध कराई गई है। यह सेवा सोमवार से शुक्रवार तक सभी कार्य दिवसों में 0900 से 1700 बजे तक उपलब्ध है।

## पेंशन सुधार

**11.35 लापता पेंशनभोगियों के मामले में परिवार पेंशन** : सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में, सरकार ने लापता पेंशनभोगियों के परिवारों को एफआईआर दायर करने की तारीख से छह महीने की अवधि के बाद परिवार पेंशन मुहैया कराई है। परिवार पेंशनभोगी के लापता होने के मामले में इसी प्रावधान के दायरे को बढ़ाया गया है ताकि परिवार पेंशनभोगी के न रहने के परिणामस्वरूप परिवारों की कठिनाई को कम किया जा सके। परिवार पेंशन अगले पात्र परिवार सदस्य को दी जाएगी।

(क) **सेना पेंशन विनियमावली, भाग-II(2008) का विनियम 18**: लम्बित जांच अधिनिर्णय में, किसी व्यक्ति के पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस/लेप्रोसी जैसी

बीमारियों के कारण सेवा से मुक्त किए जाने के मामलों में तत्काल कठिनाइयों को कम करने के लिए अंतरिम पेंशन जारी करने के लिए प्रावधान है। अब इस प्रावधान को सभी इनवेलिडमेंट आरोग्य/वृद्धि/युद्ध घायल मामले तथा सेवा से इनवेलिडिड आउट मामलों में लागू कर दिया है।

(ख) **रिजर्विस्टों को अनुग्रह राशि** : रिजर्विस्टों तथा उनके परिवारों को देय अनुग्रह राशि को 04 जून, 2013 से 10 फरवरी, 2014 के सरकारी पत्र सं. 1(06)/2010-रक्षा(पेंशन/नीति) के तहत संशोधित करके बढ़ा दिया गया है।

(ग) **समान रैंक समान पेंशन (ओआरओपी)** : 17 फरवरी, 2014 को अंतरिम बजट में रक्षा कार्मिकों के लिए 'समान रैंक समान पेंशन (ओआरओपी)' के सिद्धांत की सरकार की स्वीकार्यता की घोषणा की गई। तदनुसार, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से ओआरओपी के कार्यान्वयन के लिए उपाय किए हैं। ओआरओपी के कार्यान्वयन से पुराने पेंशनभोगियों की पेंशन में और वृद्धि होगी।

(घ) **1.1.1973 से पूर्व निशक्तता पेंशन** : दिनांक 10 फरवरी, 2014 के सरकार के पत्र सं. 12(28)/2010-रक्षा (पेंशन/नीति) के तहत जब निशक्तता की स्वीकृत सीमा 20 प्रतिशत से कम पुनः आकलित की गई हो- तो 1.1.1973 से पूर्व के अयोग्य ठहराए गए जेसीओ, अन्य रैंक और एनसी(ई)/नौसैनिक/एयरमैन को निशक्तता पेंशन का सेवा घटक प्रदान करना।

## सशस्त्र सेनाओं तथा सिविल प्राधिकारियों के बीच सहयोग



आंध्र प्रदेश में बाढ़ के दौरान आपदा प्रबंधन

**से**ना ने बड़ी संख्या में सैन्य सिविल कार्रवाई कार्यक्रम चलाए हैं जिनका उद्देश्य 'आपरेशन सद्भावना' के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद तथा विद्रोहिता से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के "दिल और दिमाग को जीतना" है ।

12.1 देश की सीमाओं की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी के अलावा, सशस्त्र बल सिविल प्राधिकारियों को कानून एवं व्यवस्था तथा/अथवा आवश्यक सेवाएं बनाए रखने में और प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव एवं राहत कार्यों में सहायता पहुंचाते हैं । उक्त अवधि के दौरान सशस्त्र बलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता का विवरण उत्तरवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है ।

## भारतीय सेना

### सैन्य सिविल कार्रवाई कार्यक्रम

12.2 सेना ने बड़ी संख्या में सैन्य सिविल कार्रवाई कार्यक्रम चलाए हैं जिनका उद्देश्य 'आपरेशन सद्भावना' के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद तथा विद्रोहिता से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के "दिल और दिमाग को जीतना" है । इन क्षेत्रों में आपरेशन सद्भावना का केन्द्र 'गुणवत्ता शिक्षा', 'महिला सशक्तिकरण', 'समुदाय तथा अवसंरचना विकास', 'स्वास्थ्य तथा पशु चिकित्सा देखभाल', 'गुर्जरो/बकरवालों का विकास' तथा 'राष्ट्र निर्माण' रहा है। संस्कृतियों के परस्पर आदान-प्रदान को बढ़ाने

के लिए छात्रों, बुजुर्गों तथा वीर नारियों द्वारा देश के अन्य भागों में 'शैक्षणिक/प्रेरणात्मक दौरों' के लिए परियोजनाएं भी चलाई गई हैं । इसके अलावा, आपरेशन सद्भावना परियोजनाओं को चलाने के दौरान जलापूर्ति, विद्युत तथा पशुपालन के प्रावधान पर महत्व दिया गया है ।



*चिकित्सा कैम्पों का आयोजन*

12.3 वर्ष 2013-14 के दौरान, जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सैन्य-नागरिक कार्रवाई चलाने के लिए कुल मिलाकर 55.27 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे ।



12.4 सेना सक्रिय रूप से आपदा प्रबंधन तथा राहत अभियानों में शामिल है। सेना द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता के विवरण उत्तरवर्ती पैराओं में दिए गए हैं :

### बाढ़ राहत आपरेशन

12.5 उत्तराखंड : उत्तराखंड में बादल फटने के बाद सेना ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई की और सक्रिय रूप से कार्मिक तैनात किए। सेना द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई के परिणामस्वरूप बचाव आपरेशनों के अति-महत्वपूर्ण आरंभिक चरण के दौरान विभिन्न कीमती जिंदगियां बचाई गईं। सेना ने एक सप्ताह के भीतर संचार लाइनों के टूट जाने की कड़ी चुनौतियों के बावजूद विशेष बलों के 150 कार्मिकों सहित 8000 कार्मिक तैनात किए। सेना द्वारा कुल मिलाकर 38,720 तीर्थयात्री बचाए गए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सेना द्वारा

सेना ने एक सप्ताह के भीतर संचार लाइनों के टूट जाने की कड़ी चुनौतियों के बावजूद विशेष बलों के 150 कार्मिकों सहित 8000 कार्मिक तैनात किए। सेना द्वारा कुल मिलाकर 38,720 तीर्थयात्री बचाए गए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

अत्यधिक आवश्यक सुविधा और चिकित्सा देखभाल मुहैया कराने के लिए चार राहत कैम्प और सात चिकित्सा कैम्प स्थापित किए गए थे। सेना विमानन की ओर से बारह (12) हेलिकॉप्टर भी तैनात किए गए थे। इन हेलिकॉप्टरों ने राहत तथा बचाव प्रयासों में अत्यधिक योगदान दिया।

कुल मिलाकर 32 चिकित्सा दल तैनात किए गए थे। 19,960 रोगियों को चिकित्सा सहायता दी गई। भारी वर्षा के कारण



टूटी सभी सड़कों पर सेना ने बहुत से फुटब्रिज तैयार किए। सेना ने गोविंद घाट पर एक श्रेणी-III एल्युमीनियम सेतु तैयार किया जिसने बड़ी संख्या में नदी पार भटक रहे तीर्थयात्रियों को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

## सेना द्वारा राहत एवं बचाव अभियान

### चिकित्सा सहायता

12.6 मध्य प्रदेश : तवा तथा बर्गी बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण होशंगाबाद जिले के कई हिस्से जलमग्न हो गए। 23 अगस्त, 2013 से सेना द्वारा होशंगाबाद में दो इंजीनियर टुकड़ियों सहित पांच टुकड़ियां तैनात की गईं। सिविल प्रशासन के समन्वय से सेना ने लगभग 700 सिविलियनों को बचाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।



12.7 गुजरात : गुजरात के वडोदरा तथा भरूच जिलों में लगातार वर्षा होने की वजह से सिविल प्रशासन ने 24 सितम्बर, 2013 को सेना से सहायता

की मांग की। सेना ने 26 सितम्बर, 2013 से 3 इंजीनियर दलों सहित 6 टुकड़ियां वडोदरा और भरूच में तैनात की गईं। लगभग 463 सिविलियनों को बचाया गया।

12.8 चक्रवात फेलीन : ओडिशा और आंध्र प्रदेश : ओडिशा तथा उत्तरी आंध्र प्रदेश में चक्रवात के खतरे के बाद सेना ने सक्रिय रूप से कार्रवाई की और मध्य भारत क्षेत्र के सामरिक मुख्यालय जबलपुर से तथा रायपुर से सीओएसए को भुवनेश्वर, ओडिशा 12 अक्टूबर, 2013 को अग्रवर्ती कार्रवाई के लिए तैनात किया। दस सेना टुकड़ियां ओडिशा में तैनात की गई थीं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी जिलों में चक्रवात राहत आपरेशन के लिए चार सेना टुकड़ियों को तैनात किया गया था। 12 अक्टूबर, 2013 को एक इंजीनियर त्वरित बल (ईटीएफ) को भी विमान द्वारा इलाहाबाद से भुवनेश्वर लाया गया था। सेना ने ओडिशा के गंजम तथा बालासोर जिलों में राहत आपरेशन चलाए।

12.9 चक्रवात 'लहर' : आंध्र प्रदेश : आंध्र प्रदेश में चक्रवात के खतरे के परिणामस्वरूप 28 नवम्बर, 2013 को इंजीनियर तथा चिकित्सा कार्मिकों सहित दस (10) संयुक्त टुकड़ियों को चक्रवात राहत आपरेशनों के लिए प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया था।

### फिलीपींस को मानवीय सहायता

12.10 8 नवम्बर, 2013 को फिलीपींस में हरिकेन 'हैयान' (स्थानीय नाम 'योलांडा') की वजह से भूस्खलन हुए। भारत द्वारा मानवीय सहायता के



भाग के रूप में भारतीय सेना ने फिलीपींस को टेंटों, कंबलों, तिरपालों, दवाइयों आदि सहित 13.82 टन राहत सामग्री भेजी ।

## कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना

**12.11 असम :** असम में गोलपारा और धुबरी जिलों में पंचायत चुनावों के दौरान हिंसा फैल जाने के कारण सिविल प्रशासन ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना की मांग की । दस सेना टुकड़ियों ने 12-19 फरवरी, 2013 को हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया ।

**12.12 जम्मू और कश्मीर :** 9 अगस्त, 2013 को किश्तवाड़ में दो समुदायों में साम्प्रदायिक झड़पें हुईं । डीसी किश्तवाड़ से मांग पत्र मिलने पर सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए तीन टुकड़ियां तैनात की गई थीं । स्थिति पर काबू पाने के लिए किश्तवाड़, जम्मू, राजौरी, सांबा और कटुआ जिलों में 54 सेना टुकड़ियों की सक्रिय रूप से तैनाती की गई थी । सेना द्वारा त्वरित तथा प्रभावी कार्रवाई किए जाने के कारण साम्प्रदायिक तनावों तथा हिंसक घटनाओं के बढ़ने को रोका जा सका ।

**12.13 साम्प्रदायिक हिंसा - उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर तथा शामली जिले :** उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और शामली जिलों में साम्प्रदायिक झड़पों के परिणामस्वरूप सिविल प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 8 सितम्बर, 2013 को सेना की मांग की । तदनुसार, 8 सितम्बर, 2013 से मुजफ्फरनगर में आठ टुकड़ियां,

शामली में एक टुकड़ी और मेरठ में एक टुकड़ी को तैनात किया गया था । मुजफ्फरनगर और शामली में तैनात की गई सैन्य टुकड़ियां क्रमशः 16 सितम्बर और 17 सितम्बर, 2013 तक तैनात थीं । सेना की उपस्थिति से सिविल प्रशासन को स्थिति को तेजी से काबू करने में मदद मिली ।

## भारतीय नौसेना

**12.14 उत्तराखंड राहत आपरेशन :** उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा के बाद जून, 2013 में गोताखोरी सहायता तथा खोज और बचाव के लिए भारतीय नौसेना मरीन कमांडो (एमएआरसीओएस) तथा नौसेना गोताखोरों को तैनात किया गया था । दो दल जिनमें प्रत्येक में एक अफसर तथा ग्यारह नौसैनिक शामिल थे, को क्रमशः हरिद्वार तथा रूद्रप्रयाग में तैनात किया गया था । इन दलों को खोज तथा बचाव आपरेशनों के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ)/स्थानीय प्राधिकारियों के साथ तैनात किया गया था ।

**12.15 आपरेशन 'फेलीन':** चक्रवात 'फेलीन' ने गोपालपुर के पास ओडिशा तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश को 12 अक्टूबर, 2013 को पार किया था । भा.नौ.पो. जलाश्व तथा भा.नौ.पो. रणविजय राहत सामग्री के साथ उपलब्ध थे, जो तीन दिनों तक 10,000 व्यक्तियों की पूर्ति के लिए पर्याप्त थी । भा.नौ.पो. इन्वेस्टीगेटर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत प्रयासों में सहायता के लिए 13 अक्टूबर, 2013 को पोर्ट ब्लेयर से 1,000 व्यक्तियों के लिए दो चिकित्सा दल, तीन गोताखोर यूनिटों, राहत सामग्री और चिकित्सा आपूर्तियां लेकर

खाना हुआ। इसके अलावा, पूर्वी नौसेना कमान के गोताखोर तथा चिकित्सा दल तैनात किए गए थे और खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति की गई थी।



आपरेशन फेलीन के दौरान नौसेना बचाव दल, आंध्र प्रदेश

**12.16 आंध्र प्रदेश में बाढ़ - आपरेशन मदद :** आंध्र प्रदेश में 25 अक्टूबर, 2013 से भारी वर्षा हुई जिसके परिणामस्वरूप 16 जिलों में बाढ़ आ गई। सिविल प्राधिकारियों से अनुरोध मिलने के आधार पर भारतीय नौसेना ने बचाव/राहत आपरेशन चलाए, जिनमें 66 कार्मिकों सहित 17 बचाव/राहत दल नौकाओं और गोताखोरी उपकरणों के साथ तैनात किए गए थे। इन दलों ने 440 व्यक्तियों को बचाया और सिविल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए 210 खाने के पैकेटों का वितरण किया।

**12.17 स्थानीय ग्रामीणों की सहायता :** 16 फरवरी, 2013 को वेदारन्यम, तमिलनाडु के पास मछुआरों के औरकत्थुरई गांव में भयंकर आग लग गई। नौसेना टुकड़ी (थोप्पुतुरई) के नौसैनिकों ने सफलतापूर्वक आग पर काबू पा लिया जिससे जान और माल की कोई हानि नहीं हुई। भारतीय नौसेना द्वारा की गई

त्वरित कार्रवाई की स्थानीय आबादी द्वारा अत्यधिक सराहना की गई।

**12.18 बड़ा अग्निशमन आपरेशन, रामानाथपुरम :** 2 जून, 2013 को चेन्नई के निकट वालनथरवी में ओएनजीसी गैस कलेक्टिंग स्टेशन के समीप घास में लगी भयंकर आग की सूचना भारतीय नौसेना प्राधिकारियों को दी गई थी। आग बुझाने तथा नियंत्रण आपरेशन के लिए नौसेना कार्मिकों तथा फायर टेंडर को तत्काल तैनात किया गया था।



बड़ा अग्निशमन आपरेशन, रामानाथपुरम, चेन्नई

**12.19 एचपीसीएल, विशाखापट्टनम में दुर्घटना :** 23 अगस्त, 2013 को एचपीसीएल के कूलिंग टावर में एक दुर्घटना हो गई थी। सूचना मिलने पर भारतीय नौसेना अस्पताल (आईएनएचएस कल्याणी) जख्मी लोगों को लाने तथा ईलाज की व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गया था। रोगियों को लाने के लिए अस्पताल तथा अन्य नौसेना स्थापनाओं की एंबुलेंसों का प्रयोग किया गया था। कुल मिलाकर 39 जख्मियों को तत्काल उपचार दिया गया था।

**12.20 तटीय सुरक्षा जागरूकता अभियान :** तटीय गांवों में भारतीय तटरक्षक तथा समुद्री पुलिस के साथ

बहुत से संयुक्त तटीय सुरक्षा जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया था। इन अभियानों का उद्देश्य तटीय गांवों के ग्रामीणों तथा मछुआरों के बीच सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाना था ताकि वे सुरक्षा एजेंसियों के 'आंख और कान' के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।

**12.21 मछुआरों के साथ संपर्क :** तमिलनाडु में स्थित सभी नौसेना टुकड़ियों ने स्थानीय मछुआरों के नेताओं तथा मत्स्यन कार्मिकों के साथ संपर्क करने के लिए जागरूकता कैंपों का आयोजन किया। मछुआरों को सलाह दी गई थी कि वे समुद्र में होने वाली सभी घटनाओं की सूचना दें ताकि उन्हें समयबद्ध सहायता दी जा सके।

**12.22 नौसेना स्वास्थ्य कैंप :**

(क) **जिला परिषद कन्या उच्च विद्यालय, कासिमकोटा (आंध्र प्रदेश) में भूतपूर्व सैनिक चिकित्सा कैंप :** आईएनएचएस कल्याणी तथा नौसेना पत्नी कल्याण संगठन (एनडब्ल्यूडब्ल्यूए) के आरोग्य ग्रुप ने 23 जून, 2013 को भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिला परिषद कन्या उच्च विद्यालय, कासिमकोटा में एक चिकित्सा कैंप का आयोजन किया। इस कैंप को भरपूर सफलता मिली जिसमें कासिमकोटा तथा इसके आस-पास रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों ने बड़ी संख्या में चिकित्सा कैंप में हिस्सा लिया।

(ख) **कारवार, कर्नाटक में चिकित्सा कैंप :** नौसेना पत्नी कल्याण संगठन (एनडब्ल्यूडब्ल्यूए) (कारवार) के अस्पताल तथा स्पर्श ग्रुप द्वारा

समुदाय संपर्क कार्यकलापों के एक भाग के रूप में 31 जुलाई, 2013 को आशा निकेतन (सुनने में अक्षम बच्चों के लिए स्कूल) में एक स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया था। इस स्थान पर दंत चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग तथा कायचिकित्सा ओपीडी स्थापित की गई थी।

(ग) **दीयू, गुजरात में चिकित्सा कैंप :** भारतीय नौसेना अस्पताल पोत (आईएनएचएस) अश्विनी, मुम्बई के चार विशेषज्ञों के साथ 22 अगस्त, 2013 दीयू में एक चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया था। कुल मिलाकर 349 स्थानीय रोगियों ने नौसेना चिकित्सा विशेषज्ञ (शल्य चिकित्सा, कायचिकित्सा, स्त्री रोग, दंत चिकित्सा तथा बाल रोग) से परामर्श प्राप्त किया तथा रोगियों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया था।

(घ) **पोरबंदर, गुजरात में चिकित्सा कैंप :** पोरबंदर में सितम्बर, 2013 में एक नौसेना चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 1500 कार्मिकों को निःशुल्क परामर्श और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई गई थीं। इस अवधि में मूलभूत जांचों के साथ-साथ कायचिकित्सा, स्त्री रोग चिकित्सा, बाल रोग चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में निःशुल्क ईलाज तथा परामर्श दिए गए थे और इस कैंप को भरपूर समर्थन मिला। यह चिकित्सा कैंप एक सामाजिक पहल थी और इसमें भा.नौ.पो. दीपक के अफसरों और कार्मिकों द्वारा रक्त दान भी किया गया था।

(ड.) **चिकित्सा कैंपों का आयोजन:** चेन्नई स्थित भा.नौ.पो. अदयार की ओर से चिकित्सा दल द्वारा 5 और 7 अक्टूबर, 2013 को क्रमशः नौसेना डिटेचमेंट मल्लीपटनम तथा जेगाथापटनम, प्रत्येक में प्रतिदिन दो चिकित्सा कैंपों का आयोजन किया गया था। कैंपों में भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ तथा इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण आए। कुल मिलाकर 735 तथा 1150 रोगियों का ईलाज किया गया और दवाइयां उपलब्ध कराई गईं।

## तटरक्षक

### 12.23 बाढ़ राहत :

(क) **बाढ़ राहत, गुजरात :** भारतीय तटरक्षक के बचाव दल ने 27 सितम्बर, 2013 को पोखंडर तथा जामनगर में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ राहत आपरेशन किया और महिलाओं तथा बच्चों सहित 44 व्यक्तियों को बचाया।

(ख) **बाढ़ राहत, मायाबंदर :** 9 अक्टूबर, 2013 को आईसीजीएच, मायाबंदर द्वारा तुगापुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की स्थानीय आबादी के बचाव/ उनको



भारतीय तटरक्षक का एएलएच पीड़ितों को बचाते हुए

निकाले जाने में सहायता के लिए स्थानीय वन कार्मिकों के समन्वय से एक बाढ़ राहत आपरेशन चलाया गया था और 8 महिलाओं सहित 20 लोगों को बचाया गया।

(ग) **चक्रवात फेलीन :** 12 अक्टूबर, 2013 को गोपालपुर (ओडिशा) में एक अत्यंत भयंकर चक्रवाती तूफान फेलीन के परिणामस्वरूप भूस्खलन हुआ। चक्रवात के दौरान निम्नलिखित दो विपदा परिस्थितियों की सूचना दी गई थी :

(i) पारादीप पत्तन के दक्षिण-पश्चिम में 10 नॉटिकल मील पर दो मछली पकड़ने वाली नौकाओं के साथ 18 मछुआरे ईंधन समाप्त होने की वजह से फंस गए थे। आईसीजीएस वज्र तथा एक ओएसवी की तैनाती निरर्थक रही और इसी बीच नौकाएं बहकर तट के निकट आ गईं थीं और मछुआरे सुरक्षापूर्वक तैर कर तट पर आ गए थे, जहां भारतीय तटरक्षक के चिकित्सा दल ने मछुआरों को देखा और उन्हें सुरक्षित पाया।

(ii) 12 अक्टूबर, 2013 को एक पनामा ध्वजयुक्त मालवाहक जलयान एमवी बिंगो जिसमें 18 कार्मिक और 8125 एमटी लौह अयस्क था, सागर द्वीप से 25 नॉटिकल मील दक्षिण-पूर्व की स्थिति में डूब गया। लाइफ बोट/राफ्ट तट की ओर लाए गए और 13/14 अक्टूबर, 2013 को सभी कर्मी सवर्णरेखा नदी के मुहाने के निकट तट पर सुरक्षापूर्वक पहुंच गए। भारतीय तटरक्षक की यूनिटों ने डूबे हुए जहाज की लगातार मॉनीटरिंग की ताकि इस क्षेत्र में किसी संभावित तेल बिखराव का पता लग सके।



(घ) **चक्रवाती तूफान 'लहर'** : 24 नवम्बर, 2013 को दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर एक गहरा निम्नदाब क्षेत्र बना जो तीव्र होकर एक चक्रवाती तूफान 'लहर' बन गया तथा 25 नवम्बर, 2013 को इसने पोर्ट ब्लेयर के निकट अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को पार कर लिया। चक्रवात के बाद खोज तथा बचाव आपरेशनों के लिए सीजीडीओ तथा सीजी हैलो के अलावा छह (6) भारतीय तटरक्षक पोतों को तैनात किया गया और 32 व्यक्तियों की जान बचाई गई।

(ड.) **एमटी 'एलिहुरस'** : 4 मार्च, 2014 को 'एमटी एलिहुरस' पर दुर्घटनापूर्वक आग लगने के कारण दो कर्मी घायल हो गए थे जिन्हें आईसीजीएस सी-143 द्वारा बचाया गया और ईलाज के लिए उन्हें पोरबंदर स्थित अस्पताल ले जाया गया।

## भारतीय वायु सेना

### आपरेशन राहत

12.24 उत्तराखंड में भारी बाढ़ों द्वारा हुई अप्रत्याशित तबाही की वजह से एक तत्काल तथा बड़े पैमाने पर राहत तथा बचाव प्रयास की आवश्यकता हुई। भारतीय वायुसेना ने इस बड़ी चुनौती के प्रति विशेष गति, संकल्प तथा धैर्य के साथ कार्रवाई की। भारतीय वायुसेना के संसाधनों को देश के अलग-अलग क्षेत्रों से लाया गया और इन आपरेशनों के मुख्य हिस्से के दौरान 45 हेलीकॉप्टर तक शामिल किए गए थे।

12.25 जिस पैमाने पर भारतीय वायुसेना ने बचाव तथा राहत आपरेशन किए, वह अभूतपूर्व था। इस आपरेशन की मात्रा

को आपरेशन राहत के 23 सितम्बर, 2013 को पूरा होने पर आंकड़ों द्वारा मापा जा सकता है, जब तक भारतीय वायुसेना ने 3,702 मिशनों पर उड़ान भरी और 24,260 सिविलियनों को बचाया और 894.9 टन राहत आपूर्ति भेजी। इस असाधारण तथा त्वरित कार्रवाई को अब तक के सर्वश्रेष्ठ वायवीय राहत आपरेशन के रूप में दर्ज किया गया है।

12.26 फंसे हुए लोगों का बचाव पूरा करने के साथ ही भारतीय वायुसेना ने आपरेशन राहत के चरण-II में प्रवेश किया। भिन्न दृष्टिकोण तथा नई



वायुसेना द्वारा देश का सबसे बड़ा बचाव अभियान

**आपरेशन राहत के 23 सितंबर 2013 को पूरा होने पर भारतीय वायु सेना ने 3707 मिशनों पर उड़ान भरी, 24,260 सिविलियनों को बचाया और 894,899 टन राहत आपूर्ति भेजी। इस असाधारण तथ त्वरित कार्रवाई को अब तक के सर्वश्रेष्ठ वायवीय राहत आपरेशन के रूप में दर्ज किया गया है।**

रणनीति के साथ भारतीय वायुसेना ने सड़कों, संचार संपर्कों के पुनर्निर्माण तथा स्थानीय लोगों के लिए आश्रय, उनके जीवन व निर्वाह के स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए उत्तराखंड सरकार की सहायता हेतु आगे बढ़कर कार्य किए।





भारतीय वायुसेना का विमान बचाव आपरेशन करते हुए

**12.27 आपरेशन त्रिवेणी :** नक्सलविरोधी आपरेशनों के लिए गृह मंत्रालय की सहायता के वास्ते भारतीय वायुसेना ने दिसम्बर, 2009 तक छह एमआई-17 हेलीकाप्टर तैनात किए । नक्सलविरोधी आपरेशनों की सहायता के लिए, तैनाती के समय से 5714 घंटों में कुल मिलाकर 7742 उड़ानें भरी गईं। इन मिशनों के दौरान, कुल मिलाकर 42,146 यात्रियों, 254 जख्मियों, 267 शवों तथा 886 टन भार को विमान द्वारा ले जाया गया ।

**12.28 अन्य एजेंसियों के लिए मानवीय सहायता तथा आपदा राहत कार्य :** मौजूदा वर्ष में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने बाढ़ राहत आपरेशनों में विभिन्न राज्य सरकारों की सहायता के लिए 3593 मिशनों पर उड़ानें भरीं, फंसे हुए 23,915 सिविलियनों को बचाया तथा 800 टन राहत सामग्री विमानों द्वारा पहुंचाई ।

**12.29 चक्रवात फेलीन :** फेलीन चक्रवात के दौरान भारतीय वायुसेना को एचएडीआर मिशन के लिए तत्पर रहने के लिए कहा गया था । भारतीय वायुसेना ने दो चरणों में हेलीकाप्टर सहायता प्रयास मुहैया

कराए । चरण-I में 11 अक्टूबर, 2013 को भुवनेश्वर में हेलीकाप्टरों को तैनात किया गया और यह 17 अक्टूबर, 2013 को समाप्त हुआ । इस चरण के दौरान, 60 टन अत्यावश्यक राहत सामग्री के भार को लाने-ले-जाने और 15 यात्रियों के बचाव सहित कुल मिलाकर 29 घंटों में 17 उड़ानें भरी गई थीं । चरण-II (25-28 अक्टूबर, 2013) में 28 घंटों में कुल मिलाकर 50 उड़ानें भरी गईं ; जिसमें 40 टन भार ढोना और 69 यात्रियों को बचाया जाना शामिल है ।

**12.30 भा.वा.से. एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर द्वारा क्षतिग्रस्त पवनहंस हेलीकॉप्टर की रिकवरी :** 'आपरेशन राहत' के लिए भारतीय वायुसेना के परिवहन तथा हेलीकॉप्टर बेडे द्वारा किए गए बचाव मिशनों के अलावा, कुछ सिविल हेलीकॉप्टर भी संचालित हो रहे थे । पवनहंस द्वारा परिचालित ऐसा एक हेलीकाप्टर हर्षिल हेलीपैड पर हार्ड लैंडिंग की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था और उसका मलबा तब तक हेलीपैड पर ही पड़ा हुआ था । इस हेलीकाप्टर की रिकवरी के लिए पवनहंस ने भारतीय वायुसेना से संपर्क किया था ।



अंडर-स्लंग आपरेशनों के दौरान पवनहंस के क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर को भा.वा.से एमआई-17 द्वारा दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है

12.31 इस आपरेशन को बड़ी सुव्यवस्था और व्यवसायिक ढंग से किया गया था । आपरेशन में सामने आई प्राकृतिक तथा मनुष्य निर्मित बाधाओं के बावजूद कार्य को सुव्यवस्थित तरीके, समुचित समन्वय तथा सभी एजेंसियों की समर्पित साझेदारी के साथ एक आईएएफ एमआई-17 वी5 का प्रयोग करके पूरा किया गया।

**12.32 22-23 जनवरी, 2013 को जम्मू-कश्मीर में पॉवर लाइन की बहाली :** जनवरी, 2013 में जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी होने की वजह से इस संपूर्ण क्षेत्र में जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था जिसमें श्रीनगर घाटी में बनिहाल दर्रे के बर्फ से ढक जाने के कारण एचटी लाइन पर आंशिक पॉवर फेलर हो गया था । 21 जनवरी, 2013 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने बिजली बहाली में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना से संपर्क किया । इस चुनौतीपूर्ण मिशन के लिए बनिहाल टॉप पर एक मरम्मत दल को विमान से ले जाने के लिए उधमपुर आधारित एक हेलीकाप्टर यूनिट को यह कार्य सौंपा गया क्योंकि उन्हें 300 मेगावाट पावर लाइन पर मरम्मत कराने की आवश्यकता थी ।

12.33 दृश्यात्मक कमी, शून्य डिग्री से नीचे तापमान, प्रतिकूल वायु परिस्थितियां, जिसके साथ उच्च घनत्व की बाधाएं थी, इनके बावजूद समूचा आपरेशन पूर्ण कुलशला तथा सटीकता से पूरा किया गया । इस मिशन से भारतीय वायुसेना की जम्मू और कश्मीर की सिविलियन आबादी को सहायता मुहैया कराने की सदैव तत्पर रहने की छवि में वृद्धि हुई है ।

**12.34 तीव्र बाढ़ों के दौरान तमिलनाडु सरकार को सहायता :** होगेनक्कल जल प्रपात के समीप तीव्र बाढ़ के दौरान कावेरी नदी के बीच में पेड़ों पर फंसे हुए 4 सिविलियनों के बचाव के लिए तमिलनाडु की सरकार ने भारतीय वायुसेना से संपर्क किया । ये सिविलियन 5 अगस्त, 2013 की शाम को फंस गए थे। भारतीय वायुसेना स्टेशन सुलुर में स्थित दो उन्नत हल्के हेलिकाप्टरों को, प्रत्येक हेलीकाप्टर पर अतिरिक्त बचाव उपकरण ले जा रहे दो गरुड़ कमांडो के साथ, बचाव मिशन का कार्य सौंपा गया था ।

12.35 पेड़-पौधे अत्यधिक घने थे तथा जमीन पर उन व्यक्तियों की ओर से कोई संकेत नहीं मिल पाने की वजह से उन्हें देखने के लिए एक लंबी उड़ान आवाजाही की आवश्यकता थी । सभी चार व्यक्तियों को गरुड़ कमांडो की मदद से कर्मियों द्वारा उठाया गया और उनकी सुरक्षा की गई ।



# राष्ट्रीय कैडेट कोर



*'अंतिम सोपान' एन सी सी छात्रों की टीम माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण अभियान - मई 2013 के दौरान*



**एनसीसी** प्रतिबद्धता, समर्पण, स्व-अनुशासन तथा नैतिक मूल्यों की भावनाओं के साथ-साथ देश के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अवसर मुहैया कराने का प्रयास करता है ताकि वे देश के जिम्मेदार नागरिक बन सकें।

13.1 राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन सी सी ) की स्थापना रा0 कैडेट कोर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत हुई थी। यह अपनी स्थापना के 65 वर्ष पूरे कर चुका है। एनसीसी प्रतिबद्धता, समर्पण, स्व-अनुशासन तथा नैतिक मूल्यों की भावनाओं के साथ-साथ देश के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अवसर मुहैया कराने का प्रयास करता है ताकि वे देश के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। राष्ट्रीय कैडेट कोर का आदर्श वाक्य है "एकता और अनुशासन"

13.2 राष्ट्रीय कैडेट कोर की कुल स्वीकृत नफरी 15 लाख कैडेट है। इसमें वर्ष 2010 में स्वीकृत दो लाख कैडेटों की नफरी शामिल है। इस अतिरिक्त दो लाख कैडेटों की नफरी को 2010-11 से 2015-16 तक नई एनसीसी यूनिटों की स्थापना करके चरण-बद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय कैडेट कोर देश के 670 जिलों में मौजूद है जिनमें 15671 संस्थाएं शामिल हैं।

13.3 मौजूदा नामांकित कैडेट नफरी का स्कन्ध-वार विवरण इस प्रकार है-

(क) सेना स्कन्ध	-	7,58,555
(ख) वायु सेना स्कन्ध	-	54,378
(ग) नौ सेना स्कन्ध	-	55,435
(घ) छात्रा स्कन्ध	-	3,04,661
<b>कुल</b>	-	<b><u>11,73,029</u></b>

13.4 इस वर्ष खेल तथा साहस के क्षेत्र में दिल्ली में अक्टूबर 2013 में एनसीसी राष्ट्रीय खेलों का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया तथा मई 2013 में एनसीसी की छात्र टीम ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

### **मुख्य गतिविधियां और प्रमुख उपलब्धियां**

13.5 2 लाख अतिरिक्त कैडेटों की नफरी के लिए तीसरे चरण में नई स्थापनाएं खड़ी करने की स्वीकृति :- सरकार द्वारा अब तीसरे चरण में 11 सेना यूनिटें तथा एक नौसेना यूनिट खड़ी करने की स्वीकृति दे दी गई है। इन यूनिटों की स्थापना के बाद इनकी संख्या बढ़कर 812 हो जाएगी।

13.6 राष्ट्रीय कैडेट कोर वरिष्ठ प्रभाग/वरिष्ठ स्कंध कैडेटों की नामांकन अवधि का संशोधन :- वरिष्ठ प्रभाग/वरिष्ठ स्कंध कैडेटों के लिए 3+1 वर्ष की अवधि के संशोधन हेतु भारत सरकार की अनुमति प्रदान कर दी गई है तथा यह नामांकन प्रशिक्षण वर्ष 2014-15 से शुरू होगा।

13.7 राज्य शिक्षा विभाग के अधीन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में नए एनसीसी सैल खोलना तथा एनसीसी गतिविधियां करना :- राज्य शिक्षा



विभाग के अधीन सभी राज्यों में एनसीसी सैल के विभागाध्यक्ष (एच ओ डी) के रूप में अपर महानिदेशकों/उप महानिदेशकों (एडीजी/डीडीजी) को नामित करने के प्रस्तावों को रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को रक्षा मंत्रालय द्वारा इस मामले से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश 12 सितम्बर 2013 को जारी कर दिए गए हैं।

13.8 एनसीसी को और अधिक जिलों में पहुंचाना :- पिछले वर्ष 633 जिलों की तुलना में इस वर्ष 670 जिलों में एनसीसी फैली हुई है।

13.9 एन सी सी छात्रा कैडेट बटालियन खड़ी करना : दूसरे चरण में 02 छात्रा कैडेट बटालियन खड़ी की गई थीं। तीसरे चरण में एक और छात्रा बटालियन खड़ी करने की सरकारी मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

## प्रशिक्षण

13.10 राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं :-

(क) संस्थागत प्रशिक्षण

(ख) शिविर प्रशिक्षण

(ग) साहसिक प्रशिक्षण

(घ) समाज सेवा तथा सामुदायिक विकास कार्य-कलाप

(च) युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम



छात्रा कैडेटों का बाधा पार प्रशिक्षण

13.11 संस्थागत प्रशिक्षण : इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को सैन्य जीवन शैली से परिचित कराना और उनमें अनुशासन, व्यक्तित्व विकास तथा व्यवस्थित जीवन मूल्यों का संचार करना है। सभी नामांकित कैडेटों को अपने-अपने स्कूलों/कालेजों में एन सी सी के प्रत्येक स्कंध के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में यह प्रशिक्षण दिया जाता है।

13.12 शिविर प्रशिक्षण : शिविर प्रशिक्षण एन सी सी के पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये शिविर कैडेटों में साहचर्य, टीम भावना, परिश्रम की महत्ता और आत्म-विश्वास का विकास करने में सहायक होते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है- "एकता एवं अनुशासन" का विकास करना। एनसीसी ने अपने कैडेटों के लिए व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में मानव मूल्यों की कक्षाएँ भी शुरू की हैं। एन सी सी द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के शिविर इस प्रकार हैं:-

शिविर प्रशिक्षण एन सी सी के पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये शिविर कैडेटों में साहचर्य, टीम भावना, परिश्रम की महत्ता और आत्म-विश्वास का विकास करने में सहायक होते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है- "एकता एवं अनुशासन" का विकास करना।

(क) वार्षिक प्रशिक्षण शिविर : वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन राज्य निदेशालयों द्वारा यह सुनिश्चित

करने के लिए किया जाता है कि जूनियर डिविजन/ वींग (जेडी/जे डब्ल्यू) के कम से कम 50% कैडेट और सीनियर डिविजन के 100% कैडेट, जिनकी संख्या लगभग 8.5 लाख है, वर्ष में ऐसे एक शिविर में अवश्य भाग लें। हर वर्ष ऐसे लगभग 1700 शिविर लगाए जाते हैं।

(ख) **राष्ट्रीय एकता शिविर (एन आई सी):** हर वर्ष कुल 37 राष्ट्रीय एकता शिविर (एनआईसी) आयोजित किए जाते हैं। सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से कुल 24200 कैडेट इन राष्ट्रीय एकता शिविरों में भाग लेते हैं। अब तक देश के विभिन्न भागों में 36 राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा निम्नलिखित स्थानों पर विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित किए गए हैं -

- (1) **विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर, लेह :** इस क्षेत्र में राष्ट्रीय कैडेट कोर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 26 अगस्त से 06 सितम्बर 2013 तक लेह में एक **विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर** का आयोजन किया गया है। इसमें देश के सभी भागों से कुल 170 कैडेटों ने भाग लिया। कैम्प में सेना तथा सिविल स्टाफ़ के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
- (2) **विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर जखामा (नागालैण्ड) :** 18 से 29 जून 2013 के दौरान जखामा (नागालैण्ड) में एक राष्ट्रीय स्तर के शिविर का आयोजन किया गया जिसमें पूरे भारत वर्ष से 600 कैडेटों ने भाग लिया।
- (3) **विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर बड़ाबाग (जैसलमेर) :** 18 से 29 अक्टूबर 2013 के दौरान बड़ाबाग, जैसलमेर में एक राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया गया और पूरे भारत से 300 कैडेटों ने इस शिविर में भाग लिया।

(5) **विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर पोर्टब्लेयर:** 09 फरवरी से 20 फरवरी 2014 के दौरान पोर्टब्लेयर में एक विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 180 कैडेटों ने भाग लिया।

(ग) **वायुसेना शिविर (वी एस सी) :** हर वर्ष वायुसेना वरिष्ठ प्रभाग तथा वरिष्ठ स्कंध के कैडेटों के लिए जाकूर एयरफील्ड, बंगलूर में 12 दिन की अवधि के लिए एक अखिल भारतीय वायुसेना शिविर का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2013 तक इस शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में (जम्मू-कश्मीर निदेशालय को छोड़कर) सभी 16 निदेशालयों के कुल 594 वरिष्ठ प्रभाग एवं वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने भाग लिया।

(घ) **नौसैनिक शिविर :** यह शिविर भी नौसेना स्कंध के वरिष्ठ प्रभाग एवं वरिष्ठ स्कंध के कैडेटों के लिए वर्ष में एक बार 12 दिन की अवधि के लिए आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 07 से 18 जनवरी 2014 तक विशाखापटनम में यह शिविर आयोजित किया गया जिसमें एन सी सी के सभी 17 निदेशालयों से वरिष्ठ प्रभाग/ वरिष्ठ स्कंध के 589 कैडेटों ने भाग लिया।

(च) **थल सैनिक शिविर :** गणतन्त्र दिवस परेड ग्राउंड, दिल्ली छावनी में हर वर्ष दो थल सेना शिविरों का आयोजन किया जाता है जिनमें से एक वरिष्ठ प्रभाग छात्रों के लिए तथा दूसरा वरिष्ठ स्कंध छात्रा कैडेटों के लिए होता है। इस वर्ष 27 सितम्बर से 08 अक्टूबर 2013

तक इन शिविरों का आयोजन किया गया। सभी 17 एन सी सी निदेशालयों से कुल 1360 कैडेटों ने इस शिविर में भाग लिया।

(छ) **नेतृत्व शिविर** : हर वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर 06 उन्नत नेतृत्व शिविरों (एएलसी) का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष जून से दिसम्बर 2013 तक इन शिविरों में कुल 1800 कैडेटों ने भाग लिया।

(ज) **पर्वतारोहण प्रशिक्षण शिविर** : कैडेटों को पर्वतारोहण की प्राथमिक जानकारी देने के लिए और उन्हें साहस की भावना से ओत-प्रोत करने के लिए इस प्रशिक्षण वर्ष में 04 पर्वतारोहण शिविर आयोजित किए गए। इस वर्ष नवम्बर 2013 में 540 कैडेटों के इन शिविरों में भाग लिया।

(झ) **गणतन्त्र दिवस शिविर 2014** : नई दिल्ली में जनवरी 2014 में गणतंत्र दिवस शिविर तथा प्रधानमंत्री रैली - 2014 का आयोजन किया गया। इस शिविर में देश भर के 2070 कैडेटों ने भाग लिया। इसके अलावा युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत मित्र देशों के कैडेटों ने भी इस शिविर में भाग लिया। पूरे माह-भर चले इस शिविर में सांस्थानिक प्रशिक्षण से सरोकार रखने वाली अन्तर निदेशालय प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं तथा राष्ट्रीय एकता जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

13.13 **गणतंत्र दिवस परेड** : एनसीसी के दो मार्चिंग दस्तों तथा एनसीसी के दो बैंडों (एक संयुक्त छात्र तथा एक छात्रा) ने 26 जनवरी 2014 को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया।



राजपथ पर एन सी सी छात्रा सैन्य टुकड़ी

13.14 **अटैचमेंट प्रशिक्षण** : एन सी सी कैडेट सशस्त्र सेना यूनिटों से जुड़कर नए नए महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करते हैं। इस वर्ष निम्नलिखित अटैचमेंट प्रशिक्षण आयोजित किए गए :-

(क) इस वर्ष महिला अधिकारियों सहित 440 अधिकारी तथा 560 वरिष्ठ स्कंध के कैडेटों सहित 20,000 कैडेटों ने नियमित सेना यूनिटों के साथ अटैचमेंट प्रशिक्षण में भाग लिया।

(ख) इस वर्ष 120 वरिष्ठ प्रभाग तथा 48 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने क्रमशः भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून और अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चैन्नई में दो-दो सप्ताह का अटैचमेंट प्रशिक्षण लिया।

(ग) 1000 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों को विभिन्न सेना चिकित्सालयों में अटैच किया गया।

(घ) वायुसेना स्कंध 16 राज्यों के एनसीसी निदेशालयों (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) 100 एन सी सी कैडेटों (76 वरिष्ठ प्रभाग तथा 24 वरिष्ठ स्कंध) ने वायुसेना स्टेशन, डुंडीगल में अटैचमेंट प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह प्रशिक्षण वर्ष में दो बार 13-13 दिन के लिए क्रमशः जून और अक्टूबर मास में आयोजित किया जाता है।

(ड.) सेना विंग के 60 एन सी सी अफसरों और 560 एस डब्लू कैडेटों ने विभिन्न सेना यूनिटों में अटैचमेंट प्रशिक्षण प्राप्त किया।

13.15 **माइक्रोलाइट फ्लाईंग** : एयर विंग (वरिष्ठ प्रभाग/वरिष्ठ स्कंध) के एनसीसी कैडेटों को हवाई अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से एनसीसी में माइक्रोलाइट फ्लाईंग का आयोजन किया जाता है। इस समय देश के सभी राज्यों में 45 जेन एयर माइक्रोलाइट तथा 06 “एक्स” एयर माइक्रोलाइट विमानों की सहायता से 47 एनसीसी एयर स्क्वाड्रनों में माइक्रोलाइट फ्लाईंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

13.16 **एयर विंग ए एन ओ के लिए कमीशन से पूर्व तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम** :- हर वर्ष एयर विंग के सहायक एनसीसी अफसरों के लिए 8/9 सप्ताह की अवधि के 03 कमीशन पूर्व पाठ्यक्रम तथा 04 सप्ताह की अवधि के 03 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम वायुसेना स्टेशन ताम्रम में आयोजित किए जाते हैं। लगभग 210 एयर विंग ए एन ओ प्रतिवर्ष विजय पाठ्यक्रम में भाग लेते हैं।

13.17 **नौसेना पोतअटैचमेंट** : नौसेना स्कंध के 295 कैडेटों को नौसेना के मुम्बई, कोच्चि तथा विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के जहाजों पर 12 दिन का समुद्री प्रशिक्षण दिया गया।

13.18 **विदेशी समुद्री यात्रा** :

(क) **नौसेना समुद्री यात्रा**

(i) एक कैडेट ने नौ सैनिक प्रशिक्षण जहाज पर सवार होकर 31 मार्च से 13 अप्रैल 2013 तक कोलंबो तथा माले की यात्रा की।

(ii) 10 कैडेटों ने नौ सैनिक पोतों पर सवार होकर 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर 2013 तक सेशेल्स तथा मॉरीशस की यात्रा की।

(ख) **तटरक्षक** : 22 फरवरी से 30 मार्च 2013तक 06 एन सी सी कैडेटों ने दक्षिण तथा सिंगापुर, जकार्ता, पोर्ट कैलांग तथा फुकेट के बन्दरगाहों का दौरा किया।

13.19 **नौसेना अकादमी अटैचमेंट प्रशिक्षण** : 09-20 दिसम्बर 2013 तक भारतीय नौसेना अकादमी, एजीमाला में 170 वरिष्ठ स्कंध के कैडेटों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

13.20 **नौसेना स्कंध के लिए तकनीकी एन सी सी शिविर** : चैन्नई के इंजीनियरिंग कॉलेजों के 115 वरिष्ठ प्रभाग/वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने 10 जून से 19 जून 2013 तक वार्षिक तकनीकी प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। कैडेटों को **आई एन एस शिवाजी** पर नौसेना इंजीनियरी स्थापनाओं तथा नेवल डॉकयार्ड, मुंबई पर शिक्षण दौरे के लिए ले जाया गया।

**साहसिक प्रशिक्षण :**

13.21 **चिल्का में अखिल भारतीय नौका दौड़ (सेलिंग रिगोटा)** : सभी एनसीसी निदेशालयों से 51 वरिष्ठ प्रभाग तथा 51 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने 06-13 नवम्बर 2013 तक भारतीय नौसेना पोत चिल्का में आयोजित अखिल भारतीय एनसीसी नौका दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। बंगला देश एन सी सी के 01 अधिकारी और 06 कैडेटों ने भी इस दौड़ में भाग लिया।

### 13.22 नौकायन अभियान :

नौकायन अभियान नौसेना प्रशिक्षण का एक रोचक अंग होता है और प्रत्येक एन सी सी निदेशालय 12 दिन के लिए न्यूनतम एक नौकायन अभियान

आयोजित करता है जिसमें कुल 400 से 500 किलोमीटर दूरी तय की जाती है। इस अभियान में प्रत्येक निदेशालय के 40 से 60 कैडेट भाग लेते हैं। वर्ष 2013-14 में विभिन्न एन सी सी निदेशालयों ने ऐसे 14 अभियान आयोजित किए।

13.23 **स्कूबा डाइविंग** : भारतीय नौसेना के नौसेना गोताखोर दलों की सहायता से मुम्बई, गोवा और चैन्नई (02) में चार स्कूबा डाइविंग शिविर आयोजित किए जाते हैं।

13.24 **विंड सर्फिंग/क्याकिंग** : नौसेना स्कंध के कैडेटों को विंड सर्फिंग और क्याकिंग की बुनियादी दक्षताओं से अवगत कराने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है।

### 13.25 पर्वतारोहण अभियान

(क) **पर्वतारोहण पाठ्यक्रम** : प्रशिक्षण वर्ष 2013-14 में सभी एन सी सी निदेशालयों से 344 वरिष्ठ प्रभाग/वरिष्ठ स्कंध कैडेटों को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग, जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान, नूनवान, पहलगँव और पर्वतारोहण तथा अन्य संबन्धित खेल निदेशालय, मनाली के विभिन्न पाठ्यक्रमों में भेजा गया।

एनसीसी में पहली बार 08 वरिष्ठ प्रभाग कैडेट और 04 पी आई स्टाफ़ के छात्र अभियान दल ने दो समूहों में 19 और 20 मई 2013 को माऊंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़ाई की।

(ख) एनसीसी छात्र तथा छात्रा पर्वतारोहण अभियान: एन सी सी प्रतिवर्ष दो पर्वतारोहण अभियान आयोजित करता है जिनमें से एक वरिष्ठ प्रभाग (छात्र)

और दूसरा वरिष्ठ स्कंध (छात्रा) के लिए होता है। 1970 से अब तक एन सी सी ने 71 पर्वतारोहण अभियान आयोजित किए गए जिनमें से 38 छात्रों के लिए तथा 33 अभियान छात्राओं के लिए आयोजित किए गए। प्रशिक्षण वर्ष 2013-14 में मनाली में माऊंट शीतिधार में सितम्बर/अक्तूबर 2013 में एक एनसीसी छात्रा पर्वतारोहण अभियान आयोजित किया गया।

(ग) **माऊंट एवरेस्ट अभियान** : एनसीसी में पहली बार 08 वरिष्ठ प्रभाग कैडेट और 04 पी आई स्टाफ़ के छात्र अभियान दल ने दो समूहों में 19 और 20 मई 2013 को माऊंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़ाई की।

13.26 **ट्रेकिंग अभियान** : वर्ष 2013-14 में एनसीसी निदेशालयों द्वारा 23 ट्रेकिंग अभियान किए गए जिनमें 11500 कैडेटों ने भाग लिया।

13.27 **पैरा सेलिंग** : एनसीसी के छात्र तथा छात्रा कैडेटों के लिए साहसिक गतिविधि के एक भाग के रूप में प्रत्येक ग्रुप मुख्यालय पर पैरा सेलिंग अभियान आयोजित किए जाते हैं।

13.28 **पैरा बेसिक पाठ्यक्रम** : प्रतिवर्ष 40 छात्र तथा 40 छात्रा कैडेटों को पैरा प्रशिक्षण स्कूल, आगरा में पैरा बेसिक पाठ्यक्रम में नामित किया जाता है। वर्ष 2013-



14 में 40 वरिष्ठ प्रभाग तथा 39 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया।

13.29 **स्लिदरिंग प्रदर्शन** : वर्ष 2013-14 में 120 कैडेटों को स्लिदरिंग में प्रशिक्षित किया गया और 25 वरिष्ठ प्रभाग तथा 25 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने एनसीसी की **प्रधानमंत्री रैली-2014** में भाग लिया।

13.30 **डेजर्ट कैमल सफारी** : 08 नवम्बर से 19 नवम्बर 2013 तक 20 भारतीय एनसीसी कैडेटों के साथ सिंगापुर के 02 अधिकारी तथा 10 कैडेट एवं कजाकिस्तान के 02 अधिकारियों एवं 12 कैडेटों ने जैसलमेर में डेजर्ट कैमल सफारी में भाग लिया।

### युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (वाई ई पी) :

13.31 **युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेश दौरे** : वर्ष 2013-14 में युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत 9 विदेश दौरे किए गए, जिनका विवरण इस प्रकार है :-

क्रम सं.	देश	अधिकारी	कैडेट
(क)	सिंगापुर (वायुसेना स्कंध)	1	4
(ख)	सिंगापुर (नौसेना स्कंध)	1	4
(ग)	रूस	2	10
(घ)	श्रीलंका - I	2	12
(च)	श्रीलंका - II	1	6
(छ)	सिंगापुर (सेना)	2	10
(ज)	वियतनाम	2	13
(झ)	कजाकिस्तान	2	12
(ट)	नेपाल	1	4
	<b>कुल</b>	<b>14</b>	<b>75</b>

13.32 **युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में विदेशी प्रतिनिधि मंडलों द्वारा किए जाने वाले दौरे** : वर्ष 2013-14 में युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी प्रतिनिधि मंडलों द्वारा भारत में निम्नलिखित दौरे किए गए :

क्र. सं.	देश	अधिकारी	कैडेट
(क)	सिंगापुर एवं कजाकिस्तान एन सी सी कैडेटों द्वारा डेजर्ट सफारी के लिए	4	18
(ख)	बंगला देश (सेलिंग रिगेटा)	1	6
(ग)	बंगला देश बेलगांव ट्रेक	1	8
(घ)	शिवाजी ट्रेल ट्रेक, श्री लंका	1	6
(च)	रूस, कजाकिस्तान, बंगला देश, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान और वियतनाम से 08 प्रतिनिधि मंडलों ने गणतंत्र दिवस शिविर (आरडीसी) 2014 में भाग लिया	13	68
(छ)	मित्र देशों के युवा संगठनों के विभागाध्यक्ष	6	0
	<b>कुल</b>	<b>26</b>	<b>106</b>

### सामाजिक सेवा एवं सामुदायिक विकास

13.33 कैडेटों में समुदाय के लिए निःस्वार्थ सेवा, परिश्रम के प्रति निष्ठा एवं स्वयं सहायता का महत्व, पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकता और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में सहायता करने की भावना पैदा करने के उद्देश्य से एनसीसी द्वारा समाज सेवा तथा सामुदायिक विकास के कार्य किए जाते हैं। ये कार्य प्रौढ़ शिक्षा, वृक्षारोपण, रक्तदान, वृद्धाश्रमों, विकलांग बच्चों के स्कूलों व अनाथालयों का दौरा करने, मलिन बस्तियों की सफाई, ग्रामीण उत्थान एवं

विभिन्न सामाजिक योजनाओं के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से किए जाते हैं। एनसीसी कैडेटों ने जिन बड़ी गतिविधियों में भाग लिया उनका विवरण आगामी अनुच्छेदों में दिया गया है :-

**कैडेटों में समुदाय के लिए निःस्वार्थ सेवा, परिश्रम के प्रति निष्ठा एवं स्वयं सहायता का महत्त्व, पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकता और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में सहायता करने की भावना पैदा करने के उद्देश्य से एनसीसी द्वारा समाज सेवा तथा सामुदायिक विकास के कार्य किए जाते हैं।**

(क) **वृक्षारोपण** : एनसीसी कैडेट पौधे लगाते हैं तथा बाद में संबंधित राज्य विभाग/कॉलेजों/स्कूलों और गाँवों के साथ मिल कर उनकी देखभाल करते हैं। इस वर्ष पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण अभियान के अंतर्गत एनसीसी कैडेटों ने देश भर में 2.31 लाख पौधे लगाए।

(ख) **रक्तदान** : जब अस्पतालों/रेड क्रॉस को आवश्यकता होती है, एन सी सी कैडेट स्वैच्छा से रक्तदान करते रहे हैं। इस वर्ष एनसीसी के 15751 कैडेटों ने स्वैच्छा से रक्तदान किया।

(ग) **वृद्धाश्रम** : पिछले वर्षों की तरह, इस वर्ष भी कैडेटों ने वृद्धाश्रमों को अपनी सेवाएं प्रदान की।

(घ) **आपदा राहत** : एनसीसी ने प्राकृतिक एवं अन्य आपदाओं और दुर्घटनाओं के समय हमेशा पीड़ितों की सहायता की है। पिछले वर्षों में एनसीसी कैडेटों ने उत्तराखण्ड में भूकम्प, सिक्किम तथा उड़ीसा में तूफान से आई आपदाओं में उत्कृष्ट सहायता प्रदान की है।

(च) **एड्स जागरूकता कार्यक्रम** : एनसीसी कैडेट एड्स/एचआईवी के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और वे देश भर में एड्स जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। विभिन्न शिविरों के दौरान एच आई वी/एड्स पर व्याख्यान तथा बातचीत के सत्र आयोजित

किए जा रहे हैं। इस वर्ष 01 दिसम्बर 2013 को एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया जिसमें सभी 17 निदेशालयों से 27600 एन सी सी कैडेटों ने भाग लिया।

(छ) **दहेज रोधी और कन्या-भ्रूण हत्या रोधी शपथ** : पूरे देश में एन सी सी कैडेटों ने दहेज रोधी और कन्या-भ्रूण हत्या रोधी शपथ ली। इसमें 30000 कैडेटों ने भाग लिया।



एड्स जागरूकता अभियान

- (ज) **नशा रोधी रैली** : देश के प्रमुख शहरों और कस्बों में लगभग 37900 एनसीसी कैडेटों ने नशारोधी रैलियों में भाग लिया।
- (झ) **पल्स पोलियो टीकाकरण** : एनसीसी कैडेटों ने राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार पूरे देश में सरकार द्वारा चलाए गए अनेक पोलियो उन्मूलन कार्यक्रमों में भी भाग लिया।
- (ट) **प्रौढ़ शिक्षा** : शिक्षा की आवश्यकता पर बल देने और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम के संचालन में सहायता के लिए एनसीसी कैडेटों ने दूर-दराज के इलाकों, गांवों और विकासाधीन क्षेत्रों का दौरा किया।
- (ठ) **सामुदायिक कार्य** : एन सी सी के 21752 कैडेटों ने ग्रामीण तथा शहरी सामुदायिक परियोजनाओं जैसे ग्रामीण सड़क सुधार, स्वच्छता अभियानों आदि जैसे अन्य विकास कार्यों में भाग लिया।
- (ड) **कुष्ठ रोधी अभियान** : एन सी सी कैडेटों ने पूरे देश में कुष्ठ रोधी अभियानों का आयोजन किया तथा वे इस क्षेत्र में विभिन्न स्वयं सेवी/सरकारी संगठनों की सहायता कर रहे हैं।
- (ढ) **कैंसर जागरूकता कार्यक्रम** : लगभग 23,000 एन सी सी कैडेटों ने विभिन्न शहरों में आयोजित कैंसर जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- (त) **तम्बाकू रोधी अभियान** : 31 मई 2013 को मनाए गए तम्बाकू-रोधी दिवस (नो टोबैको डे) पर सभी निदेशालयों के लगभग 37,900 कैडेटों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। इस दिन तंबाकू के कुप्रभावों के बारे में आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए सभी एनसीसी निदेशालयों

में एनसीसी कैडेटों द्वारा विभिन्न रैलियों/रोड शो/नाटकों का आयोजन किया गया।

- (थ) **नागरिक शिष्टाचार और तत्संबंधी नियमों के प्रति जागरूकता** : एन सी सी कैडेट विभिन्न शहरों में आयोजित यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियानों में नियमित रूप से भाग लेते हैं। इस अवधि के दौरान कैडेट विभिन्न यातायात नियंत्रण चौकियों पर तैनात रहते हैं और इस प्रकार वे स्थानीय यातायात पुलिस के संसाधनों में इजाफ़ा करते हैं।
- (द) **गाँवों तथा मलिन बस्तियों का अंगीकरण**- एन सी सी देश के विभिन्न भागों में गाँवों व मलिन बस्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए 939 गांवों/मलिन बस्तियों का अंगीकरण किया है। इससे एनसीसी कैडेटों को समाज के विभिन्न वर्गों और गाँवों में रहने वाले लोगों के साथ जुड़ने का अवसर भी मिलता है।

## राष्ट्रीय स्तर पर खेल गतिविधियां

13.34 **एन सी सी राष्ट्रीय खेल** : एन सी सी राष्ट्रीय खेल नई दिल्ली में 17 से 27 अक्टूबर, 2013 तक आयोजित किए गए। कुल 2100 कैडेटों ने फुटबाल, हॉकी, एथलेटिक्स, खो-खो, कबड्डी और निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। पश्चिम बंगाल और सिक्किम निदेशालय समग्र चैम्पियन और महाराष्ट्र निदेशालय उप-विजेता रहा।

13.35 **जवाहरलाल नेहरू हॉकी कप टूर्नामेंट** : इस वर्ष प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट 2013, में जूनियर ब्वायज और सब-जूनियर ब्वायज की श्रेणियों ने भाग लिया जहां उन्होंने देश की कुछ सर्वोत्तम टीमों और कुछ विदेशी टीमों के विरुद्ध खेला।

13.36 **सुब्रतो कप फुटबाल टूर्नामेंट** : जूनियर ब्वायज और सब-जूनियर ब्वायज और जूनियर गर्ल्स की श्रेणियों में एन सी सी टीमों ने प्रतिष्ठित सुब्रतो कप फुटबाल टूर्नामेंट 2013 में भाग लिया जहां उन्होंने देश की कुछ सर्वोत्तम टीमों और कुछ विदेशी टीमों के विरुद्ध खेला। सब-जूनियर ब्वायज एन सी सी टीम सेमीफाइनल में पहुंची और जूनियर ब्वायज एन सी सी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची।

13.37 **अखिल भारतीय जी वी मावलंकर शूटिंग चैम्पियनशिप** : फायरिंग एन सी सी की एक केन्द्रीय प्रशिक्षण गतिविधि है, अतः शूटिंग विधा का एन सी सी की खेलकूद गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एन सी सी राष्ट्रीय खेल 2013 के दौरान चुनिंदा

एन सी सी कैडेटों ने इस वर्ष अखिल भारतीय जी वी मावलंकर शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। एन सी सी शूटिंग टीमें गत कई वर्षों से इस स्पर्धा में अच्छा कर रही हैं। इस वर्ष 46 कैडेटों ने भाग लिया और एन सी सी शूटिंग टीम ने 6 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक जीते।

13.38 **राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप प्रतियोगिता** : प्रतिवर्ष एन सी सी शूटिंग टीमें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। वर्ष 2013 में, 30 एन सी सी शूटरों का 57वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया। टीम ने 3 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक जीते।





## विदेशों के साथ रक्षा सहयोग



भारतीय सेना ने पी एल ए के साथ चीन में 4-14 नवम्बर, 2013 तक संयुक्त अभ्यास "हाथ में हाथ" आयोजित किया।

## मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है ।

14.1 मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है । इसमें रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र सेनाओं द्वारा पारस्परिक विश्वास और समझ बनाने और बढ़ावा देने, युद्ध स्थितियों से बचने और संघर्ष निवारण और समाधान के लिए योगदान देने संबंधी पहलें और कार्यकलाप शामिल हैं। उच्च स्तरीय यात्राओं, वार्ताओं, प्रशिक्षण के आदान-प्रदान, संयुक्त/बहुपक्षीय सेना अभ्यासों, सेना से सेना के बीच वार्ताओं और रक्षा सहयोग के अन्य रूपों में रक्षा कूटनीति संबंधी पहलों का अनुसरण किया गया है ।

14.2 भारत ने **अफगानिस्तान** को उसकी राजनीतिक और सुरक्षा परिस्थिति को स्थिर बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों में अपने सहयोग को सतत जारी रखा । भारत, अफगान राष्ट्रीय सेना के सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, चिकित्सा प्रशिक्षण और चिकित्सा सहायता के रूप में सहायता करता रहा है ।

14.3 **बांग्लादेश** के साथ रक्षा सहयोग को द्विपक्षीय दौरों और रक्षा संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आदान-प्रदान से और सुदृढ़ किया गया है। जनरल इकबाल करीम भुइयान, सेनाध्यक्ष, बांग्लादेशी सेना ने 1-4 अप्रैल, 2013 को भारत का दौरा किया था। भारत-

बांग्लादेश नौसेना से नौसेना स्टाफ के बीच आरंभिक वार्ताएं 15-17 अप्रैल, 2013 को भारत में आयोजित की गई थीं । चौथी भारत-बांग्लादेश सेना से सेना स्टाफ के बीच वार्ताएं 25-28 अगस्त, 2013 को ढाका में आयोजित की गई थीं ।

14.4 भारत के **भूटान** के साथ ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ रक्षा संबंध रहे हैं । भूटान में 1963 में स्थापित भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (आई एम टी आर ए टी) रॉयल भूटान आर्मी के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करता है । रॉयल भूटान आर्मी के मुख्य संक्रिया अधिकारी मेजर जनरल बाटू-शेरिंग ने 12-17 सितम्बर, 2013 तक भारत का दौरा किया था ।

14.5 भारत और **चीन** के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता 14-15 जनवरी, 2013 को बीजिंग में आयोजित की गई थी । रक्षा सचिव ने भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और लेफ्टिनेंट जनरल क्यूई ज्यांगुओ, डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए) ने चीनी पक्ष का नेतृत्व किया ।

14.6 रक्षा मंत्री ने 4-7 जुलाई, 2013 तक चीन में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उक्त दौरे के दौरान रक्षा मंत्री की प्रधानमंत्री ली

केक्यांग और रक्षा मंत्री जनरल चांग वेंक्यांग के साथ बैठकें हुईं। माननीय प्रधानमंत्री के 22-24 अक्टूबर, 2013 तक चीनी दौरे के दौरान भारत और चीन के बीच सीमा रक्षा सहयोग के बारे में 23 अक्टूबर, 2013 को एक

**माननीय प्रधानमंत्री के 22-24 अक्टूबर, 2013 तक चीनी दौरे के दौरान भारत और चीन के बीच सीमा रक्षा सहयोग के बारे में 23 अक्टूबर, 2013 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए ।**

करार पर हस्ताक्षर किए गए । रक्षा सचिव ने भारत की ओर से इस करार पर हस्ताक्षर किए । इस करार में सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने संबंधी उपायों को सुदृढ़ करने की इच्छा प्रकट की गई है ।

14.7 भारतीय सेना और पी एल ए के बीच तीसरा संयुक्त सेना अभ्यास 'हाथ में हाथ' 4-14 नवम्बर, 2013 को चीन में आयोजित किया गया था । 6वीं वार्षिक रक्षा और सुरक्षा वार्ता (ए डी एस डी) 24 जनवरी, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी । रक्षा सचिव ने भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और ले. जनरल वांग गुआंगझांग, डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए) ने चीनी पक्ष का नेतृत्व किया ।

14.8 हाल के वर्षों के दौरान भारत और **मालदीव** के बीच रक्षा संबंधों में निरन्तर वृद्धि होती रही है। श्री मोहम्मद नाजिम, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री, मालदीव ने 14-19 अप्रैल, 2013 और 11-15 दिसम्बर, 2013 तक भारत का दौरा किया । रक्षा मंत्री के साथ हुई उनकी बैठक के दौरान, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग संबंधी पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया । ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद शियाम सी डी एफ

मालदीव ने 3-8 फरवरी, 2014 तक डिफेक्सपो में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था । उन्होंने अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में पासिंग आउट परेड का पुनरीक्षण करने के लिए 15-16 मार्च, 2014

को भी भारत का दौरा किया ।



मालदीव के रक्षा मंत्री कर्नल (सेवा निवृत्त) मोहम्मद नाजिम की नवम्बर 2013 में भारत की यात्रा के दौरान एस एन सी, कोच्चि में आयोजित किए गए समारोह के दौरान उनको ए एल एच भेंट किया गया।

14.9 **म्यांमार** के साथ रक्षा सहयोग में बेहतर प्रगति हो रही है । म्यांमार के साथ चल रहे रक्षा सहयोग संबंधी कार्यक्रमों में दौरे का नियमित आदान-प्रदान, भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा बंदरगाह पर अहवान और प्रशिक्षण आदान-प्रदान शामिल हैं । रक्षा मंत्री ने 21-22 जनवरी, 2013 को म्यांमार का दौरा किया था । भारतीय नौसेना और म्यांमार नौसेना के बीच आरंभिक समन्वित गश्त (कोरपेट) का आयोजन 17-21 मार्च, 2013 को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आई एम बी एल) पर किया गया था । वाइस एडमिरल थुरा थेट



स्वे, कमांडर-इन-चीफ म्यांमार नौसेना ने 29 जुलाई से 1 अगस्त, 2013 को भारत का दौरा किया था। सेनाध्यक्ष ने 29 अक्टूबर से 02 नवम्बर, 2013 को म्यांमार का दौरा किया था। दूसरी भारतीय नौसेना-म्यांमार नौसेना स्टाफ वार्ताएं 5-7 नवम्बर, 2013 को नेपेयीताव, म्यांमार में आयोजित की गई थी। वाइस सीनियर जनरल सोई विन, डिप्टी कमांडर-इन-चीफ रक्षा सेवाएं एवं कमांडर-इन-चीफ आर्मी, म्यांमार ने 11-14 दिसम्बर, 2013 तक भारत का दौरा किया था।

14.10 भारत, **नेपाल** के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। नेपाली सेना के कार्मिक पर्याप्त संख्या में प्रतिवर्ष भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। जनरल गौरव एस जे बी राणा, सेनाध्याक्ष, नेपाली सेना ने 7-15 जनवरी, 2013 और 23 सितम्बर से 6 अक्टूबर, 2013 को भारत का दौरा किया था। सितम्बर-अक्टूबर, 2013 में इनकी यात्रा के दौरान इन्होंने प्रथम बटालियन स्तरीय संयुक्त सेना अभ्यास 'सूर्य किरण' का अवलोकन किया जो भारतीय सेना और नेपाली सेना के बीच 23 सितम्बर से 6 अक्टूबर, 2013 को भारत में आयोजित किया गया था। भारत के सेनाध्यक्ष ने 10-11 जून, 2013 और 13-14 मार्च, 2014 को नेपाल का दौरा किया था जिसके दौरान उन्होंने द्वितीय बटालियन स्तरीय संयुक्त सेना अभ्यासों का अवलोकन किया था जो 5-18 मार्च, 2014 को सलझांडी, नेपाल में आयोजित किए गए थे।

14.11 **श्रीलंका** के साथ रक्षा संबंधी आदान-प्रदान क्षेत्र में मौजूद साझा सुरक्षा विषयों की पृष्ठभूमि में किए जाते हैं। तीसरी भारत-श्रीलंका सेना स्टाफ वार्ताएं 23-25 सितम्बर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की

गई थीं। तीसरी भारत-श्रीलंका नौसेना स्टाफ वार्ताएं 25-26 सितम्बर, 2013 को कोलंबो में आयोजित की गई थीं। भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना के बीच संयुक्त अभ्यास 'स्लीनेक्स' गोवा के तट पर 4-7 नवम्बर, 2013 को आयोजित किया गया था। नौसेनाध्यक्ष ने नवम्बर 25-28, 2013 को श्रीलंका का दौरा किया था। पांचवी भारतीय वायु सेना-श्रीलंकाई वायु सेना स्टाफ वार्ताएं 4-6 दिसम्बर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थीं।

14.12 **इंडोनेशिया** के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेनाओं के बीच समन्वित गश्त (कोरपेट) का 21वां चक्र 6-25 मई, 2013 को और 22वां चक्र 9-27 सितम्बर, 2013 को आयोजित किया गया था। नौसेना स्टाफ से नौसेना स्टाफ की छठवीं वार्ताएं 27-28 अगस्त, 2013 को जकार्ता में आयोजित की गई थी। दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त सेना अभ्यास 'गरुड़ शक्ति' का 18 नवम्बर, से 1 दिसम्बर, 2013 को इंडोनेशिया में आयोजन किया गया। भारत-इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की चौथी बैठक 20 दिसम्बर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। उपप्रमुख, एकीकृत रक्षा स्टाफ (डी सी आई डी एस) मुख्यालय, आई डी एस ने 19-20 मार्च, 2014 को जकार्ता अंतरराष्ट्रीय रक्षा वार्ता-2014 में भाग लेने में इंडोनेशिया के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा 28 मार्च से 3 अप्रैल, 2014 के दौरान आयोजित किए गए बहुपक्षीय सेना अभ्यास 'कोमोडो' में भारतीय नौसेना पोत ने भाग लिया था।

14.13 **मलेशिया** के साथ रक्षा संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। 5वीं नौसेना स्टाफ से नौसेना स्टाफ वार्ताएं 17-

19 जून, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थीं। 10वीं मलेशिया-भारत रक्षा सहयोग संबंधी बैठक (मिडकॉम) 21 जून, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। रक्षा सचिव ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जबकि मलेशियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री दातो श्री डा. हाजी इस्माइल बिन हाजी अहमद, जनरल सेक्रेटरी, रक्षा मंत्रालय, मलेशिया ने किया। नौसेनाध्यक्ष ने 23-26 सितम्बर, 2013 को मलेशिया का दौरा किया था। मलेशिया के साथ सेना स्टाफ वार्ताओं का चौथा दौर 22-24 अक्टूबर, 2013 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। जनरल तान श्री दातो श्री रोडजली बिन दाउद, वायु सेना प्रमुख, रायल मलेशियाई वायु सेना ने 26-29 नवम्बर, 2013 को भारत का दौरा किया था। छठवीं वायु सेना स्टाफ से वायु सेना स्टाफ वार्ताएं 18-20 दिसम्बर, 2013 के दौरान मलेशिया में आयोजित की गई थीं।

14.14 हाल ही के वर्षों के दौरान भारत और **सिंगापुर** के बीच रक्षा संबंध निरन्तर प्रगाढ़ हो रहे हैं। 7वीं भारत-सिंगापुर रक्षा कार्यकारी समूह की बैठक 28 जनवरी, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। 9वीं नौसेना स्टाफ से नौसेना स्टाफ वार्ताएं 11-13 मार्च, 2013 को सिंगापुर में आयोजित की गई थीं। 8वीं सेना स्टाफ से सेना स्टाफ वार्ताएं 13-15 मार्च, 2013 को भारत में आयोजित की गई थीं। मेजर जनरल रविन्दर सिंह, सेना प्रमुख सिंगापुर ने 19-22 मार्च, 2013 को भारत का दौरा किया था। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त सेना अभ्यास 'सिम्बैस' दक्षिणी चीनी समुद्र में 16-30 मई, 2013 को आयोजित किया गया था। नौसेनाध्यक्ष ने 31 मई से 2 जून, 2013 को सिंगापुर की यात्रा की थी। रक्षा

मंत्री ने 3 जून, 2013 को सिंगापुर का दौरा किया, इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अगस्त 2013 से पांच वर्षों की अवधि के लिए भारत में संयुक्त सेना प्रशिक्षण और अभ्यासों के आयोजन के लिए द्विपक्षीय करार में भी विस्तार किया। वायु सेना स्टाफ वार्ताओं का 7वां दौर 23-25 सितम्बर, 2013 को सिंगापुर में आयोजित किया गया था। सेनाध्यक्ष ने 21-24 जनवरी, 2014 को सिंगापुर का दौरा किया था। "निर्भीक कुरुक्षेत्र" (कवचित अभ्यास) नामक सेना अभ्यास 1-31 मार्च, 2014 को बबीना में आयोजित किया गया था।



भारत के रक्षा सचिव और सिंगापुर के स्थायी रक्षा सचिव सिंगापुर सेना द्वारा और पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रशिक्षण और अभ्यास सुविधाओं के प्रयोग का विस्तार करने के लिए हस्ताक्षित करार संबंधी दस्तावेजों का आदान-प्रदान करते हुए।

14.15 **थाईलैंड** के साथ रक्षा सहयोग में बेहतर प्रगति हो रही है। दूसरी भारत-थाईलैंड रक्षा वार्ता 18 फरवरी, 2013 को थाईलैंड में आयोजित की गई थी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व अपर सचिव ने जबकि जनरल निपत थोंग्लेक उप स्थायी रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय, थाईलैंड ने थाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। भारतीय नौसेना और रायल थाई नौसेना के बीच समन्वित गश्त (कोरपेट) का 16वां चक्र 18-



26 अप्रैल, 2013 को और 17वां चक्र 13-21 नवम्बर, 2013 को आयोजित किया गया था। वायु सेना स्टाफ से वायु सेना स्टाफ के बीच चौथी वार्ता 20-22 मई, 2013 को थाईलैंड में आयोजित की गई। रक्षा मंत्री ने 5-6 जून, 2013 को थाईलैंड की राजकीय यात्रा की और वहां के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान साझा चिंता के रक्षा संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। छठवीं नौसेना स्टाफ से नौसेना स्टाफ वार्ताएं 8-10 जुलाई, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

14.16 भारत-वियतनाम संबंध मैत्रीपूर्ण और साहार्दपूर्ण रहे हैं। कर्नल जनरल दो बा टी बाई, उप मंत्री, राष्ट्रीय रक्षा, चीफ आफ जनरल स्टाफ वियतनाम ने भारत का दौरा किया था और 24 सितम्बर, 2013 को रक्षा मंत्री से मुलाकात की। 8वीं भारत-वियतनाम सुरक्षा वार्ता 8 नवम्बर, 2013 को वियतनाम में आयोजित की गई थी। रक्षा सचिव ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जबकि उप रक्षा मंत्री कर्नल जन.न्यूएन ची विन्ह ने वियतनाम के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 20 नवंबर, 2013 को वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव की भारत यात्रा के दौरान भारत और वियतनाम के बीच वर्गीकृत सूचना के आदान-प्रदान के पारस्परिक संरक्षण के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये गए।

14.17 भारत और **आस्ट्रेलिया** के मध्य काफी वर्षों से द्विपक्षीय रिश्ते सौहार्दपूर्ण रहे हैं। सातवीं नौसेना स्टाफ -से-नौसेना स्टाफ के मध्य वार्ता 7 मार्च 2013 को सिडनी में आयोजित की गई। रक्षा मंत्री ने जून 4-5 जून, 2013 को आस्ट्रेलिया की यात्रा की और अपने समकक्ष मिस्टर स्टीफन स्मिथ से मुलाकात

की। इसके पश्चात रॉयल आस्ट्रेलियन नौसेना के प्रमुख वाईस एडमिरल आर.जे.ग्रिग्स ने 10-13 जून, 2013 को भारत की यात्रा की। सेनाध्यक्ष ने 3-6 सितंबर, 2013 को आस्ट्रेलिया की यात्रा की। भारत-आस्ट्रेलिया रक्षा - नीति वार्ता का तीसरा सत्र 4 अक्टूबर, 2013 को भारत में आयोजित किया गया। वार्ता की सह-अध्यक्षता अपर सचिव के स्तर पर की गई। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सुरक्षा परिपेक्ष्य से संबंधित पारस्परिक हितों के विभिन्न मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

14.18 **जापान** के साथ भारत के रक्षा संबंधों में निरंतर प्रगति हो रही है। उच्च स्तरीय यात्राओं और प्रशिक्षणों के आदान-प्रदान में वृद्धि हो रही है। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक ने 20-24 जनवरी, 2013 के दौरान जापान की राजकीय यात्रा की। सेनाध्यक्ष ने 11-15 फरवरी, 2013 को जापान की यात्रा की। 24-26 फरवरी, 2013 के दौरान जापान के समुद्री स्वयं रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ, एडमिरल कत्सुस्तोही कवानो ने और 5-8 मई, 2013 के दौरान जापान के सतही स्वयं रक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ईजी किमीजुका ने भारत का दौरा किया। राष्ट्रीय रक्षा, जापान के प्रशासनिक उप मंत्री, श्री मसनोरी निशि ने 8-10 जुलाई, 2013 को भारत का दौरा किया। चैन्नई के तट पर दोनों नौसेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास 'जीमेक्स' का आयोजन 19-22 दिसंबर, 2013 के दौरान किया गया। जापान के रक्षा मंत्री श्री इत्सुनोरी ओनोडेरा ने 5-8 जनवरी, 2014 को भारत का दौरा किया। इसमें उन्होंने पारस्परिक हित के विषयों पर रक्षा मंत्री से चर्चा की।

14.19 भारत और **कोरिया गणराज्य** के मध्य साझा मैत्रीपूर्ण संबंध और रक्षा सहयोग रहा है जो कि इस द्विपक्षीय संबंध का एक पहलू है। सी ओ एस सी के अध्यक्ष ने 8-11 जुलाई, 2013 के दौरान कोरिया गणराज्य का दौरा किया। कोरिया गणराज्य के वायुसेनाध्यक्ष, जनरल सूनग ह्वान ने 13-15 नवंबर 2013 के दौरान भारत का दौरा किया। अपर सचिव की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने 23-24 दिसंबर, 2013 को आयोजित उद्घाटन रक्षा नीति वार्ता (डी पी डी) में शामिल होने के लिए सिओल का दौरा किया। कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय में, नीति उप मंत्री, लेफ्टिनेंट जनरल यो, जे सुआंग ने कोरिया गणराज्य की ओर से वार्ता की सह-अध्यक्षता की। कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 16 जनवरी, 2014 को दोनों देशों के बीच वर्गीकृत सैन्य सूचना के संरक्षण संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर किये गये। कोरिया गणराज्य के उप रक्षा मंत्री ने 'डिफैक्सपो-2014' में भाग लेने के लिए फरवरी 2014 में भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव से मुलाकात की।

14.20 भारत **ओमान** के साथ सौहार्दपूर्ण रक्षा संबंध बनाए हुए है। भारत-ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति (जे एम सी सी) की छठी बैठक 6 जनवरी, 2013 को मस्कट में आयोजित की गई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व रक्षा सचिव जबकि ओमानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री मोहम्मद, बिन नासेर, अल-रसबी, अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय ओमानी सल्तनत द्वारा किया गया। 14-19 अप्रैल, 2013 के दौरान नौसेनाध्यक्ष द्वारा यू ए ई और ओमान का दौरा किया गया। भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नौसेना ने 23-26 सितंबर, 2013 को ओमान के तट पर 'नसीम अल-बहार 13' नामक एक सेनाअभ्यास का आयोजन

किया। भारतीय वायुसेना और ओमान की रॉयल वायुसेना के बीच तीसरे संयुक्त वायुसेना अभ्यास 'ईस्टर्न ब्रिज' का आयोजन 2-12 अक्टूबर, 2013 के बीच मसीरहा द्वीप पर किया गया। जे एम सी सी की सातवीं बैठक का आयोजन 29 जनवरी, 2014 को भारत में किया गया। भारतीय पक्ष का नेतृत्व रक्षा सचिव जबकि ओमानी पक्ष का नेतृत्व श्री मोहम्मद बिन नसीर अल-रसबी, महासचिव, रक्षा मंत्रालय, ओमानी सल्तनत द्वारा किया गया।

14.21 **कतर** के साथ हमारे रिश्ते मैत्रीपूर्ण रहे हैं। तीसरी भारत-कतर संयुक्त रक्षा समिति (जे डी सी) की बैठक 16 सितंबर, 2013 को दोहा में आयोजित की गई थी। भारत की ओर से अगुवाई संयुक्त सचिव (पी आई सी) और कतर की ओर से अगुवाई ब्रिगेडियर मोहम्मद, एम अब्दुला अल-सुवेदी, कतर राज्य के रक्षा मंत्री, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी मामलों के मुख्य, महा समन्वय का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई।

14.22 **यू ए ई** के साथ चौथी नौसेना स्टाफ से नौसेना स्टाफ की वार्ता का आयोजन 21-22 अक्टूबर, 2013 को नई दिल्ली में किया गया था। छठी भारत-यू ए ई संयुक्त रक्षा सहयोग समन्वय समिति की बैठक का आयोजन 27 अक्टूबर, 2013 को आबु धाबी में किया गया था। बैठक की सह-अध्यक्षता संयुक्त सचिव (पी आई सी) और यू ए ई की जी एच क्यू संयुक्त संभारिकी कमांड और कमांडर मेजर जनरल इशाक मोहम्मद अल बलूशी द्वारा की गई।

14.23 **इज़राइल** के साथ रक्षा संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। वायुसेनाध्यक्ष ने 20-23 जनवरी, 2013 को इज़राइल की यात्रा की। रक्षा अधिप्राप्ति, उत्पादन और विकास (एस डब्ल्यू जी- डीपीपीडी)

पर भारत इज़राइल उप-कार्य समूह की आठवीं बैठक 20 मई, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसकी सह-अध्यक्षता भारत की ओर से महानिदेशक (अधिग्रहण) और इज़राइल की ओर से ब्रिगेडियर जनरल शाम्या अवेइली, निदेशक, एस आई बी ए टी, रक्षा मंत्रालय, इज़राइल द्वारा की गई। मेजर जनरल गुई जुर, थलसेनाध्यक्ष, इज़राइल रक्षा बलों ने 11-14 नवंबर, 2013 को भारत का दौरा किया। 11 मार्च, 2014 को इज़राइल में सेना स्टाफ से सेना स्टाफ, नौसेना स्टाफ से नौसेना स्टाफ और वायु सेना स्टाफ से इज़राइली वायु सेना स्टाफ के बीच आयोजित वार्ता की गई। सेनाध्यक्ष ने 18-21 मार्च, 2014 को इज़राइल का दौरा किया। इज़राइली रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक मेजर जनरल डन हरेल ने 'डिफैक्सपो-2014' में भाग लेने के लिए फरवरी, 2014 में भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव से भी मुलाकात की।

14.24 भारत के **सऊदी अरब** के साथ संबंध लगातार सुदृढ़ हो रहे हैं। दोनों पक्षों ने सऊदी अरब के उप-प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की भारत यात्रा के दौरान 26 फरवरी, 2014 को रक्षा सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

14.25 भारत के **मध्य एशियाई गणतंत्रों (सी ए आर)** के साथ परंपरागत मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहे हैं। इन देशों के साथ रक्षा के क्षेत्र संबंधी कार्य-कलापों में भारत और सी ए आर के परस्पर लाभ में निरंतर विस्तार हो रहा है। भारत-तज़ाकिस्तान रक्षा संबंधी संयुक्त कार्य समूह (जे डब्ल्यू जी) की बैठक 22-23 मार्च, 2013 को भारत में आयोजित की गई थी। भारत में 26 अक्टूबर से 7 नवंबर, 2013 को भारत और तज़ाकिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त विशेष बलों के अभ्यास का आयोजन किया गया। तीसरी संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक 9-11 मार्च 2014 को तज़ाकिस्तान में आयोजित की गई।

14.26 क्रिगिज रक्षा मंत्री मेजर जनरल तालिबेक ओमूरालिवे ने 11-15 सितंबर, 2013 को भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों से संबंधित विभिन्न विषयों पर रक्षा मंत्री से चर्चा की और दोनों पक्षों के रक्षा स्थापनाओं के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति प्रकट की गई।

14.27 **मंगोलिया** के साथ हमारे द्विपक्षीय रक्षा संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नौवा संयुक्त अभ्यास 'एक्स-नोमाडिक एलिफैंट' 11-23 जून, 2013 के दौरान मंगोलिया में आयोजित किया गया। रक्षा सहयोग पर मंगोलिया-भारत संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक 22 नवंबर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

14.28 भारत और **रूस** के बीच पारस्परिक भरोसे और विश्वास पर आधारित दीर्घ स्थाई रक्षा संबंध हैं। यह ही एक मात्र ऐसा देश है जिसके साथ दोनों देशों के रक्षा मंत्री के स्तर पर भारत का संस्थागत वार्षिक रक्षा सहयोग तंत्र है। सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आई जी आई आर सी - एम टी सी) की तेरहवीं बैठक 18 नवंबर, 2013 को मास्को में आयोजित की गई थी। बैठक की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्री और रूसी संघ में रक्षा मंत्री श्री एस.के.शोइगू द्वारा की गई। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने 13वीं आई आर आईजीसी-एमटीसी बैठक की समाप्ति पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आई एन एस विक्रमादित्य के अधिष्ठापन संबंधी समारोह में भी 15-16 नवम्बर, 2013 को भाग लिया।

14.29 भारत-रूस की उच्च स्तरीय प्रबोधन समिति की 6वीं बैठक का आयोजन 2 सितंबर, 2013 को

मास्को में हुआ । इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा सचिव और एफ एस एम टी सी, रूस के निदेशक मि. अलेक्जेंडर वी. फोमिन द्वारा साथ-साथ की गई । सैन्य तकनीक सहयोग पर भारत-रूस कार्य समूह की 13वीं बैठक 9-10 सितम्बर, 2013 को मास्को में सम्पन्न

हुई । इस बैठक की अध्यक्षता महानिदेशक (अधिग्रहण) और एफ एस एम टी सी, रूस के प्रथम उप निदेशक मि. ए.ए. बायत्सव द्वारा संयुक्त रूप से की गई ।

14.30 भारत में दोनो सेनाओं के मध्य 'इन्द्र' नामक संयुक्त सेना अभ्यास 16-28 अक्टूबर, 2013 को किया गया । मि. ए.वी. फोमिन, निदेशक, एफ एस एम टी सी, जो रूस के उप प्रधान मंत्री दमित्री रोगोजिन के भारत के दौरे के दौरान उनके साथ थे, ने 26 फरवरी, 2014 को रक्षा सचिव से मुलाकात की और द्विपक्षीय सैन्य तकनीकी सहयोग मुद्दों पर चर्चा की ।

14.31 भारत और फ्रांस सौहार्दपूर्ण और पारस्परिक हितकारी रक्षा सम्बन्धों की साझेदारी को बनाए हुए हैं। मि. जीन-वाईवेस ली ड्रियन, फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ आए प्रतिनिधिमण्डल के एक भाग के रूप में 14 फरवरी, 2013 को भारत का दौरा किया और रक्षा मंत्री से मुलाकात की । सेना अध्यक्ष ने 27-30 मई, 2013 को फ्रांस का दौरा किया। रक्षा राज्य मंत्री ने पेरिस एयर शो देखने के लिए 18-19 जून, 2013 को फ्रांस का दौरा किया। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने भी 25-27 जुलाई, 2013 को भारत का

**भारत-रूस की उच्च स्तरीय प्रबोधन समिति की 6ठी बैठक का आयोजन 2 सितम्बर, 2013 को मास्को में हुई । इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा सचिव और एफ एस एम टी सी, रूस के निदेशक मि. अलेक्जेंडर वी. फोमिन द्वारा साथ-साथ की गई ।**

दौरा किया । 26 जुलाई, 2013 को रक्षा मंत्री के साथ बैठक के दौरान द्विपक्षीय सम्बन्धों, रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी, द्विपक्षीय रक्षा आदान-प्रदान और सुरक्षा विषयों पर चर्चा की गई। संयुक्त सेना अभ्यास 'शक्ति 2013' का आयोजन 9-21 सितम्बर, 2013 तक फ्रांस में

किया गया।

14.32 वर्ष के दौरान नार्वे के साथ रक्षा संबन्धों में गति आई। मि. आइसटीन बो, उप-रक्षा मंत्री, नार्वे ने 10-14 दिसम्बर, 2013 को भारत का दौरा किया और 13 दिसम्बर, 2013 को रक्षा राज्य मंत्री से मुलाकात की । बैठक के दौरान दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई थी ।

14.33 1995 में भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग वार्ता 'रक्षा परामर्शदात्री समूह' के लिए विचारार्थ विषय पर हस्ताक्षर करने के बाद स्थापित हुई। तब से, भारत और यू.के. के मध्य रक्षा सम्बन्धों में निरन्तर वृद्धि हो रही है । दोनों देशों के मध्य उच्च स्तरीय दौरों, प्रशिक्षण और विशेषज्ञ आदान-प्रदान तथा रक्षा उत्पादन के लिए संयुक्त परियोजनाओं पर नियमित आदान- प्रदान होता है ।

14.34 सर स्टीफन डॉलटन, वायु सेनाध्यक्ष, रायल, यू.के ने 6-9 मार्च, 2013 को भारत का दौरा किया। भारत में 3-30 अप्रैल, 2013 को 'अजय वारियर' और यू.के में 10-18 अक्टूबर, 2013 को 'कैम्बियन पेट्रोल' नामक दो संयुक्त सेना अभ्यास यू.के के साथ किए गए थे । संयुक्त नौसेना अभ्यास 'कोनकान'

का आयोजन 14-19 अक्टूबर, 2013 को गोवा के तट पर किया गया था। मि. इयान थाम्पसन, रक्षा स्थायी सचिव, यू.के. ने 3-4, फरवरी 2014 के दौरान भारत का दौरा किया और 4 फरवरी, 2014 को भारत- यू.के. रक्षा परामर्शदायी समूह 'डीसीजी' की 15वीं बैठक में भाग लिया ।

14.35 संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के रक्षा सम्बन्ध दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण कारक है । द्विपक्षीय रक्षा सहयोग सैन्य सहयोग क्रियाकलापों के नियमित आयोजन, विशेषज्ञता के आदान-प्रदान, उच्च स्तरीय अधिकारियों के दौरों के आदान-प्रदान, रक्षा अनुसंधान में सहयोग और संयुक्त सेना अभ्यासों के नियमित आयोजन के माध्यम से आगे बढ़ता है।

14.36 संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दो संयुक्त सेना अभ्यास 3-17 मई, 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 'युद्ध अभ्यास' और भारत में 3-6 अक्टूबर, 2013 को 'शत्रुजीत' आयोजित किए गए । वायु सेनाध्यक्ष ने 22-25 जुलाई, 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया। जनरल रेमण्ड टी ओडिनो, संयुक्त राज्य सेना के सेनाध्यक्ष ने 23-26 जुलाई, 2013 तक भारत का दौरा किया । दो संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत में 5-11 नवम्बर, 2013 को 'मालाबार 13' और संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 से 13 नवम्बर, 2013 तक 'संगम' आयोजित किए

1995 में भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग वार्ता 'रक्षा परामर्शदात्री समूह' के लिए विचारार्थ विषय पर हस्ताक्षर करने के बाद स्थापित हुई। तब से, भारत और यू.के. के मध्य रक्षा सम्बन्धों में निरन्तर वृद्धि हो रही हैं।

गए। सेनाध्यक्ष ने 2-5 दिसम्बर, 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया ।

14.37 ब्राजील के साथ रक्षा संबंध उत्साहपूर्ण और मित्रवत हैं । तीसरी भारत-ब्राजील संयुक्त रक्षा समिति की बैठक 21 मई, 2013 को नई दिल्ली

में आयोजित की गई । रक्षा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई ।

14.38 भारत के उपराष्ट्रपति के पेरू के दौरे के दौरान 28 अक्टूबर, 2013 को भारत-पेरू रक्षा सहयोग करार पर हस्ताक्षर करने के साथ पेरू के साथ रक्षा संबंधों को औपचारिक रूप प्रदान किया जाना था ।

14.39 जनरल अबडेल क्रिम बेनयाहिया की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय अलजीरियाई प्रतिनिधि मण्डल ने 23-25 अक्टूबर, 2013 को भारत का दौरा किया और रक्षा मंत्रालय में अधिकारियों से मुलाकात की । द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न मुद्दों पर बैठकों में चर्चा की गयी ।

14.40 जनरल अबडेल फत्ताह एल सीसी, मिश्र के रक्षा मंत्री ने 18-20 मार्च, 2013 को मिश्र के राष्ट्रपति के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल के भाग के रूप में भारत का दौरा किया और रक्षा मंत्री के साथ बैठक की । भारत -मिश्र संयुक्त रक्षा समिति (जे डी सी) की चौथी बैठक नई दिल्ली में 01 मई, 2013 को आयोजित की गई । जे डी सी की बैठक के दौरान,



दोनों पक्षों ने रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की ।

14.41 मि. मोशूशू डेविड सेहलोहो, लेसोथो राज्य के प्रधान रक्षा सचिव ने भारत का दौरा किया और रक्षा सचिव के साथ 23 अगस्त, 2013 को एक बैठक की । दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से संबंधित पारस्परिक हितों के मुद्दों पर चर्चा की ।

14.42 नौसेनाध्यक्ष ने 3-6 फरवरी, 2013 को मारीशस का दौरा किया । श्रीमती के.ओ.एफ वेंग-पोरून, वरिष्ठ मुख्य कार्यकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय, मारीशस सरकार ने अगस्त, 2013 के प्रथम सप्ताह में भारत का दौरा किया और 5 अगस्त, 2013 को रक्षा सचिव से मुलाकात की । दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा सहयोग संबंधी क्रियाकलापों की पुनरीक्षा की ।

14.43 भारत-नाइजीरिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की उद्घाटन बैठक 22 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी । जे डी सी सी बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की । उप-एडमिरल डीजे ईज्योबा, नौसेनाध्यक्ष, नाइजीरियाई नौसेना ने 9-12 दिसम्बर, 2013 को भारत का दौरा किया ।

14.44 भारत और **सेशलस** के मध्य सम्बन्ध उत्साहपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे हैं । भारत सेशलस के सशस्त्र बलों के क्षमता निर्माण में उसके साथ भागीदारी कर रहा है। एक डार्नियर-228 विमान, भारत द्वारा सेशलस को सेशलस के विदेश मंत्री के भारत दौरे के दौरान जनवरी, 2013 में सौंपा गया था । संयुक्त सेना अभ्यास 'लिमिटर' 2-15 दिसम्बर, 2013 को सेशलस में आयोजित किया गया ।

14.45 जनरल (पी एस सी) आबेद इलूहमान मोहम्मद जैन अहमद, महासचिव 'रक्षा मंत्रालय ' **सूडान** सरकार ने 11-13 सितम्बर, 2013 को भारत का दौरा किया और रक्षा सचिव से मुलाकात की । बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के सम्भावित क्षेत्रों की तलाश की ।

14.46 सैन्य पुलिस कोर, तंजानियन पीपुल्स' रक्षा बलों के चार सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने 22-28 फरवरी, 2013 को भारत का दौरा किया ।

14.47 **ए डी एम एम प्लस:** भारत ए डी एम एम प्लस मंचों के अन्तर्गत आयोजित की गई विशेषज्ञ कार्यकारी समूह की सभी गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहा है । भारतीय सशस्त्र बलों ने बुनेई में 10-22 जून, 2013 को आयोजित किए गए मानवीय सहायता और आपदा राहत/सैन्य मेडिसिन (एच ए डी आर/ एम एम) अभ्यास में भाग लिया । रक्षा राज्य मंत्री ने 29 अगस्त, 2013 को बुनेई दारूसलम में आयोजित की गई दूसरी ए डी एम एम प्लस बैठक में भाग लिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने 7-13 सितम्बर, 2013 को इण्डोनेशिया में आयोजित किए गए आतंकवाद रोधी अभ्यास (सीटीएक्स) में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया । भारतीय नौसेना ने 28 सितम्बर से 01 अक्टूबर, 2013 तक आस्ट्रेलियाई तट पर आयोजित किए गए समुद्रवर्ती सुरक्षा क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास (एफ टी एक्स) में भाग लिया । पांच मौजूदा ई डब्ल्यू जी के अतिरिक्त, मानवीय माइन एक्शन (एच एम ए) संबंधी एक नई ई डब्ल्यू जी की स्थापना की गयी है। भारत 2014 से 2017 तक वियतनाम के साथ एच एम ए संबंधी ई डब्ल्यू जी में सह-अध्यक्षता करेगा।

14.48 भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका (आई बी एस ए) त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग : रक्षा संबंधी आई बी एस ए संयुक्त कार्य समूह (आईबीएसए डीजेडब्ल्यूजी) की 5वीं बैठक का आयोजन 23-24 मई, 2013 को किया गया था । भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व संयुक्त सचिव (योजना और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग) द्वारा किया गया, ब्राजील के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व रियर एडमिरल

रिनाटो रोड्रिग्स डी एक्वीयर फ्रीर, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के उप प्रमुख द्वारा किया गया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व ले.जनरल वी आई रामलाकन, कोऑपरेट स्टाफ प्रमुख द्वारा किया गया । इस बैठक में मंच के अन्तर्गत संवर्द्धित हो रहे रक्षा सहयोग क्रियाकलापों की समीक्षा की गई और वर्ष 2013-14 के लिए एक कार्य योजना का सूत्रपात किया गया ।

## समारोह और अन्य कार्यक्रमलाप



*समापन समारोह के दौरान प्रकाश से जगमग करता हुआ राष्ट्रपति भवन,  
साउथ ब्लॉक एवं नॉर्थ ब्लॉक का दृश्य*

**र**क्षा मंत्रालय स्वायत्त संस्थाओं के माध्यम से अकादमिक तथा साहसिक दोनों प्रकार के कार्यकलापों को प्रोत्साहन देता है।

15.1 रक्षा मंत्रालय स्वायत्त संस्थाओं को नियमित रूप से आर्थिक सहायता देकर अकादमिक तथा साहसिक दोनों प्रकार के कार्यकलापों को प्रोत्साहन देता है। ये संस्थाएं हैं:

- (i) रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली;
- (ii) दार्जिलिंग और उत्तर काशी स्थित पर्वतारोहण संस्थान; और
- (iii) पहलगांव स्थित जवाहर पर्वतारोहण एवं शीत क्रीड़ा संस्थान।

15.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन संस्थानों के महत्वपूर्ण कार्यकलाप आगे के पैराग्राफों में दिए जा रहे हैं।

### **रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए)**

15.3 नवम्बर, 1965 में स्थापित रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए), समय-समय पर यथासंशोधित के सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का (पंजाब संशोधन अधिनियम 1957) के तहत एक पंजीकृत संस्था है। यह संस्थान रक्षा और

सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का सृजन और प्रचार-प्रसार करके राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा और सुरक्षा के सभी पहलुओं पर अनुसंधान और नीति से संबंधित एक स्वायत्तशासी निकाय है।

15.4 चूंकि विश्व के शेष भागों के साथ भारत की प्रति स्पर्धा गहरी हुई है, सामरिक समुदाय के साथ आई डी एस ए की पारस्परिक क्रिया भी बढ़ी है। आई डी एस ए ने जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, जलसुरक्षा और साइबर एवं अंतरिक्ष सुरक्षा जैसे उभरते हुए मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए शोध क्षेत्र का विस्तार किया है। संस्थान ने नई चुनौतियों के उद्भव और उसके प्रति भारत की अनुक्रिया का विस्तार से विश्लेषण किया है। रक्षा कूटनीति पर विशेष ध्यान दिया गया और सरकार द्वारा कई सुरक्षा वार्ता प्रारंभ की गई है। आई डी एस ए छात्रों के लिए पड़ोस में हो रहे विकास, प्राथमिकता वाले क्षेत्र बने रहे। वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में पुस्तकें, मोनोग्राफ, पेपर आदि निकाले गए।

15.5 आईडीएसए की बाहरी गतिविधियों में काफी विस्तार हुआ है। विदेशों के कई विद्वान आगंतुकों और प्रतिनिधिमंडलों का आई डी एस

में आथित्य किया गया। महान थिंक टैंकों और विश्वविद्यालयों को भी इसमें बुलाया गया था। आईडीएसए की वेबसाइट शोध कर्ताओं, विद्यार्थियों और आम जनता के लिए सुरक्षा और रक्षा के व्यापक मुद्दों पर जानकारी का स्रोत बन गया है। आईडीएसए की पहुंच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया माध्यमों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से कई शोध परियोजनाएं चलाई गईं। आईडीएसए का व्यापक प्रकाशन कार्यक्रम है। रक्षा अध्ययनों पर इसके फ्लैगशीप जर्नल, विश्लेषण और त्रैमासिक जर्नल महत्वपूर्ण संदर्भ-स्रोतों के तौर पर उभरे हैं।

15.6 रक्षा मंत्रालय आईडीएसए को निधि उपलब्ध कराता है और यह स्वायत्त रूप से कार्य करता है। आईडीएसए से छात्र अध्ययन संस्थानों, रक्षा बलों और सिविल सेवाओं में जाते हैं। शोध निकायों के 54 छात्रों के लिए 13 केन्द्रों के तहत कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस संस्थान ने वर्ष के दौरान अपने विजिटिंग फेलोशिप कार्यक्रम के तहत विभिन्न देशों से 19 विजिटिंग फेलो तथा अपने इंटरनशिप कार्यक्रम के तहत 26 शिक्षकों की मेजबानी की इस से संस्थान का नाम हुआ है और विदेशों में इसकी पहचान बढ़ी है। वर्ष के दौरान (31 मार्च, 2014 तक) आई डी एस ए के 72 छात्रों को विदेशों में सेमिनारों, गोल मेज

सम्मेलनों और संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

15.7 अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार/वार्ताएं : इस अवधि के दौरान आई डी एस ए द्वारा राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कई सेमिनार, गोल मेज सम्मेलनों, लेक्चरों और वार्ताओं का आयोजन किया।

15.8 संस्थान ने दिनांक 30-31 अक्टूबर, 2013 को 'भारत और दक्षिण एशिया : क्षेत्रीय अवबोधन का अन्वेषण' विषय पर सातवां दक्षिण एशिया सम्मेलन का संचालन किया। 'पश्चिम एशिया में उभरती प्रवृत्ति: क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव' विषय पर 15वां एशियाई सुरक्षा सम्मेलन (दिनांक 13-15 फरवरी, 2013) आयोजित किया गया। 'एशिया में उभरती सामरिक प्रवृत्ति और भारत की अनुक्रिया' विषय पर दिनांक 19-21 फरवरी, 2014 तक 16वां एशियाई सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया।

15.9 उपर्युक्त दो महत्वपूर्ण सम्मेलनों के अतिरिक्त, संस्थान ने निम्नलिखित का भी आयोजन किया:-

- नार्वे के तीन शोध संस्थानों: फ्रिजाज नानसेन संस्थान (एफएनआई), नार्वेजियन रक्षा अध्ययन संस्थान (आईएफएस) और शांति शोध संस्थान ओस्लो के निकट सहयोग से "एसिआर्कटिक" शीर्षक से आर्कटिक विषय पर दो-दिवसीय सम्मेलन।

**'एशिया में उभरती सामरिक प्रवृत्ति और भारत की अनुक्रिया' विषय पर दिनांक 19-21 फरवरी, 2014 तक 16वां एशियाई सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया।**



- भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईसीएसएसआर) के सहयोग से “स्वदेशी संकल्पना और शब्दकोश: कौटिल्य का अर्थशास्त्र” का विकास विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन।
- “आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां: राज्य संरचना और अनुक्रिया” विषय पर दिनांक 9 अक्टूबर, 2013 को एक दिन का सेमिनार आयोजित किया।
- दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 को आयोजित की गई भारतीय थिंकटैंकों का राष्ट्रीय सम्मेलन;
- “भागीदारी और समृद्धि के लिए भारत-आस्ट्रेलिया दृष्टिकोण को मूर्त रूप देना” विषय पर दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को द्वितीय भारत-आस्ट्रेलिया वार्ता।

15.10 **वाई.बी.चह्वान मेमोरियल व्याख्यान:** “भारत की समुद्री सुरक्षा- भविष्य की चुनौतियां” विषय पर चौथा वाई.बी. चह्वान मेमोरियल व्याख्यान दिनांक 26 नवम्बर, 2013 को एडमिरल (सेवानिवृत्त) अरुण प्रकाश द्वारा दिया गया। इसकी अध्यक्षता डॉ सीराजा मोहन ने की।

15.11 **विशेष और महान व्यक्तियों के व्याख्यान :** वर्ष के दौरान संस्थान ने कई महान व्यक्तियों के व्याख्यान आयोजित किए। फ्रांस गणराज्य के रक्षा मंत्री द्वारा “भारत-फ्रांस रक्षा भागीदारी: सामरिक स्वायत्तता का विकल्प” विषय पर दिया गया व्याख्यान उनमें से महत्वपूर्ण था।

15.12 **द्विपक्षीय मेलजोल:** संस्थान की उपलब्धियों का एक महत्वपूर्ण भाग वह संबंध है जो इसने विश्वभर के अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थिंक

टैंकों और प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ बनाए हैं और उसे संजों कर रखा है। उन अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों/ थिंक टैंकों, तथा जिन विषयों पर उन के साथ विचार-विमर्श हुए हैं वे निम्नानुसार हैं :-

- “उभरती हुई अन्तरराष्ट्रीय सामरिक गति की: भारतीय और मंगोलियाई परिदृश्य” विषय पर दिनांक 14 मार्च, 2013 को सामरिक अध्ययन संस्थान (आईएसएस), उलान बटार।
- “बहु ध्रुवीकरण के युग में नई चुनौतियां और भागीदारी: भारतीय और यूरोपीय परिदृश्य” विषय पर जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल एंड एरिया स्टडीज (जीआईजीए), हम्बर्ग के साथ।
- “भारत-चीन संबंध” पर दिनांक 1 अप्रैल, 2013 को चीनी समकालीन अन्तरराष्ट्रीय संबंध संस्थान (सीआईसीआईआर) के साथ।
- भारत-वियतनाम संबंधों, भारत-आसियान संबंधों चीन का उदय और दक्षिण चीन सागर में समुद्री मुद्दों पर दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को डिप्लो-मेटिक अकेडमी ऑफ वियतनाम, (डीएवी), वियतनाम के साथ।
- “भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य” विषय पर दिनांक 3 जुलाई, 2013 को बांग्लादेश अन्तरराष्ट्रीय और सामरिक अध्ययन संस्थान (बीआईआईएसएस) के साथ।
- “भारत में जापान के समुद्री लोकतंत्र के लिए भारत महत्वपूर्ण हैं” विषय पर दिनांक 25 सितम्बर, 2013 को राष्ट्रीय रक्षा अध्ययन संस्थान, (एनआईडीएस), जापान के साथ।

15.13 अन्तराष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान (आईआईएसएस), लंदन के सहयोग से आईडीएसए द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2013 को 'रक्षा, बलों का निवारण व प्रयोग' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

15.14 आईडीएसए के प्रकाशन : वर्ष 2013 के दौरान महत्वपूर्ण प्रकाशनों में जो आईडीएसए के छात्रों द्वारा लिखे गए और संपादित किए गए, निम्नलिखित शामिल हैं :-

- डिफेंस एक्वीजिशन: इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस (श्री विनय कौशल एवं श्री लक्ष्मण के बेहरा द्वारा संपादित);
- एसियन स्ट्रैटेजिक रिव्यू (श्री एस डी मुनि और श्री विवेक चढ्ढा द्वारा संपादित);
- मिशन मार्स: इंडियाज़ क्वेस्ट फॉरवर्ड रेड प्लैनेट (श्री अजय लेले द्वारा लिखित);
- चीन इयर बुक 2012 (श्री मती रुक्मणी गुप्ता द्वारा संपादित);
- खाड़ी क्षेत्र में विकास: अगले दो दशकों में भारत के लिए चुनौतियां एवं संभावनाएं (श्री रूमेल दहिया द्वारा संपादित);
- स्टेबिलिटी एण्ड ग्रोथ इन साउथ एशिया (श्री सुमित कुमार द्वारा संपादित)
- इंडिया एंड अफ्रीका इनहांसिंग म्युचुअल इंगेजमेंट (श्रीमती रूचिता बेरी द्वारा संपादित)।

इनके अतिरिक्त संस्थान ने वर्ष के दौरान 15 मोनोग्राफों, 33 इश्यू ब्रीफों और 2 पॉलिसी ब्रीफों का भी प्रकाशन किया।

15.15 आईडीएसए की वेबसाइट: आईडीएसए प्रकाशनों को संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाता है। वेबसाइट देखने वालों के लिए अधिकतर प्रकाशनों तक खुली पहुँच दी गई है। प्रकाशनों को देखने की छूट से छात्रवृत्ति और संचार के लिए एक स्वस्थ माहौल बनता है। इस से लेखक के विचार को पूरी दुनिया के साथ बांटने में मदद मिलती है और प्रकाशन डिजिटल फार्म में सुरक्षित रहते हैं जिससे ये बहुत अधिक दिनों तक भी सुरक्षित रहते हैं।

15.16 आईडीएसए का 49वां स्थापना दिवस: आईडीएसए का 49वां स्थापना दिवस 9 नवम्बर, 2013 को मनाया गया। उपाध्यक्ष, योजना आयोग ने 'भारतीय अर्थ शास्त्र और राष्ट्रीय सुरक्षा' विषय पर इस वर्ष का व्याख्यान दिया और उत्कृष्टता के लिए सातवां के. सुब्रहमण्यम पुरस्कार व अध्यक्षीय पुरस्कार प्रदान किए। सातवां के.सुब्रहमण्यम पुरस्कार विंग कमांडर (डॉ.) अजय लेले, अनुसंधान अध्येता, आईडीएसए, को प्रदान किया गया। उपाध्यक्ष ने उत्कृष्टता के लिए अध्यक्ष का पुरस्कार श्री साम राजीव, एसोसिएट अध्येता, आईडीएसए को प्रदान किया।



## पर्वतारोहण संस्थान

15.17 रक्षा मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकारों के

साथ मिलकर तीन पर्वतारोहण संस्थान पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, उत्तराखंड में उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान तथा जम्मू-कश्मीर में पहलगाम स्थित जवाहर पर्वतारोहण संस्थान एवं शीत क्रीड़ा संस्थान चलाता है। ये संस्थान पंजीकृत समितियों के रूप में चलाए जाते हैं और उन्हें स्वायत्तशासी निकायों का दर्जा प्रदान किया गया है। रक्षा मंत्री इन संस्थानों के अध्यक्ष होते हैं और संबंधित राज्य के मुख्य मंत्री इन संस्थानों के उपाध्यक्ष होते हैं। इन संस्थानों का प्रशासन कार्यकारी परिषदों द्वारा चलाया जाता है जिनमें प्रत्येक संस्थान की आम सभा द्वारा चुने गए सदस्य, दानदाताओं और/अथवा पर्वतारोहण के उद्देश्य को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों में से नामित सदस्य तथा केंद्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

15.18 ये संस्थान पर्वतारोहण को एक खेल के रूप में प्रोत्साहन देते हैं, पर्वतारोहण को बढ़ावा देते हैं और युवाओं में साहसिक भावना उत्पन्न करते हैं। पर्वतारोहण संस्थानों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:-

- (क) चट्टानों और उन पर चढ़ने की तकनीकों के विषय में सैद्धांतिक प्रशिक्षण देना;
- (ख) पर्वतों तथा अन्वेषण में रुचि एवं प्रेम उत्पन्न करना; और
- (ग) शीत-क्रीड़ाओं के प्रति प्रोत्साहित करना तथा उनका प्रशिक्षण देना।

15.19 ये पर्वतारोहण संस्थान आधारभूत और उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम, अनुदेश पद्धति पाठ्यक्रम, खोज व बचाव और साहसिक क्रियाकलाप संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। इन पाठ्यक्रमों में सेना, वायु सेना, नौसेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्मिक और भारतीय नागरिकों तथा विदेशी भी प्रशिक्षण लेते हैं। इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए पाठ्यक्रम, अवधि, ग्रेडिंग और अन्य ब्यौरा हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की वेबसाइट [www.hmidarj@gmail.com](http://www.hmidarj@gmail.com) पर और नेहरू पर्वतारोहण की वेबसाइट [www.nimindia.net](http://www.nimindia.net) पर और जवाहर पर्वतारोहण संस्थान की वेबसाइट [www.jawaharinstitutepahalgam.com](http://www.jawaharinstitutepahalgam.com) पर उपलब्ध है।

15.20 **नियमित पाठ्यक्रम:** संस्थानों द्वारा अप्रैल से दिसंबर, 2013 तक आयोजित पाठ्यक्रम और इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित पुरुषों और महिलाओं की संख्या तालिका 15.1 में दी गई है।

तालिका सं. 15.1

संस्थान	आधार-भूतपाठ्यक्रम		उन्नतपाठ्यक्रम		साहसिकपाठ्यक्रम		अनुदेश पद्धति पाठ्यक्रम		खोज व बचाव पाठ्यक्रम	
	पाठ्य क्रमों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या	पाठ्य क्रमों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या
हिमालय पर्वतारोहण	5	296	3	138	1	92	-	-	-	-
नेहरू पर्वतारोहण	5	320	3	86	4	149	1	35	1	35
जवाहर पर्वतारोहण	5	380	2	110	-	-	1	08	-	-

15.21 हिमालय पर्वतारोहण संस्थान ने 183 विद्यार्थियों के लिए दो विशेष साहसिक पाठ्यक्रम और 50 प्रशिक्षुओं के लिए चार पाठ्यक्रम भी आयोजित किए।

15.22 राष्ट्रीय पर्वतारोहण संस्थान ने विभिन्न संगठनों के लिए 12 विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए जिसमें 522 पुरुषों और महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

15.23 जवाहर पर्वतारोहण संस्थान द्वारा 1326 पुरुषों और महिलाओं के लिए 41 विशेष साहसिक पाठ्यक्रम; 29 पुरुषों के लिए एक बुनियादी पैरा-ग्लाइडिंग पाठ्यक्रम 1711 पुरुषों और महिलाओं के लिए दो पर्यावरण शिविरों और 20 विद्यार्थियों के लिए एक व्हाइट वाटर राफ्टिंग पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया।

15.24 रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित पंजीकृत सोसाइटी के रूप में एक नया संस्थान नामतः राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान जनवरी, 2013 मेंदिरांग, अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। रक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष और अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। इस नए संस्थान के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है:-

(क) पर्वतारोहण के अतिरिक्त, एक्वा एडवेंचर और एयरो एडवेंचर गतिविधियों में सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण देना।

(ख) युवाओं में साहसिक गतिविधियों और अन्वेषणों में रुचि और प्रेम उत्पन्न करना।

(ग) प्रकृति कार्यशालाओं के जरिए हिमालय क्षेत्र में

पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण का बोध उत्पन्न करना।

15.25 निमास अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय संस्थान है जहां पर्वतारोहण, एयरो एडवेंचर और एक्वा एडवेंचर से संबंधित गतिविधियों के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। संस्थान में पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षु सम्पूर्ण भारत और विदेशों से होंगे।

15.26 यह संस्थान दिरांग स्थित अस्थायी मुख्यालय से कार्य करना प्रारंभ कर चुका है। यह संस्थान प्रारंभ में केवल पर्वतारोहण पाठ्यक्रम ही चलाएगा और एक्वा एवं एयरो गतिविधियां उनके उपकरणों के भंडारण की क्षमता सृजित हो जाने पर प्रारंभ होगी।

15.27 निमास ने वर्ष के दौरान 28 विद्यार्थियों के लिए आधारभूत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम, 40 छात्रों के लिए ट्रेकिंग गाइड पर एक विशेष पाठ्यक्रम, 20 छात्रों के लिए इको-कैम्प प्रबंधन पर एक विशेष पाठ्यक्रम और 20 सेना कार्मिकों के लिए एक विशेष रॉक-क्लाइंबिंग पाठ्यक्रम चलाया।

## **समारोह, सम्मान व पुरस्कार**

15.28 गणतंत्र दिवस परेड, समापन समारोह, शहीद दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोहों के आयोजन की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की है। वीरता तथा विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोहों का आयोजन भी रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति सचिवालय

के साथ मिलकर किया जाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित समारोह संबंधी आयोजनों का ब्यौरा आगामी पैराओं में दिया गया है।

**15.29 स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोह :** स्वतंत्रता दिवस समारोह का शुभारंभ, लालकिले पर स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में सामूहिक देशभक्ति गान के साथ हुआ। तीनों सेनाओं तथा दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री को गारद सम्मान दिया। तत्पश्चात, प्रधानमंत्री ने सेनाओं के बैंड द्वारा बजाए गए राष्ट्रीय गान के साथ ही लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को संबोधित किए जाने के बाद समारोह का समापन विद्यालयों से आए बच्चों और एन सी सी कैडेटों द्वारा राष्ट्रीय गान तथा गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। बाद में दिन के दौरान, राष्ट्रपति ने उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर फूल-माला चढ़ाई जिन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे।

15.30 स्वतंत्रता दिवस 2013 के अवसर पर वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई जो तालिका 15.2 में दिए गए हैं।



लेफ्टि कमांडर अभिलाश टॉम भारत के राष्ट्रपति से कीर्ति चक्र प्राप्त करते हुए।

15.31 **विजय दिवस** 16दिसंबर, 2013 को विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर फूलमाला चढ़ाई।

15.32 **अमर जवान ज्योति समारोह, 2014 :** प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी, 2014को प्रातःकाल इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर पुष्पमाला चढ़ाई। उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट

### सारणी संख्या 15.2

पुरस्कार	कुल	मरणोपरांत
अशोक चक्र	01	01
कीर्ति चक्र	03	01
शौर्य चक्र	10	02
बार टू सेना मेडल (जी)	02	-
सेना मेडल (जी)	21	-
नौसेना मेडल (जी)	01	-
वायु सेना मेडल (जी)	05	-



का मौन रखा गया जिन्होंने देश की अखंडता की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए थे ।

**15.33 गणतंत्र दिवस समारोह, 2014 :** राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज पहराने के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने सेनाओं के बैडों द्वारा बजाए गए राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के बाद राष्ट्रीय सलामी दी। इस अवसर पर जापान के प्रधानमंत्री महामहिम मि. शिंजो अबे मुख्य अतिथि थे।

**15.34** 61 कैवलरी के आरोही दस्ते, मेकेनाइज्ड दस्ते जिनमें टी-90 टैंक (भीष्म) शामिल थे, आईसीवीबीएमपी-II (सारथ), शस्त्र प्रणालियां, स्मैर्च 300 एमएम मल्टी राकेट लांचर प्रणाली, टी-72 फूल विड्थ माइन प्लो, ट्रांसपोर्टेबल साटल टर्मिनल, पीएमएस (ब्रिजिंग सिस्टम), ओएसए-एके-शस्त्र प्रणाली, उन्नत हल्के हेलिकाप्टरों द्वारा उड़ान मार्च, तीनों सेनाओं, अर्ध सैन्य बलों, दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनएसएस आदि के मार्चिंग दस्ते और बैंड परेड का हिस्सा थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के उपस्कर दस्ते में एलसीए तेजस, अस्त्र और हेलिना मिसाइलें, एमबीटी अर्जुन एमके-II, मानव रहित प्रणाली झांकी शामिल थी।

**15.35** जिन 25 बच्चों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया उनमें से पांच को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार प्रदान दिया गया। 20 वीरता पुरस्कार प्राप्त बच्चों ने सेना की सुसज्जित जीपों पर सवार होकर परेड में भाग लिया। राज्यों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की झांकियां एवं विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन परेड के अन्य आकर्षण थे। 18 झांकियां तथा स्कूली बच्चों

के 5 कार्यक्रमों ने देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रस्तुत किया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा मोटरसाइकिल पर प्रदर्शन और तत्पश्चात भारतीय वायु सेना के विमानों के फ्लाई पास्ट के साथ परेड का समापन हुआ।

**15.36** गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित वीरता तथा विशिष्ट सेवा पुरस्कारों का ब्यौरा सारणी संख्या 15.3 में दिया गया है ।

### सारणी संख्या 15.3

पुरस्कार	कुल	मरणोपरांत
वीरता पुरस्कार		
कीर्ति चक्र	3	2
शौर्य चक्र	10	3
बार टू सेना मेडल वायु सेना मेडल (वीरता)	2	-
सेना मेडल/ नौसेना मेडल/ वायु सेना मेडल(वीरता)	64	5
विशिष्ट पुरस्कार		
परम विशिष्ट सेवा मेडल	28	-
उत्तम युद्ध सेवा मेडल	5	-
अति विशिष्ट सेवा मेडल बार	7	-
अति विशिष्ट सेवा मेडल	45	-
युद्ध सेवा मेडल	19	-
सेना मेडल बार (कर्त्तव्य परायणता)	5	-
सेना मेडल/ नौसेना मेडल/ वायु सेना मेडल(कर्त्तव्यपरायणता)	58	-
विशिष्ट सेवा मेडल बार	10	-
विशिष्ट सेवा मेडल	112	1

**15.37 समापन समारोह, 2014:** समापन समारोह सदियों पुरानी उन दिनों की सैन्य परंपरा

है जब सूर्यास्त होने पर सेना युद्ध बंद कर देती थी। समापन समारोह गणतंत्र दिवस समारोहों में भाग लेने के लिए दिल्ली में एकत्र हुई सैन्य टुकड़ियों के प्रत्यागमन का सूचक है। यह समारोह 29 जनवरी, 2014 को विजय चौक पर आयोजित किया गया जो गणतंत्र दिवस उत्सवों का पटापेक्ष था। इस समारोह में तीनों सेनाओं के बैंडों ने भाग लिया। समारोह के समापन के अवसर पर राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद भवन और इंडिया गेट की प्रकाश-सज्जा भी की गई।

**15.38 शहीद दिवस समारोह, 2014 :** 30 जनवरी, 2014 को, राष्ट्रपति ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर फूलमाला चढ़ाई। उप राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद 1100 बजे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे।

**15.39 सशस्त्र सेना झंडा दिवस (एएफएफडी):** संपूर्ण देश में प्रतिवर्ष की भांति 7 दिसम्बर, 2013 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। यह दिवस हमारी सीमाओं की अखंडता की सुरक्षा करने में हमारे बहादुर सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों को याद करने और रूग्ण भूतपूर्व सैनिकों

के बच्चों निशक्त वीरों का सम्मान करने और विधवाओं, कल्याण के प्रति एकजुटता व समर्थन व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है।

## राजभाषा प्रभाग

15.40 संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु रक्षा मंत्रालय में राजभाषा प्रभाग कार्य कर रहा है। यह प्रभाग इस प्रयोजनार्थ राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों तथा इस संबंध में नोडल विभाग अर्थात् राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के संबंध में रक्षा मंत्रालय (सचिवालय), तीनों सेना मुख्यालयों, अंतर सेवा संगठनों, रक्षा उपक्रमों तथा मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। माननीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गठित दो अलग-अलग हिंदी सलाहकार समितियां हैं। इन समितियों का गठन शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी मामलों में मंत्रालय के संबंधित विभागों को सलाह देने की दृष्टि से किया गया है। राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित कार्य में सरकारी कार्य में हिंदी के प्रगामी

संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए रक्षा मंत्रालय में राजभाषा प्रभाग कार्य कर रहा है। यह प्रभाग रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सहायता एवं मार्ग दर्शन प्रदान करता है।

प्रयोग हेतु प्रत्येक वर्ष जारी किए गए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हिंदी, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्रदान करना तथा स्टाफ को बिना झिझक के हिंदी में कार्य करने के

लिए सक्षम बनाने हेतु हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करना शामिल है। मॉनीटरी कार्य में मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों, रक्षा उपक्रमों और अनुभागों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण करना, मंत्रालय के दोनों राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की तिमाही बैठकें आयोजित करना, नई दिल्ली स्थित अंतर सेवा संगठनों तथा तीनों सेना मुख्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लेना और सुधारात्मक उपाय करने के लिए उपर्युक्त कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करना शामिल है।

**15.41 वार्षिक कार्यक्रम:** राजभाषा विभाग से प्राप्त वर्ष 2013-14 के वार्षिक कार्यक्रम को इस के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी रक्षा संगठनों को परिचालित किया गया। हिंदी में मूल पत्राचार बढ़ाने, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजातों को द्विभाषी रूप में जारी करने, हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित करने तथा हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दिया जा रहा है। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में इस संबंध में हुई प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

**15.42 अनुवाद कार्य :** वर्ष के दौरान मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों तथा अनुभागों से काफी मात्रा में प्राप्त सामग्री का अनुवाद कार्य पूरा किया गया। उपर्युक्त कार्य में संसद सदस्यों/विशिष्ट व्यक्तियों से

प्राप्त पत्रादि, रक्षा मंत्री/रक्षा राज्य मंत्री के कार्यालयों से जारी होने वाले पत्र आदि रक्षा संबंधी स्थाई समिति, लेखा परीक्षा पैरा मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्ताव, संसदीय प्रश्न तथा परामर्शदात्री समिति के समक्ष रखे जाने वाले दस्तावेज तथा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट आदि शामिल थे।

**15.43 हिंदी सलाहकार समिति की बैठक:** रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग तथा भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में 23 मार्च, 2013 को आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन किया जा चुका है। रक्षा उत्पादन विभाग की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 06 नवम्बर, 2013 को आयोजित की गई।

**15.44 रक्षा संबंधी विषयों पर मूल रूप से हिंदी में लिखी पुस्तकों संबंधी पुरस्कार योजना :** 2011-13 के ब्लाक वर्ष के लिए योजना के व्यापक परिचालन और समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से योजना के तहत प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थीं। प्राप्त पुस्तकों के मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है।

**15.45 हिंदी पखवाड़ा:** अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मंत्रालय में 14 से 30 सितंबर, 2013 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप

लेखन, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि, निबंध लेखन की कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके अलावा, हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। कुलमिलाकर 145 कर्मचारियों/अधिकारियों ने उपरोक्त प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

**15.46 संसदीय राजभाषा समिति द्वारा विभिन्न रक्षा संगठनों के निरीक्षण :** गत वर्षों की भांति, संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति ने इस वर्ष भी देश के विभिन्न भागों में स्थित कई रक्षा संगठनों का निरीक्षण दौरा किया। निरीक्षण प्रश्नावलियों की समीक्षा कर तथा अपेक्षित संशोधनों का सुझाव देकर मंत्रालय ने निरीक्षणाधीन कार्यालयों की सहायता की। निरीक्षण के दौरान कार्यालयों द्वारा दिए गए आश्वासनों को समिति के निदेशों और अपेक्षाओं के अनुरूप पूरा किया जा रहा है।

## अशक्त व्यक्तियों का कल्याण

15.47 रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग को छोड़ कर) तथा रक्षा उत्पादन विभाग के सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में अशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः सारणी संख्या 15.4 और 15.5 में प्रस्तुत किया गया है।

**15.48 सशस्त्र बल :अशक्त व्यक्ति** (समान अवसर, अधिकारों की संरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 और 47 के तहत किए गए उपबंधों में अशक्त व्यक्तियों के लिए सेवा में भर्ती तथा उन्हें सेवा में बनाए रखने के मामले में सुरक्षोपाय निर्धारित किए गए हैं। तथापि, सशस्त्र सेना कार्मिकों द्वारा निष्पादित की जाने वाली ड्यूटियों की प्रकृति के मद्देनजर, सभी समाघात पदों को, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी की गई विशेष अधिसूचनाओं के कारण उक्त धाराओं की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।

### सारणी संख्या 15.4

सेवाओं में अशक्तता वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण  
(1 जनवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार)

समूह	कर्मचारियों की संख्या				
	कुल	पहचाने गए पदों पर	दृष्टिविहीन	बधिर	अस्थि संबंधी विकलांगता
समूह क	2982	600	0	0	5
समूह ख	13441	3959	19	9	109
समूह ग	165581	25565	214	336	1355
समूह घ	62225	490	141	108	241
<b>योग</b>	<b>244229</b>	<b>306614</b>	<b>374</b>	<b>453</b>	<b>1710</b>

### सारणी संख्या 15.5

रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में सेवाओं में अशक्तता वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला वार्षिक विवरण  
(1 जनवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार)

समूह	कर्मचारियों की संख्या				
	कुल	पहचाने गए पदों पर	दृष्टिविहीन	बधिर	अस्थि संबंधी विकलांगता
समूह क	1882	22	1	2	14
समूह ख	32218	392	14	19	233
समूह ग	65827	1516	136	183	1092
समूह घ	44	8	0	0	1
<b>योग</b>	<b>99971</b>	<b>1938</b>	<b>151</b>	<b>204</b>	<b>1340</b>

15.49 **रक्षा उत्पादन विभाग:** रक्षा मंत्रालय के तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अशक्त व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ उपलब्ध कराने के लिए अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा जो रियायतें और छूट निर्धारित की गई हैं उनके अलावा बहुत-सी रियायतें एवं छूट अशक्त व्यक्तियों को प्रदान की जाती हैं।

15.50 **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन:** अशक्त व्यक्तियों के कल्याण के संबंध में सरकार की नीतियों एवं अनुदेशों को लागू करने में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन वचनबद्ध है। भर्ती एवं पदोन्नति में

3% आरक्षण सरकार के अनुदेशों के अनुसार अशक्त व्यक्तियों को प्रदान किया जा रहा है।

### भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

15.51 **भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग:** युद्ध के दौरान या दुर्घटनाओं एवं अन्य कारणों से कुछ सैनिक अशक्त हो जाते हैं और उन्हें सेवा से बाहर निकाल दिया जाता है। इन भूतपूर्व सैनिकों को विशेष चिकित्सा देखभाल और स्वावलंबी होने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ऐसे कार्मिकों का देख-रेख एवं पुनर्वास केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा वित्तीय रूप से समर्थित विशेष संस्थाओं में किया जाता है।





## सतर्कता यूनिटों की गतिविधियां

**र**क्षा मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग को रक्षा मंत्रालय और इसके अधीन आने वाले विभिन्न यूनिटों के कर्मचारियों के संबंध में भ्रष्टाचार की प्रथाओं, कदाचार और अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतें निपटाने का कार्य सौंपा गया है।

16.1 रक्षा मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग को रक्षा मंत्रालय और इसके अधीन आने वाले विभिन्न यूनिटों के कर्मचारियों के संबंध में भ्रष्टाचार की प्रथाओं, कदाचार और अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतें निपटाने का कार्य सौंपा गया है। यह रक्षा मंत्रालय की ओर से सतर्कता संबंधी मामलों और शिकायतों पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी) इत्यादि के साथ मध्यस्थता के लिए नोडल प्वाइंट के रूप में कार्य करता है। सतर्कता प्रभाग भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से उपायों की पहल करता है।

16.2 प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से रक्षा विभाग (भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग सहित) और रक्षा उत्पादन विभाग से संबंधित सतर्कता संबंधी कार्य उनके संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा संभाला जा रहा है।

16.3 केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार रक्षा मंत्रालय के अधीन सभी विभागों/संगठनों/ यूनिटों में सुशासन पर जोर देने के उद्देश्य से 28 अक्टूबर से

2 नवंबर, 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

## रक्षा विभाग

16.4 पारदर्शिता, निष्पक्ष व्यवहार, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने, भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ सक्रियकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

16.5 सतर्कता कार्य से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों, मामलों और अन्य कार्यों का समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के संपर्क में रहते हैं तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी) को भेजी जाने वाली सभी रिपोर्टें निर्धारित आवधिक अंतरालों पर भेजी गई थी।

**मंत्रालय संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में लंबित मामलों सहित विभिन्न चरणों में लंबित सतर्कता मामलों पर कड़ी निगरानी रखता है, ताकि इन मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटान किया जा सके।**

16.6 मंत्रालय संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में लंबित मामलों सहित विभिन्न चरणों में लंबित सतर्कता मामलों पर कड़ी निगरानी रखता है, ताकि इन मामलों

का समयबद्ध तरीके से निपटान किया जा सके। लंबित मामलों की स्थिति की मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा उपयुक्त अंतरालों पर मानीटरी की जाती है।

16.7 इस अवधि के दौरान, मुख्य सतर्कता आयोग (सी वी सी) द्वारा कुल 17 शिकायतें विचारार्थ भेजी गईं, जिन पर कार्रवाई की गई थी। इस वर्ष के दौरान और गत वर्ष में प्राप्त हुई कुल 16 शिकायतों के तर्कसंगत निपटान किए गए। वर्ष 2013-14 के दौरान समूह 'क' के 3 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी गई। इस वर्ष के दौरान, 3 अधिकारियों को बड़ी शास्ति प्रदान की गई तथा 1 अधिकारी को माफी दी गई।

16.8 सतर्कता भवन, नई दिल्ली में 11 सितंबर, 2013 को मुख्य सतर्कता आयुक्त (सी वी सी) द्वारा ली गई वार्षिक आंचलिक समीक्षा बैठक, 2013 के दौरान अनेक ऐसे क्षेत्रों का पता चला जिन पर कार्रवाई अपेक्षित है। सी वी सी ने रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक अधिप्राप्तियों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और समानता पर जोर दिया।

## रक्षा उत्पादन विभाग

16.9 आयुध निर्माणी बोर्ड : सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान, सतर्कता संवाद पत्र 'सजग' का प्रकाशन किया गया।

16.10 साक्षात्कार में अंकों को समाप्त करके भर्ती प्रक्रिया में विवेकाधिकारों को कम करने जैसे प्रणाली सुधार संबंधी उपाय किए गए।

16.11 संयंत्र एव मशीनरी नियमावली को अद्यतन करके इसे आयुध निर्माणी बोर्ड के इंटरनेट पर डाला गया।

## हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल)

16.12 कर्मचारियों की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं को सतर्कता की दृष्टि से सुधारने के लिए, सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम निर्धारित नियमित आधार पर आयोजित किए जाते हैं।

16.13 इस वर्ष के दौरान, सक्रिय सतर्कता पहलों के रूप में निम्नलिखित पुस्तिकाओं, पत्रिकाओं और रिपोर्ट का संकलन किया गया और इन्हें जारी किया गया :-

(क) अधिप्राप्ति में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की परितुलना करने वाली द्विभाषी पुस्तिका।

(ख) कार्यों, सामान एवं सेवाओं के लिए निविदाओं पर सी वी सी के दिशानिर्देशों के सार के संकलन की द्विभाषी पुस्तिका।

(ग) 'सार्वजनिक' रोजगार पर द्विभाषी पुस्तिका जिसमें संवैधानिक उपबंध, प्रमुख न्यायालय निर्णय, विभिन्न पी एम ई में सर्वोत्तम प्रथाएं, भर्ती नीतियां, भर्ती प्रौद्योगिकी, सुविधाजनक सलाह, विचारणीय बिंदु इत्यादि शामिल हैं।

(घ) अधिप्राप्ति, विक्रेता पंजीकरण, परिवहन किराए पर लेने, भर्ती, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता संबंधी खर्च इत्यादि के संदर्भ में तंत्र अध्ययन पर रिपोर्ट।

(ड) पाक्षिक द्विभाषी बुलेटिन 'वी 2' जिसमें प्रत्येक एकल विषय समर्पण के साथ इस विषय पर कंपनी नीति, सी वी सी के दिशा-निर्देशों, न्यायालय के निर्णय इत्यादि जैसे सभी संदर्भ शामिल किए गए हैं।

(च) 'मार्गदर्शन' नामक द्विभाषी सतर्कता संवाद पत्र जिसमें निवारक सतर्कता रणनीतियों पर आलेख, क्षेत्रीय अधिकारी वर्ग के लेख, सतर्कता विभाग की गतिविधियों की अद्यतन जानकारी इत्यादि शामिल हैं।

16.14 एच ए एल के सतर्कता विभाग को 'ओ एल आई वी' नामक ऑनलाइन सतर्कता निकासी कार्यक्रम के डिजाइन एवं कार्यान्वयन के लिए इन-हाउस प्रयासों की पहचान स्वरूप सतर्कता अध्ययन परिमंडल द्वारा 19 अगस्त, 2013 को वर्ष 2013 के लिए सतर्कता नवप्रवर्तन पुरस्कार से नवाजा गया है। कंपनी के 34000 से भी अधिक कर्मचारियों को सतर्कता निकासी जारी करने के लिए ओ एल आई वी, कंपनी के एच आर पोर्टल के साथ मिलकर सतर्कता आंकड़ों के संचयन का कार्य करता है।

16.15 एच ए एल के कर्मचारियों के लिए 28 अक्टूबर, 2013 को भारत के पूर्व न्यायाधीश एवं कर्नाटक राज्य के पूर्व लोकायुक्त द्वारा वार्षिक सतर्कता वार्ता का आयोजन किया गया था।

16.16 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी ई एल) : यहां 28 अक्टूबर से 02 नवंबर, 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2013 मनाया गया था। इस सप्ताह के दौरान, स्लोगन लेख, निबंध लेख, कार्टून/पोस्टर पेंटिंग, वाद-विवाद, व्यंग्य रचना एवं प्रश्नोत्तरी जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं।

16.17 प्रौद्योगिकीय क्षमता के प्रभाव से पारदर्शिता में बढ़ोतरी करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई:

(क) विक्रेताओं के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना;

(ख) भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना;

(ग) 10 लाख से अधिक मूल्य की कार्य संविदाओं, सेवा संविदाओं, पूंजीगत मदों एवं गैर-उत्पाद मदों के संदर्भ में दी गई संविदाओं/जारी किए गए खरीद आर्डरों के ब्यौरे कंपनी की वेबसाइट पर डाले जाते हैं;

(घ) 5 लाख से अधिक मूल्य की नामांकन/एकल निविदा आधार पर दी गई संविदाओं/जारी किए गए खरीद आर्डरों के ब्यौरे कंपनी की वेबसाइट पर डाले जाते हैं;

(ड) विक्रेता भुगतान सूचना प्रणाली को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है।

(च) इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सर्विस (ई सी एस)/ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस (ई एफ टी) का कार्यान्वयन किया गया है तथा सितंबर, 2013 तक कर्मचारियों को 99.93% एवं विक्रेताओं को 97.48% भुगतान ऑनलाइन किए गए हैं।

16.18 गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जी आर एस ई) : सतर्कता निकासी और शिकायतों के निपटान संबंधी नीति निर्देश जारी किए गए।

16.19 जी आर एस ई के कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक आचार संहिता का प्रस्ताव किया गया है,



और यह विचारधीन है। इससे कंपनी में वृत्तिदक्षता और संगठनात्मक संस्कृति में सुधार आएगा।

16.20 28 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2013 तक मनाया जाने वाला सतर्कता जागरूकता सप्ताह, प्रकरण अध्ययनों, विचार-विमर्शों, प्रबंधन खेलों एवं फिल्म शो के जरिए जागरूकता फैलाने के कारण और अधिक नवप्रवर्तनकारी और मनमोहक हो गया था।

16.21 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल): सतर्कता का समग्र उद्देश्य कारपोरेट के सुशासन के अनुसार संगठन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और संगठन के कार्यों के संबंध में नागरिकों के बीच विश्वास पैदा करना है। किसी गलती/निर्धारित प्रक्रियाओं/दिशा निदेशों में उल्लंघन को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण और आकस्मिक जांचें की जाती हैं। सभी नए प्रबंधन प्रशिक्षणार्थियों एवं अधिकारी वर्ग को सतर्कता की भूमिका एवं इसके कार्यों से अवगत कराया गया।

16.22 सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2013 तक मनाया गया। इसके दौरान, कंपनी में अधिकारी वर्ग, कर्मचारियों एवं सी आई एस एफ के कार्मिकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का प्रबंध किया गया। गोवा के विभिन्न हायर सैकेण्ड्री स्कूलों एवं कालेजों से आए विद्यार्थियों के लिए वाद-विवाद एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उपाध्यक्ष, एम पी टी गोवा ने 'सुशासन, आचार नीति नैतिक मूल्यों' पर एक भाषण दिया। प्रबंधन के साथ विक्रेताओं की बैठक आयोजित कराई गई।

16.23 हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एच एस एल): नियमित गतिविधियों के अलावा, निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित किए गए:-

(क) इस वर्ष के दौरान, अनुशासनिक कार्यवाही एवं निविदा प्रक्रियाओं पर तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

(ख) 28 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। यार्ड में सुसंगत बैनर लगाए गए। 'सुशासन संवर्धन' पर एक वाद-विवाद प्रतियोगिता का एच एस जूनियर एवं डिग्री कालेजों में आयोजन किया गया। 'सुशासन संवर्धन-सतर्कता का सकारात्मक योगदान' पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया।

16.24 माझगांव डॉक लिमिटेड (एम डी एल): माझगांव डॉक लिमिटेड का सतर्कता विभाग, कंपनी में निवारक एवं दंडात्मक सतर्कता कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करता है। यह अधिप्राप्ति, उपसंविदा, भर्ती इत्यादि सहित कंपनी की विभिन्न गतिविधियों में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। सतर्कता, विभाग यह भी सुनिश्चित करता है कि कंपनी की कार्य प्रणाली के सभी क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा कायम रहे। सतर्कता सप्ताह 28 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2013 तक मनाया गया जिसके दौरान सतर्कता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों/समारोहों का आयोजन किया गया।

16.25 बी ई एम एल लिमिटेड (बी ई एम एल): बी ई एम एल की शिकायत समाधान नीति को सी वी

सी अनुदेशों के अनुरूप बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। सी वी सी द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका को, जिसमें मोबाइल फोन और सी वी सी के वी आई जी ई वाई ई पोर्टल पर इंटरनेट द्वारा शिकायत के पंजीकरण एवं इसे दर्ज कराने की प्रक्रिया का ब्यौरा दिया गया है, कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

16.26 बदलते व्यापार परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, संवेदनशील क्षेत्रों की सूची की समीक्षा की गई तथा नए क्षेत्रों को संवेदनशील अधिसूचित किया गया। बी ई एम एल के विपणन प्रभाग के क्षेत्रीय/जनपद स्तर के कार्यालयों की वार्षिक निरीक्षण योजना तैयार की गई तथा अलग-अलग प्रभागों के विविध पृष्ठभूमि वाले तीन सतर्कता अधिकारियों के दल ने योजना के अनुसार निरीक्षण किया।

16.27 ई-लाइब्रेरी के रूप में सी वी सी/रक्षा मंत्रालय के परिपत्रों को एस ए पी/ ई आर पी पर अपलोड किया जा रहा है। ई आर पी में प्रभागों में समान पार्ट संख्या के लिए अंतिम क्रय मूल्य मुहैया कराया जाता है। अधिप्राप्ति अधिकारियों को यह आश्वासन देने की सलाह दी गई है कि उन्होंने अधिप्राप्ति पद कार्रवाई करते समय अंतिम क्रय मूल्य का सत्यापन कर लिया है।

16.28 निम्नलिखित रैड फ्लैग्स की जांच करने के लिए एस ए पी-ई आर पी पर क्रय मॉड्यूल की सतर्कता द्वारा नियमित आधार पर मानीटरी की जाती है तथा सिस्टम में संशोधन के लिए इसके परिणाम की सूचना प्रबंधन को दी जाती है :-

(क) क्रय मांग का क्रय आर्डर से लिंक न होना

(ख) यदि एक मद के लिए बहुत से आर एफ क्यू बनाए जा रहे हैं।

(ग) यदि विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं को मूल्य लाभ देने और/या डी ओ पी से बचने के लिए क्रय मांग को विभाजित कर दिया जाता है।

16.29 प्रोन्नत/कार्यभार ग्रहण करने वाले नए अधिकारी वर्ग को सतर्कता जागरूकता का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रभागों में शामिल किए गए नये सतर्कता अधिकारियों के लिए सुग्राहीकरण कार्यक्रम भी चलाया जाता है।

16.30 सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2013 तक मनाया गया। सी एम डी एवं सी वी ओ का अभिभाषण इस वर्ष का आकर्षण का केंद्र था, जिसमें के जी एफ, मैसूर एवं बेंगलूर स्थित तीनों प्रभागों को लाइव टू-वे-वीडियो प्रसारण द्वारा जोड़ा गया था। 'सुशासन संवर्धन-सतर्कता का सकारात्मक योगदान' शीर्षक पर 'विग-किरण' नामक एक विशेष जर्नल के तीसरे रूपांतर को भी प्रकाशित किया गया।

16.31 **मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)** : वर्ष के दौरान, दंडात्मक सतर्कता पर ध्यान केंद्रित करके कंपनी में सतर्कता प्रशासन में सुधार करने के लिए प्रभावी उपाय किए गए। कर्मचारियों में जागरूकता लाने के लिए वर्ष के दौरान कर्मशाला स्तर के अधिकारियों के साथ परस्पर विचार-विमर्श किया गया। अधिप्राप्ति संबंधी फाइलों की यादृच्छिक आधार पर संवीक्षा और रद्दी माल के निपटान के दौरान आयोजित की गई आकस्मिक जांचें सतर्कता विभाग द्वारा की गई पहलों में से कुछेक पहलें हैं।

16.32 सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में, कर्मचारियों को शिक्षा देने के लिए संगत विषयों पर

जानकारी देने के लिए जाने-माने सतर्कता विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया।

**16.33 भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल):** पारदर्शिता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए:-

- (क) एकीकृत सामग्री प्रबंधन नियमावली का डी पी पी एवं डी पी एम के अनुरूप प्रकाशन किया गया।
- (ख) भर्ती नियमावली/नियमों का अद्यतन किया गया।
- (ग) 90% से अधिक मूल्य की अधिप्राप्ति ई-अधिप्राप्ति के माध्यम से की गई।
- (घ) सुपुर्दगी पर भुगतान एवं विविध के अलावा, सभी भुगतान ई-भुगतान के माध्यम से किए गए।
- (ङ) संविदाकारों के बिलों की निकासी के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई जिससे संविदाकारों को बिलों की स्थिति का पता लगाने में सुविधा होती है।
- (च) कंपनी में कंप्यूटरकृत फाइल ट्रैकिंग प्रणाली (एफ टी एस) आरंभ की गई।

**16.34 सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2013 तक मनाया गया,** जिसके दौरान 'सुशासन संवर्धन - सतर्कता का सकारात्मक योगदान' शीर्षक पर जाने-माने व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान दिए गए। अधिकारी वर्ग के साथ सतर्कता संबंधी विचार-विमर्शों का आयोजन किया गया। कर्मचारियों के लिए निबंध/स्लोगन लेख प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा बी डी एल स्कूलों के बच्चों के लिए निबंध/स्लोगन लेख

एवं पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

**16.35 निवारक/सक्रिय सतर्कता के भाग के रूप में,** प्रबंधन को निम्नलिखित सिस्टम सुधार उपाय सुझाए गए:-

- (क) टी ए एल परियोजना के लिए कंटेनरों की अधिप्राप्ति संबंधी रिपोर्ट के आधार पर, प्रबंधन ने एफ आर पी कंटेनरों के स्थान पर 'रोटो मोल्डेड पालिथीलीन-कंटेनरों' की अधिप्राप्ति करने का निश्चय किया, जिसकी वजह से लगभग 63.5 लाख रुपए की बचत हुई।
- (ख) 'इब्राहीमपटनम एवं विजाग यूनिटों में वृक्षारोपण' के काम के बारे में एक विवेकपूर्ण जांच की गई तथा प्रणालीगत सुधार हेतु सिफारिशों वाली एक रिपोर्ट प्रबंधन को सौंपी गई, जिसके कारण लगभग 46 लाख रुपए की बचत हुई।

**16.36 रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई:** सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डी पी एस यू) एवं आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ एफ बी) की विभिन्न गतिविधियों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, कार्रवाई किए जाने योग्य बिंदुओं की एक व्यापक सूची तैयार की गई तथा इसकी सूचना सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रमों एवं आयुध निर्माणी बोर्ड को दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रमों एवं आयुध निर्माणी बोर्ड से तिमाही स्थिति रिपोर्टें मंगवाकर, इन कार्रवाई योग्य बिंदुओं के अनुपालन की मानीटरी की गई, इन स्थिति रिपोर्टों की समीक्षा की गई और आगामी तिमाही रिपोर्टों में

समीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन की सूचना दी गई। मंत्रालय स्तर पर गहन एवं नियमित मानीटरिंग द्वारा, निम्नलिखित कार्रवाई का कार्यान्वयन किया गया:

- (क) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रमों में सभी अधिप्राप्ति/क्रय नियमावलियों को अद्यतन करना।
- (ख) भर्ती नियमावली/नियमों को अद्यतन करना। लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्तियों के समावेशन/प्रारंभिक चरण में साक्षात्कार को महत्व देना और साक्षात्कार अधिकतम 15% तक ही रखा जाएगा।
- (ग) विक्रेताओं/संविदाकारों को यथासंभव सभी भुगतान ई-भुगतान द्वारा किए जाएं।
- (घ) हाउस आबंटन में विवेक आधारित कोटा को 5% के अंदर कर दिया गया है और इसका प्रयोग एक समिति द्वारा किया जाता है।
- (ङ) संविदाकारों द्वारा बिलों की परिस्थिति की ऑन लाइन ट्रैकिंग को सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रमों एवं आयुध निर्माणी बोर्ड में लागू किया गया।
- (च) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रमों एवं आयुध निर्माणी बोर्ड में सी वी ओ और सी एम डी के बीच नियमित संरचनात्मक बैठकें कराना।
- (छ) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणी बोर्ड में संवेदनशील पदों की संख्या का पता लगाना।

16.37 सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न रक्षा उपक्रमों में प्रचलित अच्छी सतर्कता प्रथाओं का चयन किया

गया तथा अपनी-अपनी कंपनियों में उपयुक्त रूप से इन्हें अपनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रमों में इन्हें परिचालित किया गया।

## रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग

16.38 वर्ष 2013-14 के दौरान डी आर डी ओ के सतर्कता एवं सुरक्षा निदेशालय द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां निम्नवत हैं-

- इस निदेशालय ने गृह मंत्रालय (एम एच ए) के आसूचना ब्यूरो के साथ समन्वय किया तथा सी ए आई आर बेंगलुरु, जी टी आर ई बेंगलुरु एल आर डी ई बेंगलुरु, एच ई एम आर एल पुणे, एन एस टी एल विशाखापतनम और डी एल आर एल हैदराबाद के निरीक्षणों में मदद की।
- इस निदेशालय ने ए डी ई बेंगलुरु, डी ई ए एल देहरादून, डी एल जोधपुर, डी एल आर एल हैदराबाद, एच ई एम आर एल पुणे, पी एक्स ई बालासोर, आई टी आर चांदीपुर, ए एस एल हैदराबाद एवं ए सी ई एम नासिक की सुरक्षा लेखा परीक्षा की है।
- संवेदनशील अनुसंधान एवं संवेदनशील दस्तावेजों की हैंडलिंग से संबंधित सुरक्षा मामलों से वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को अवगत कराया गया ताकि सूचना संबंधी सुरक्षा चूक को सावधानी पूर्वक रोका जा सके। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की सभी प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठानों के महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत निदेशकों, वरिष्ठ वैज्ञानिकों और कार्मिकों के लिए 8 अगस्त, 2013 को आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा आर सी आई हैदराबाद में एक सुरक्षा सुग्राही कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

## महिला सशक्तीकरण और कल्याण



माइक्रोलाइट फ्लाईंग के एयरोडायनामिक्स सीखती महिला अफसर



**राष्ट्रीय रक्षा** के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में निरन्तर वृद्धि हो रही है। महिलाओं को रक्षा उत्पादन यूनिटों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और सशस्त्र सेनाओं में डॉक्टर और नर्सिंग अफसर के रूप में नियुक्त किया जाता है।

17.1 राष्ट्रीय रक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में निरन्तर वृद्धि हो रही है। महिलाओं को रक्षा उत्पादन यूनिटों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और सशस्त्र सेनाओं में डॉक्टर और नर्सिंग अफसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। सशस्त्र सेनाओं की संभारिकी और विधि जैसी विभिन्न गैर-योधी शाखाओं में महिलाओं की भर्ती शुरु करने से उनके लिए व्यापक भूमिका की परिकल्पना की गई है।

### **भारतीय सेना**

17.2 **सेना में महिला अफसर :** सशस्त्र सेनाओं में महिला अफसर लगभग 80 वर्षों से सेवा कर रही हैं और उन्होंने बड़ी सक्षमता व विशिष्टता के साथ सेवा की है। इन्हें सैन्य परिचर्या सेवा में 1927 में तथा चिकित्सा अफसर संवर्ग में 1943 में शामिल किया गया था। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में स्थाई और अल्पकालीन सेवा कमीशन, दोनों प्रकार के अफसर हैं।

17.3 एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में, सेना में महिला अफसरों के अल्पकालीन सेवा कमीशन की अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर

दिया गया है जिससे सेना में और अधिक महिलाएं भर्ती होंगी। इसके अलावा, उनके पदोन्नति के अवसरों में पर्याप्त रूप से वृद्धि की गई है। वे पहले केवल एक पदोन्नति अर्थात् 5 वर्ष की सेवा के बाद मेजर रैंक में पदोन्नति के लिए पात्र थीं। महिला अल्पकालीन सेवा कमीशन अफसरों को क्रमशः 2,6 तथा 13 वर्ष की संगणनीय सेवा के बाद क्रमशः कैप्टन, मेजर तथा लेफ्टि. कर्नल तक के समय-मान में बड़ी पदोन्नति दी जाती है। यह स्थाई सेवा कमीशन अफसरों को उपलब्ध पदोन्नतियों के समान है। इसके अलावा, लिंग समानता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सेना में अल्पकालीन सेवा कमीशन में महिला अफसरों की प्रशिक्षण अवधि 24 सप्ताह से बढ़ाकर 49 सप्ताह कर दी गई जो अल्पकालीन सेवा कमीशन के पुरुष अफसरों के समान है।

17.4 राष्ट्र की रक्षा और देश की प्रादेशिक अखंडता का संरक्षण करने में सशस्त्र सेनाओं की भूमिका और जिम्मेदारी को दृष्टिगत रखते हुए, सेनाओं में महिलाओं की भर्ती और रोजगार संबंधी भावी नीति का निरूपण नवम्बर, 2011 में किया गया है, जो इस प्रकार है:-

(i) तीनों सेनाओं में, जिन शाखाओं/कोरों में महिला अफसरों को इस समय भर्ती किया जा रहा है वहां उन्हें अल्पकालिक कमीशन अफसर (एसएससीओ) के रूप में भर्ती किया जाता रहे;

(ii) महिला एस एस सी ओ तीनों सेनाओं की विशिष्ट शाखाओं अर्थात् सेना की जज एडवोकेट जनरल और सेना शिक्षा कोर और नौसेना तथा वायु सेना में उनके तदनु रूप शाखाओं; नौसेना में नेवल कंस्ट्रक्टर व वायु सेना में लेखा शाखा में पुरुष एस एस सी ओ के साथ स्थाई कमीशन प्रदान किए जाने के लिए विचारार्थ पात्र होंगी।

(iii) उपर्युक्त के अलावा, वायु सेना में तकनीकी, प्रशासन, संभारिकी तथा मौसम विज्ञान शाखाओं में स्थाई कमीशन प्रदान किए जाने हेतु महिला एस एस सी ओ पुरुष एस एस सी ओ के साथ विचारार्थ पात्र होंगी।

17.5 स्थाई कमीशन प्रदान किया जाना उम्मीदवार की रजा मंदा और प्रत्येक सेना द्वारा यथानिर्धारित सेना विशेष की आवश्यकताओं, रिक्तियों की उपलब्धता, उपयुक्तता, उम्मीदवार की मेरिट की शर्त के अध्याधीन है।

राष्ट्र की रक्षा और देश की प्रादेशिक अखंडता का संरक्षण करने में सशस्त्र सेनाओं की भूमिका और जिम्मेदारी को दृष्टिगत रखते हुए, सेनाओं में महिलाओं की भर्ती और रोजगार संबंधी भावी नीति का निरूपण नवम्बर, 2011 में किया गया है।

## भारतीय नौसेना

17.6 महिला अफसर : महिलाओं को नौ सेना में कार्यपालक (प्रेक्षक, ए.टी.सी. विधि और संभारिकी संवर्ग), शिक्षा शाखा और इंजीनियरी शाखा के नौसेना वास्तुशिल्प संवर्ग में अल्प सेवा कमीशन अफसरों के रूप में भर्ती किया जा रहा है।

17.7 महिला अफसरों को स्थाई कमीशन : रक्षा मंत्रालय ने कार्यपालक शाखा (विधि संवर्ग), शिक्षा शाखा और इंजीनियरी शाखा (नौसेना वास्तुशिल्प) की अल्प सेवा कमीशन महिला अफसरों के लिए भविष्य लक्षी प्रभाव से स्थाई कमीशन प्रदान करना शुरू किया है।

17.8 यौन उत्पीड़न रोकने के उपाय: यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर नौसेना कार्मिकों को सुग्राही बनाने के विभिन्न उपाय निम्नलिखित हैं :-

(i) अधिकारियों के प्रारम्भिक प्रशिक्षण स्तर के दौरान, कोच्चि में एक जेन्डर सेन्सीटाइजेशन कैम्पस का संचालन नेतृत्व और व्यवहारिक अध्ययन केन्द्र में किया जाता है।

(ii) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने की आवश्यकता की पुनरावृत्ति करने के लिए कमान/यूनिट स्तर पर आवधिक व्याख्यान दिए जाते हैं।

## भारतीय वायु सेना

17.9 1990 तक, भारतीय वायु सेना की चिकित्सा अथवा दंत चिकित्सा शाखाओं में ही महिलाओं को

भर्ती किया जाता था। वर्ष 1991 में, भारत सरकार ने अल्पकालीन सेवा कमीशन के माध्यम से ग्राउंड ड्यूटी गैर-तकनीकी शाखाओं में और बाद में 1992-1993 में तकनीकी और उड़ान शाखाओं (परिवहन और हेलिकॉप्टर शाखा) में भी महिला अफसरों की भर्ती को अनुमोदित किया था। इस समय, महिलाओं को युद्धक उड़ान विधा को छोड़कर भारतीय वायु सेना की सभी शाखाओं में एस एस सी संवर्ग में नियुक्त किया जाता है।

**17.10 रक्षा बलों में महिलाएं :** महिला अधिकारी भारतीय वायु सेना में अधिकारी संवर्ग का हिस्सा हैं। बिना लिंग भेद भाव के, एस एस सी अधिकारियों के लिए वर्तमान सीमा उड़ान और ए ई शाखाओं में स्थापना का 20 प्रतिशत और गैर-तकनीकी ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में 25 प्रतिशत है।

**17.11 उपाय :** भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारियों को साहसिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए पर्याप्त और समान अवसर प्रदान किए जाते हैं।

**17.12 साहसिक क्रिया कलापों और खेलों में भारतीय वायु सेना महिलाएं**

- (क) भारतीय वायु सेना की स्काइडाइवरों ने एयर डेविल टीम द्वारा आयोजित अनेक प्रतिष्ठित स्काइडाइविंग प्रदर्शनों में भाग लिया है।
- (ख) तीन महिला अफसरों ने सफलतापूर्वक व्यावसायिक उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा किया है।
- (ग) एक महिला अफसर ने अक्टूबर, 2013 में 'गंगोत्री से गंगासागर' रिवर राफ्टिंग अभियान में भाग लिया।



सर्व-महिला भारतीय वायु सेना स्काइडाइविंग टीम

- (घ) एक महिला अफसर ने सुब्रतो कप 2013 के दौरान मैच रैफरी की हैसियत से भाग लिया।
- (ङ) एक महिला अफसर भारतीय वायु सेना गोल्फ टीम की सदस्य है।
- (च) एक महिला अफसर ने माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ाई की है।

**17.13 कल्याण :** जहां तक संभव है, वायु सेना मुख्यालय विवाहित महिला अफसरों से भारतीय वायु सेना में सेवारत उनके पतियों के साथ एक ही स्थान पर तैनाती हेतु अनुरोधों पर विचार करता है और उन्हें मानता है। महिला अफसरों/फ्लाइट कैडेटों और अन्य महिला कर्मचारियों को बहुत अनुकूल काम काज का वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। 'भारतीय वायु सेना में लिंग-संवेदनशीलता' सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए भारतीय वायु सेना के प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न सुग्राह्यीकरण पाठ्यक्रम और इस विषय पर कार्यशालाएं भी शुरू की गई हैं।



उडान कौशल का प्रदर्शित करती हुई भारतीय तटरक्षक महिला पायलेट

## भारतीय तट रक्षक

17.14 भारतीय तट रक्षक वर्ष 1997 से सहायक कमांडेंट के रूप में महिला अधिकारियों की भर्ती, सामान्य ड्यूटी (स्थाई) सामान्य ड्यूटी (पायलट/नौचालन) और सामान्य ड्यूटी (कानून) शाखाओं में कर रहा है। महिला अधिकारियों की तैनाती केवल गैर-समुद्री नियुक्तियों में की जाती है। सामान्य ड्यूटी और सामान्य ड्यूटी (वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस धारक) शाखाओं में महिला अधिकारियों के लिए अल्प सेवा नियुक्ति स्कीम हाल ही में प्रारम्भ का गई है जो सेवा में महिला अधिकारियों की भर्ती में वृद्धि करेगी। वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस धारक महिला अधिकारियों की भर्ती फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग विमान दोनों में उडान के लिए की जाती है। महिला और पुरुष उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया समान है। भारतीय तट रक्षक की महिला अधिकारियों के साथ अधिवाषिंता तक सेवा करने का विकल्प होता है,

**रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन एक ऐसा संगठन है जो लिंग भेदभाव रहित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक महिला वैज्ञानिक राष्ट्रीय महत्व की महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं का नेतृत्व कर रही हैं**

अल्प सेवा स्कीम के अंतर्गत नियुक्त किए गए अधिकारियों को छोड़कर वर्तमान में, भारतीय तट रक्षक में 103 महिला अधिकारी हैं।

## रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

17.15 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन एक ऐसा संगठन है जो लिंग भेदभाव रहित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। इसके परिणामस्वरूप अनेक महिला वैज्ञानिक राष्ट्रीय महत्व को महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं को नेतृत्व कर रही हैं। रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग अपने महिला कर्मचारियों के सशक्तीकरण और कल्याण की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है। सरकारी अनुदेशों और इस विषय पर जारी निदेशों, दोनों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि महिला कर्मचारियों को उनके कौशल और ज्ञान में वृद्धि करने, अपने अन्तर्निहित क्षमता को पूर्णता तक पहुंचाने का समान अवसर मुहैया कराया जाता है। प्रबंधन द्वारा संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनके कार्य और उत्पादन को महत्व दिया जाता है और उसकी कद्र की जाती है।

17.16 महिलाओं के लिए अनेक कल्याणकारी उपाय किए गए हैं। संपूर्ण देश में स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की विभिन्न प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में शिशुगृह खोले गए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रत्येक शाखाओं/स्थापनाओं में महिला प्रकोष्ठ मौजूद रहे हैं। शिकायत समितियों का गठन किया गया

है जो अनन्य रूप से यौन उत्पीड़न के मुद्दे का निपटान करते हैं।

17.17 अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन के अवसर पर, डीआरडीओ ने चंडीगढ़ के निकट रामगढ़ में टर्मिनल बैल्स्टिक्स रिसर्च लेबोरेट्री में “विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान में महिलाएं (डब्ल्यू आई एस ई आर-2013)” पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संपूर्ण देश से 350 से अधिक महिला वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संगोष्ठी में भाग लिया। संगोष्ठी का मुख्य विषय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान में महिलाओं के योगदान को उजागर करना था।

### **रक्षा उत्पादन विभाग**

17.18 आयुध निर्माणी संगठन: आयुध निर्माणी संगठन में महिला कर्मचारियों/अधिकारियों की नफरी 7291 है। यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण करने के लिए संगठन की प्रत्येक निर्माणी/यूनिट और मुख्यालयों में शिकायत समितियां गठित की गई हैं। सभी निर्माणियों/यूनिटों में भी महिला कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

17.19 हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल): 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार एच ए एल में महिला कर्मचारियों की नफरी 2595 है। महिला कर्मचारियों को सभी सांविधिक कल्याण सुख-सुविधाएं दी गई हैं। मातृत्व अवकाश को भी 84 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। इस छुट्टी के अतिरिक्त,

सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए, आवश्यकता के आधार पर वेतन रहित अवकाश भी प्रदान किया जाता है।

17.20 भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल): भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड की सम्पूर्ण कम्पनी में विभिन्न यूनिटों/ कार्यालयों में लगभग 2100 महिला कर्मचारी हैं। भारत इलैक्ट्रानिक लिमिटेड की सभी यूनिटों/कार्यालयों में एक वरिष्ठ महिला कार्यपालक के नेतृत्व में गठित शिकायत समिति कार्य कर रही हैं। विभिन्न कल्याणकारी उपाय जैसे शिशुगृह, उपचर्या अवकाश, भी महिला कर्मचारियों को प्रदान की जाती हैं। महिला कर्मचारियों को नर्सिंग ब्रेक दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में महिला मंच की शीर्ष संस्था द्वारा बी ई एल को वर्ष 2012-13 का 'सर्वोत्तम महिला कर्मचारी पुरस्कार (गैर-कार्यकारी श्रेणी)' दिया गया था।

17.21 गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई): जीआरएसई में 130 महिला कर्मचारी हैं। जीआरएसई महिला शक्ति को संगठित करने तथा उसका उपयोग करने तथा महिला कर्मचारियों के विरुद्ध भेदभाव और लैंगिक पक्षपात को रोकने के लिए नियमित रूप से सेन्सीटाइजेशन कार्यशालाओं का आयोजन करता है। एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में एक शिकायत समिति, जिसमें एक एनजीओ प्रतिनिधि होता है, का गठन कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण करने के लिए किया गया है।

17.22 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल): जीएसएल में महिलाओं की अधिकारिता को प्रमुख



महत्व दिया जाता है और उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में उनके पुरुष सहभागियों के बराबर समझा जाता है। यौन उत्पीड़न की रोकथाम और शिकायतों के निवारण के लिए एक 'शिकायत समिति' का गठन किया गया है जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक महिला प्रतिनिधि और एक स्वतंत्र स्थानीय एनजीओ प्रतिनिधि होता है

**17.23 हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल):** एक 'जेन्डर बजटिंग प्रकोष्ठ' का गठन चार महिला अधिकारियों से किया गया है जो सभी जेन्डर अनुक्रियाशील बजटिंग पहलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। यह प्रकोष्ठ सामान्य विकास कार्यक्रमों जैसे कि कौशल बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण, शिशुगृह का रख-रखाव, स्वास्थ्य, कार्यस्थल पर जल और सफाई आदि कल्याण सुविधाओं का प्रावधान का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

**17.24 माझगांव डाक लिमिटेड (एमडीएल):** एमडीएल में सीपीएसयू फोरम 'सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं' की एक यूनिट कार्यरत है। कार्यस्थल में लिंग विशिष्ट मुद्दों के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। इस प्रकोष्ठ की प्रमुख एक महिला अधिकारी होती है। प्राप्त सभी शिकायतों का निवारण तत्परतापूर्वक किया जाता है और उनका नितान्त गोपनीय ढंग से निपटान किया जाता है।

**17.25 बीईएमएल लिमिटेड :** बीईएमएल में महिला कर्मचारियों/अधिकारियों की नफरी 319 है। महिलाओं को भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और विकास आदि में समान अवसर दिए जाते हैं। निर्माणी अधिनियम मातृत्व लाभ अधिनियम आदि के अंतर्गत

सभी लागू सांविधिक प्रावधान, का अनुपालन भी अक्षरशः किया जा रहा है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, 'लिंग साम्यता और भेदभाव-रोधीनीति' बनाई गई थी जो लिंग समानता को प्रोत्साहित करेगी। कम्पनी में कार्पोरेट कार्यालय सहित सभी उत्पादन यूनिटों में महिला प्रकोष्ठों को गठन किया गया है जो महिला कर्मचारियों/ अधिकारियों के यौन उत्पीड़न के मुद्दे का निवारण करेंगे। उन महिला कर्मचारियों/ अधिकारियों जिनके 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, को प्रतिमाह 200/- रुपए का शिशु सदन भत्ता दिया जाता है।

**17.26 भारत डायनमिक्स लिमिटेड (बीडीएल):** बीडीएल में 331 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें से 92 कार्यकारी ओर 239 गैर-कार्यकारी हैं और ये कम्पनी में कुल कर्मचारियों का 10.75 प्रतिशत हैं। महिला कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, कम्पनी सीपीएसयू मंच अर्थात 'सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं' द्वारा आयोजित सम्मेलनों/कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है। वरिष्ठ महिला अधिकारी के नेतृत्व वाली एक शिकायत समिति' का भी गठन किया गया है जो यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच पड़ताल करती है।

**17.27 मिश्र धातु निगम लिमिटेड ( मिधानि):** मिधानि महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए संविधि के अनुसार सभी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार महिला कर्मचारियों की नफरी 60 है। मिधानि में 8 मार्च, 2014 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आन्तरिक तथा बाहरी कार्यक्रमों के लिए कार्यकारी और गैर-कार्यकारी दोनों महिला

कर्मचारियों को नामित किया गया था। मिधानि 7 करोड़रु. की लागत से फास्टनर्स के निर्माण हेतु एक प्लान्ट स्थापित कर रहा है, जो अनन्य रूप से महिला कर्मचारियों द्वारा चलाया जाएगा।

**17.28 गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए):** मुख्यालय और प्रत्येक डीजीक्यूए स्थापना पर महिला प्रकोष्ठ मौजूद हैं जो कार्यालय में और परिवारों में अपनी महिला सदस्यों के प्रति भेदभाव, उत्पीड़न अथवा कठिनाई की शिकायतों का निपटान करते हैं। महिला कर्मचारियों के लिए प्रतिष्ठित क्षेत्रों से व्यक्तियों के साथ संगोष्ठियों और संवाद का आयोजन किया जाता है और उन्हें पाठ्येतर कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

**17.29 मानकीकरण निदेशालय (डीओएस) :** एक महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति गठित की गई है जो मानकीकृत निदेशालय के किसी भी महिला कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच पड़ताल करेगी।

### **भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग**

**17.30 भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, लगभग 29**

लाख भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण का निपटान करता है जिसमें सशस्त्र सेनाओं के पूर्व कार्मिकों की विधवाएं और उनके आश्रित सदस्य शामिल हैं। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत लड़कियों और महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

**17.31 चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग से पहले सन्तान भत्ता पा रहे सशस्त्र सेना के कार्मिकों की अविवाहित/विधवा पुत्रियों को अब 6 सितम्बर, 2007 से कुटुम्ब पेंशन की अनुमति दी गई है।** विधवाएं भी शर्तों के अधीन दोहरी कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र हैं।

**17.32 प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति की राशि 2250/- रु प्रति माह कर दी गई है।**

**17.33 भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं, महानिदेशालय के अधीन पुनर्वास प्रशिक्षण की पात्र हैं।** पुनर्वास महानिदेशालय की कई रोजगार योजना जैसे कोल टिप्पर योजना, तेल उत्पाद एजेंसियां, सरप्लस वेहिकल्स आदि भी भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए खुली हैं।

## रक्षा मंत्रालय के विभागों के कार्यों की सूची

### क रक्षा विभाग

1. भारत और उसके प्रत्येक विभाग की रक्षा करना, इसमें रक्षात्मक तैयारियां तथा ऐसे सभी काम आते हैं जो युद्ध के समय युद्ध को ठीक ढंग से चलाने तथा युद्ध के बाद सेना को कारगर ढंग से विसंगठित करने के लिए सहायक हैं।
2. संघ की सशस्त्र सेनाएं अर्थात् सेना, नौसेना वायु सेना।
3. रक्षा मंत्रालय के समेकित मुख्यालय जिनमें सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय और रक्षा सेवा मुख्यालय भी शामिल हैं।
4. सेना , नौसेना और वायुसेना के रिजर्व ।
5. प्रादेशिक सेना ।
6. राष्ट्रीय कैडेट कोर।
7. सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित कार्य।
8. रिमाउंट, वेटरनरी और फार्म संगठन ।
9. कैंटीन भंडार विभाग ।
10. रक्षा प्राक्कलनों में वेतनभोगी सिविलियन सेवाएं।
11. हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेवीगेशनल चार्ट बनाना।
12. छावनियों की स्थापना, छावनी क्षेत्रों की हदबंदी और कुछ क्षेत्रों को उसकी सीमा के बाहर निकालना, ऐसे क्षेत्रों के स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐसे क्षेत्रों में छावनी बोर्डों का गठन तथा प्राधिकारी और उनकी शक्तियां तथा उनमें आवास संबंधी विनियम (इसमें किराया नियंत्रण भी शामिल है)।
13. रक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, अभिरक्षा और उसकी वापसी । अनधिकृत कब्जा करने वालों को रक्षा भूमि और संपत्ति से बेदखल करना।
14. रक्षा लेखा विभाग।
15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को जिस खाद्य सामग्री की खरीद का काम सौंप गया है उसे छोड़कर, सेना की जरूरतों की पूर्ति के लिए खाद्य सामग्री की खरीद और उसका निपटान।
16. तटरक्षक संगठन से संबंधित सभी मामले जिनमें निम्नांकित भी शामिल हैं -
  - (i) तेल बिखराव के प्रति समुद्री क्षेत्र की निगरानी ।
  - (ii) बंदरगाहों के जल क्षेत्र और अपतटीय खोज और उत्पादन प्लेटफार्मों, तटीय रिफाइनरियों और अनुषंगी सुविधाओं जैसे कि सिंगल बॉय मूरिंग (एस बी एम), कूड तेल टर्मिनलों (सी ओ टी)

और पाइपलाइनों के 500 मीटर के भीतर के सिवाए विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में तेल बिखराव के प्रति उपाय।

- (iii) तटीय तथा विभिन्न समुद्री क्षेत्रों के समुद्री पर्यावरण में तेल प्रदूषण को दूर करने के लिए केन्द्रीय समन्वय एजेंसी।
- (iv) तेल बिखराव आपदा हेतु राष्ट्रीय आकस्मिकता योजना का कार्यान्वयन, और
- (v) तेल बिखराव रोकथाम और नियंत्रण कार्य हाथ में लेना, देश में जलपोतों और अपतटीय प्लेटफार्मों का निरीक्षण कार्य करना, इसमें वाणिज्य, पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बंदरगाहों की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र शामिल नहीं है।

17. देश में गोताखोरी और संबंधित कार्यकलापों से संबंधित मामले।

18. केवल रक्षा सेवाओं के लिए अधिप्राप्ति ।

## **ख रक्षा उत्पादन विभाग**

1. आयुध निर्माणी बोर्ड और आयुध निर्माणियां
2. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
3. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
4. माझगांव डाक लिमिटेड

5. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
7. भारत डायनामिक्स लिमिटेड
8. मिश्र घातु निगम लिमिटेड
9. गुणता आश्वासन महानिदेशालय और वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय सहित रक्षा गुणता आश्वासन संगठन ।
10. मानकीकरण निदेशालय सहित रक्षा उपस्करों और भंडारों का मानकीकरण ।
11. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
12. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
13. वैमानिकी उद्योग का विकास और नागर उड्डयन मंत्रालय तथा अंतरिक्ष विभाग से संबंधित प्रयोक्ताओं को छोड़कर अन्य के बीच समन्वय।
14. रक्षा उपस्करों का स्वदेशीकरण, विकास तथा उत्पादन और रक्षा उपस्करों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी ।
15. रक्षा निर्यात और रक्षा उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ।

## **ग रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग**

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही प्रगति का राष्ट्रीय सुरक्षा पर होने वाले प्रभाव का जायजा लेकर रक्षा मंत्री को उसकी जानकारी और सलाह देना।

2. हथियारों, हथियार-प्लेटफार्मों, सैन्य संक्रियाओं, निगरानी, सहायता और संभारिकी आदि से संबंधित सभी वैज्ञानिक पहलुओं के संबंध में और संघर्ष के सभी संभावित क्षेत्रों में रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं और अंतर सेवा संगठनों को सलाह देना।
3. ऐसी प्रौद्योगिकियों, जिनका भारत को निर्यात विदेशी सरकारों के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नियंत्रण का विषय है, के अर्जन के बारे में विदेशी सरकारों के साथ समझौता प्रलेखों से संबंध सभी मामलों पर रक्षा मंत्रालय की नोडल समन्वय एजेंसी के रूप में विदेश मंत्रालय की सहमति लेकर कार्य करना।
4. राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा डिजाइन, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रम तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना।
5. विभाग की एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, स्थापनाओं, रेजों, सुविधाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निर्देशन और प्रशासन।
6. वैमानिकी विकास एजेंसी।
7. सैन्य विमानों के डिजाइन, उड़ान योग्यता का प्रमाणन, उनके उपस्करों तथा भंडारों से संबंधित मामले।
8. संसाधन जुटाने के लिए विभाग के कार्यकलापों से तैयार प्रौद्योगिकियों के संरक्षण और हस्तांतरण से संबंधित सभी मामले।
9. रक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी शस्त्र प्रणालियों और तत्संबंधी प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण और मूल्यांकन के कार्यों में भाग लेना तथा वैज्ञानिक विश्लेषण में सहायता करना।
10. उत्पादन यूनिटों और उद्यमों द्वारा सशस्त्र सेनाओं के लिए उपस्कर और भंडारों के विनिर्माण या विनिर्माण के प्रस्तावों के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के प्रौद्योगिकीय तथा बौद्धिक संपदा संबंधी सभी पहलुओं पर सलाह देना।
11. पेटेंट अधिनियम 1970 (1970 का 39) की धारा 35 के अंतर्गत प्राप्त मामलों पर कार्रवाई करना।
12. राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी अध्ययन और जनशक्ति को प्रशिक्षण संबंधी अध्ययन और जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों, संस्थानों तथा कार्पोरेट निकायों को वित्तीय तथा अन्य सामग्री संबंधी सहायता देना।
13. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विदेश मंत्रालय के परामर्श करके निम्नलिखित मामलों सहित राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबद्ध मामले:-
  - (i) अन्य देशों और अंतः सरकारी एजेंसियों के अनुसंधान संगठनों से संबंधित मामले विशेष रूप से जो अन्य कार्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय पहलुओं से संबंधित हैं।
  - (ii) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों के तहत कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी-



विदों को प्रशिक्षण और विदेशी छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए विदेश स्थित विश्वविद्यालयों, शैक्षिक और अनुसंधान-उन्मुख संस्थाओं के साथ व्यवस्था करना।

14. विभाग के बजट से निर्माण कार्य करना और भूमि खरीदना जो विभाग के बजट के नामे डाले जाते हैं।
15. विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित सभी मामले।
16. इस विभाग के बजट से सभी प्रकार के भंडारों, उपकरणों और सेवाओं का अर्जन।
17. विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरिया।
18. राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय पहलुओं को प्रभावित करने वाले कार्यकलापों से संबंधित भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, एजेंसी के साथ समझौता अथवा व्यवस्था करके इस विभाग को सौंपे गए और इस विभाग द्वारा स्वीकार किए गए कोई भी अन्य कार्य।

## घ भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

1. भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित मामले, जिनमें पेंशनभोगी भी शामिल हैं।
2. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना।
3. पुनर्वास महानिदेशालय तथा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से संबंधित मामले।
4. निम्नलिखित का प्रशासन:

- (क) सेना के वास्ते पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और 2);
- (ख) वायुसेना के वास्ते पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और 2);
- (ग) नौसेना पेंशन विनियम, 1964; और
- (घ) सशस्त्र सैन्य कार्मिकों को हताहत पेंशनरी अवाडों के हकदारी विनियम, 1982

## ड रक्षा (वित्त) प्रभाग

1. सभी रक्षा मामलों की वित्त संबंधी जांच करना।
2. रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालयों के विभिन्न अधिकारियों को वित्तीय सलाह देना।
3. रक्षा मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग के रूप में कार्य करना।
4. व्यय संबंधी सभी योजनाओं/प्रस्तावों को तैयार करना और उनके कार्यान्वयन में सहायता करना।
5. रक्षा योजनाएं तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में सहायता करना।
6. रक्षा सेनाओं के लिए रक्षा बजट और अन्य प्राक्कलन, रक्षा मंत्रालय के सिविल प्राक्कलन, रक्षा पेंशनरों के संबंध में प्राक्कलन तैयार करना और बजट के अनुरूप योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखना।
7. बजट बनाने के बाद यह सुनिश्चित करना कि व्यय न तो बहुत कम हो और न ही अनपेक्षित रूप से अधिक हो।

8. सशस्त्र सेना मुख्यालयों की शाखाओं के प्रमुखों को अपने वित्तीय दायित्व का निर्वाह करने के लिए सलाह देना।
9. रक्षा सेवाओं के लिए लेखा प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
10. रक्षा सेवाओं के लिए विनियोजन लेखा तैयार करना।
11. रक्षा लेखा महानियंत्रक के माध्यम से रक्षा व्यय के भुगतानों और आंतरिक लेखापरीक्षा के दायित्व का निर्वाह करना।

1 जनवरी, 2013 से आगे पदासीन मंत्री, सेनाध्यक्ष और सचिव

रक्षा मंत्री

श्री ए.के. अंटनी  
श्री अरुण जेटली

24 अक्टूबर, 2006 से 26 मई, 2014  
दिनांक 27 मई, 2014 से आगे

रक्षा राज्य मंत्री

श्री जितेन्द्र सिंह  
श्री इंद्रजीत सिंह राव

28 अक्टूबर, 2012 से 26 मई, 2014  
दिनांक 27 मई, 2014 से आगे

रक्षा सचिव

सेनाध्यक्ष

श्री शशि कांत शर्मा,  
14 जुलाई, 2011(पूर्वाह्न) 23 मई, 2013(पूर्वा.)  
श्री आर.के. माथुर,  
31 मई, 2012 (अपराह्न) से आगे

जनरल विक्रम सिंह,  
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी  
24 मई, 2013 (पूर्वा.) से आगे

सचिव रक्षा उत्पादन

नौसेनाध्यक्ष

श्री आर. के. माथुर  
1 अक्टूबर, 2012 (पूर्वाह्न) से 6 अगस्त, 2013 (अप.)  
श्री गोकुल चन्द्र पति  
07 अगस्त, 2013 (पूर्वा.) से आगे

एडमिरल डी.के.जोशी  
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम, एडीसी  
31 अगस्त, 2012 (अपराह्न) से 26 फरवरी, 2014 तक

एडमिरल आर.के.धवन

पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एडीसी  
17 अप्रैल, 2014 से आगे

सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण

वायुसेनाध्यक्ष

श्री विजय छिब्रर  
10 सितम्बर, 2012 (अपराह्न) से 31 जनवरी, 2013  
श्री आर.के. माथुर  
31 जनवरी, 2013 से 12 फरवरी, 2013 (अप.)

एयर चीफ मार्शल एनएके ब्राउन,  
पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, एडीसा  
31 जुलाई, 2011 (अपराह्न) से 31 दिसम्बर, 2013 (अप.)  
एयर चीफ मार्शल अरुण राहा,

श्री राजीव गुप्ता

12 फरवरी, 2013 (अपराह्न) से 04 जुलाई, 2013 (अप.)

पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम एडीसा

31 दिसम्बर, 2013 (अप.) से आग

सुश्री संगीता गैरोला

04 जुलाई, 2013 (अप.) से आगे

सचिव(रक्षा अनुसंधान एवं विकास) तथा रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार

डॉ. वी.के.सारस्वत

31 अगस्त, 2009(अपराह्न) से 31मई, 2014 (अप.)

डा. अविनाश चन्द्र

31 मई, 2013 (अप.) से आगे

सचिव रक्षा वित्त

श्रीमती प्रीति मोहंती

2 जुलाई, 2012 (पूर्वाह्न) से 30 जून, 2013 (अप.)

श्री अरुणव दत्त

01 जुलाई, 2013 (अप.) से आगे

## (II) लेखा परीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन पर वर्ष 2013 की रिपोर्ट सं. 2013 रिपोर्ट में शामिल महत्वपूर्ण पैराएं नीचे दी गई हैं:-

रिपोर्ट में शामिल की गई महत्वपूर्ण पैराओं की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं।

### रक्षा मंत्रालय

1. रक्षा मंत्रालय ने जुलाई, 2004 तक पूर्ण होने वाले 180 करोड़ रुपए की लागत पर हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लि. (एचएएल) द्वारा इंटरमिडिएट जेट ट्रेनर (आईजेटी) के डिजाइन और विकास की संस्वीकृति जुलाई, 1999 में दी थी। हालांकि आईजेटी के डिजाइन और विकास की प्रारंभिक परिचालन मंजूरी (आईओसी) अभी तक अनुमोदन के स्तर तक पहुँचनी थी, मंत्रालय ने एचएएल द्वारा सीमित श्रृंखला उत्पादन (एलएसपी) (मार्च, 2006) और श्रृंखला उत्पादन (एसपी) (मार्च, 2010) की संयुक्त संभलाई की भी संस्वीकृति दे दी। लेखा परीक्षा ने निम्नलिखित पाया:-

वास्तविक रूप से मार्च, 2007 के लिए अनुसूचित आईओसी छः वर्षों के विलंब के बाद भी प्राप्त नहीं की जा सकी। विभिन्न चरणों पर कई विफलताओं से विकास में रुकावट आई थी।

विभिन्न चरणों के लिए अनुसूचित समय सीमा में बाधाएं ईजन डिजाइन को निश्चित न करने, ईजन के भार में परिवर्तन और अपर्याप्त दबाव वाले इजन के साथ प्रयोग के कारण आई थी। निर्धारित संख्या में उड़ाने पूरी करने के बाद दोनों नमूनों की दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप विमान के ढांचे को मजबूत बनाने

के लिए उड़ान परीक्षण गतिविधियों और संशोधनों को स्थगित किया गया।

फेब्रिकेशन के लिए निर्धारित प्रक्रिया और संरचनात्मक परीक्षण नमूने की जांच जिससे डिजाइन की मजबूती साबित करने के लिए बुनियादी एयरफ्रेम के डिजाइन भार की डेढ़ गुना तक जांच की जानी थी, पहले नमूने के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कम भार भी नमूना विमानकबन्ध में दरार आई जिससे दूसरे विंग का निर्माण करना पड़ा जिस पर 38.78 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

चूंकि कंपनी स्टाल विशेषताएं और स्पिन परीक्षा का सुधार नहीं कर सकी, अतः 23.59 करोड़ रुपए की लागत से दिसम्बर 2012 में काफी देरी से एक सलाहकार को नियुक्त किया गया।

एलएसपी को उद्धृत करते समय उपकरणों/घटकों के लिए अस्थायी खरीद मूल्य अपनाने के परिणामस्वरूप 63.59 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय किया गया।

विकास के लिए 180 करोड़ रुपए की वास्तविक मंजूरी के प्रति, परियोजना पर पहले से ही 516 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है।

एचएएल को निधियां जारी करने के लिए निर्धारित मापदंड निश्चित और पर्याप्त भौतिक प्रगति से संबंधित नहीं थे। एलएसपी के लिए 487 करोड़ रुपए की संस्वीकृति लागत के प्रति मंत्रालय द्वारा आईओसी



की प्राप्ति से पहले जारी की गई राशि 444 करोड़ रुपए थी। एसपी के संबंध में 6180 करोड़ रुपए की संस्वीकृति के प्रति जारी राशि 3075 करोड़ थी किंतु व्यय केवल 168 करोड़ रुपए था।

इंजन के लिए संविदा दर मंगाने के बावजूद असीमित कुल तकनीकी जीवन के साथ और बाद में जीवन काल में वृद्धि के साथ इंजन के लिए घटे हुए प्रारंभिक जीवन की स्वीकृति की मांग के परिणामस्वरूप 131 करोड़ रुपए का परिहार्य व्यय हुआ।

आवश्यकता के लिए पहले से ही लाइन प्रतिस्थापन इकाइयों की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप 114.76 करोड़ रुपए के सामान की वारंटी समाप्त हो गई।

आवश्यकता के अनुसार एयरक्राफ्ट की सुपुदर्शी न होने के कारण मार्च, 2013 तक आईएएफ के पयलटों के मध्यवर्ती स्तर प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

### (पैरा सं. 7.8)

2. भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) की सशस्त्र बलों द्वारा वांछित परिष्कृत रक्षा उपकरणों ने निर्माण के उद्देश्य से स्थापना की गई थी। बीडीएल भारत में नियंत्रित प्रक्षेपास्त्रों के लिए एक प्रमुख उत्पादन एजेंसी है। बीडीएल की भानूर यूनिट को कोनकुर्स एटीजीए सिस्टम्स और युनिफाइड लांचरों के निर्माण के लिए स्थापित (1988) किया गया था और एमओडी द्वारा किए गए करार के भाग के रूप में 1989 से बीडीएल की भानूर यूनिट को कोनकुर्स मिसाइलों के उत्पादन का कार्य दिया गया था। चूंकि कोनकुर्स मिसाइल ईआरए पैनल लगे टैंकों को ध्वस्त

नहीं कर पाए थे, अतः थलसेना ने कोनकुर्स के उन्नत रूप कोनकुर्स-एम मिसाइल को समाविष्ट करने की जरूरत को पहचाना जो ईआरए द्वारा संरक्षित टैंकों को ध्वस्त करने में सक्षम थी (1994)

लेखापरीक्षा ने पाया कि कोनकुर्स-एम के उन्नत रूप की आवश्यकता की स्वीकृति की तिथि (1944) से करार को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में लगभग आठ वर्ष लगे। इसके अतिरिक्त, तकनीक के समावेश में प्रत्याशित से अधिक समय लगा और इसके कारण करार के निष्पादन में तीन वर्षों का विलम्ब हुआ और थलसेना द्वारा लगाए गए 38.81 करोड़ रुपए के निर्णीत हर्जाने (एलडी) के अलावा 14,722 मिसाइलों की आपूर्ति में विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप 283.72 करोड़ रुपए की हानि हुई। बकाया 13,278 मिसाइलों की आपूर्ति के लिए अनुमानित हानि 297.25 करोड़ रुपए है और संभावित एलडी 75.57 करोड़ रुपए है। बीडीएल ने दो चरणों में क्रमशः 50 करोड़ रुपए और 130 करोड़ रुपए की लागत से मिसाइलों के उत्पादन के लिए क्षमता संवर्धन की योजना बनाई (अगस्त, 2010)। चरण-1 मार्च, 2012 तक और चरण-2 मार्च, 2013 तक पूरा होना था। यद्यपि पहला चरण मार्च 2012 तक पूर्ण होना था, तथापि, फरवरी, 2013 तक 59.27 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी क्षमता 3000 मिसाइल प्रति वर्ष के समान स्तर पर ही रही।

लेखा परीक्षा ने आगे पाया कि एमओडी ने थल सेना के लिए मै. रोसोबोरेन एक्सपोर्ट के साथ 1223 करोड़ की लागत से 10,000 कोनकुर्स-एम की खरीद के लिए एक रार इस आधार पर

किया कि टीओटी के समावेश की कठिनाईयों के कारण बीडीएल उनके संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं था। इससे पता चलता है कि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता से बचने के लिए एमओडी की कोनकुर्स-एम मिसाइलों के स्वदेशी उत्पादन के प्रयास अक्टूबर, 2002 में किए गए करार के तहत केबीपी से 249 करोड़ रुपए की लागत पर तकनीक खरीदने के बावजूद विफल रहे।

**(पैरा 7.3)**

3. भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने खरीद के लिए विदेशी विक्रेता मै0 रीनमैटल एयर डिफेंस, एजी, ज्युरिक (आरएडी) के साथ इस तथ्य के बावजूद करार किया कि सीबीआई पहले ठेकों में तथाकथित भ्रष्ट पद्धति अपनाने के लिए फर्म के सौदों की जांच कर रही है जिससे फर्म को काली सूची में डाले जाने का जोखिम था। चूंकि फर्म अंत में काली सूची में डाल दी गई थी, अतः इसके परिणामस्वरूप बीईएल की 502.31 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

**(पैरा सं.7.4)**

4. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने जनवरी, 2013 तक पाँच चरणों (0 से 4) में 320 शक्ति इंजनों के सह विकास और स्वदेशी उत्पादन के लिए 878.08 करोड़ की लागत पर टर्बोमेक, फ्रांस (टीएम) के साथ सह-परिचालन करार (करार) पर हस्ताक्षर किए (जनवरी 2003)। विभिन्न फेजों के लिए एसेम्बली किट की आपूर्ति टीएम द्वारा सहमति मूल्य पर की जानी थी जो कि सुपुर्दगी के वर्ष तक वैध

स्वतः वृद्धि (2002 आधार वर्ष के रूप में) का विषय था।

लेखा परीक्षा ने देखा की एक दशक से अधिक के बाद भी एएलएच की आवश्यकताओं के अनुरूप इंजन के विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं की गई है जैसा कि अवगत कराया गया था। विभिन्न जलवायु परिस्थितियों और ऊँचाई पर परिचालन के लिए इंजनों की विभिन्नताओं के लिए आवश्यकता का पूर्वानुमान नहीं लगाया गया जिसके कारण समय और निधि के रूप में अधिक निवेश वाले आशोधन निरंतर किए गए। एचएएल को टीएम की विफलता के कारण अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा जो शक्ति इंजनों के विकास और उत्पादन में विदेशी भागीदारों के साथ किए गए अनुचित पक्षपात को दर्शाया था। विदेशी सहयोगी द्वारा अनिवार्य क्षतिपूर्ति का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफलता ने आत्मनिर्भरता के प्रति योगदान में भारतीय उद्योगों को अवसर से वंचित कर दिया। मुफ्त तकनीकी सहायता के इष्टतम उपयोग के बिना अतिरिक्त जानकारी की प्राप्ति ने परियोजना की अधिक लागत में योगदान दिया।

इस प्रकार, प्रौद्योगिकी प्राप्त करने और शक्ति इंजनों के विनिर्माण की उपलब्ध इन-हाउस क्षमता के गैर-निर्धारण में एचएएल की अक्षमता ने रक्षा बलों में एएलएच के समय से प्रेरणा को प्रभावित किया और इसके परिणामस्वरूप एचएएल को 204.27 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान भी हुआ।

**(पैरा सं. 7.7)**

## कार्यकारी सारांश

### पृष्ठभूमि

सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्त्रादिक मदों (जीएस एवं सी) तथा सामान्य भंडार के उत्पादन में आयुध फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता (ओएफबी) एवं आयुध उपस्कर समूह मुख्यालय कानपुर (ओईएफएचक्यू) के नियंत्रण के अंतर्गत आयुध उपस्कर समूह (ओईएफजी) की पांच (फैक्ट्रियां) संलग्न हैं। इन मदों की मुख्य प्राप्तकर्ता (लगभग 77 प्रतिशत) थल सेना है।

ओईएफजी में संसाधनों के अल्प उपयोग, उत्पादन के कार्य-निष्पादन में कमी, भंडार एवं मशीनरी की अधिप्राप्ति में दोष, अदक्ष उत्पादन नियोजन आदि के बारे में भारत के नियंत्रण-महालेखा परीक्षक के पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लेख किया गया था। 1999-2004 की अवधि के लिए इन फैक्ट्रियों का कार्य निष्पादन, फरवरी-जून 2004 के दौरान पुनरीक्षित किया गया इसके परिणामों को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के 2005 के प्रतिवेदन संख्या 06 के पैरा 8.2 में समाविष्ट किया गया है। उत्पादन योजना, क्षमता का उपयोग, थल सेना (उत्पादनों के मुख्य प्राप्तकर्ता) को सही समय पर विशिष्ट गुणवत्ता के जीएस एवं सी उत्पादन को निर्गमित करने तथा उत्पादन आदि के क्षेत्र को केन्द्र बिन्दु बनाकर जनवरी-जुलाई, 2011 के दौरान हमारे द्वारा नये सिरे से ओईएफजी का कार्य निष्पादन पुनरीक्षित किया गया। वर्ष 2011-12 के लिए, जहां भी इस प्रतिवेदन में उल्लिखित है, अप्रैल 2013 के बाद में डाटा संग्रहित किया गया था।

वर्ष 2008-12 के दौरान इन फैक्ट्रियों की कार्य-निष्पादन लेखा परीक्षा, योजना से लेकर उसे कार्यान्वित करने तक की प्रणालगत कमियों को दर्शाता है।

### मूल निष्कर्ष

#### 1. वार्षिक उत्पादन लक्ष्य के निर्धारण में दोष/त्रुटि

लक्ष्य की वैभिन्यता एवं फैक्ट्रियों की क्षमता, वार्षिक उत्पादन लक्ष्य के निर्धारण में विलंब तथा फैक्ट्रियों द्वारा एक पक्षीय स्तर पर लक्ष्य को न्यून करना जैसी कमियों के साथ विद्यमान थी जिसके परिणामस्वरूप सेना को मदों की आपूर्ति में चूक हुई।

(अध्याय-III)

#### 2. अधिप्राप्ति मानकों का उल्लंघन

ओएफबी के सामग्री प्रबंधन एवं अधिप्राप्ति नियम पुस्तक (एमएमपीएम) के पैराग्राफ 3.1.1, 3.7.7, 4.6.1 तथा अनुलग्नक-47 में अधिप्राप्ति मानकों, प्रक्रिया आदि का वर्णन है। हमने देखा कि 2008-11 के दौरान एमएमपीएम में विद्यमान इन प्रावधानों का उल्लंघन कर भंडार की अधिप्राप्ति के कारण 165.54 करोड़ रुपए की कीमत के भंडार का अति प्रावधान हुआ। इसी प्रकार निर्धारित प्रावधान के विरुद्ध खुली निविदा जांच (ओटीई) के द्वारा निर्धारित एमएमपीएम में 20 प्रतिशत खरीद के प्रति, चार फैक्ट्रियों ने इना उल्लंघन करते हुए ओटीई के द्वार केवल चार से दस प्रतिशत खरीद की। ओटीई के स्थान पर सीमित निविदा जांच (एलटीई) पर निर्भरता के कारण, 40 आपूर्ति आदेशों के माध्यम से 14 मदों की अधिप्राप्ति में 12.31 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय पाया गया।

इसके अतिरिक्त ओएफबी के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए (अप्रैल 2007) ओएफबी द्वारा निर्धारित अंतिम खरीद दर से आठ प्रतिशत अधिक दर की औचित्यपूर्ण सीमा का उल्लंघन करते हुए भम् 94.33 करोड़ रुपए मूल्य के 107 आपूर्ति आदेश ओईएफजी द्वारा प्रस्तुत किए गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि फैक्ट्रियों द्वारा आदेशों को प्रस्तुत करने के पहले मूल्य की उपयुक्तता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

जुलाई 2007 के ओएफबी के निर्देश के अनुरूप आपूर्तिकर्ताओं के गठजोड़ को समाप्त करने में विफलता के कारण विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से 102 आदेशों के द्वारा 33.91 करोड़ रुपए मूल्य के भंडार की अधिप्राप्ति एक समान दरों पर की गई है।

एमएमपीएम में दिये गये विशिष्ट समय सीमा की तुलना में पांच फैक्ट्रियों द्वारा 2008-12 में दिए गए 11689 आदेशों में से 430.63 करोड़ रुपए के 4117 आदेशों के प्रस्तुतिकरण में भारी विलम्ब (1441 दिनों तक) हुआ।

#### (अध्याय-IV)

### 3. मदों के उत्पादन तथा सेना को निर्गम में चूक

228 में से 116 मामलों में जीएस एवं सी मदों के उत्पादन एवं सेना को निर्गम में कमी की प्रतिशतता 21 से 100 प्रतिशत के मध्य रही। 2008-12 के दौरान प्रत्येक वर्ष में विश्लेषित 52 मदों में से, 34 से 41 मदों के संबंध में कमी का मूल्य 1147.13 करोड़ रहा। इसके अतिरिक्त, अगले वर्ष में अवधि उपरांत उत्पादित व निर्गमित मदों का मूल्य 493.08 करोड़ रुपए रहा। कार्य को बाह्य स्रोतों से कराने के बावजूद जी.एस. एवं सी. मदों के निर्गम,

में स्थानिक चूक तथा कई मामलों में लक्ष्य के एक पक्षीय न्यूनीकरण से सेना को गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। ओई.ई.एफ.जी., अर्ध सैनिक बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी विफल रहा, क्योंकि 2008-12 के दौरान जी.एस. एवं सी. मदों की उनकी आवश्यकता (1068.36 करोड़ रुपए) का केवल 2.62 प्रतिशत से कम भाग ही पूरा कर सका।

#### (अध्याय-V)

### 4. संसाधनों का अल्प उपयोग

2008-12 में उपलब्ध मानक श्रम घंटों का पूर्ण उपयोग न होने पर भी, फैक्ट्री प्रबंधन ने औद्योगिक कर्मचारियों को 48.68 करोड़ रुपए समयोपरि भुगतान की अनुमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त 2011-12 में उजरती कार्य लाभ के रूप में फैक्ट्रियों ने आई.ई. को 10.91 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अदायगी की। मशीनों के एक शिफ्ट उपयोग के कारण, क्षमता का अल्प उपयोग हुआ जो की 45 से 69 प्रतिशत के मध्य था।

#### (अध्याय-VI)

### 5. निम्न स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण एवं उत्पादों का आश्वासन

स्थापित मदों के संबंध में भी गुणवत्ता आश्वासन स्तर पर फैक्ट्रियों द्वारा अकुशल उत्पादन तथा अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण 'सुधार हेतु वापसी' (आरएफआर) की बढ़ोत्तरी का कारण बना। वर्ष 2008-12 के दौरान 31 मदों के संबंध में, 266 में से 72 मामलों में यह देखा गया कि उच्च दर 20 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक थी। 2009-11 के दौरान दो फैक्ट्रियों में 11.66 करोड़ रुपए के पांच मदों की अंतिम रूप

से अस्वीकृति हुई। नियमित उपभोक्ता परिवारों के अतिरिक्त हमने प्रयोक्ता के स्तर पर 10.42 करोड़ रुपए के अस्वीकृति के पांच मामलों को पाया, जबकि वे सभी गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों द्वारा निरीक्षण में स्वीकृत कर दी गई थी।

### (अध्याय-VII)

#### 6. मांगकर्ताओं को उत्पाद को जारी करने में आवर्ती हानि

मांगकर्ताओं को मदों के निर्गमन में 2008-12 के दौरान ओ.एफ.बी. के अनुपयुक्त मूल्य निर्धारण प्रणाली और अप्रभावी लागत नियंत्रण के कारण चार फैक्ट्रियों में आवर्ती हानियां हुईं। 2008-12 के दौरान ओ.ई.एफ.जी. को 226.09 करोड़ रुपए की शुद्ध हानि का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त अन्य फैक्ट्री की तुलना में एक फैक्ट्री में सामान्य मदों की उत्पादन लागत अधिक होने के कारण 16 मामलों में 105.47 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। ओ.ई.एफ.जी. का प्रति वर्ष केवल छः प्रतिशत का उत्पादन अंश था जबकि 2008-12 के दौरान आयुध फैक्ट्री संगठन का प्रत्यक्ष श्रम लागत 16 से 18 प्रतिशत तक था। अपने अतिशय मूल्य के कारण ओ.ई.एफ.जी. अपने उत्पादनों के लिए संभाव्य विपणन क्षेत्र स्थापित नहीं कर पा रहा था।

### (अध्याय-VIII)

#### 7. अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण

ओ.ई.एफ.एच.क्यू. द्वारा फैक्ट्रियों में अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण एवं उचित अनुश्रवण के अभाव के साथ-साथ अप्रभावी अनुश्रवण एवं दिशानिर्देश के कारण, समाप्त/अनुपस्थित अधिपत्र के श्रम प्रभारों को दर्ज करने में अनियमितता,

अस्वीकृतियों/रद्दी से व्युत्पन्न हानियों का अविनियम्यताकरण एवं बिना सामग्री/अधिक सामग्री के आहरण से निर्माण हुआ। ओ.ई.एफ.जी. के कार्यों पर उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा किया गया अनुश्रवण भी अपर्याप्त था।

### (अध्याय-IX)

#### संस्तुतियां

- मंत्रालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि सेना और ओएफबी निकटवर्ती समन्वय के साथ ओईएफजी की क्षमता और सेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्पादन के लक्ष्य को निर्धारित करें। ओएफबी को लक्ष्य निर्धारण बैठक के पूर्व ही सेना के प्रत्येक मद के लिए अपनी उत्पादन क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
- फैक्ट्रियों को अधिप्राप्ति के लिए आवश्यक समय देने के लिए मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेना तथा ओएफबी लक्ष्य निर्धारण बैठक का आयोजन सही समय पर करें।
- ओएफबी को सुनिश्चित करना चाहिए कि फैक्ट्रियां अधिक अधिप्राप्ति से बचने के लिए विश्वसनीय एवं विशुद्ध प्रावधान हेतु भंडार की शुद्ध आवश्यकता को आकलन में निर्धारित नियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करें।
- ई-अधिप्राप्ति प्रणाली को सभी फैक्ट्रियों में क्षमता से लागू करना चाहिए तथा सभी फैक्ट्रियों को सामंजस्यपूर्ण डाटाबेस अनुरक्षित करना चाहिए।



- ओएफबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गठजोड़ीकरण से बचने के लिए जुलाई 2007 के ओएफबी के दिशानिर्देशों का अधिप्राप्ति एजेंसियों को कड़े रूप से पालन करना चाहिए।
- यथार्थपरक उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए की ओईएफजी विवेकपूर्ण उत्पादन और अधिप्राप्ति योजना को व्यवस्थापित करें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए कि आयुध फैक्ट्रियों के लेखे में क्रेडिट के साथ-साथ थल सेना के लेखे से डेविट तभी हो, जब परेषिती थल सेना द्वारा उनके डिपो द्वारा भंडार स्वीकृत एवं परीक्षित हो जाय जिससे अवधि उपरांत निर्गमन को दोषपूर्ण लेखांकन समाप्त हो सके।
- दरों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए एक तकनीक को निर्मित कर और कार्यों के वाहयस्रोतीकरण को कम करने के लिए समर्पित क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर ओएफबी को बाहय स्रोतों से कार्य की नीति को व्यवस्थित करना चाहिए।
- ओएफबी को ओईएफएचक्यू में एक डाटाबेस तैयार करना चाहिए जो कार्यों के वाहस्रोतीकरण के लिए उचित तथा नवीनतम दरों के साथ हो और जिसे सभी फैक्ट्रियों द्वारा उपभोग किया जा सके।
- ओएफबी को सुनिश्चित करना चाहिए कि फैक्ट्रियां अपने उत्पादन क्रियाकलापों को दक्षतापूर्ण नियोजन करे, कार्यभार आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी श्रमशक्ति को सही दिशा में विवेकपूर्ण तरीके से तैनात करें तथा कार्य के लिए समयोपरि भुगतान पर निर्भरता के पूर्व उपलब्ध एसएमएच का पूर्ण रूप से उपयोग करें।
- मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओएफबी निश्चित किए गए आउटपुट एमएमएच के ऊपर अतिरिक्त 25 प्रतिशत छोड़कर उजरती कार्य लाभ का भुगतान करने के लिए सही प्रणाली का पालन करे।
- क्षमता उपयोग तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ओएफबी को फैक्ट्रियों में युगल शिफ्ट कार्य को कार्यरूप में लाने का प्रयास करना चाहिए।
- उचित पहचान के बाद सभी अधिक/अप्रचलित/ अनुपयोगी/रद्दी को निस्तारित करने के लिए ओएफबी को विभिन्न फैक्ट्रियों में सामग्री भंडारण की सामयिक पुनरीक्षा की प्रणाली को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।
- ओएफबी को इस बात को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि फैक्ट्रियां इनपुट सामग्रियों के निरीक्षण के लिए निर्धारित मानकों को कर्मठता से परिपालित करें।
- ओएफबी को फैक्ट्रियों के स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण कर्मचारी द्वारा आवश्यक शत-प्रतिशत पूर्व निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करना चाहिए।
- मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओएफबी तथा फैक्ट्रियां सभी संबंधित क्रियाकलाप के लेखांकन और अभिलेखीकरण तथा मुख्य रूप से नियोजन एवं उत्पादन जैसे क्षेत्रों में अपने आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली को मजबूत करे ।
- ओईएफजी द्वारा एक विस्तृत एवं प्रभावी आंतरिक प्रणाली विकसित किया जाना चाहिए जिससे

बिना सामग्री अथवा अधिक सामग्री के आहरण से निर्माण तथा श्रम प्रभारों को दर्ज करने में होने वाली अनियमितताओं से बचा जा सके।

## पर वर्ष 2013 की रिपोर्ट सं. 2013

### अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए हेलिकॉप्टरों का अधिग्रहण

- भारतीय वायुसेना (आईएफ) का संचार स्क्वाड्रन अतिविशिष्ट व्यक्तियों को हवाई परिवहन उपलब्ध कराने हेतु वायुयान एवं हेलिकॉप्टरों के एक बेडे का रखरखाव करता है। भारतीय वायुसेना ने इस स्क्वाड्रन में एमआई-8 हेलिकॉप्टरों का उनके कालप्रभावन और परिचालन परिसीमान के कारण हेलिकॉप्टरों के एक उन्नत रूपांतर के साथ प्रतिस्थापन करने का प्रस्ताव दिया (अगस्त, 1999)। रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने 3726.96 करोड़ (यूरो, 556,262,026) की कुल लागत पर 12 एडब्ल्यू-101 हेलिकॉप्टरों की अधिप्राप्ति के लिए मैसर्स अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल लि0, यूके के साथ एक संविदा की (फरवरी 2010)। वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों के अधिग्रहण की अनुपालन लेखापरीक्षा की गयी तथा लेखापरीक्षा के मुख्य निकायों का उल्लेख नीचे किया गया है:
- विद्यमान एमआई-8 हेलिकॉप्टरों के प्रतिस्थापन के लिए मार्च 2002 में जारी किए प्रारंभिक प्रस्ताव हेतु अनुरोध में 6000 मीटर की एक अनिवार्य ऊंचाई की आवश्यकता अनुबद्ध की गई। ईएच-101 हेलिकॉप्टर (बाद में अगस्ता वेस्टलैंड के एडब्ल्यू-101 के रूप में पुनर्नामकरण किया गया) का क्षेत्रीय मूल्यांकन नहीं किया जा सका था, क्योंकि इसे केवल 4572 मीटर तक की ऊंचाई

की उड़ान भरने के लिए प्रमाणित किया गया था। प्रथम प्रस्ताव हेतु अनुरोध को एक परिणामी एकल विक्रेता वाली स्थिति के आविर्भाव के कारण बाद में निरस्त कर दिया गया। 2006 में जारी परिशोधित प्रस्ताव हेतु अनुरोध में 6000 मीटर ऊंचाई की आवश्यकता संबंधी अनिवार्य सेवाओं की गुणात्मक आवश्यकता को कम करके 4500 मीटर कर दिया गया और कम से कम 1.8 मीटर की कैबिन ऊंचाई को शामिल किया गया। जहां कम से कम 1.8 मीटर की कैबिन ऊंचाई की अनिवार्य आवश्यकता ने प्रतिस्पर्धा को कम कर दिया, वहां ऊंचाई की आवश्यकता को कम करना, उत्तर और पूर्वोत्तर के अनेक क्षेत्रों में परिवहन के लिए 6000 मीटर की अनिवार्य परिचालन आवश्यकता के विपरीत था। सेवाओं की गुणात्मक आवश्यकताओं की पुनः संरचना का उद्देश्य, अर्थात् एकल विक्रेता की स्थिति से बचना, पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि सेवाओं की गुणात्मक आवश्यकताओं के आधार पर की गई अधिग्रहण प्रक्रिया में एक बार फिर एकल विक्रेता की स्थिति उत्पन्न हो गई और एडब्ल्यू-101 अगस्ता वेस्टलैंड का चयन किया गया।

- मार्च 2002 में ग्यारह विक्रेताओं को जारी प्रारंभिक प्रस्ताव हेतु अनुरोध को प्रधान मंत्री कार्यालय की शंकाओं के कारण निरस्त कर दिया गया, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप एकल विक्रेता वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। 2006 के परिशोधित प्रस्ताव हेतु अनुरोध में, प्रतिस्पर्धा हो बढ़ाने के लिए सेवाओं की गुणात्मक आवश्यकताओं को व्यापक बनाने के बजाय उन्हें और अधिक सीमित कर दिया गया, जिसके कारण सीमित श्रेणी के हेलिकॉप्टरों के विकल्प सीमित हो गए। परिशोधित प्रस्ताव

- हेतु अनुरोध केवल छः विक्रेता को जारी किए गए थे।
- अगस्ता वेस्टलैंड के एडब्ल्यू-101 का फील्ड मूल्यांकन परीक्षण मर्लिन एमके-3ए और सिव-01 और यात्री कैबिन का मॉक अप प्रतिनिधि हेलिकाप्टरों पर किया गया न कि वास्तविक हेलिकाप्टर पर, जबकि सिकास्की के वास्तविक एस.92 हेलिकॉप्टर का मूल्यांकन किया गया। फील्ड मूल्यांकन परीक्षण के चरण में भी अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा प्रस्तावित हेलिकॉप्टर अपने विकास के चरण में था। विभिन्न क्रियाविधियों का अनुसरण करते हुए हेलिकॉप्टरों के मूल्यांकन से वांछित आश्वासन नहीं दिया जा सका कि दोनों सूचीबद्ध विक्रेताओं को समान अवसर उपलब्ध कराया गया था।
  - ऐसे अनेक उदाहरण देखे गए हैं जहां मंत्रालय ने रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2006 के प्रावधानों से विचलन किया और सितम्बर 2006 में प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी किया गया। जहां विचलन के लिए अनुमोदन अत्यधिक सावधानी के साथ और अपवादात्मक परिस्थितियों में ही प्राप्त किया जाना अपेक्षित था, वहां इस मामले में किए गए निरंतर विचलन रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के उस मूल्य उद्देश्य के विरुद्ध हैं, जिसके लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2006 के पैराग्राफ 75 को शामिल किया गया है।
  - अधिग्रहण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में 10 वर्षों से अधिक समय के विलंब के कारण भारतीय वायुसेना विद्यमान हेलिकॉप्टरों पर परिचालन प्रतिकूलताओं का निरंतर सामना करती रही।
  - बेंचमार्किंग के उद्देश्य से मूल्य के औचित्य का अवधारण करने पर रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2006 में बल दिए जाने के बावजूद संविदा वार्तालाप समिति द्वारा निकाला गया बेंचमार्क मूल्य (4871.5 करोड़ रुपए) अविवेकी रूप से अधिक था और इस प्रकार इसने मूल्य संबंधी बातचीत के लिए हेलिकॉप्टरों के प्रस्तावित मूल्य (3966 करोड़ रुपए ) के साथ तुलना हेतु कोई भी यथार्थ आधार मुहैया नहीं कराया था।
  - 1240 करोड़ रुपए की लागत पर 04 हेलिकॉप्टरों की अतिरिक्त अधिप्राप्ति परिहार्य थी, क्योंकि निर्धारित आवश्यकता विगत में अतिविशेष व्यक्तियों को परिवहन उपलब्ध कराने वाले विद्यमान हेलिकॉप्टरों की कम उपयोगिता दर के अनुरूप नहीं थी।
  - अगस्ता वेस्टलैंड ने सात कार्यक्रमों को प्रशिक्षित किया था, जिन्हें ऑफसेट संविदा के भाग के रूप में पूरा किया जाना था। अनुमत किए गए आफसेट रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के प्रावधानों के उपयुक्त नहीं थे, इसके अतिरिक्त आफसेट बाध्यताओं के पालन के लिए चयनित अनेक भारतीय ऑफसेट भागीदार (आईओपी) पात्र नहीं थे।
  - आईडीएस इंफोटेक (भारतीय आफसेट भागीदार) द्वारा निष्पादित की जाने वाली सेवाओं के प्रकार और निर्यात आदेशों से संबंधित आफसेट संविदा में अस्पष्टता थी। अगस्ता वेस्टलैंड ने इस आफसेट कार्यक्रम के अंतर्गत आईडीएस इंफोटेक द्वारा 2011 से 2014 तक निष्पादित किए जाने वाले कार्य का वर्षवार ब्यौरा दिया गया हालांकि यह कार्य 2010 में संविदा करने से बहुत समय पहले ही पूरा किया गया था।

नियंत्रक/महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों/लोक सेवा समिति की रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां (एटीएनएस) 31-12-13 की स्थिति के अनुसार

क्रम संख्या	वर्ष	2013-14 (31.12.2013 तक) के दौरान लेखा परीक्षा के पुनरीक्षण के बाद जिन पैराओं/लोक लेखा रिपोर्टों पर एटीएनएस लोक लेखा समिति को प्रस्तुत की गई हैं, उनकी संख्या	उन पैराओं/लोक लेखा रिपोर्टों का ब्यौरा जिन पर 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां लंबित हैं	लेखा परीक्षा को भेजी गई एटीएनएस की संख्या	उन एटीएनएस की संख्या जो भेजी गई लेकिन अभ्युक्तियों के साथ वापस भेज दी गई और लेखा परीक्षा जिनकी मंत्रालय द्वारा पुनः प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा कर रहा है	उन एटीएनएस की संख्या जिनका लेखा परीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर लिया गया है लेकिन जो मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं की गई हैं
1	1987-88				1	
2	1988-89				2	
3	1990-91				1	
4	1996-97				1	
5	1997-98				2	
6	2001-02			1	1	
7	2002-03					
8	2003-04				1	
9	2004-05				3	
10	2005-06	1			1	
11	2006-07					
12	2007-08			1		
13	2008-09	2		1	3	
14	2009-10			2	3	
15	2010-11	13		5	10	
16	2011-12	16	2	13	5	
17	2012-13	17	2	22	12	1
	योग	49	4	45	46	1

# रक्षा उत्पादन विभाग (2012-13) के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी)

## खंड - 1

### दृष्टि, ध्येय, लक्ष्य और कार्य

#### दृष्टि

हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए आवश्यक हथियार, प्लेटफार्मा, हथियारों, गोला-बारूद और अन्य सामग्रियों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना।

#### ध्येय

1. देश के भीतर ही नवोन्नत रक्षा उपस्करों के डिजाइन, विकास और उत्पादन की सामर्थ्य को प्रोत्साहन देना। 2. सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली आयुध निर्माणियों, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों की सामर्थ्य एवं क्षमता में वृद्धि को सुगम बनाना। 3. रक्षा उपस्करों की गुणवत्ता सुधारने और इनकी समय पर सुपुर्दगी करने के लिए नीतियों, पहलों और प्रोत्साहनों को बढ़ावा देना। 4. भारतीय रक्षा उद्योग को आत्म-निर्भर बनाने के लिए अनुसंधान एवं विकास के कार्य को बढ़ावा देना। 5. आयुध निर्माणी बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और निजी क्षेत्र की विशाल रक्षा कंपनियों को विश्व रक्षा उपस्करों की गुणवत्ता स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए इनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाना।

#### लक्ष्य

1. सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकतानुसार उन्हें हथियारों/गोला-बारूद और अन्य उपस्करों की समय पर सुपुर्दगी देना।
2. हमारे देश की सशस्त्र सेनाओं की अधिप्राप्ति में भारतीय उत्पादों की हिस्सेदारी को बढ़ाना।
3. अधुनिकीकरण और क्षमता विकास
4. अनुसंधान एवं विकास की अधिक से अधिक परियोजनाएं आरंभ करना और इनके लिए आवंटन में वृद्धि करना।
5. सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणी बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधारों को सुगम बनाना एवं इनका मार्गदर्शन करना।
6. अधिप्राप्ति को अधिक पारदर्शी बनाना।

#### कार्य

1. रक्षा उपस्करों का स्वदेशीकरण, विकास एवं उत्पादन।
2. रक्षा उपस्करों के विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
3. नागर विमानन मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग के साथ जुड़े उपभोगताओं को छोड़कर अन्य सभी के मध्य समन्वय और वैमानिकी उद्योग का विकास।
4. रक्षा निर्यात और रक्षा उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
5. डीजीक्यूए एवं डीजीएक्यूए सहित रक्षा गुणता आश्वासन संगठनों का निरीक्षण करना।
6. मानकीकरण निदेशालय के माध्यम से रक्षा उपस्करों और भंडारों के मानकीकरण को बढ़ावा देना।
7. निम्नलिखित संगठनों और उपक्रमों के कार्यों का निरीक्षण और मानीटरिंग करना: (क) आयुध निर्माणी बोर्ड एवं आयुध निर्माणियां (ख) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (ग) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (घ) माझगांव डॉक लिमिटेड (ड.) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (च) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (छ) भारत डायनामिक्स लिमिटेड (ज) मिश्र धातु निगम लिमिटेड (झ) बीईएमएल लिमिटेड (ञ) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड



**रक्षा उत्पादन विभाग का कार्यानिष्पादन आकलन [रिपोर्ट प्रस्तुत उपलब्धियां] (2012-13)**  
**कार्यानिष्पादन आकलन रिपोर्ट**

उद्देश्य	महत्व	कार्यवाही	सफलता सूचक	यूनिट	महत्व	लक्ष्य/मानदण्ड/मान					कार्य निष्पादन			
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	औसत 70%	खराब 60%	उपलब्धियां	सं. स्कोर	वेटेड स्कोर	जैसा कि एचपीसी द्वारा यथा अनुमोदित
1 सैन्य बलों को उनकी आवश्यकता अनुसार शस्त्रों/ गोलाबारूदों और उपकरणों की आपूर्ति करना	30.00	वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2013 तक सुपुर्दगी के लिए देय (200 अददे) कवचित वाहनों की सुपुर्दगी	सुपुर्द की गई संख्या	संख्या	4.00	200	190	181	172	163	194	94.0	3.76	194
		वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2013 तक सुपुर्दगी के लिए देय गोलाबारूद की सुपुर्दगी	सुपुर्द की गई गोलाबारूद की मूल्य	करोड़ रु० में	4.00	4990	4740	4503	4278	4064	5036	100.0	4.0	5036
		वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2013 तक सुपुर्दगी के लिए देय (1100 अददे) पिनाका रॉकेट की सुपुर्दगी	सुपुर्द की गई संख्या	संख्या	4.00	1100	1045	992	943	895	918	64.79	2.59	918
		वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2013 तक सुपुर्दगी के लिए देय (50 अददे) एलएफजी गन की सुपुर्दगी	सुपुर्द की गई संख्या	संख्या	3.00	50	47	45	43	41	44	75.0	2.25	44
		वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2013 तक सुपुर्दगी के लिए देय (6000 अददे) प्रेक्षपास्त्रों की सुपुर्दगी	सुपुर्द की गई संख्या	संख्या	4.00	6000	5700	5415	5144	4887	5530	84.04	3.36	5530
		वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2013 तक सुपुर्दगी के लिए (14 अददे) देय सुपुर्द किए गए पोतों की सं०	सुपुर्द की गई संख्या	संख्या	4.00	14	13	12	11	10	9	0.0	0.0	9
		वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2013 तक सुपुर्दगी के लिए (73 अददे) देय विमान/हेलीकॉप्टरों की सुपुर्दगी	सुपुर्द की गई संख्या	संख्या	3.00	73	69	65	62	59	55	0.0	0.0	55
		वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2013 तक सुपुर्दगी के लिए (20 अददे) सेना को देय डिजिटल रेडियो ट्रकिंग सिस्टम (डीआरटीएस) की सुपुर्दगी	सुपुर्द की गई संख्या	संख्या	1.50	20	15	10	7	5	19	98.0	1.47	19

**रक्षा उत्पादन विभाग का कार्यानिष्पादन आकलन [रिपोर्ट प्रस्तुत उपलब्धियां] (2012-13)**  
**कार्यानिष्पादन आकलन रिपोर्ट**

उद्देश्य	महत्व	कार्यवाही	सफलता सूचक	यूनिट	महत्व	लक्ष्य/मानदण्ड/मान						कार्य निष्पादन		
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	औसत 70%	खराब 60%	उपलब्धियां	सं स्कोर	वेटेड स्कोर	जैसा कि एचपीसी द्वारा यथा अनुमादित
2 हमारे सैन्य बलों द्वारा अधिप्राप्ति में भारतीय उत्पादों के अंश में वृद्धि	30.00	वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2013 तक सुपुर्दगी के लिए (10000 अर्द्ध) सेना को देय पैसीन नाइट विजन डिवाइस की सुपुर्दगी	सुपुर्द की गई संख्या	संख्या	1.50	10000	9000	8000	7000	6000	10364	100.0	1.5	10364
		वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2013 तक सुपुर्दगी के लिए (50 अर्द्ध) देय रखार एवं अग्नि निर्वंत्रण की सुपुर्दगी	संख्या सुपुर्द	संख्या	0.99	50	45	40	35	30	60	100.0	0.99	60
		विनिर्माण विक्रेता की सं० में वृद्धि	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता में वृद्धि	%	6.00	6	5	4	3	2	6	100.0	6.0	6
3 आधुनिकीकरण एवं क्षमता संवर्धन	15.00	निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना	मंजूर की गई लाइसेंसों की संख्या	संख्या	6.00	50	45	40	35	32	50	100.0	6.0	50
		टी 90 टैंकों के स्वदेशीकरण में वृद्धि करना, स्वदेशीकरण के इसके वर्तमान स्तर 60% से बढ़ाकर इसे सकल रूप से 65% करना	वर्तमान स्तर से स्वदेशीकरण के प्रतिशत में संघयी वृद्धि	%	6.00	5	4	3	2	1	5	100.0	6.0	5
		सुखाई विमान के स्वदेशीकरण में वृद्धि करना, स्वदेशीकरण के इसके वर्तमान स्तर 33% से बढ़ाकर इसे सकल रूप से 41% करना	वर्तमान स्तर से स्वदेशीकरण के प्रतिशत में संघयी वृद्धि	%	6.00	8	6	4	2	1	5	100.0	6.0	8
		पी-17 के स्वदेशीकरण में वृद्धि करना, स्वदेशीकरण के इसके वर्तमान स्तर 53% से बढ़ाकर इसे सकल रूप से 57% करना	वर्तमान स्तर से स्वदेशी-करण की प्रतिशत में संघयी वृद्धि	%	6.00	4	3	2	1	4	100.0	6.0	4	
		आयुध निर्माणियों का आधुनिकीकरण	आधुनिकीकरण पर हुआ व्यय	करोड़ रु० में	1.00	900	855	812	771	732	748	64.1	0.64	748

**रक्षा उत्पादन विभाग का कार्यानिष्पादन आकलन [रिपोर्ट प्रस्तुत उपलब्धियां] (2012-13)**  
**कार्यानिष्पादन आकलन रिपोर्ट**

उद्देश्य	महत्व	कार्यवाही	सफलता सूचक	यूनिट	महत्व	लक्ष्य/मानदण्ड/मान						कार्य निष्पादन		
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	औसत 70%	खराब 60%	उपलब्धियां	सं स्कोर	वेटेड स्कोर	जैसा कि एचपीसी द्वारा यथा अनुमोदित
		आयुध निर्माणी इटारसी में एमजी संयंत्र की क्षमता संवर्धन आयुध निर्माणी बोर्ड की महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजनाएं आयुध निर्माणी, नालंदा के विशिष्ट उत्पादों के लिए (सृजन/क्षमता का संवर्धन) शिपयाडॉ का आधुनिकीकरण	क्षमता संवर्धन पर हुआ व्यय प्रतिशत पूर्ण	करोड़ ₹0 में %	1.00	38.8	36.8	34.8	32.8	30.8	32.85	70.25	0.7	32.85
		शिपयाडॉ का आधुनिकीकरण	आधुनिकीकरण पर किया गया व्यय	करोड़ ₹0 में	1.00	829	788	749	712	676	332.69	0.0	0.0	332.69
		शिपयाडॉ (एमडीएल) में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना (गोलियथ क्रेन घटक का पूरा होना)	प्रतिशत पूर्ण	%	1.00	100	95	90	85	80	100	100.0	1.0	100
		बीडीएल का आधुनिकीकरण	आधुनिकीकरण पर किया गया व्यय	करोड़ ₹0 में	1.00	60	57	54	51	48	72.14	100.0	1.0	72.14
		बीडीएल में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना- (कॉनकर्स एम एटीजीएम का क्षमता संवर्धन)	प्रतिशत पूर्ण	%	1.00	50	45	40	35	30	14	0.0	0.0	14
		एचएएल का आधुनिकीकरण	आधुनिकीकरण पर किया गया व्यय	करोड़ ₹0 में	1.00	450	428	407	387	368	456	100.0	1.0	456
		एचएएल में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजनाएं परिवहन विमान प्रभाग एचएएल, कानपुर में उत्पादन परिचालन उच्च मूल्य वाली मशीनरी की शुरुआत संविदा को अंतिम रूप देने के लिए अर्जित प्रतिशतता	पूरा किया गया चरण	%	1.00	100	90	80	70	60	92	92.0	0.92	92
		बीइएल का आधुनिकीकरण	आधुनिकीकरण पर किया गया व्यय	करोड़ ₹0 में	1.00	342	325	309	294	279	347	100.0	1.0	347

**रक्षा उत्पादन विभाग का कार्यानिष्पादन आकलन [रिपोर्ट प्रस्तुत उपलब्धियां] (2012-13)**  
**कार्यानिष्पादन आकलन रिपोर्ट**

उद्देश्य	महत्व	कार्यवाही	सफलता सूचक	यूनिट	महत्व	लक्ष्य/मानदण्ड/मान						कार्य निष्पादन		
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	औसत 70%	खराब 60%	उपलब्धियां	संस्कोर	वेटेड स्कोर	जैसा कि एचपीसी द्वारा यथा अनुमोदित
		बीइएमएल में महत्वपूर्ण परियोजनाएं (फील्ड के नजदीक एन्टीना मापक सुविधा का सृजन)	प्रतिशत पूर्ण	%	1.00	100	95	90	85	80	100	100.0	1.0	100
		मिथानि का आधुनिकीकरण	आधुनिकीकरण पर किया गया व्यय	करोड़ ₹0 में	1.00	57	54	51	48	80.24	100.0	1.0	80.24	
		मिथानि में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजनाएं/सिगरेलिंग मिल घटक का पूरा होना	प्रतिशत पूर्ण	%		100	95	90	85	80	100.0	1.0	100	
		बीइएमएल का आधुनिकीकरण	बीइएमएल के आधुनिकीकरण पर किया गया व्यय	करोड़ ₹0 में	120	114	108	102	97	88.26	0.0	0.0	88.26	
		बीइएमएल में महत्वपूर्ण परियोजनाएं (एयरोस्पेस एस इ जेड परियोजना देवानाहली में एक हेंगर का निर्माण)	प्रतिशत पूर्ण	%	1.00	100	90	80	70	60	0	0.0	0.0	0
	3.00	डी पी एस यूज में आर एण्ड डी प्रयास	किया गया व्यय	करोड़ ₹0 में	2.00	1533	1454	1379	1308	1240	2406.39	100.0	2.0	2406.39
		ओ एफ बी में आर एण्ड डी प्रयास	किया गया व्यय	करोड़ ₹0 में	1.00	46	43	41	39	37	27.49	0.0	0.0	27.49
	5.00	डीपीएसयू और आरसी द्वारा हस्ताक्षरित किये गये समझौता ज्ञापन का कठोरतापूर्वक अनुवीक्षण करना	डीपीएसई द्वारा सर्वोत्कृष्ट रेटिंग	संख्या	1.50	5	4	3	2	1	5	100.0	1.5	5
		डीपीएसई द्वारा 'बहुत अच्छा' रेटिंग	संख्या	1.00		3	2	1	0	0	3	100.0	1.0	3
		आर एफ डी और आर सी की सब्सीडियरीज को अंतिम रूप देना	समय पर पूरा हुआ	दिनांक	1.00	30/04/2012	10/05/2012	15/05/2012			30/4/2012	100.0	1.0	30/4/2012

**रक्षा उत्पादन विभाग का कार्यानिष्पादन आकलन [रिपोर्ट प्रस्तुत उपलब्धियां] (2012-13)**  
**कार्यानिष्पादन आकलन रिपोर्ट**

उद्देश्य	महत्व	कार्यवाई	सफलता सूचक	यूनिट	महत्व	लक्ष्य/मानदण्ड/मान						कार्य निष्पादन		
						उत्कृष्ट 100%	वृद्ध अच्छा 90%	अच्छा 80%	औसत 70%	खराब 60%	उपलब्धियां	संस्कोर	वेटेड स्कोर	जैसा कि एचपीसी द्वारा यथा अनुमोदित
		प्रयोगशाला के गुणवत्ता में सुधार	एनएबीएल प्रत्यापन प्राप्त प्रयोगशालाओं की संख्या	संख्या	1.50	8	6	5	4	3	8	100.0	1.5	8
6 अधिप्राप्ति में पारदर्शिता बढ़ाना	2.00	अधिप्राप्ति में पारदर्शिता बढ़ाना	डीपीएसयू और ऑएफबी से 03 अधिकारियों की समिति द्वारा ई अधिप्राप्ति की लेखा परीक्षा	दिनांक	2.00	30/09/2012	31/10/2012	30/11/2012	25/09/2012	100.0	2.0	25/09/2012		
परिणाम रूपरेखा प्रणाली (आर एफ डी) प्रणाली का दक्षतापूर्ण संचालन	5.00	अनुमोदन के लिए मसौदे को समय से प्रस्तुत करना वर्ष 2011-12 आर एफ डी के लिए परिणामों को समय से प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण कार्यनीतिक योजनाओं की समीक्षा	समय पर प्रस्तुतिकरण समय पर प्रस्तुतिकरण अगले 05 वर्षों के लिए कार्यनीतिक योजनाओं की समीक्षाको अंतिम रूप देना	दिनांक	2.0	05/03/2012	06/03/2012	07/03/2012	08/03/2012	09/03/2012	27/04/2012	0.0	0.0	27/04/2012
				दिनांक	1.0	01/05/2012	03/05/2012	04/05/2012	05/05/2012	06/05/2012	04/05/2012	80.0	0.8	04/05/2012
				दिनांक	2.0	10/12/2012	15/12/2012	20/12/2012	24/12/2012	31/12/2012	10/12/2012	100.0	2.0	10/12/2012
प्रशासनिक सुधार	6.00	भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए प्रशासक उपायों का कार्यान्वयन करना आइएसओ 9001 प्रमाणीकरण कार्यान्वित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	2.0	100	95	90	85	80	83	66.0	1.32	91.396
				दिनांक	2.0	10/12/2012	15/12/2012	20/12/2012	24/12/2012	31/12/2012	10/12/2012	100.0	2.0	05/12/2012
		विभागीय नवोन्मेष कार्य योजना (आईएपी) को समय से तैयार करना	समय पर प्रस्तुतिकरण	दिनांक	2.0	01/05/2013	02/05/2013	03/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	01/05/2013	100.0	2.0	01/05/2013



**रक्षा उत्पादन विभाग का कार्यानिष्पादन आकलन [रिपोर्ट प्रस्तुत उपलब्धियां] (2012-13)**  
**कार्यानिष्पादन आकलन रिपोर्ट**

उद्देश्य	महत्व	कार्यवाही	सफलता सूचक	यूनिट	महत्व	लक्ष्य/मानदण्ड/मान						कार्य निष्पादन		
						उत्कृष्ट	वृद्ध अच्छा	अच्छा	औसत	खराब	उपलब्धियां	सं स्कोर	वेटेड स्कोर	जैसा कि एचपीसी द्वारा यथा अनुमोदित
। आन्तरिक दक्षता / अनुक्रियाशीलता को बेहतर बनाना/ मंत्रालय/विभाग को सेवा प्रदान करना	2.00	सर्वोत्तम कार्यान्वयन	नागरिक चार्टर की समीक्षा तथा पुनः प्रस्तुतीकरण करना	दिनांक	1.0	10/12/2012	15/12/2012	20/12/2012	24/12/2012	31/12/2012	04/10/2012	100.0	1.0	04/10/2012
			जन शिकायत निवारण प्रणाली क कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	%	1.0	100	90	80	70	60	20.70	0.0	0.0	20.70
			वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद के समक्ष रिपोर्ट की प्रस्तुत की तिथि से नियत तिथि (4 महीना) के भीतर प्रस्तुत एटीएन की प्रतिशतता	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5	100
फ्रेमवर्क वित्तीयजवाबदेही ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करना	2.00	सी एण्ड एजी के पैराओं पर एटीएन का समय से प्रस्तुतीकरण	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद के समक्ष रिपोर्ट की प्रस्तुतीकरण की तिथि से नियत तिथि (6 माह) के भीतर प्रस्तुत किए गए एटीआरएस का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60	0	0.0	0.0	0
			पीएसी रिपोर्ट पर पीएसी सचिवालय को एटीआर समय से प्रस्तुत करना	%	0.5	100	90	80	70	60	73.33	0.37	73.33	
		31.03.2012 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत सीएजी (कैम) रिपोर्ट के लेखा परीक्षा षेडों पर लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाये एटीआर का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60	73.33	0.37	73.33	
			31.03.2012 से पहले संसद को प्रस्तुत की गई पीएसी रिपोर्ट पर लंबित एटीआर का शीघ्र निपटान	%	0.5	100	90	80	70	60	0	0.0	0.0	0

• अनिवार्य लक्ष्य

कुल संयुक्त स्कोर : 79.08  
पीएमडी संयुक्त : 79.4

**खण्ड 3 :**  
**कार्य निष्पादन आकलन रिपोर्ट**

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 10/11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए संक्षिप्त मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य
सैच्य बलों को उसके आवश्यकतानुसार शस्त्रों/गोला बारूदों और उपकरणों की समय से सुपुर्दगी	[1.1] वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2013 सुपुर्दगी के लिए देय कबचित वाहनों की सुपुर्दगी (200 अदद)	[1.1.1] सुपुर्द की गई संख्या		-	190	-	-	-
	[1.2] वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2013 तक सुपुर्दगी के लिए देय गोला बारूदों की सुपुर्दगी	[1.2.1] सुपुर्द की गई गोला बारूदों का मूल्य		-	4740	-	-	-
	[1.3] वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2013 तक सुपुर्दगी के लिए देय पिनाका सॉकेट की सुपुर्दगी (1100 अदद)	[1.3.1] सुपुर्दगी की संख्या	संख्या	-	-	1045	-	-
	[1.4] वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2013 तक सुपुर्दगी के लिए देय एलफजी गनों की सुपुर्दगी (50 अदद)	[1.4.1] सुपुर्दगी की संख्या	संख्या	-	-	47	-	-
	[1.5] वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2013 तक सुपुर्दगी के लिए देय मिसाइलों की सुपुर्दगी (6000 अदद)	[1.5.1] सुपुर्दगी की संख्या	संख्या	-	-	5700	-	-
	[1.6] वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2013 तक सुपुर्दगी के लिए देय पोतों की सुपुर्दगी (14 अदद)	[1.6.1] सुपुर्दगी की संख्या	संख्या	-	-	13	-	-
	[1.7] वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2013 तक सुपुर्दगी के लिए देय विमान/हेलीकॉप्टर की सुपुर्दगी (73 अदद)	[1.7.1] सुपुर्दगी की संख्या	संख्या	-	-	69	-	-

**खण्ड 3 :**  
**कार्य निष्पादन आकलन रिपोर्ट**

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 10/11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए संक्षिप्त मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य
	[1.8] वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2013 तक सुपुर्दगी के लिए सेना को देय डिजिटल रेडियो ट्रैकिंग सिस्टम ( डीआरटीएस) की सुपुर्दगी (20 अद्व)	[1.8.1] सुपुर्दगी की संख्या	संख्या	-	-	15	-	-
	[1.9] वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2013 तक सुपुर्दगी के लिए देय सेना के लिए मैसिव नाईट विजन डिवाइस की सुपुर्दगी (1000 अद्व)	[1.9.1] सुपुर्दगी की संख्या	संख्या	-	-	9000	-	-
	[1.10] वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2013 तक सुपुर्दगी के लिए देय खार एवं अग्नि नियंत्रण प्रणाली की सुपुर्दगी (50 अद्व)	[1.10.1] सुपुर्दगी की संख्या	संख्या	-	-	45	-	-
[2] हमारे सैन्य बलों द्वारा अधिप्राप्ति में भारतीय उत्पादों के अंश में वृद्धि की जा रही है	[2.1] विनिर्माण विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि	[2.1.1] विगत की वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि	%	-	-	5	-	-
	[2.2] निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना ।	[2.2.1] मंजूर की गई लाइसेंसों की संख्या	संख्या	-	-	45	-	-
	[2.3] टी-90 टैंकों का स्वदेशीकरण में वृद्धि करना, स्वदेशीकरण के वर्तमान स्तर (60S) से बढ़ाकर इसे संचयी रूप से (65S) करना	[2.3.1] वर्तमान स्तर से स्वदेशीकरण प्रतिशत में संचयी वृद्धि	%	-	-	4	-	-
	[2.4] सुखोई विमानों का स्वदेशीकरण कर इसके स्वदेशीकरण के वर्तमान स्तर (33S) से बढ़ाकर इसे संचयी रूप से (41S) करना	[2.4.1] वर्तमान स्तर से स्वदेशीकरण प्रतिशत में संचयी वृद्धि	%	-	-	6	-	-

**खण्ड 3 :**  
**कार्य निष्पादन आकलन रिपोर्ट**

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 10/11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए संक्षिप्त मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य
	[2.4] पी-17 का स्वदेशीकरण कर इसके स्वदेशीकरण के वर्तमान स्तर (33S) से बढ़ाकर इसे संघी रूप से (41S) करना	[2. 5.1] वर्तमान स्तर से स्वदेशीकरण प्रतिशत में संघी वृद्धि	%	-	-	3	-	-
[3] आधुनिकीकरण एवं क्षमता संवर्धन	[3.1] आयुध निर्माणियों का आधुनिकीकरण	[3. 1.1] आधुनिकीकरण पर किया गया व्यय	करोड़ ₹0 में	-	-	855	-	-
	[3.2] आयुध निर्माणी, इ। एस्सी में एनजी प्लॉट का क्षमता संवर्धन	[3. 2.1] क्षमता का संवर्धन पर किया गया व्यय	करोड़ ₹0 में	-	-	36.8	-	-
	[3.3] आयुध निर्माणी बोर्ड की महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना नालन्दा के विनिर्दिष्ट उत्पादों के लिए क्षमता का सृजन/संवर्धन	[3. 3.1] S पूर्ण	%	-	-	41	-	-
	[3.4] शिपयार्डों का आधुनिकीकरण	[3. 4.1] आधुनिकीकरण पर किया गया व्यय	करोड़ ₹0 में	-	-	788	-	-
	[3.5] (एमडीएल) शिपयार्ड में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना (गोलियथ क्रेन घटक की पूर्णता)	[3. 5.1] S पूर्ण	%	-	-	95	-	-
	[3.6] बीडीएल का आधुनिकीकरण	[3. 6.1] आधुनिकीकरण पर किया गया व्यय	करोड़ ₹0 में	-	-	57	-	-
	[3.7] बीडीएल में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना (हैट्टु-व् एटीजीएम का क्षमता विस्तार)	[3. 7.1] S पूर्ण	%	-	-	45	-	-

**खण्ड 3 :**  
**कार्य निष्पादन आकलन रिपोर्ट**

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 10/11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए संक्षिप्त मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य
	[3.8] एचएएल का आधुनिकीकरण	[3. 8.1] आधुनिकीकरण पर किया गया व्यय	करोड़ ₹0 में	-	-	428	-	-
	[3.9] एचएएल में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना (परिवहन विमान प्रभाग, एच-एएल कानपुर में उच्च मूल्य संयंत्रों से उत्पादन सक्रिय आरंभ- संविदा को अंतिम रूप देने के लिए अर्जित प्रतिशत	[3. 9.1] पूरा किया गया चरण	%	-	-	90	-	-
	[3.10] बीईएल का आधुनिकीकरण	[3. 10.1] आधुनिकीकरण पर किया गया व्यय	करोड़ ₹0 में	-	-	325	-	-
	[3.11] बीईएल में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना (फील्ड के नजदीक एण्टीना मापण सुविधा का सृजन)	[3. 11.1] S पूर्ण	%	-	-	95	-	-
	[3.12] मिथानि का आधुनिकीकरण	[3. 12.1] आधुनिकीकरण पर किया गया व्यय	करोड़ ₹0 में	-	-	57	-	-
	[3.13] मिथानि में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजनाएं । रिग सोलिंग मिल घटक का कार्य पूर्ण	[3. 13.1] S पूर्ण	%	-	-	95	-	-
	[3.14] बीईएमएल का आधुनिकीकरण	[3. 14.1] आधुनिकीकरण पर किया गया व्यय	करोड़ ₹0 में	-	-	114	-	-
	[3.15] बीईएल में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना (एयरोस्पेस एसइजेड परियोजना देवनाहली) में एक हैंगर का निर्माण	[3. 15.1] S पूर्ण	%	-	-	90	-	-



**खण्ड 3 :**  
**कार्य निष्पादन आकलन रिपोर्ट**

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 10/11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए संक्षिप्त मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य
[4] और अधिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को शुरू करना और आर एण्ड डी के लिए आबंटन बढ़ाना	[4.1] डीपीएस यूज में आर एण्ड डी प्रयास	[4. 1.1] किया गया व्यय	करोड़ ₹0 में	-	-	1454	-	-
	[4.2] ओएफबी में अनुसंधान एवं विकास प्रयास	[4. 2.1] किया गया व्यय	करोड़ ₹0 में	-	-	43	-	-
[5] डीपीएसयू और ओएफबी के कार्यकलापों में सुविधा उपलब्ध कराना और सुधार पर नजर रखना	[5.1] डीपीएसयू और ओएफबी द्वारा हस्ताक्षर किए गए							
समझौता ज्ञापन का अनुवीक्षण करना	[5. 1.1] डीपीएसई द्वारा सर्वोत्कृष्ट रेटिंग्स	संख्या	-	-	4	-	-	-
	[5. 1.2] डीपीएसई द्वारा बहुत अच्छा रेटिंग्स	संख्या	संख्या	-	-	2	-	-
	[5.2] आरसी की आरफडी सब्सिडियरी को अंतिम रूप देना	[5. 2.1] समय से समापन	दिनांक	-	-	10/05/2012	-	-
	[5.3] प्रयोगशाला की गुणवत्ता सुधारना	[5. 3.1] एनएबीएल प्रत्यापन प्राप्त करने वाले प्रयोगशालाओं की संख्या	संख्या			6		
[6] अधिप्राप्ति में पारदर्शिता बढ़ाना	[6.1] अधिप्राप्ति में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए	[6. 1.1] डीपीएसयू और ओएफडी अधिकारियोंकी 3 समिति द्वारा लेखा परीक्षा की अधिप्राप्ति	दिनांक			31/10/2012		

**खण्ड 3 :  
कार्य निष्पादन आकलन रिपोर्ट**

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 10/11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए संक्षिप्त मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य
I आरएफडी प्रणाली का सक्षमकार्यनिष्पादन	अनुमोदनार्थ मसौदे को समय से प्रस्तुत करना वर्ष 2011-12 आरएफडी के लिए परिणामों की समय से प्रस्तुती	समय से प्रस्तुती	दिनांक	05/03/2012	06/03/2012	27/04/2012	08/03/2012	09/03/2013
	रणनीति योजना की समीक्षा	समय से प्रस्तुती	दिनांक	01/05/2012	03/05/2012	03/05/2012	05/05/2012	06/05/2012
	अगले पांच वर्षों के लिए रणनीतिक योजना की समीक्षा को अंतिम रूप देना	अगले पांच वर्षों के लिए रणनीतिक योजना की समीक्षा को अंतिम रूप देना	दिनांक	10/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	24/12/2012	31/12/2012
I प्रशासनिक सुधार	भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए छोटे रणनीति का का क्रियान्वयन	क्रियान्वयन का प्रतिशत	%	100	95	95	85	80
	आइएसओ 9001 प्रमाणीकरण-क्रियान्वित करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करना	आइएसओ 9001 प्रमाणीकरण-क्रियान्वित करने के लिए एक कार्य योजना को अंतिम रूप देना	दिनांक	10/12/2012	15/12/2012	15/12/2012	24/12/2012	31/12/2012
	विभागीय नवाचार कार्य योजना (ईएपी) को समय से तैयार करना	समय से प्रस्तुती	दिनांक	05/07/2012	06/07/2012	02/05/2013	08/07/2012	09/07/2012
I मंत्रालय/विभाग की आन्तरिक सक्षमता/संवर्धनशीलता सेवा प्रदान करने को बेहतर बनाना	सेवोत्तम का क्रियान्वयन	सिटीजन चार्टर की समीक्षा और पुनः प्रस्तुत करना	दिनांक	10/12/2012	15/03/2013	15/12/2012	24/12/2012	31/12/2012
		लोक शिकायत निवारण प्रणाली के क्रियान्वयन का स्वतंत्र लेखा परीक्षा	%	100	95	95	85	80
I वित्तीय जवाबदेही फ्रेमवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करना	सी एण्ड एजी के लेखा परीक्षाओं पर एटीएन की समय से प्रस्तुति	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद के लिए रिपोर्ट की प्रस्तुती की तिथि से देय तिथि (4 महीने) के भीतर अधिकतर एटीएन प्रस्तुत कर दिया गया ।	%	100	90	90	70	60

**खण्ड 3 :**  
**कार्य निष्पादन आकलन रिपोर्ट**

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 10/11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए संक्षिप्त मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य
	पीएसी रिपोर्ट पर पीएसी सचिवालय को ए टी आर की समय से प्रस्तुति	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद के लिए रिपोर्ट की प्रस्तुति की तिथि से देय तिथि (6 माह) के भीतर अधिकतर एटीआर प्रस्तुत कर दिया जाए	%	100	90	90	70	60
	31.03.2012 से पहले संसद को प्रस्तुत सी एण्ड ए जी रिपोर्ट की लेखा पैराओं पर लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाए ए टी एन का प्रतिशत	%	100	90	90	70	60
	31.03.2012 से पहले संसद को प्रस्तुत पीएसी रिपोर्ट पर लंबित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान अधिकांश बकाए ए टी आर को निपटाया गया	%	100	90	90	70	60

## भाग-4

### सफलता सूचकों और प्रस्तावित मापांक प्रणाली का विवरण और परिभाषा

सफलता सूचकों और प्रस्तावित मापांक प्रणाली का विवरण और परिभाषा :

सफलता सूचकों और प्रस्तावित प्रणाली को समय सीमा के संदर्भ में लक्ष्यों की पूरी की जाने वाली प्रतिशतता एवं भौतिक रूप से अर्जित संख्या को सारणी-1 में दर्शाया गया है। रक्षा उत्पादन विभाग के उद्देश्य मूलतया यह सुनिश्चित करने के लिए बने हैं कि आयुध निर्माणियां और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम उन हथियारों, गोला-बारूद, आयुधों और उपस्करों का पर्याप्त संख्या में उत्पादन करें जिनकी हमारे सैन्य बलों को जरूरत है एवं इन्हें समय पर उन्हें सौंपे।

## भाग-5

### अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य निष्पादन अवधारणा

अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य निष्पादन अवधारणा :

उपस्करणों के उत्पादन का निर्धारण सैन्य बलों की जरूरतों के अनुसार किया जाता है। जबकि रक्षा उत्पादन विभाग का लक्ष्य स्वदेशी विनिर्माण को अधिकतम करना है फिर भी इसे आवश्यक रूप से रक्षा क्षमता के बनाने के मातहत रहना पड़ता है। सैन्य बल, उपस्करणों की प्रकृति को तय करते हैं जिनसे रक्षा क्षमता और आगे बढ़े। कई बार, आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को देखते हुए इस प्रकार की प्रौद्योगिकी वाले उपस्करणों का आयात करना पड़ता है। इस प्रकार स्वदेशी उत्पादन और रक्षा उत्पादन विभाग के प्रयासों की सफलता ऐसे कारकों पर आधारित होती है।



**खण्ड 6 :**  
**विभाग/मंत्रालय का परिणाम/प्रभाव**

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता सूचक	यूनिट	वित्त वर्ष 10/11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए संक्षिप्त मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य
1 आयुध निर्माणियों का उत्पादन	सैन्य बल, डीजीक्यूए, ओईएम	कुल निर्णम	करोड़ ₹0 में	11211	11700	12935	13581	14260
2 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपकरणों का कारोबार मूल्य	सैन्य बल, ओईएम, डीजीक्यूए	मात्रा	करोड़ ₹0 में	30086	31590	33170	34829	36570



विशेष बल स्लिथरिंग ओपरेशन पर

पृष्ठ आवरण: भा नौ पो विक्रमादित्य



